राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3	सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का छठा दिवस	संख्या: 3

बुधवार,
05 फरवरी 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं आभार

जोगेश्वर गर्ग, श्री, सरकारी मुख्य सचेतक को जन्म दिन की शुभकामनाएं

श्री अध्यक्ष: आज सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी का जन्म दिन है, सदन की ओर से हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग, सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा खड़े होकर आभार प्रदर्शन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल। श्री लक्ष्मण।

बस्सी के महाविद्यालयों में रिक्त पद

25. श्री लक्ष्मण (बस्सी): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के बस्सी, कानोता तथा बांसखोह में संचालित महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त हैं? विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) बस्सी, कानोता तथा बांसखोह के राजकीय महाविद्यालयों में विषयवार शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभिन्न विषयों में सहायक आचार्यों के 1936 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अभ्यर्थना प्रेषित की गयी है। जिन पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। महाविद्यालयों में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासम्भव भरा जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिए।

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री जी एवं हायर एजुकेशन मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि दो कॉलेज तो ऐसे हैं जो केवल अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही चल रहे हैं, जैसे बांसखोह एवं कानोता, वहां एक भी पोस्टिंग नहीं है। बस्सी के कॉलेज में विज्ञान के विषय में एक में पोस्टिंग है, बाकी खाली हैं। विद्या संबल के भरोसे तो शिक्षा का बंटाढार हो रहा है। आपने इसमें जवाब दिया है कि यथासंभव, तो यथासंभव का मतलब क्या है? प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? इनका आप स्पष्ट जवाब दें, आप शिक्षा को क्यों इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके बस्सी में 18 पद स्वीकृत हैं और 16 भरे हुए हैं, 2 रिक्त पद हैं। आपके तीनों कॉलेजों में 90 परसेंट पद भरे हुए हैं। आपकी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसखोह में 7 पद स्वीकृत हैं और पूरे 7 पद भरे हुए हैं। आपके राजकीय महाविद्यालय कानोता में 7 पद स्वीकृत हैं और उनमें से 6 पद भरे हैं, एक पद रिक्त है, आपके 90 परसेंट पद भरे हुए हैं।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भरे हुए नहीं हैं, यह तो शिक्षा संबल के अतिथि शिक्षक हैं, स्थाई पोस्टिंग तो दोनों ही कॉलेजों में नहीं है। बस्सी के कॉलेज में विज्ञान विषय में एक में पोस्टिंग है, बाकी तो आपके अतिथि टीचर्स से करवा रहे हैं, पदस्थापन कहां है?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्या संबल में कॉलेजेज ज्यादा खुली हैं तो वहां विद्या संबल ले रखे हैं और उनमें हम गैस फैक्ल्टी से काम ले रहे हैं। बच्चों के भविष्य की हमें चिंता है और भजन लाल जी की सरकार निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के लिये अच्छा कार्य करेगी।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): साहब, जल्दी भर्ती करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेश घोगरा।

रामसागडा (डूंगरपुर) में महिला छात्रावास खोलने की कार्ययोजना

26. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के तहसील मुख्यालय रामसागडा में महिला छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला डूंगरपुर के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में संचालित बालक एवं बालिका छात्रावासों में नामांकन बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले के जनजाति छात्रावासों में खेल प्रशिक्षक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा महिला छात्रावास स्वीकृत नहीं किये जाते हैं।

(2) जनजाति बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर जिले में संचालित बालक-बालिका आश्रम छात्रावास, खेल छात्रावास, कॉलेज छात्रावास, बहूद्देशीय छात्रावास एवं आवासीयविद्यालय में कुल प्रवेशित क्षमता 6020 के विरूद्ध 5817 विद्यार्थी नामांकित है। छात्रावासों में छात्र क्षमता बढ़ाने का विधिवत औचित्य पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधन व बजट की उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छात्र क्षमता बढ़ाने का परीक्षण कराया जा सकेगा।

(3) डूंगरपुर जिले के जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास में 22 कोच, कॉलेज छात्रावास में 01 कोच एवं खेल छात्रावास में खेल प्रशिक्षक के 04 पद सहित कुल 27 पद स्वीकृत है। बालक आश्रम छात्रावासों में खेल प्रशिक्षक/कोच का पद वर्तमान में स्वीकृत नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: कल जो हमने तय किया था कि उत्तर पढ़ा हुआ मानकर आप पूरक प्रश्न पूछो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पढ़ना चाहिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): पढ़ना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो इस पर आ रहा है। समय कम लगेगा, कल ही तो निर्णय किया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक विनम्र निवेदन है कि सभी प्रश्नों का उत्तर सभी के पास नहीं जाता है। अपनी यह व्यवस्था थोड़ी विधिवत हो जाये, तब तक चलने दें। ....(व्यवधान).... हम सब फ्लोर पर रिकार्ड में लाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर रिकार्ड पर नहीं है। जब तक पढ़ेंगे नहीं, रिकार्ड पर नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष: सभी के टेबलेट पर आ रहा है और साथ में हां और ना लॉबी में रहता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जवाब तो रिकार्ड पर आयेगा तभी होगा। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: कल सब ने हां भरी थी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य पूछना चाहे तो पूछ ले, नहीं तो उत्तर आ गया और सीधा सप्लीमेंट्री पूछता है तो दिक्कत क्या है? आपके टेबलेट में सारे प्रश्न-उत्तर हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): सप्लीमेंट्री पूछ लें, लेकिन माननीय मंत्री महोदय को पढ़ना चाहिये। सदन को पता चलना चाहिये कि जवाब क्या है। ....(व्यवधान)....

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मूल प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी को पढ़ना चाहिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज आपका जन्म दिन है, विराज जाओ आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): ये काहे के लिये खड़े हो गये?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप गलत परम्परा डाल रहे हैं, नहीं उठाया जा सकता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काहे के लिये खड़े हो गये? इनको नियमों का पता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैंने अनुमति दी है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): इनको बिठाइए, बिठाइए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैंने अनुमति दी है, फिर क्यों बोल रहे हो?

व्यवस्था का प्रश्न

सरकार को प्रेषित प्रश्नों की सम्बन्धित विभागों को निर्दिष्टता सरकार का अन्दरूनी विषय

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह लिखा हुआ है कि जनजाति विभाग कोई छात्रावास नहीं खोलता। मेरा यह सुझाव है कि जब इस तरह का प्रश्न हो तो सम्बन्धित डिपार्टमेंट को जाना चाहिये। जब इस विभाग का यह प्रश्न ही नहीं था तो जिससे सम्बन्धित था, उसको यह क्वेश्चन रेफर किया जाना चाहिये था, डेफर किया जाना चाहिये था, तब जाकर यह जवाब आता। इसके उत्तर में ही यह आ गया कि जनजाति विभाग खोलता ही नहीं है, तो उनका तो मूल प्रश्न ही गायब हो गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): खण्ड 2 और 3 का उत्तर भी सुन लो।

श्री अध्यक्ष: माननीय विराजिए, आपके संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि विधान सभा सचिवालय किसको प्रश्न भेजता है, वह तय करते हैं। हमारे जिस मंत्री के पास भी आया, इसमें हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। भले ही वह किसी का भी हो, हम जवाब देने के लिये उत्तरदायी हैं और इसलिए इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को कोई एतराज करने का अधिकार ही नहीं है।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि प्रक्रिया कानून का अध्याय 7 में लिखा हुआ है ....(व्यवधान).... इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रश्न का उत्तर पढ़ा जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को चलने दें। धीरे-धीरे हम एक्सपर्ट हो जायेंगे तो फिर इसको ठीक कर देंगे, यह मेरा निवेदन है। ....(व्यवधान)....

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा नियम प्रक्रिया और

परम्पराओं से चलती है। पहले भी इस प्रकार की व्यवस्था रही है कि क्वेश्चन के आंसर को पढ़ा हुआ माना गया है और माननीय सदस्य को सीधा सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पढ़ना पड़ेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसके बाद भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसके बाद कोई नियम नहीं है, नियम यहां तक ही है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप आसन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: दोनों की बात आ गई, दोनों विराजो। इस विषय पर साधारणत: माननीय सदस्य का प्रश्न किस विभाग का है, वह खुद लिखता है। वह भी सोच समझकर लिखे, ताकि दूसरे विभाग वाला मुद्दा अपने आप समाप्त होगा और हम भी सचिवालय में इसको और चैक करेंगे, ताकि वह सही जगह जाये।

नंबर दो, जो मुद्दा उठा है, मैंने परसों यह व्यवस्था दे दी कि अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर आएं, इसके लिए सबके टेबलेट पर आ जाता है। सम्बन्धित मंत्री के भी आ जाता है और विधायक के भी आ जाता है। बाकी तो कोई पूरक प्रश्न पूछ भी नहीं सकता। इसके अलवा किसी को देखना भी है तो वह दोनों लॉबियों में रहता है, इसलिए इसको पढ़ा हुआ मानकर पूरक प्रश्न पूछेंगे तो अधिक प्रश्न आयेंगे।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को जानकारी रहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था हो गई है, बाकी प्रश्नकाल के बाद। माननीय मंत्री जी, प्रश्नकाल के बाद।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था से सम्बन्धित ही मेरा एक आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: मेरे चैम्बर में आकर बताइए। ....(व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह यू ट्यूब पर लाइव जाता है, जनता को पता चलना चाहिये कि इसका जवाब क्या है। ....(व्यवधान).... माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे प्रार्थना है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: सब लोग बैठिए, आसन पाँवों पर है, बैठिए। ....(व्यवधान).... माननीय संसदीय मंत्री जी, बैठिए। आप बैठिए, बैठिए, इनका अंकित नहीं हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: आपसे आग्रह है आप विराजो। आप माननीय मंत्री महोदय हो, जब एक बार व्यवस्था दे दी और आपको लगता है ....(व्यवधान).... मेरी बात तो पूरी सुनो। यदि व्यवस्था में आपको कोई सुझाव देना है तो मेरे चैम्बर में आइए, अपन डिसकस करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो वह भी करेंगे, लेकिन एक बार जब व्यवस्था दे दी, व्यवस्था

बहस का मुद्दा नहीं होती। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है आप जीरो ऑवर के बाद चैम्बर में आइए, अपन बात करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, आप हमारी बात सुन लें और इस व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें और फिर भी आपको लगे कि नहीं, मेरी व्यवस्था ही सर्वोपरि रहेगी तो फिर इस पर विचार करेंगे, एक बार हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, चैम्बर में सुन लेंगे।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री का जवाब आ गया है, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब भी जनजाति की बात आती है तो सामने वाले सदस्य को या तो बोलने नहीं दिया जाता है या उसकी आवाज दबाई जाती है। प्राचीन काल से भी दबाई गई और आज भी दबाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछो, और कोई बात नहीं।

Msk/rtm/05.02.25/1110/1b

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मैं टीएडी मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग महिला छात्रावास खोलना चाहता है या नहीं, नहीं चाहता है तो क्यों नहीं चाहता है? तो कौनसा विभाग खोलेगा, यह मुझे जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष: ठीक, माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पहली बात तो मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा, उनको जानकारी देना चाहूंगा कि विभाग महिला छात्रावास नहीं खोलता है, न नियमों में है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आपका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है, मेरी समझ में नहीं आता। अगर आपको लगता है, सरकार वहां पर वृद्धाश्रम चलाती है, वहां पर महिला भी रह सकती है, पुरुष भी रहते हैं। आवासीय चलाती है। दूसरा कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आपको प्रश्न पूछने का हक है। यह नहीं, आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछेंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पूछना चाहता हूं कि आप नामांकन क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं? क्या आदिवासियों को उनका हक नहीं दिलाना चाहते?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बैठिये, पहले सुनें। अध्यक्ष महोदय

जी, मैंने हवाला दिया है कि हम नियमों में नहीं खोल सकते हैं, यह नियमों में है। आप नियम बनाते ना, आप भी सरकार में रहे, बनाते नियम।

श्री अध्यक्ष: चलिये, अगला प्रश्न, श्री विनोद कुमार।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): महिला हॉस्टल खोलने का प्रावधान नहीं है, यह मैं आपको जानकारी दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर आ गया है। ...(व्यवधान)... अगला प्रश्न पुकार लिया, बैठें। आप केवल टिप्पणियां कर रहे हैं, पूरक प्रश्न पूछते नहीं हैं। यह नहीं होगा। ...(व्यवधान)... नहीं, आपने दो बार, आपने लगातार तीन मिनट गंवा दिये। कभी मंत्री कैसे बने, कभी यह नहीं है। यह आपका मुद्दा नहीं है। मुख्य मंत्री जी जिसको बनाना चाहेंगे, बनेगा।

अगला प्रश्न। श्री विनोद कुमार।

गोलूवाला उप तहसील का क्रमोन्नयन

27. श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उप तहसील गोलूवाला को तहसील में तथा गंधेली व जाखड़ांवाली को उप तहसील में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): जी नहीं। वर्तमान में गोलूवाला उप तहसील में 03 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं 12 पटवार मण्डल स्थित हैं, जो मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करती है।

वर्तमान में गंधेली व जाखड़ांवाली को उप तहसील बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव राजस्व विभाग में विचाराधीन नहीं है।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): मेरे को उत्तर प्राप्त हो गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उप तहसील गोलूवाला को तहसील बनाने के मापदण्ड क्या हैं? मेरा दूसरा प्रश्न जाखड़ांवाली और गंधेली को उप तहसील बनाने के संबंध में सरकार के क्या मापदण्ड हैं? अगर किसानों की बात हो, आम जन की बात हो, उसको देखते हुए क्या सरकार राहत पहुंचाने का काम करेगी?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): वर्तमान में गोलूवाला उप तहसील में 03 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं 12 पटवार मण्डल स्थित हैं, जो मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करती है, तहसील बनने के लिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, गंधेली व जाखड़ांवाली को उप तहसील में क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं या नहीं, गंधेली रावतसर तहसील का आईएलआर है। इसमें कुल 8 आईएलआर और 29 पटवार मण्डल हैं। जाखड़ांवाली पीलीबंगा तहसील में है, जिसमें 9 आईएलआर और 38 पटवार मण्डल हैं। अगर इन आईएलआर को उप तहसील बनाते हैं तो जो पुरानी तहसील हैं, रावतसर और पीलीबंगा, उन दोनों को बांटा

जाये तो दोनों संभव नहीं है। नॉर्म्स के अनुसार एक तहसील बनाने के लिए 30 पटवार मण्डल एवं 6 व 8 पटवारमण्डलों पर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त होना आवश्यक है।

इसी प्रकार उप तहसील बनाने के लिए 15 पटवार मण्डल एवं 6 व 8 पटवार मण्डलों पर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त होना आवश्यक है। इसलिए राजस्व विभाग के नियमानुसार ये इसमें पात्रता नहीं रखते हैं।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हो गया, चलिए। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 28

श्री मनोज कुमार।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में लम्बित कृषि कनेक्शन

29. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नये कृषि कनेक्शन की डिमांड राशि जमा करवाने के बाद भी कनेक्शन लम्बित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि कनेक्शनों को समय पर जारी करने के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में कितने कृषि कनेक्शन, किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) जी हां। कृषि कनेक्शन नीति-2017 के अनुसार जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार सामान्य श्रेणी में 22.02.2022 तक आवेदकों के कनेक्शन को करने का निर्णय लिया गया था। विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में सामान्य श्रेणी के 22.02.2022 तक आवेदक एवं तुरन्त प्राथमिकता वाले जमा मांग पत्र आवेदकों के 981 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना लंबित है, जिनमें से 102 कनेक्शन फसल खड़ी होने/रास्ता उपलब्ध न होने के कारण कनेक्शन जारी करने का कार्य बाधित है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। उक्त लंबित कृषि कनेक्शन फसल कटने के साथ एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): पुरानी सरकार ने जो कनेक्शन नहीं किये, पुरानी सरकार की गलती के कारण एक-एक साल की डिमांड रही, परन्तु मैं हमारे मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों को दिन में बिजली देने और कनेक्शन जल्दी जारी करने के लिए कुसुम योजना की क्या प्रगति है? इसमें कब तक करेंगे, बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुसुम योजना के तहत तीनों विद्युत वितरण निगमों में कुसुम योजना कंपोनेट 'ए' व 'सी' के अंतर्गत 17155 मेगावाट क्षमता के विभिन्न 33 केवी सब-स्टेशनों पर 6560 सौलर पॉवर प्लांट के लिए स्थान चिह्नित किये गये हैं। प्रदेश में कुसुम कंपोनेट 'ए' के तहत 693 मेगावाट क्षमता के 591 प्लांटों के लिए कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, जिससे 303.25 मेगावाट क्षमता के 257 प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। कुसुम कंपोनेट 'सी' के तहत 4443 मेगवाट क्षमता के 1753 प्लांट लगाने के कार्यादेश दिये जा चुके हैं, जिससे 136 मेगावाट के 56 प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में 5136.50 मेगावाट क्षमता के 2344 प्लांटों के कार्यादेश दिये जा चुके हैं, जिससे 466.40 मेगावाट क्षमता के 313 प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। जिन 33 केवी स्टेशनों को कुसुम योजना के तहत सौलर प्लांट स्थापित कर जोड़ा गया है, उन स्टेशनों से निकलने वाले 11 केवी के फीडरों पर सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिए तुरन्त प्राथमिकता से कनेक्शन जारी करने की योजना है। तथा कुसुम योजना के तहत हमने प्लांट स्थापित किये हैं और आगे जो स्थापित होंगे, उससे हमारे मुख्य मंत्री जी की घोषणा कि हम दो साल में किसानों को दिन में बिजली देंगे, उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): धन्यवाद, मंत्री जी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री डूंगरराम गेदर।

सूरतगढ़ में बसों का संचालन

30. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(1) क्या सरकार सूरतगढ से छतरगढ़, दन्तौर व बज्जु मार्ग पर रोडवेज बस का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सूरतगढ से अनूगढ़ रोड जैतसर (1जीबी) में टिकट खिड़की व बस स्टॉप निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ में सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ मार्ग पर किन-किन स्थानों पर बस स्टॉपेज निर्धारित हैं? क्या रोडवेज बस सभी बस स्टॉपेज पर ठहरती है? यदि नहीं, तों क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ मार्ग पर संचालित लोक परिवहन की कितनी बसों को परमिट जारी किया गया है? बस स्वामी का नाम व बस नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) निगम के सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन किए जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सूरतगढ़ से अनूपगढ़ रोड जैतसर (1 जीबी) पर पूर्व से ही बस स्टॉप निर्धारित है।

उक्त बस स्टॉप से निगम की मात्र 2 बसें ही संचालित होने तथा निगम के सीमित संसाधनों के कारण टिकट खिड़की लगाए जाने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) सूरतगढ से श्रीगंगानगर व अनूपगढ मार्ग पर संचालित निगम बसों हेतु निर्धारित बस स्टॉपेज की सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है, उक्त मार्गों पर संचालित निगम बसें निर्धारित बस स्टॉप पर रुकती हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र में सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर अधिसूचित मार्ग पर 20 बसें एवं सूरतगढ से अनूपगढ अधिसूचित मार्ग पर 20 बसें संचालित हैं, जिसकी सूचना परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट- 3 पर संलग्न है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): साहब, मेरे पास जवाब आ गया है। मैं मंत्री महोदय ये यह पूछना चाहता हूं कि आपने उत्तर में दिया है कि सूरतगढ़ से अनूपगढ़ रोड पर जैतसर (1जीबी) है, वह द्रुतगामी बस का स्टॉप है। जैतसर एक मण्डी है, जहां पुलिस थाना है, तहसील है, कृषि उपज मण्डी है, धान मण्डी है, वहां द्रुतगामी बस का बस स्टैण्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां एक ही बस रुकती है। बहुत सारी बसों का संचालन सूरतगढ़ से अनूपगढ़ होता है, बाकी बसों को रोकने काम, स्टॉप का काम करेंगे, क्या इसकी मंशा है या नहीं, है तो कितनी बसों का स्टॉप करने का आपका विचार है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): सूरतगढ़ से छतरगढ़, दन्तौर, बज्जू मार्ग पर निगम की कोई सेवा पूर्व में नहीं रही है। वर्तमान में निगम के पास सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल संचालित किया जाना संभव नहीं है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सर, मैं सूरतगढ़ और अनूपगढ़ की बात कर रहा हूं, छतरगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर सुन लीजिये।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): रोड ही दूसरा है। सूरतगढ़ से बसें चलती हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आपको दूसरा भी पूरक प्रश्न पूछने देंगे, आप दूसरा पूछना।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपकी सरकार ने भी कोई विचार नहीं रखा। हम वहां यात्री भार देख लेंगे, अगर बैठता है तो जांच करा लेंगे, अगर होगा तो हम करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अब बोलिये।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): दूसरा यह है कि सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर रोड पर बस स्टॉप की सूची आपने दी है, लेकिन लोक परिवहन की बसें 1 एसआर, 15 चक, 22 चक, 22 डीबी, 12 मासी, 3 एचएच और ढाकावाली, इन बस स्टॉपों पर रुकती है, वहां बार-बार

धरना प्रदर्शनों से बसों को रोका जाता है। क्या लोक परिवहन बसों को आप वहां उन बस स्टॉप पर रोकने के लिए पाबंद करेंगे? यदि वे नहीं रुकती हैं तो फिर उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): सूरतगढ़ से गंगानगर व अनूपगढ़ मार्ग पर निगम बसों के स्टॉपेज पूर्व से ही निर्धारित हैं और वे रुक रही हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 31

श्री संदीप शर्मा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री मनीष यादव।

शाहपुरा (जयपुर) में नवीन नलकूप

32. श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में वर्तमान में कितने ट्यूबवैल सूख गए? उक्त ट्यूबवैल के स्थान पर कितने नए ट्यूबवैल स्वीकृत कर खोदे गये तथा कितने स्वीकृति के अभाव में लम्बित हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित ट्यूबवैल स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में विभिन्न पेयजल योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में 22 नलकूप सूखे हैं। जिनमें से 01 नलकूप के विरूद्ध नवीन नलकूप स्वीकृति उपरांत निर्मित करवाया जा चुका है एवं 04 नलकूपों के विरूद्ध नवीन नलकूपों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। शहर/ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार शेष 17 नलकूपों में से शहरी क्षेत्र के 07 नलकूपों के विरूद्ध नवीन नलकूपों के निर्माण हेतु स्वीकृतियां तकनीकी उपादेयता भू-जल उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जारी की जानी प्रस्तावित है तथा ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में नवीन नलकूप स्वीकृत होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के 10 सूखे नलकूपों के विरूद्ध नवीन नलकूप स्वीकृत किया जाना विचाराधीन नहीं है। शहर/ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मुझे उत्तर प्राप्त हो गया है। पूरक प्रश्न। क्या विभाग द्वारा असफल हुए नलकूपों में असफल होने के कारणों का तकनीकी विश्लेषण करवाया गया है तथा भविष्य में नलकूपों को लेकर क्या कार्ययोजना है?

mdp/rtm/05.02.2025/11:20/1c

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में टोटल 22 ट्यूबवेल बिलकुल ड्राई हो चुके थे। इनमें एक वापस कम्प्लीट कर दिया। चार ट्यूबवेल हमने सेंक्शन कर दिए, जिन पर काम चल रहा है। 7 के हमने प्रपोजल मांगे हैं और लगभग 5 ट्यूबवेल की डीपनिंग करने का हमने प्रोसेस चालू कर दिया है और उसके वर्क आर्डर चालू कर रहे हैं। 5 बिलकुल ड्राई हो गये हैं।

इसके अलावा शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 43 ट्यूबवेल ऐसे थे, जिनके अन्दर कहीं मोटर में प्रॉब्लम थी, कहीं केबल की प्रॉब्लम थी, कहीं पर स्टार्टर की थी, कहीं पर डीपनिंग की थी और जो केसिंग पाइप लाइन थी, लगभग 3400 मीटर की 96 लाख रुपये की हमने स्वीकृति जारी कर दी है। 5 ट्यूबवेल नये लगाने की बजट के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, उनकी भी हमने सेंक्शन जारी कर दी है। ये सारे काम आने वाले समय में पूरा करके देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, विराजिए।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): दूसरा, आपकी सरकार के 14 माह के कालखंड में कोर्ट स्टे से प्रभावित 41 गांवों की जेजेएम स्कीम में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी तथा इन गांवों में सरकार कब तब जेजेएम के तहत पेयजल उपलब्ध करवा देगी? साथ ही जिन गांवों में जेजेएम स्कीम की वित्तीय बिड अभी जो 10-11 गांवों में जारी की गयी है, उनका वर्क आर्डर कब तक जारी कर देंगे?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के तहत 83 योजनाओं में 142 नलकूप स्वीकृत हैं। इनमें 26 नलकूप सूखे पाये गये हैं। इनके जल जीवन मिशन के तहत 76 संशोधित योजनाओं में कुल 163 नलकूप स्वीकृत एवं 12 नलकूप सूखे पाये गये हैं। शेष कार्य प्रगतिरत हैं और एज-पर रिक्वायरमेंट आधार पर जो भी ट्यूबवेल सूखे हैं जल जीवन मिशन में, उनको हम दोबारा या तो कांट्रेक्टर से करवाएंगे या उनके खिलाफ कार्यवाही करके दोबारा करेंगे। इसके साथ-साथ वहां पर गणपति ट्यूबवेल जिन पर ईडी ने भी कार्यवाही की, उसके खिलाफ कोर्ट में चला गया था। कोर्ट से भी डिस्पोजल के लिए कहेंगे और 10 गांव आपने जो गोविंदगढ़ के बताए, उनकी एफसी के अन्दर हम मिनट्स में ले रहे हैं और आने वाले महीने के अंत तक उसका वर्क आर्डर जारी कर देंगे।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। ललित मीना।

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों को मुआवजा

33. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार किशनगंज तहसील की हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र में आये गांवों की भूमि व मकानों के मुआवजे भूमि अर्जन, पुनर्वास और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में प्रावधान नहीं होने के कारण डूब क्षेत्र में आये गाँवों के लिए अन्य किसी प्रकार का अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त परियोजना हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत कर दिया है? यदि हां, तो मुआवजा एवं अनुदान से कब तक लाभान्वित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि (1) किशनगंज तहसील की हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र में आये गॉवों की भूमि एवं मकानों का मुआवजा ''भू स्वामियों'' को भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में प्रावधान होने से भुगतान किया गया/जा रहा है, लेकिन राजकीय भूमि पर बने मकानों को मुआवजा दिये जाने का प्रावधान नहीं होने से विशेष अनुग्रह राशि दिया जाना विचाराधीन है ।

(2) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा हथियादेह परियोजना हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है ।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजकीय भूमि, सिवाय चक, वन भूमि, गैर मुमकिन चरागाह में डूब क्षेत्र में आए लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, परंतु रामगंज मंडी के ताकली में पहले मुआवजा विशेष पैकेज के अंतर्गत दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे भी हथियादेह में 442 परिवारों का एक्सग्रेसिया के तहत आपके यहां पेंडिंग हैं। इनको कब तक स्वीकृत करवा देंगे। आप कोई भी अतिरिक्त बजट सैंक्शन कराने का विचार रखते हैं या नहीं रखते?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हथियादेह परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हमारे विगत कार्यकाल 2013 से 2018 के दौरान 14/12/16 को जारी की गयी थी। बांध निर्माण हेतु दिनांक 05/10/18 को कार्यादेश दिया था। पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में बांध निर्माण हेतु वन क्षेत्र भूमि अवाप्ति हेतु हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं की। हमने 04/10/24 को प्रकरण प्रथम स्टेज क्लीयरेंस हेतु दिल्ली मुख्यालय को भिजवाया है।

पिछली सरकार ने सरकारी भूमि पर बने मकानों हेतु विशेष अनुग्रह राशि के प्रस्ताव पांच साल तक तैयार नहीं किये। हमने प्रस्ताव तैयार करवा कर जुलाई 2024 में मंगवाए, जो प्रक्रियाधीन है तथा प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के पास विचाराधीन हैं। मंत्रिमंडल से सक्षम स्वीकृति के उपरांत भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा

कि पिछले सत्र में भी मैंने आपको निवेदन किया था कि 442 परिवार मुआवजे के लिए आज भी सरकारी भूमि में बांट जो रहे हैं। आपने आश्वस्त किया था इस सदन के माध्यम से कि हम इसको मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में रखकर इनको मुआवजा देने के लिए हम कृत संकल्प लेते हैं। मेरा आज सदन के माध्यम से निवेदन है कि आपने कहा था विशेष तौर से आप स्वयं भी प्रयास करके इनको मुआवजा दिलाएंगे। 650 लोगों को तो मुआवजा मिल गया, जिनको विभाग ने दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा सदन के माध्यम से विशेष आग्रह है कि 442 परिवार हैं, इसलिए इनको विशेष रूप से मंत्रिमंडल में रखकर आप अनुशंसा करवाकर मुआवजा स्वीकृत करवाएं। मंत्री महोदय, कब तक करवा देंगे?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशासनिक विभाग के स्तर पर विचाराधीन है, इसका जल्दी निस्तारण किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नानालाल निनामा।

जनजाति क्षेत्र में मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की कार्ययोजना

34. श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में बजट 2024-25 में 250 मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाने की घोषणा के तहत जनजाति क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने-कितने मां-बाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत 250 मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाने की घोषणा के तहत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मां-बाड़ी खोलने की संख्या निर्धारित नहीं है। क्षेत्र की आवश्यकता, 6 से 12 वर्ष के छात्रों की उपलब्धता, विद्यालय से दूरी इत्यादि मापदण्डों पर सर्वे कराया जाकर मां-बाड़ी खोलने का निर्णय किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री को बताना चाहता हूं कि 2024-25 की 250 मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाने की घोषणा के तहत आपके विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्र के किन-किन जिलों में सर्वे कराया और मापदण्ड के अनुसार किन जिलों के किन विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां खोले जाने का उपयुक्त स्थान निर्धारित किया जाकर, अब तक कितनी मां-बाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य महोदय जी ने कहा कि पिछले समय में बजट 2024 में जो घोषणा हुई थी 250, कहां-कहां खोलने का आपने किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग ने

नवीन मां-बाडियों हेतु 131 मां-बाडियों के प्रस्ताव स्वीकृत करके उनको खोलने के आदेश जारी किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सर्वे का सवाल था, 250 मां-बाडियों के सर्वे के लिए जो प्रस्ताव आए, वे प्रस्ताव सर्वे करवा दिये गये हैं और बाकी प्रस्ताव जो हैं, वे प्रक्रियाधीन हैं। उनको भी हम जल्दी पूरा करेंगे। जहां तक आपकी विधान सभा का सवाल है, आपकी विधान सभा में भी हमने 5 मां-बाडियों के प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं। आपके यहां से हमारे पास 16 प्रस्ताव आए थे, उसमें से हमने 5 स्वीकार किए हैं।

अध्यक्ष महोदय जी, इनका दूसरा सवाल था कि जिलेवार मां-बा़डियां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि, आपकी विधान सभा घाटोल की बता रहा हूं, पूरा सुनिए। आपका विधान सभा दो जिलों में विभाजित है। आपके प्रतापगढ़ में 15 और बांसवाड़ा मिलाकर आपके यहां 118 मां-बाड़ी केन्द्र संचालित हैं और 5 हमने अभी किये हैं। ये जोड़ेंगे तो आपकी संख्या बढ़ेगी। आप और चाहते हैं, यदि आप प्रस्ताव भेजेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र 2 जिलों में विभाजित है। घाटोल में तो पर्याप्त खुले हैं, लेकिन जो पीपलखूंट पंचायत समिति है, वह ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत गरीब लोग रहते हैं। स्कूलों की दूरी बहुत है। माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह पूछना चाहूंगा कि पीपलखूंट पंचायत समिति में मां-बाड़ी खोलने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? दूसरा बजट आ गया है, अभी तक आपकी 250 पूरी नहीं हुई। माननीय मंत्री महोदय, बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, हमारी जो मां-बाडियां हैं, वह जो बच्चे वंचित हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी एक सीमा है। एक से डेढ़ किलोमीटर के एरिये में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा, हमारा डे-केयर है। डे-केयर हमारा 9 से 5 बजे तक चलता है। उनका उद्देश्य यह है कि जो मजदूर हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं...।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी पीपलखूंट पंचायत समिति का पूछ रहा हूं। आप दूसरी बातें मत बोलिए। पीपलखूंट बिखरी आबादी है। वहां खोलने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उत्तर तो पूरा सुनिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप उत्तर तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर सुन लीजिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): ये डे-केयर हैं। जो श्रमिक जाते हैं, उनके बच्चों की देखभाल के लिए है। उनको हम भोजन भी देते हैं। आपके यहां पीपलखूंट का सवाल है। आपके यहां हमने बहुत ज्यादा मां-बाडियां खोली हैं। अगर और भी प्रस्ताव देंगे तो उस पर हम विचार करेंगे।

Ans/rtm 11.30 1d 05.02.2025

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): पीपलखूंट की तो कोई बात ही नहीं की। पंचायत समिति पीपलखूंट के लिए प्रस्ताव तो हमने भेज दिए, अब तक पहुँचे या नहीं पहुँचे लेकिन आप पीपलखूंट पंचायत समिति में खोलने का विचार रखते हैं या नहीं रखते है क्या?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रस्ताव तो दे दिए अब वह खोलने का विचार रखते है या नहीं रखते, बस इतना ही पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, मैंने पहले ही कहा कि आपके प्रस्ताव आप जहां खोलना चाहते हैं और भेजे, हम उनका सर्वे कराएंगे। नियमों में आता है तो खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री केसाराम चौधरी।

जोजावर ग्राम (मारवाड़ जंक्शन) की ओरण भूमि का आवंटन

35. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील मारवाड़ जंक्शन के ग्राम जोजावर (वर्तमान राजस्व ग्राम अनजी की ढाणी) के पुराने खसरा नम्बर 806 क्षेत्रफल 240 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रथम सेटलमेन्ट के समय से संवत 2020 तक राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण दर्ज थी? यदि हां, तो उक्त खसरा नम्बर की भूमि घोड़े चराने हेतु किस नियम के तहत कब व किसको आवंटित की गई ? आवंटन आदेश की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त खसरा नम्बर की भूमि कि किस्म परिवर्तन कब और किस आदेश से की गई व पुराने खसरा नम्बर (नए खसरा नम्बर 2112, 2714, 2091) आज तक किस-किस व्यक्ति के नाम किस-किस आदेश अथवा दस्तावेज से हस्तांतरित हुई ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त पुराने खसरा नम्बर 806 वर्तमान राजस्व ग्राम अनजी की ढाणी के खसरा नम्बर 2112, 2714, 2091 वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भूमि का पुनः गैर मुमकिन ओरण सरकारी भूमि दर्ज करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) यह सही है कि राजस्व ग्राम जोजावर के पुराने खसरा नम्बर 806 रकबा 240 बीघा 09 बिस्वा की भूमि प्रथम सेटलमेन्ट की मिसल बंदोबस्त के अनुसार गै0मु0 ओरण के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जो कि सम्वत 2020 तक दर्ज रही। जमाबन्दी सम्वत् 2021-2024 में अंकित नोट के अनुसार उक्त भूमि घोडे चरने हेतु केसरीसिंह के खाता संख्या 487 में रकबा जोड़ा गया। सुलभ सन्दर्भ हेतु जमाबन्दी सम्वत् 2021-2024 की प्रति परिशिष्ट-अ संलग्न है। उक्त नोट में आवंटन नियम का उल्लेख नहीं है।

(2) खसरा नम्बर 806 की भूमि के राजस्व रिकार्ड में हुए परिवर्तन की सूची परिशिष्ट-ब

संलग्न है। खसरा नम्बर 806 के नए खसरा नम्बर 2112, 2714 व 2091 की भूमि के राजस्व रिकार्ड में हुए परिवर्तन की सूची परिशिष्ट-स संलग्न है।

(3) ग्राम अनजी की ढाणी के वर्तमान खसरा नम्बर 2112, 2714, 2091 की भूमियों के खातेदारान् का विवरण सहित सूची परिशिष्ट-द संलग्न है।

(4) जिला कलक्टर, पाली से जमाबन्दी सम्वत् 2021-2024 में अंकित नोट में संदर्भित आदेश/फैसले की प्रति चाही गई है। जिसकी प्राप्ति उपरांत नियमों के संदर्भ में परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं सीधा पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): पूरा पढ़ना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। वह पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य, आप पूछिये ना। उत्तर आ गया, अब पूरक प्रश्न।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय मंत्री महोदय, आप विराजिये, आपका जवाब मेरे पास है। उस जवाब में आपने जिस तरह का जवाब दिया है वह एक दूसरे की विरोधाभास में है, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूं।

क्या सरकार जिस व्यक्ति के जमाबंदी खाता संख्या 487 में पहले से 01 हजार 88 बीघा खातेदारी भूमि दर्ज हो उसको गैर मुमकिन ओरण खसरा नम्बर 806 की 240 बीघा 09 बिस्वा भूमि पटवारी द्वारा जमाबंदी में घोड़ा चरने हेतु नोट लगाकर उसके खाते में जोड़ सकते हैं ? यदि नहीं तो क्या सरकार बिना नियम, बिना सक्षम आवंटन आदेश मात्र पटवारी नोट से खसरा नम्बर 806 की अवैध तरीके से खुर्दबुर्द हुई 240 बीघा 09 बिस्वा भूमि पुन: गैर मुमकिन ओरण दर्ज करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व ग्राम जोजावर के पुराने खसरा नम्बर 806 रकबा 240 बीघा 09 बिस्वा की भूमि प्रथम सेटलमेन्ट में मिसल बंदोबस्त के अनुसार गैर मुमकिन ओरण के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जो कि सम्वत 2020 तक दर्ज रही। जमाबन्दी सम्वत् 2021-2024 में अंकित नोट के अनुसार उक्त भूमि घोड़े चराने हेतु केसरीसिंह के खाता संख्या 487 में रकबा जोड़ा गया। सुलभ सन्दर्भ हेतु जमाबन्दी सम्वत् 2021-2024 की प्रति परिशिष्ट-अ संलग्न है। उक्त नोट में आवंटन नियम का उल्लेख नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

खसरा नम्बर 806 की भूमि के राजस्व रिकार्ड में हुए परिवर्तन की सूची परिशिष्ट-ब संलग्न है। खसरा नम्बर 806 के नए खसरा नम्बर 2112, 2714 व 2091 की भूमि के राजस्व रिकार्ड में हुए परिवर्तन की सूची परिशिष्ट-स संलग्न है। ग्राम अनजी की ढाणी के वर्तमान खसरा नम्बर 2112, 2714, 2091 की...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह तो वही चारों जवाब पढ़ रहे हैं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): हां, पढ़ना पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः आप सुनिये।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): डिटेल बतानी पड़ेगी। क्या किया है यह नहीं बताना पड़ेगा? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): मतलब हम कुछ नहीं बोले, आप जो कह रहे हो वह सही है, यूं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं तो आराम से ही पूछ रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि यह सारा जवाब तो इसमें है।

श्री अध्यक्षः बैठिये।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): 240 बीघा गौण भूमि किसी के नाम दर्ज हुई, कोई मामूली बात नहीं है।

श्री अध्यक्षः आप इसको पढ़िये।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये मुझे बोलने नहीं देते।

श्री अध्यक्षः मैं बैठा हूं ना, आप बोलिए, आपको रोका किसने है?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): ग्राम अनजी की ढाणी के वर्तमान खसरा नम्बर 2112, 2714, 2091 की भूमियों के खातेदारान् का विवरण सहित सूची परिशिष्ट-द संलग्न है। ...(व्यवधान)...

माननीय केसाराम जी चौधरी बता रहे हैं, यह भूमि पूर्व में ओरण के नाम दर्ज थी। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि जिला कलक्टर, पाली से जमाबन्दी सम्वत् 2021-2024 में अंकित नोट में संदर्भित आदेश/फ़ैसले की प्रति चाही गई है। जिसकी प्राप्ति उपरांत नियमों के संदर्भ में परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सा पूछा है कि जिस व्यक्ति के खाते में 01 हजार 88 बीघा ऑलरेडी जमीन है, क्या उसी को ओरण की जमीन और वही पटवारी का नोट घोड़ा चरने के लिए, यह राजस्व में कौनसी किस्म है घोड़ा चरने की। ...(व्यवधान)... इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस जमीन को वापिस ओरण में दर्ज करें।

आपने "ब" में जवाब दिया है केसरीसिंह पुत्र चक्रवतीसिंह को 240 बीघा केसरसिंह ने बेच दी। चक्रवतीसिंह ने हसन महमद को पूरी जमीन बेच दी। हसन महमद ने बख्तावरमल को 120 बीघा बेच दी। आपने फिर अनुलग्नक-स में 235 बीघा 09 बिस्वा जमीन बराबर हिस्से में कर दी, फिर 05 बीघा जमीन कहां गई? 05 बीघा के साथ-साथ अनुलग्नक-स में क्रम संख्या 9 पर दौलतराज, लक्ष्मण कंवर को वसीयत की है। माननीय, आपसे निवेदन करता हूं...

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दौलतराज की बैंगलोर में मृत्यु हुई, मृत्यु की तारीख 07.07.1994 है।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह वहां की नगरपालिका का मृत्यु प्रमाण पत्र है। जोजावर से मृत्यु सर्टिफिकेट जारी होता है उसमें दौलतराज की मृत्यु 25.12.1995 बताई गई है। इस तरह से एक व्यक्ति दो बार मर सकता है? ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये आपके काम हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः सब लोग बैठिये। ...(व्यवधान)... आप ही का उत्तर है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कांग्रेस सरकार के काम पर शेम-शेम कर रहे हो धन्यवाद आपको ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ओरण की जमीन खा गये ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपके मंत्री महोदय खड़े हैं। उत्तर सुनिये। बैठिये ...(व्यवधान)...

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य जी ने जो सवाल किए हैं, जिला कलक्टर से पूरी जांच कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये ...(व्यवधान)... आसन पाँव पर है। माननीय मंत्री महोदय, इस विषय को, उत्तर को मैंने भी पढ़ा है, उसमें काफी विसंगतियां लगती हैं। आप सदस्य को अपने चैम्बर में बुलाकर उसका समाधान करिये और सही उत्तर दे दीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ओरण की भूमि का विषय है, गम्भीर विषय है। ओरण की भूमि किसी के नाम बिना किसी विधिवत आदेश के हंस्तांरित हो जाना बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे मंत्री महोदय ने कहा है ...(व्यवधान)... किसके नाम हुई नाम खोल दे अभी हम। यहां के विधायक रह चुके हैं उनके नाम हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम हुई है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसकी हम पूरी जांच कराएंगे और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय, बैठिये। आप विराजो। बैठिये ...(व्यवधान)... मैं खड़ा हूं फिर भी बोल रहे हैं। नो, आप भी बैठिये। माननीय मंत्री महोदय और सदस्य की बात मैंने सुनी, मैंने इस उत्तर को भी पढ़ा, यह प्रश्न बहुत गंभीर है। जैसा कि मैंने कहा उत्तर में कुछ विसंगतियां दिखती हैं, चैम्बर में आप बुलाकर इनका समाधान कीजिए ...(व्यवधान)... नो, बैठिये। श्रीचंद जी बैठिये। मैं खड़ा हूं फिर भी खड़े हो रहे हो ...(व्यवधान)... कौन बोला, मैं अभी सदन से निकालूंगा इस तरह से बीच में बोलेंगे तो।

VPS-RTM-05.02.2025-11.40-1e

माननीय, आपको सदन से बाहर जाना है? अब वह ही बोलेगा जो सदन से बाहर जाएगा।

यह क्या तमाशा है? सदन को, आप सुनिये, जिसका प्रश्न है, आप सुनिये तो सही, जिसका प्रश्न है वह मंत्री केवल बोल सकता है, बाकी मंत्री बीच में नहीं बोल सकते। संसदीय मंत्री बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो। हां, आप बोलिये।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इन खातेदारों का नाम रखना चाहता हूं। पहले नम्बर पर अमृतलाल पुत्र चम्पालाल माली, भृगराज सिंह पुत्र खुशवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी- जोजावर। ...(व्यवधान)... एक मिनट, एक मिनट। दिलीप पुत्र शिव सिंह वगैरह, अर्जुनराम पुत्र हरिराम, जाति राइका, जवानराम पुत्र बगदीराम राइका, खुशवीर सिंह पुत्र जालम सिंह, जाति राजपूत, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपको उत्तर तो सुनना पड़ेगा। नाम तो बोलेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): इन्दु कुमारी पत्नी सुखवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी- जोजावर। ...(व्यवधान)... ये खातेदार हैं इस जमीन में। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ। अब आपके दो प्रश्न हो गये, आप बाद में मिल लेना। अब आप विराजिये। ...(व्यवधान)... आपका हो गया, मंत्रीजी को भी मैंने पूरा अवसर दे दिया।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृतलाल के तो दस्तखत भी नहीं है और यह जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसकी कॉपी आप कहें तो मैं टेबल कर दूं?

श्री अध्यक्ष: हां, आप पेश कर दो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) द्वारा कागज टेबल किया गया।)

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री कालीचरणजी सराफ।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ओरण जमीन का मामला है, भगवान की जमीन है, ये कांग्रेसी, भगवान को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। भगवान की जमीन को भी खा गये। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या व्यवस्था है? यह क्या कह रहे हैं? काहे का कांग्रेसी? आप कैसे इल्जाम लगा रहे हो?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। माननीय विपक्ष के नेता, आप भी बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप भी बैठिये। उनको बैठाया है, आप भी बैठिये। मुझे यह लगता है कि शायद हम लोग सदन नहीं चलाना चाहते? बैठिये। सदन चलाना है? प्रश्न काल के अन्दर केवल पूरक प्रश्न जिस माननीय सदस्य का है, ...(व्यवधान)... आप बैठिये। बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। ...(व्यवधान)...

प्रश्न काल आज से नहीं, इस सदन में वर्षों से होता आया है। प्रश्न जिसका है वह दो पूरक प्रश्न पूछेगा, मंत्रीजी पूरा उत्तर देंगे और यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो कई बार मैंने तीसरा प्रश्न

पूछने की भी अनुमति दी है, लेकिन बाकी सदस्यगण और बीच में मंत्रीगण, मंत्री केवल संसदीय कार्य मंत्री, उसमें बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं और इधर विपक्ष के नेता कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई मंत्री, किसी मंत्री के उत्तर में यदि उसका भी प्रश्न है तो वह जरूर उत्तर दे लेकिन बीच-बीच में यदि करेंगे तो फिर यह सदन इस तरह तो नहीं चलेगा। मैं स्पष्ट सबको कह रहा हूं। यदि सदन चलना है तो व्यवस्था के अनुसार चलेगा। अपने व्यवस्था है। प्रश्न में कोई बात रह गयी तो विपक्ष का नेता पूछेगा। मंत्रीजी की कोई बात रह गयी तो संसदीय कार्य मंत्री उसको पाइंट आउट करेगा। ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता हुई तो सचेतक कर सकता है बाकी सब खड़े जायेंगे, यह अनुमति किसी को भी नहीं है और इधर से भी बैठे-बैठे बोल रहे हो, यदि कोई बोलेगा तो सदन से बाहर जाने के लिए भी वह तैयार रहें।

अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर शहर में नई बसों की खरीद

36. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर की जनसंख्या के आधार पर शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितनी बसें संचालित होना आवश्यक है तथा वर्तमान में कितनी बसें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बसों की कमी दूर करने के लिये नई बसें खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 10 हजार की आबादी पर 6 बसों के हिसाब से 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 2400 बसों का प्रावधान है।

वर्तमान में जेसीटीएसएल द्वारा जयपुर शहर में 27 मार्गों पर 200 बसों का संचालन किया जा रहा हैं।

इसके अतिरिक्त आमजन को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित 43 मार्गों पर 2424 मिनी बसों पर परमिट जारी किये हुए हैं।

इनके अलावा 41913 ऑटो रिक्शा (थ्री-व्हीलर) एवं 45508 ई-रिक्शाओं को पंजीकृत किया हुआ है।

(2) जी हाँ। जयपुर शहर हेतु बसों की कमी को दूर करने के लिये नई पी.एम. ई बस सेवा योजना में 150 इलेक्ट्रिक बसों की भारत सरकार के स्तर से निविदा दिनांक 2 जनवरी 2025 को खोली जा चुकी है, जिसके परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, परीक्षणोपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

राज्य सरकार स्तर से 300 सीएनजी चलित एसी मिडी बसों की निविदा प्रक्रियाधीन है। जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक 06.02.25 को खोली जावेगी। निविदा खोली जा कर परीक्षण के पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपका जवाब आ गया, मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं, आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष: हां, आप पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह बताया है कि शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत जयपुर शहर में 2400 बसें होनी चाहिए। आपने अपने जवाब में यह बताया कि वर्तमान में 200 बसें संचालित हैं और सितम्बर, 2025 में 100 बसें और कबाड़ हो जाएंगी और केवल 100 बसें ही रह जाएंगी। क्या यह भी सही है कि गत पांच वर्षों में सी.एन.जी. और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के तीन प्रस्ताव बने और सरकार ने उनको मंजूरी नहीं दी। मैंने यह पूछा था और 09.07.2019 को एक प्रश्न का जवाब आया सरकार का कि मामला प्रक्रियाधीन है। फिर मैंने यह पूछा 18 जुलाई, 2023 को तो सरकार ने कहा कि मामला प्रक्रियाधीन है और आपने भी अभी जवाब में यह कहा है कि मामला प्रक्रियाधीन है तो, भगवन, आप यहां बसें चलाओगे या मामला प्रक्रियाधीन ही रहेगा। आप यह बताइये कि सरकार इनको मंजूरी कब तक दे देगी और सड़क पर कब तक ये बसें आ जाएंगी? पहला प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और माननीय सदन को यह बताना चाहूंगा कि मैंने जवाब में यह साफ लिखा है कि 150 इलेक्ट्रिक बसें जो भारत सरकार हमको देगी, उनकी भारत सरकार के स्तर पर निविदा 02 जनवरी, 2025 को खोली जा चुकी है, जिसके परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जब निविदा खुलेगी, निविदा तकनीकी निविदा है और वित्तीय निविदा है और उसके अलावा राज्य सरकार ने 300 बसें सी.एन.जी. चलित एसी मिडी बसों की निविदा प्रक्रियाधीन है जिसकी तकनीकी निविदा 06.02.2025 को खोली जाएगी और खोलने के बाद यथाशीघ्र उसका परीक्षण कर नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि आपने अपने जवाब में 43 मार्गों पर 2424 निजी बसों के परमिट जारी किये, यह बताया है और 41913 ऑटो रिक्शा और 45508 ई-रिक्शा बताया है तो क्या जनता को निजी क्षेत्र के रहमोकरम पर छोड़ दिया आपने? सारा ट्रैफिक जाम इनके कारण रहता है तो क्या जो शहरी मानकों के हिसाब से 2400 बसें चलाने का जो मापदंड है, क्या उसके हिसाब से अब यह जो आपने 300 और 150 बसें, यह तो 450 बसें ही हुई तो 2400 बसें चलाने का विचार है या नहीं और है तो कब तक चलाओगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में क्या हुआ और ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पिछले सालों की तो ये भुगत ही रहे हैं।

श्री अध्यक्षः आप उत्तर सुनिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): उसके बारे में हम चर्चा, परिचर्चा नहीं करें क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से सारी परिस्थितियों का पता है। मैं आपको और सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी हम एक नई प्रक्रिया के तहत बसें खरीदने की बजाए हमारी कुछ कम्पनियों से बातचीत चल रही है जो महाराष्ट्र में ई.वी. और सी.एन.जी. बसें रखती हैं और उन्होंने विभिन्न नगर निकायों को किराये पर दे रखा है। उसमें प्रतिदिन न्यूनतम किलोमीटर के आधार पर उनको भुगतान करना पड़ता है। ड्राइवर, बसों का रखरखाव, उनका बाकी सारा सिस्टम उनका होता है, हमारा काम सिर्फ एक कंडक्टर रखकर उनसे आय अर्जित करना, जनता को सेवा देना और जो आय अर्जित हो वह अगर पर्याप्त हो तो ठीक है वरना सरकार कुछ और मिलाकर उनकी सेवाओं का भुगतान करेगी, हम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा और है। यह जो 45508 ई-रिक्शा चल रहे हैं जयपुर में उनमें अधिकांश बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये इनको चला रहे हैं तो मैं यह चाहूंगा कि आप इनकी जांच करें और यह इस प्रकार के यदि लोग हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या है तो उनके लाइसेंस निरस्त करके उनको बंद करें क्योंकि यह जितनी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है जयपुर की, वह केवल उनके कारण से बिगड़ रही है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, इसमें ई-रिक्शा का नहीं है। इसमें ई-रिक्शा नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा तो माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि प्रक्रियाधीन है। माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि बसें हम किराये पर लेंगे तो आप तो पूरा ही प्राइवेट कर रहे हो। मेरा तो एक सुझाव है कि आप एक आदमी टिकट लेकर ही बैठा दो न, वह टिकट ले ले। प्राइवेट में वह टिकट लेकर सवारी कर लेगा और आप भुगतान कर देना।

श्री अध्यक्षः आप सुझाव इनके चैम्बर में जाकर दे देना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यानी, सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नेता प्रतिपक्ष, यह काम इसलिए करना आवश्यक है कि आपने पिछले पांच साल तक केवल प्रक्रियाधीन ही रखी, कोई व्यवस्था की नहीं आपने बसों की। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री बालमुकुन्दाचार्य।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः आपको कुछ जोड़ना है? एक मिनट।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): जी। मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष को

जानकारी देना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में जितने उपक्रम हैं, जो एक्सक्लूसिवली ऐसा क्षेत्र है जिसका प्राइवेट क्षेत्र में कहीं कोई काम नहीं है, वह जरूर सफल है बाकी हमें जनता की मेहनत की कमाई का सही तरीके से सदुपयोग हो और आमजन को सुविधाएं भी मिले क्योंकि रोजगार उसमें भी मिलेगा, ड्राइवर उसमें भी रहेगा, कंडक्टर उसमें भी रहेगा।

ssy/rtm/05.02.2025/11.50/1f

मरम्मत उसकी भी होगी। सारे काम होंगे तो उसमें कहां दिक्कत आ रही है? कुछ सरकारी चलेंगी, कुछ किराये पर लेंगे। जनता का धन बचेगा। जनता को अच्छी सुविधा मिलेगी। अगर वह सही तरीके से सेवाएं नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेंगे।

श्री सभापतिः चलिये, धन्यवाद। श्री बालमुकुन्दाचार्य।

भट्टा बस्ती (किशनबाग), जयपुर में सरकारी भूमि पर अवैध कनेक्शन

37. श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भट्टा बस्ती किशनबाग जयपुर में सरकारी एवं वन भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कितनों को, कब-कब जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस्तियों में सरकार द्वारा विद्युत लाइनें एवं ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं? यदि हां, तो कब व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कनेक्शन जारी करने तथा विद्युत लाईन डालने एंव ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? सरकार उक्त के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कनेक्शनों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) भट्टा बस्ती, किशनबाग, जयपुर में प्रचलित ''विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें'' में वर्णित नियमावली के अनुसार कब्जेदार की हैसियत से निवास करने वाले घरेलू आवेदकों को कनेक्शन जारी किये गये थे। निगम द्वारा मई 2013 से पूर्व उक्त बस्ती में 127 घरेलू कनेक्शन जारी किये गये जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) निगम द्वारा उक्त उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए पूर्व में विद्युत लाइन व दो ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये है।

(3) बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(4) जी नहीं। उक्त विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। स्थानीय निकाय अथवा वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर विद्युत कनेकशन हटा

लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न था कि भट्टा बस्ती किशनबाग जयपुर में सरकारी भूमि पर अवैध कनेक्शन के निमित्त, मैं जवाब से संतुष्ट हूं।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि शहर में, परकोटे में इस समय खुले में काफी तार, ट्रांसफार्मर, तारों का जाल फैला हुआ है। इससे कई जगह आगजनी एवं चिंगारियां उठती रहती हैं। इससे नुकसान होता है। वहां पर्यटक, ट्युरिस्ट भी घूमता है और लोकल लोगों को भी समस्या है। लोड काफी बढ़ा हुआ भी है। इस कारण से भी और पिछले वर्षों में कुछ हुआ नहीं इसलिए भी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप कृपया उसको कब तक करा देंगे?

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि परकोटा क्षेत्र में तारों का जाल फैला हुआ है, उसके सौंदर्य करण का आपका प्रस्ताव है। उस सौंदर्य करण का काम स्थानीय निकाय, जेडीए के माध्यम से अंडर ग्राउंड पाइप लाइन डालकर किया जाता है। डिस्कॉम का काम केवल हमारी जो वर्तमान में लाइनें डली हुई हैं, उनसे कनेक्शन देना है। अगर आप सौंदर्य करण का काम अंडर ग्राउंड पाइप लाइन के माध्यम से कराना चाहते हैं तो प्रस्ताव जेडीए को प्रस्तुत करें। स्थानीय निकाय द्वारा करने का उसमें प्रावधान है।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न। हां बोलें, 2 हो गये, चलो।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि अवैध कनेक्शन पिछले 5 वर्ष में, हमारी सरकार आने से पूर्व काफी तेज गति से हुए। सरकारी भूमियों पर भी हो गये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जांच कराई गयी है? पहले भी मैंने यह सवाल रखा था। पुनः दोबारा निवेदन करता हूं। अगर आपने कराई है तो कितने पाये गये? अभी भी जांच की आवश्यकता है। अवैध कनेक्शन काफी संख्या में हो रखे हैं। चाहे वह भट्टा बस्ती क्षेत्र हो या फिर किशन बाग़ हो, उन क्षेत्रों में आप कब तक जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सदस्य ने जिस भट्टा बस्ती का जिक्र किया है, उनका मूल प्रश्न भी है। उसमें 127 वैध कनेक्शन हैं। उसके अलावा लगभग 2013 से उस बस्ती में कनेक्शन अभी जारी नहीं किये जा रहे हैं। माननीय सदस्य का अवैध कनेक्शन के बारे में जो सुझाव है, हम विजिलेंस टीम के माध्यम से जहां-जहां अवैध कनेक्शन हैं, अभियान चलाकर के ऐसे अवैध कनेक्शनों को हटाकर, उनके खिलाफ कार्यवाही निरंतर करते हैं। आगे इस कार्यवाही को तेज करते हुए अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय जब्बर सिंह।

आसीन्द में आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भवन निर्माण

38. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आसीन्द में आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतु भूमि का आवंटन हो चुका है? यदि हां, तो उक्त का भवन निर्माण कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) जी हां। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय आसींद (भीलवाड़ा) हेतु 0.21 हैक्टर भूमि आवंटित की जा चुकी है। उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2024-25 में दिनांक 04.11.24 को 45.0 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस स्वीकृति के उपरान्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, आसीन्द के द्वारा टेण्डर प्रकिया पूर्ण कर, वर्क आर्डर जारी किये जा चुके है एवं दिनांक 28.01.2025 को भवन का शिलान्यास भी किया जा चुका है।

(2) उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु टेण्डर प्रकिया पूर्ण कर, कार्य आदेश जारी हो चुके है एवं दिनांक 28.01.2025 को भवन का शिलान्यास भी किया जा चुका है।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछो।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। आसीन्द शहर में आपने आयुर्वेद चिकित्सालय के लिए भूमि भी आवंटित कर दी और 45 लाख रुपये का फंड भी जारी करके शिलान्यास भी हो गया। मैं सरकार का और आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

मंत्री महोदय, साथ ही मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि भूमि थोड़ी कम है, 0.21 हैक्टेयर जगह है चिकित्सालय के लिए। आसीन्द शहर बहुत बड़ा शहर है। नगरपालिका को आदेश करके आप थोड़ी भूमि और बढ़वा देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। इसके आलवा 45 लाख रुपये का जो फंड जारी हुआ है, वह मेरे हिसाब से बिल्डिंग के लिए भी कम पड़ेगा। मेरा निवेदन रहेगा आसीन्द की जनता की ओर से कि इसमें थोड़ा फंड भी आप बढ़वा देंगे तो आपकी अति कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इनके राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2024-25 में 45.0 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। शेष राशि आप बढ़वाने की बात कर रहे हो तो आपके लिए यह प्रस्ताव राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2025-26 में रखेंगे, निश्चित रूप से होंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। डॉ. जसवंत सिंह यादव।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

39. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला कोटपूतली-बहरोड में जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है? यदि हां, तो कहां व नहीं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उक्त केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार बहरोड के स्टेडियम में ही जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले और खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) जी हां। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के आदेश क्रमांक 8445 दिनांक 28.01.2025 द्वारा नवगठित जिला कोटपूतली-बहरोड में जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है, जो दिनांक 01.02.2025 से कार्य प्रारम्भ करेंगे।

(2) कोटपूतली-बहरोड जिला मुख्यालय पर जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र कार्य करेगा।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न, अच्छा।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): पढ़ूं क्या पूरा?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री महोदय, जवाब तो आ गया।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): तो आप बोलिये ना।

श्री अध्यक्षः हां बोलिये, पूरक प्रश्न पूछिये ना।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री महोदय ने जब मेरा प्रश्न लगा तब तो ओपनिंग हुई नहीं थी। प्रश्न के बाद में इन्होंने खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया। लेकिन अब इसमें जवाब दिया है कि जिला मुख्यालय पर, अब जो जिला मुख्यालय कोटपूतली-बहरोड़ इसी तरह और भी जगह हैं राजस्थान में वहां भी परेशानी आयेगी। आपने क्या क्राइटेरिया बनाया है? किसको आप जिला मुख्यालय मानते हैं? कोटपूतली को या बहरोड को? यदि इस क्राइटेरिया को लेंगे कि जहां स्टेडियम भी हो, जहां सारी सुविधाएं भी हो और अपने मापदंड को पूरा कर रहा हो, उसको लेंगे, क्या आधार रहेगा? किस आधार पर आप करेंगे? कोटपूतली में खोलेंगे या बहरोड में खोलेंगे? क्या आधार रहेगा? किसको आप हैडक्वार्टर मानेंगे?

श्री अध्यक्षः बैठिये। माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने 28 जनवरी को ही आदेश पारित कर दिये। सभी नव गठित जिलों के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिये। हमने उन सभी को कह दिया है कि वहां के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके, वहां के जो खेल संगठन हैं उनसे बात करके, यह तय करें कि जो जिला प्रशिक्षण केन्द्र हैं वह कहां पर खोला जायेगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ठीक है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी में जल जीवन मिशन योजना

40. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत पेयजल योजनाओं में 100 से 150 की आबादी वाली ढाणियों को सम्मिलित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ढाणियों को पेयजल योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की कुल 58 ग्राम पंचायतों के 237 ग्रामों एवं चिह्नित 672 ढाणियों में से 197 ग्रामों एवं 671 ढाणियों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु भू-जल आधारित योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है।

इनमें से 18 ग्रामों एवं उनकी 66 ढाणियों को लाभान्वित किये जाने हेतु स्वीकृत 18 योजनाओं के कार्य भू-जल स्त्रोत सस्टेनेबल नहीं होने के कारण प्रारंभ नहीं करवाये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

उपरोक्तानुसार थानागाजी विधानसभा के 58 ग्रामों एवं 67 ढाणियों को ईसरदा बांध परियोजना/ईआरसीपी परियोजना से सतही जल उपलब्ध होने के पश्चात लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ब' व 'स' पर संलग्न है।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब आ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा प्रश्न यह था कि जो स्कीमें तैयार हो गईं वहां 100-100, 150-150 की आबादियां बची हुई हैं, उनको उन स्कीमों में जोड़ने की योजना है या नहीं हैं? अगर है तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में टोटल 58 ग्राम पंचायतों में 237 गांव और 672 ढाणियां थी। इसमें से हमने 197 गांवों की स्कीमें बना दी। 672 ढाणियों की हमने स्कीमें बना दी। बाकी बचे हुए 18 गांव और 66 ढाणियों के अन्दर पानी की उपलब्धता, 35 लीटर उतनी तो है, बाकी 55 लीटर घर-घर कनेक्शन के लिए होनी चाहिए उतना नहीं है। इनको हम ईसरदा से ईआरसीपी के प्रपोजल में जोड़ रहे हैं।

दूसरी चीज की पानी के लिए गर्मी में सोर्स की जहां पर कमी पड़ेगी, वहां पर हम टैंकरों की व्यवस्था करेंगे। बाकी जितने भी आपके गांव हैं उनमें करीब-करीब सभी को हमने जोड़ दिया है। उनके टेंडर लगा दिये हैं। आने वाले समय में उनको पूरा करके देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूछें।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन आपसे यह है कि मेरी

स्कीमें तैयार हो गई। चाहे द्वार चौगान हो, चाहे किशोरी हो, ऐसे बड़े-बड़े गांव हैं जहां स्कीम तैयार हो गयी। उन गांवों के अन्दर 100-100, 150-150 की आबादी वाली ढाणियां रह गयी हैं। उनको जोड़ने का आपका प्लान है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जल जीवन मिशन में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गांव, बस्तियों से दूर एकल घरों और खेतों में स्थित घरों के अतिरिक्त सभी ढाणियों को हम इसमें जोड़ रहे हैं। ऐसा कोई सिंगल घर है जो खेत के ऊपर है, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं, सबको जोड़ रहे हैं। जितनी भी आपकी टोटल ढाणियां हैं, 672 को ही हम जोड़ रहे हैं और 237 गांवों को जोड़ रहे हैं। कोई ऐसा घर है जो खेत में अलग है, वह इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन में नहीं है, वही बचेगा। बाकी सारे ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): मैं सिंगल कनेक्शन की बात नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष: आपके 2 हो गये। श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): मैं सिंगल कनेक्शन की बात नहीं कर रहा। 100-100, 150-150 आबादी वाली ढाणियां हैं। जो नजदीक हैं, उनकी बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कह दिया, सबके कर रहे हैं। श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): वैसे तो जो हमारे पास आई है, हमारे पास जो रिकार्ड है उस रिकार्ड के आधार पर जो हैं ...(व्यवधान)... कोई आपकी नॉलेज में हो तो ...(व्यवधान)...

गंगनहर की वितरिकाओं द्वारा पानी का वितरण

41. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या गंगनहर की वितरिकाओं में उनकी क्षमता के अनुसार पानी छोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो प्रत्येक वितरिका की पानी क्षमता कितनी है एवं प्रत्येक वितरिका से वर्ष 2024 में रबी व खरीफ की फसलों के लिए सिंचाई हेतु कितना पानी छोड़ा गया ? क्या उक्त सुविधा प्रत्येक किसान को उसकी पर्ची अनुसार प्राप्त हुई है? यदि नहीं तो, क्यों?

(2) क्या सरकार गंगनहर के प्रत्येक किसान को उसकी पर्ची अनुसार समय पर पूरा पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 2024 में रबी व खरीफ की फसलों में वितरिका की टेल पर पूरा पानी उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) **जी हॉं, गंगनहर की वितरिकाओं में पानी उनकी क्षमता के अनुसार छोड़ा जा रहा है। गंगनहर की सभी वितरिकाओं/नहरों की डिजायन**

क्षमता एवं फसल चक्र खरीफ (दिनांक 16.04.2024 से 15.10.2024) व रबी (दिनांक 16.04.2024 से 20.01.2025) में गंगनहर की सभी वितरिकाओं में छोड़े गये पानी का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। जी हाँ, उक्त सिंचाई पानी प्रत्येक किसान को स्वीकृत बाराबंदी एवं पर्ची के अनुसार प्राप्त हुआ है।

(2) गंगनहर परियोजना में सतरोजा बाराबंदी लागू है। प्रत्येक नहर में पानी प्रवाहित होने के दौरान हर किसान को स्वीकृत बाराबंदी में अंकित अवधि के अनुसार निर्धारित समय व वार को पानी उपलब्ध होता है।

(3) वर्ष 2024 में रबी व खरीफ की फसलों में वितरिकाओं की टेल पर सामान्यतया पूरा पानी उपलब्ध करवाया गया है। यदा कदा नहरों में साफ सफाई नहीं होने के कारण टेल पर पानी की मात्रा प्रभावित हो जाती है, जिसे समय समय पर संबंधित अध्यक्ष के माध्यम से साफ-सफाई करवाकर टेल पर पूरा पानी उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जाते है। टेल पर पूरा पानी उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें एच, जी.जी. व समेजा वितरिका की प्राप्त हुई है। वर्तमान में इन नहरों की साफ सफाई करवा दी गई है तथा पूरा पानी उपलब्ध हो रहा है।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): मेरे पास जवाब आ चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गंगनहर की कई नहरें काफी पुरानी हो चुकी हैं। जिसकी वजह से टेलों तक पानी पूरा पहुंच नहीं रहा है। क्या सरकार इन नहरों पर री-लाइनिंग करने का विचार रखती है? अगर हां तो तक तक? अगर नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्तमान में इस प्रकार की 10 नहरों की री-लाइनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 3 नहरें और भी जाइका के अंतर्गत प्रस्तावित की गई हैं।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): बाकी जो नहरें बची हैं उनका विचार रखते हैं?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि गंगनहर परियोजना हेतु पानी फिरोजपुर फीडर के मार्फत बीकानेर कैनाल की आरडी-45 पर प्राप्त होता है। फिरोजपुर फीडर में जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने से पूर्ण जल प्रवाह क्षमता अनुसार नहीं होता है, जिससे गंगनहर प्रणाली में जल प्रवाह में उतार-चढ़ाव आता है। हमने फिरोजपुर फीडर के पुनः निर्माण हेतु डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग से दिनांक 13.2.2024 को स्वीकृत कराई।

spp/rtm/05.02.2025/12:00/1g

तथा पंजाब सरकार के सिंचाई अधिकारियों से तालमेल स्थापित कर डी.पी.आर. तैयार करवाई गई तथा वर्ष 2024-25 के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं कि 200 करोड़ का बजट का प्रावधान किया। राजस्थान के विभागीय अधिकारियों की मेहनत

और हमारे अधिकारियों के तालमेल से वर्तमान में फिरोजपुर फीडर की डी.पी.आर. एडवांस स्टेज में केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है तथा शीघ्र स्वीकृति कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल समाप्त।

घोषणा

महाराष्ट्र के मंत्री एवं माननीय सदस्यगण की राज्यपाल दीर्घा में उपस्थिति

आज अपना सौभाग्य है कि अपने बीच महाराष्ट्र के मंत्री डॉ. सुरेश भाऊ खाड़े राज्यपाल दीर्घा में बैठे हैं। इनके साथ विधान सभा सदस्य भी बैठे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की समीक्षा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के जी.एस.एस. जेरण में ओवरलोड की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री भगवाना राम सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में नवनिर्मित ट्रोमा सेन्टर को प्रारम्भ न किये जाने से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की सीएचसी प्रतापगढ़ के भवन का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में नोहर फीडर, अमर सिंह ब्रांच एवं सिद्धमुख नहर में पानी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर की नगर परिषद सीमा का विस्तार नहीं किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वन भूमि पर बसी आबादी को पट्टे जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव की अन्तरराष्ट्रीय सीमावर्ती जमीन को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से जिला चूरू में कृषि भूमि का रूपान्तरण आबादी भूमि में नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(11) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश में एन.एच.एम. में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मांगों को अनदेखा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री सुरेश मोदी एवं 30 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के नवगठित तीन संभाग एवं 09 जिलों को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, श्री गणेश घोगरा, श्री सुरेश मोदी एवं श्री रामकेश को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री कैलाश चन्द वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू के जगतपुरा क्षेत्र में सीवरेज एवं सड़कों के अभाव से आमजन को हो रही असुविधा के संबंध में।

(3) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान में सौर उर्जा संयंत्रों की स्थापना से हो रहे दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में।

(4) श्री भागचन्द टांकड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के गुढ़ाकटला में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(5) श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री रेवन्तराम डांगा, सदस्य की ओर से नागौर जिले में जंगली सुअरों की बढ़ती आबादी से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(7) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण योजना बनाये जाने के संबंध में।

(8) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से प्रदेश में मूल निवास से अन्यत्र स्थित कृषि भूमि वाले किसानों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिये जाने के संबंध में।

(9) श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के वन क्षेत्र सामरिया हरडा में बॉयोलोजिकल पार्क की स्थापना किये जाने के संबंध में।

(10) श्री अंशुमान सिंह भाटी, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में मूंगफली खरीद में

अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(11) श्री राजेन्द्र, सदस्य की ओर से तहसील महवा को जिला बनाये जाने के संबंध में।

(12) श्री मनोज कुमार (सादुलपुर),सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में स्वीकृत सड़कों एवं रेलवे अण्डर ब्रिज का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

(13) श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से बिलाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में कब्जेशुदा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार किसानों को दिये जाने के संबंध में।

(14) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कतिपय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र को मगरा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

(15) श्री कुलदीप, सदस्य की ओर से अल्ट्राटेक सीमेन्ट प्लान्ट, मोहनपुरा कोटपुतली द्वारा क्रेशर संचालन एवं हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 05.02.2025 को शून्यकाल में बोलने हेतु 31 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा चार पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

पर्ची

क्र.सं.	पर्ची सं.	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	26	श्री गोविन्द प्रसाद	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरथाना को उपखण्ड चिकित्सालय एस डी एच सेटेलाइट चिकित्सालय में एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।
2.	30	श्री हरलाल सहारण	जिला चूरू में मिनि सचिवालय निर्माण के सम्बन्ध में।
3.	18	श्री गोपाल शर्मा	जयपुर शहर में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की अनाधिकृत बिक्री से बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं नौजवानों में नशे की लत में वृद्धि के सम्बन्ध में।
4.	9	श्री चेतन पटेल कोलाना	बड़ौद पी एच सी की 108 एम्बुलेंस संख्या RJ14 PE 8188 को दीगोद से पुनः बड़ौद स्थानान्तरित करवाने बाबत्।

जिनके प्रस्ताव हैं उनमें सबसे पहले श्री चन्द्रभान सिंह चौहान। ..(व्यवधान).. एक मिनट, आप बोलिये।

व्यवस्था का प्रश्न

न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन विषयों पर चर्चा की अनुमति नियमों के प्रतिकूल

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने एक स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया है 13

नंबर का। इसके सम्बन्ध में अनेक मामले माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस भी जारी किये और संज्ञान भी लिया है और सरकार की ओर से जवाब भी पेश हुए हैं। कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियम के अध्याय 13 का नियम 123 यह कहता है - `जो मामले न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषय पर चर्चा उठाने का प्रस्ताव। साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी न्यायिक, अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो।`

मेरा आपसे यह अनुरोध है चूंकि यह मामला न्यायालय में लम्बित है और सरकार का जो भी पक्ष है, वह सरकार ने वहां पर रखा है। फिर भी आप अनुमति देंगे तो बोल लें। नहीं तो जो मामले न्यायालय में लम्बित होते हैं, उन पर चर्चा नहीं हो तो ठीक रहेगा। नहीं तो यह नियम के विरुद्ध होगा और इसमें 8 पूर्व की आज्ञा से हुए हैं। आसन से जो आज्ञा है, उसमें भी यही कहा गया है कि जो मामले न्यायालय में लम्बित हों, उसकी चर्चा विधान सभा के पटल पर नहीं हो। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्षः कौनसा, यह जिले वाली? जिले वाली कह रहे हैं न।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हां, जिले वाली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सारे जिले कोर्ट में नहीं हैं। दो ही गये हैं, तो दो के अलावा बात कर सकते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं, दो से ज्यादा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, कोर्ट में दो ही लोग गये हैं। जिलों के लिये दो ही लोग गये हैं। आप बता दो हमें। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः एक-एक करके बोलें तो सदन के सामने विषय सही आ जावे। आपको बोलने दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं आपकी बात भी मान लूं, नेता, प्रतिपक्ष। ..(व्यवधान)... एक सैकण्ड। मैं मेरी बात पूरी कर दूं। मान लो, मैं नेता, प्रतिपक्ष की बात को एक सैकण्ड के लिये मान भी लिया जावे। दो मामले लम्बित हैं। यहां तो खोले नहीं हैं कि दो में चर्चा नहीं करेंगे। इसका कोई विवरण तो दिया नहीं है। सभी का एक साथ दिया है। दूसरा, जो दो जिलों के लिये या संभागों के लिये जो भी निर्णय होगा, वह प्रभावित करेगा। वह न्यायिक निर्णय होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, उससे हम सब पाबन्द होंगे। ऐसे विषय की चर्चा नहीं हो सकती। एक बार आप विचार करें। पूरी आथोरिटी देख लें, उसके बाद भी आपको ठीक लगे तो जो भी आपका आदेश होगा, वह शिरोधार्य होगा।

jyg/rtm/05.02.25/12.10/1h

मेरा पुनः निवेदन है कि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं उनको उठाना नहीं चाहिए। इस पर स्पष्ट नियम है, बाध्यकारी नियम है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इतना बड़ा निर्णय हो गया, संभाग-जिले खत्म कर दिये, चर्चा से भी डर रहे हो? जो कोर्ट के अन्दर है।

श्री अध्यक्षः आप उस पर बोलो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो कोर्ट के अन्दर है उसको नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)...अध्यक्षजी की व्यवस्था के बाद, आपकी व्यवस्था के बाद।

श्री अध्यक्षः इन्होंने जो मुद्दा उठाया है न्यायालय वाला उस पर बोलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, आपकी व्यवस्था के बाद कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा, जो जिले कोर्ट में गये हैं, उनको हम कोट नहीं करेंगे, उसके अलावा तो हम बात करेंगे। वो तो हम कह सकते हैं, उसमें क्या एतराज है आपको? और वो तो पीआईएल है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): और यही आंसर अब आपके खुद के क्वेश्चन का आंसर होगा। पीआईएल का मतलब यह है कि वो आम जन को इफेक्ट करेगा। पीआईएल का मतलब यही होता है, वह इंडिविजुअल केस नहीं है। ...(व्यवधान)...सुन लो। बैठे-बैठे नहीं बोलें, कृपया सुनें।

श्री अध्यक्षः बैठे-बैठे न बोलें, आपको भी अवसर देंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पीआईएल आपने खुद ने कहा कि वो पीआईएल है। पीआईएल का तात्पर्य ही यही है कि वो आमजन को इफेक्ट करेगा, वो आमजन के द्वारा किया हुआ माना जायेगा। यही पीआईएल होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो। वो एक व्यक्ति का नहीं है। उस पर जो निर्णय आयेगा वो निर्णय सभी को प्रभावित करेगा। उससे सभी पक्ष प्रभावित रहेंगे, ऐसी स्थिति में जब यह बाध्यकारी नियम है तो आप इस पर एक बार विचार कर लें। यदि आप कहें तो मैं ये सारे पूर्व के जो आदेश हैं, इस आसन के द्वारा दिये गये जो आदेश हैं, उसकी प्रतियां मैं आपके यहां रख देता हूं। उसके बाद आप जो भी ठीक हो, निर्णय दें, लेकिन आप इस पर विचार कर लें। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, डीबी में विचाराधीन है, पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यह किसी इंडिविजुअल का नहीं है, तो ऐसे विषय को यहां पर नहीं उठाया जा सकता।

श्री अध्यक्षः आप लोग बैठें।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे मामले जो हम सदन में डिस्कस करते हैं ऑलरेडी, पीआईएल के अधीन कोर्ट में विचाराधीन होते हैं तो यह व्यवस्था आप दीजिये कि भविष्य में किसी भी मामले में अगर पीआईएल है तो यह बड़ा सोचने का विषय है कि इससे सदन के सारे अधिकार छिन जायेंगे, इतनी पीआईएल लगती है माननीय कोर्ट में, अगर उनको लेकर हम

चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जायेगी, फिर तो सदन का उद्देश्य ही खत्म हो जायेगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः एक बार ही, एक विषय, एक सदस्य, एक बार बोलें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बार बोल रहा हूं। अभी यहां पर चर्चा आयी, अवैध कनेक्शन काटने की, कितने मामले चल रहे होंगे कनेक्शन काटने के कोर्टों के अन्दर, तो फिर चर्चा ही मत करो। ये कोई बात नहीं होती है। ...(व्यवधान)...

यह कोई बात नहीं होती है। कितने ही अपन यहां पर डिस्कस करते हैं, कितने जमीनों के केस आ रहे हैं, कितनी चीजें आ रही हैं, इसका मतलब तो इस पर कोर्ट का केस है, आप चर्चा ही मत करो। जो बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कही है, अध्यक्षजी आपकी व्यवस्था के बाद में और इस प्रकार का इनको अगर कोई एतराज है तो हम दो जिलों की चर्चा नहीं करेंगे जो कोर्ट में गये हैं बाकी की तो चर्चा कराइये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसका मेरा सप्लीमेंट्री इतना-सा ही जवाब है कि जैसा माननीय सदस्य ने बताया, जैसा नेता, प्रतिपक्ष ने बताया कि न्यायालय में तो मामले अनेक चलते होंगे, अनेक चलते होंगे वो स्पेसीफिक करना पड़ता है, जो विषय वस्तु, जिले सही बने हैं या गलत बने, जिले सही खत्म किये या गलत खत्म किये, यह विषय वस्तु न्यायालय में विचाराधीन है। इसी विषय वस्तु को आप यहां उठाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इस विषय वस्तु को जो न्यायालय में विचाराधीन है, उसको प्रभावित करने वाला कोई भी विषय विधान सभा के पटल पर डिस्कस नहीं होना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः एक बार हो गया, व्यवस्था देने दीजिये। कोई नयी बात कहनी है तो कहो।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नियम क्या कहते हैं, साधारणतः, जब चेयर ने फैसला दे दिया है इसकी चर्चा की जा सकती है, नियमों में इस पर प्रतिबंध नहीं है। आप नियम वापस पढ़ो, आप बहुत ज्ञाता हो, विद्वान हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नियम क्या कहते हैं, साधारणतः, उस नियम के अंतर्गत ही स्पीकर को यह अधिकार है चर्चा कराने का, और स्पीकर ने फैसला दे दिया है, ये नियम खुद ही कह रहा है। आप खुद विद्वान हो, ज्ञाता हो, वकील हो, उसके बावजूद आपने खुद ने नियम पढ़े हैं, साधारणतः का अधिकार किसको है, चेयर को है, चेयर फैसला दे चुकी है, उसके बाद में ये विवाद करने के लिए ही यहां पर तर्क रख रहे हो। ये नियम नहीं कह रहे हैं।

श्री अध्यक्षः बैठिये।

मैंने सभी पक्षों को सुना, नियम भी पढ़े, आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मेरे चेम्बर में दोनों पक्षों के दो-दो, तीन-तीन लोगों को बुलाकर इस पर चर्चा करेंगे। इस पर निर्णय हम आगामी दिनों में देंगे। ...(व्यवधान)...यह मेरी व्यवस्था है। आज इस पर चर्चा नहीं होगी। ... (व्यवधान)...

श्री चन्द्रभान सिंह। **...**(व्यवधान)...

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे।)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आसन की व्यवस्था का सम्मान कीजिये।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा कि मेरे चेम्बर में चर्चा के बाद अगले सप्ताह में इस पर निर्णय करेंगे। **...**(व्यवधान)...

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.16 बजे 12.31 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

MLS/RTM/05.02.2025/12:30/1k

(12:31 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। माननीय सदस्यगण, आपने वादा किया था कि वेल में नहीं आएंगे, आप अपनी सीटों पर जाइये। माननीय सदस्यगण, व्यवस्था सुन लीजिये। व्यवस्था सुन लीजिये। माननीय सचेतक, व्यवस्था सुन लीजिये। माननीय सदस्यगण, व्यवस्था सुन लीजिये। चूंकि इस पर 30 लोगों ने स्थगन लगाया है, इसलिए 30 लोग चर्चा में भाग नहीं ले सकते। दो ही लोग चर्चा में भाग लेते, इसलिए आधे घंटे की इस विषय पर परसों चर्चा करवायी जायेगी। आज न करके परसों आधे घंटे की चर्चा इस सदन में इसी विषय पर होगी। ...(व्यवधान)... जो व्यवस्था देता है, वह व्यवस्था में संशोधन भी कर सकता है। ...(व्यवधान)...

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मांगें

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। एनएचएम आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत 7 हजार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ की प्रमुख मांगों को पूर्ण करने के क्रम में। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें सैलेरी के रूप में 25 हजार रुपये मिलते हैं। 15 हजार रुपये प्रति माह इंसेंटिव्ज जोड़ दिये जाएं ताकि इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो। इससे सरकार पर किसी तरह का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

जिस प्रकार से झारखण्ड, उत्तर प्रदेश में सीएचओज को स्थायी किया गया है, राजस्थान सरकार भी इस हेतु कदम उठाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बल मिले। सीएचओज पर तलवार लटकी रहती है और आये दिन उनके काम में दिक्कत आती है, अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन सीएचओज को परमानेंट करें। यदि परमानेंट नहीं कर पाएं तो जिस प्रकार से झारखण्ड और उत्तर प्रदेश में इन्हें पैसा मिल रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में भी करें, क्योंकि इन लोगों की वर्षों से यह मांग है, जिस कारण से स्वास्थ्य सेवाओं में दिक्कत आ रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इनकी मांग की पूर्ति की जाये। माननीय चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं। चिकित्सा मंत्री जी, आप सीएचओज के बारे में सोचें। आज-कल इनकी काफी हड़तालें और धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। काफी ज्ञापन इन लोगों ने दिये, पर इनकी मांगों की पालना नहीं हुई। अतः इनकी मांगों की पालना करें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेश घोगरा।

(माननीय सदस्य के सदन कूप में होने के कारण नहीं बोला गया।)

295, श्री मनीष यादव। श्री कैलाश चन्द वर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जगतपुरा में सीवरेज एवं सड़कों का अभाव

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। बगरू विधान सभा शहरी क्षेत्र के वार्डों में सड़क एवं सीवरेज लाइन के सम्बन्ध में।

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बगरू में नगर निगम (ग्रेटर) के जगतपुरा जोन में वार्ड संख्या 104 से लेकर 124 तक के वार्ड आते हैं। इन सभी वार्डों की अधिकांश कॉलोनियां जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भी हैं। फिर भी सीवरेज एवं सड़क नहीं होने के कारण स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा जिन कॉलोनियों में सीवर लाइन उपलब्ध है, वहां पर भी बारिश के मौसम के चलते ओवरफ्लो की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की लगभग आधी आबादी इन वार्डो में निवास करती है, परन्तु कॉलोनियों में सीवरेज एवं सड़क निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जयपुर नगर निगम (ग्रेटर) के जगतपुरा जोन के विभिन्न वार्डों में सीवरेज एवं सड़क निर्माण कार्यों के लिए एकमुश्त बजट आवंटित कर अनुगृहीत करें।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्रों के दुष्प्रभाव

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

राजस्थान सरकार को राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के लिए बधाई देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नीति का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करना और आर्थिक विकास में योगदान करना है। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास सतत् विकास और न्यायपूर्ण संक्रमण के सिद्धान्तों का पालन करते होना चाहिए। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान, जो अविकसित है और जहां शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, सौर संयंत्रों के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित हो रहा है।

सौर ऊर्जा संयंत्रों ने यहां धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पवित्र ओरण और गोचर भूमि का उल्लंघन किया है, जिसका संरक्षण स्थानीय समुदायों ने अपने जीवन की कीमत पर किया था। इन संयंत्रों के कारण पारिस्थितिकीय संकट बढ़ रहा है और स्थानीय समुदायों की पशुपालक आजीविका समाप्त हो रही है। इसके अलावा, कम्पनियां बड़े पैमाने पर पेड़-पौधों की कटाई कर रही हैं, जिससे सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहा है।

हाई-टेंशन लाइनों के कारण जैव विविधता का नुकसान और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सौर पैनलों के कारण स्थानीय तापमान में वृद्धि हो रही है, जो और अधिक कठिनाइयां पैदा कर रही है। इसके अलावा, कई किसानों को अत्यधिक विषम शर्तों पर अपनी भूमि सौर कम्पनियों को पट्टे पर देने के कारण किसानों को न तो उचित मुआवजा मिल रहा है और न ही भूमि के उचित दाम मिल रहे हैं। किसानों को जान-बूझकर परेशान किया जा रहा है और युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं।

अतः मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रभावों पर विधान सभा में व्यापक चर्चा की जाये और एक नीति बनायी जाये, जो स्थानीय आजीविका, किसानों के भूमि अधिकारों और ओरणों के संरक्षण की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

श्री अध्यक्ष: श्री भागचन्द टांकड़ा।

बांदीकुई के गुढाकटला में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के गुढाकटला में उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महाविद्यालय की नितान्त आवश्यकता है। यहां राजकीय उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महाविद्यालय न होने से गरीब तबके की बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। गुढाकटला में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग विगत कई वर्षों से चली आ रही है। विभिन्न संगठनों के माध्यम से विद्यार्थियों, आम जनता, जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की मांग सरकार के समक्ष रखी, किन्तु आज दिनांक तक उक्त स्थान

पर राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला जा सका, जिसके कारण यहां के विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं को लगभग 30 किलोमीटर दूर दौसा में अध्ययन करना पड़ता है, जिससे इनको आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। उल्लेखनीय है कि प्राइवेट संस्थानों द्वारा संचालित महाविद्यालयों में महंगी फीस से गरीब तबके के विद्यार्थियों को काफी परेशानी होती है।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के गुढाकटला में एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ताकि क्षेत्र को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके।

mkd/rtm/05.02.2025/12:40/1l

श्री अध्यक्ष: श्री भागचन्द टांकड़ा। श्री अमित चाचाण, श्री अमित चाचाण। श्री रेवन्तराम डांगा।

नागौर जिले में जंगली सूअरों की बढ़ती आबादी से किसानों को परेशानी

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 1986 के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर निवेदन है कि पूरे राजस्थान में और विशेषकर नागौर जिले में पिछले 2-3 वर्षों से हर गांव में किसानों के सामने जंगली सूअरों की संख्या बढ़ने से उनसे फसलों को बचाने की बहुत बड़ी समस्या आई हुई है। पहले नील गायों की समस्या थी, जो किसानों की फसलों को खराब करती थी और अब जंगली सूअर का आतंक नील गाय से भी ज्यादा हो गया है। जंगली सूअरों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अकेला किसान खेत में इनसे अपनी फसल को बचा नहीं सकता। ये इतने हिंसक और खूंखार हैं कि इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। बिना हथियार के केवल लकड़ी या डंडे से इनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। जंगली मादा सूअर एक बार में ही 20-20 बच्चों को जन्म देती है, जिससे इनकी संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है। इनकी समस्या का हल किसानों के पास नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इस मामले में संज्ञान लेकर इस समस्या से निजात दिलाने का कोई उपाय करे। यह समस्या सरकार के समर्थन और सहयोग से ही हल हो सकती है, जिससे किसानों को राहत मिले और जंगली सूअरों से उनकी फसल का बचाव हो सके।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जंगली सूअरों की समस्या का समाधान कराने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर हेतु जल संरक्षण योजना

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर निवेदन है कि

वर्तमान में भूजल स्तर में तेजी से बढ़ रही गिरावट और भूजल की गुणवत्ता जहां एक भयावह खतरे का संकेत है, वहीं पीने के साफ़ पानी की कमी के भीषण संकट की चेतावनी भी है। जाहिर है इससे भविष्य में काफी परेशानियों से देश-प्रदेश की जनता को दो चार होना होगा। जल की शक्ति यह है कि इसके आधार पर एक पूरी संस्कृति निर्मित हो सकती है और इसके अभाव में एक क्षेत्र नष्ट भी हो सकता है, इसलिए जल की शक्ति को समझना मानव के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। याद रहे धरा पर 97 प्रतिशत जल समुद्र का खारा है, केवल मात्र तीन प्रतिशत ही मीठा पानी है, जो हर जीव को जीवन दान देता है। इसलिए जीव, मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी इन सभी का निकट का रिश्ता है। हकीकत यह है कि 1960 के बाद पानी की मांग दोगुनी हो गयी है और यह 2025 आते-आते 25 प्रतिशत और बढ़ जायेगी। भूजल दोहन की श्रेणी में अपना देश शिखर पर है।

वैज्ञानिक जलवायु में आ रहे बदलाव में भूजल दोहन की बड़ी भूमिका मानते हैं। ऐसे में भूजल प्रबन्धन और भूजल उपयोग सम्बन्धी रणनीतियों पर व्यापक ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में लगातार आबादी में बढ़ोतरी, बढ़ता शहरीकरण और नजदीकी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर गहन खेती के साथ लगातार भू जल गिरावट हालात को और भयावह बना रहे हैं। बीते एक दशक में हुए अध्ययन से यह साबित हो चुका है कि हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा के मैदानों के पूरे विस्तार तक भूमि के व्यापक हिस्से में भूजल की बड़े पैमाने पर कमी हुई है।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जल संकट के साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर सभी सदस्यों सहित पूरे सदन को चिन्तन के साथ सरकार को प्रदेश के भविष्य की जल मांग को लेकर जल संरक्षण की योजना के साथ आने वाले भयावह संकट से उभरने को तैयार होना होगा। धन्यवाद, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री पूसाराम गोदारा, श्री पूसाराम गोदारा। श्री विकास चौधरी, श्री विकास चौधरी। श्री अंशुमान सिंह भाटी।

बीकानेर में मूंगफली खरीद में अव्यवस्था व भ्रष्टाचार

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर निवेदन है खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के कारण काश्तकारों को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में।

जिला बीकानेर की खरीफ फसल मूंगफली का वर्ष 2024-25 में कुल बीजान क्षेत्र व संभावित उत्पादन का आकलन राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा किया गया। फिर भी प्रत्येक वर्ष की भांति मूंगफली फसल खरीद केन्द्र पर आने के बाद बारदाना, लेबर, भण्डारण की कमी से तुलाई रुक जाती है और कोई जवाबदेही भी निर्धारित नहीं की जाती। दिनांक 18.11.2024 को खरीद शुरू की जाकर आगामी 90 दिन तक खरीद की जानी है। जिसके कारण लगभग 32,436 वंचित काश्तकारों का आगामी खरीद तारीख तक खरीद हो पाना सम्भव नहीं है। विभाग के पास पूर्व से आंकड़े उपलब्ध होने के बावजूद भी बारदाना, क्यूआर

कोड व भंडारण की व्यवस्था नहीं की गयी।

राजफैड द्वारा समय पर खरीद की सूचना के बाजवूद भी राजस्थान के अधिकांश जिलों में टेंडर प्रक्रिया के बाद खरीद की जा रही है लेकिन बीकानेर में शर्तों की जटिलता के कारण टेंडर नहीं हुआ। खरीद केन्द्रों पर बार-बार बारदाना खत्म होने, मजदूर की कमी, जिंस में नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण काश्तकारों के जिंस तुलाई में ज्यादा समय लगने के कारण काश्तकार को लगभग 10-15 दिनों तक वाहनों के किराये, भोजन, आवास व अन्य खर्चा का भी भुगतान करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान होता है।

खरीद केन्द्रों पर जिला स्तर पर गिरोह कार्य करता है, जो कि पटवारी से मिलीभगत कर फर्जी गिरदावरी व बटाईदार प्रमाण पत्र द्वारा राजफैड से टोकन कटवाकर करोड़ों रुपयों का मूंगफली खरीद में घोटाला किया जा रहा है।

मेरा सहकारिता मंत्री महोदय से आग्रह है कि मूंगफली खरीद में हो रहे कथित भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाये एवं अव्यवस्थाओं को सुधारा जाए और लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र।

महवा तहसील का जिला में क्रमोन्नयन

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत दौसा जिले की महवा तहसील को नवीन जिला बनवाने के संबंध में निवेदन है कि महवा तहसील जो कि दौसा जिले के लास्ट बॉर्डर पर है वहां के अंतिम गांव की दूरी भी दौसा से लगभग 120 से 130 किमी है। महवा तहसील के गांव अलवर, भरतपुर, करौली जिले की सीमाओं से सटे हुए हैं। उक्त तहसील राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयपुर और आगरा के मध्य स्थित है। अलवर, राजगढ़, करौली, डीग, कामां, खेरली, कठूमर, भरतपुर, जयपुर, वैर, भुसावर, नदबई, हलैना, रैनी, गड़ी सवाई राम, बयाना, हिंडौन टोडाभीम, मेहंदीपुर बालाजी, सिकंदरा, मानपुर, महवीर जी दौसा, गोवर्धन धाम एवं दिल्ली-मुंबई हाईवे आदि की तरफ जाने वाले रास्ते महवा होकर ही गुजरते हैं। देश का प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की दूरी लगभग 18 किमी है। उक्त तहसील में प्रसिद्ध मंदिर किले वाली देवी और बड़ा महादेव के मंदिर स्थित है। यहां मंडावर में रेल्वे स्टेशन स्थित है।

साथ ही, दो कृषि उपज मंडी महवा, मंडावर और तीन पंचायत समित्ति महवा, मंडावर, बैजुपाडा एवं दो उपखंड कार्यालय महवा और मंडावर, महवा में एक सीओ सर्किल कार्यालय स्थित है और पुलिस थानों में महवा, मंडावर, सलेमपुर बलाहेडी और बैजुपाडा के साथ लगभग आधा दर्जन पुलिस चौकी स्थापित है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक जिला अस्पताल महवा और बैजुपाडा, हुडला, बालाहेडी, मंडावर, सांथा एवं बडागांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। इस क्षेत्र में करीब दो दर्जन 33/11 केवी GSS हैं और इनके अलावा 120 केवी और 220 केवी के जीएसएस भी संचालित हैं। मंडावर व महवा में दो नगरपालिका क्षेत्र हैं।

अतः, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन है की महवा व आसपास के लोगों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए महवा को नवीन जिला बनाने की कृपा करें, जिससे वहां के आसपास के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें, धन्यवाद।

Bhs/Rtm/05.02.25/12.50/1m

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

सादुलपुर में स्वीकृत सड़कों एवं रेलवे अण्डरब्रिज का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाया जाना

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

संदर्भ- मेरे विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में विभिन्न प्रकार की योजनाओं में स्वीकृत सड़कें जिनकी निविदाएं प्रकियाधीन हैं या कार्य प्रगति पर है, उन सभी सड़कों एवं अण्डरब्रिज के कार्य पूर्ण करने बाबत।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कुछ सडकें एवं अण्डरब्रिज स्वीकृति के बाद उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जिसमें सड़क एवं आर. यू. बी. स्वीकृति वर्ष 2023-24 जारी हो गई थी।

गागडवास से पातवान (हरियाणा सीमा तक) लम्बाई 2.25 किमी., लुटाणा मगनी बास से मोरका (हरियाणा सीमा तक) वाया सुरतपुरा 8.5 किमी., चनाना छोटा से ढाणा तक 4 किलोमीटर, ढिगारला से चैनपुरा छोटा तक 7 किलामीटर, बिसलाण से लुटाणा मगनी बास सड़क किलोमीटर 5/0 से 8/0 दूरी 3 किलोमीटर, आर.यू.बी. निर्माण कार्य रेलवे चैनेज संख्या 145/0-1 हनुमानगढ़ सादुलपुर सैक्शन सिध्दमुख, आर.यू.बी. निर्माण कार्य रेलवे चैनेज संख्या 205/2-3 रेवाड़ी सादुलपुर सैक्शन।

श्री अध्यक्ष: खड़े-खड़े बातचीत नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अतः विशेष उल्लेख की मार्फत सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर मे उक्त सड़कों व आर. यू. बी. का निर्माण कार्य अतिशीघ्र करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कब्जेशुदा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की किसानों को प्रदायगी

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत उठाये जाने वाले लोक महत्त्व के विशेष उल्लेख बाबत् निवेदन है कि बिलाड़ा नगरपालिका सन् 1974 में बनी थी, नगरपालिका बिलाड़ा में 63%

जनसंख्या काश्तकारों की है जिनका मूल व्यवसाय खेती है एवं उक्त क्षेत्र डेयरी एवं कोओपरेटिव सोसायटी, राजस्थान में उत्कृष्ट कार्य में हमेशा प्रथम रहा है। किसानों के पास छोटी जोत (सीमांत किसान) होने से यहां के काश्तकारों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के आस-पास सटी पथरीली सरकारी भूमि को किसानों द्वारा अपने खून पसीने की मेहनत से इस भूमि को खेती लायक सुधारकर काबिल काश्त बनाया है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: चार मिनट की जगह 30 मिनट दे दिये और क्या चाहिये। आधे घंटे की बहस करा दी। 30 मिनट दे दिये। 4 की जगह 30 मिनट।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): जब से ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनी उसके बाद आज दिन तक नगरपालिका क्षेत्र में नियमन/आवंटन नहीं हुआ है जबकि काश्तकारों का सरकारी भूमि पर कब्जा काश्त नगरपालिका बनने से पहले का है। यह यथावत चल रहा है। नियमन योग्य भूमि नगरपालिका के मास्टर प्लान से परे हैं। माउंट आबू नगरपालिका की तर्ज पर इस नगरपालिका को भी किसान वर्ग की नगरपालिका घोषित की जावे।

इस समय सरकारी भूमि को नगरपालिका के खाते में दर्ज किये जाने की कार्यवाही चल रही है यदि यह भूमि नगरपालिका के खाते में दर्ज हो गई तो काश्तकारों को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए उक्त भूमि को सरकारी खाते में ही रखी जावे, नहीं तो इस क्षेत्र के किसानों को मानसिक एवं आर्थिक नुकसान होगा। उनके द्वारा सुधार की गई सरकारी भूमि को नियमन/आवंटन की जावे या रियायती/डीएलसी दर पर उन्हें खातेदारी दी जावे तो स्थानीय किसानों को जो आय मिलेगी जिससे स्थानीय किसान समृद्ध व खुशहाल होगा एवं राज्य सरकार की आय भी बढ़ेगी। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा।

जहाजपुर के कतिपय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र का मगरा क्षेत्र सम्मिलन

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना विगत सरकार द्वारा जिला भीलवाड़ा में मगरा से वंचित रखे जा रहे विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर को मगरा क्षेत्र घोषित करवाने हेतु।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये लोक महत्व में सरकार से विशेष आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र अरावली पहाड़ों से घिरा हुआ है, यह क्षेत्र आधारभूत विकास, सामुदायिक एवं अन्य आधारभूत भौतिक परिसम्पत्तियों के सृजन से वंचित है। आधारभूत सुविधाओं जैसे ग्राम स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण आंतरिक सडकें, शिक्षा एवं गांवों में रोशनी की व्यवस्था में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। स्थानीय नागरिकों के रोजगार एवं जीविकोपार्जन हेतु लघु एवं कुटीर उधोगों का अभाव है, यह क्षेत्र पुरातत्व पर्यावरण संरक्षण, कला संस्कृति एवं पर्यटन विकास की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है।

मगरा क्षेत्र में भीलवाड़ा जिला शामिल रहा है लेकिन विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर की 58 ग्राम पंचायतों व नगर पालिका के 25 वार्डों को मगरा क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाकर विगत कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर सौतेला व्यवहार किया। विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के 33 ग्राम पंचायतों की पंचायत समिति कोटड़ी क्षेत्र को भारत सरकार के नीति आयोग ने अति पिछड़ेपन के तथ्यों को देखते हुए भारत सरकार की सम्पूर्णता अभियान के दौरान आकांक्षी ब्लाक में शामिल कर कैम्पों का आयोजन किया गया। अतः विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की 58 ग्राम पंचायतों व नगर पालिका जहाजपुर के 25 वार्डों को मगरा क्षेत्र में शामिल करते हुए मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत समग्र विकास किया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री कुलदीप।

मोहनपुरा (कोटपूतली) में क्रैशर संचालन एवं हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों को कारित परेशानी

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट मोहनपुरा कोटपूतली द्वारा आबादी के पास चलाई जा रहे पत्थर पीसने के क्रेशर को व हैवी ब्लास्टिंग को बंद करवाने या फिर ग्राम मोहनपुरा के बचे हुए शेष भाग जोधपुरा का पुनर्वास करवाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तार्गत में एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुरा संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना पिछले 785 दिनों से लगातार जारी है अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में संबंधित उच्च अधिकारियों को अनेकों ज्ञापन देने के उपरांत भी ग्राम वासियों की समस्याओं का प्रशासन द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट मोहनपुरा कोटपूतली द्वारा मुख्य आबादी के 80-85 मीटर की दूरी पर पत्थर पीसने के क्रेशर एवं हैवी ब्लास्टिंग रात दिन कार्य करते रहने से ध्वनि प्रदूषण के कारण आमजन की सुनने की क्षमता कम हो गई है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आबादी के नजदीक क्रेशर के दिन रात चलने से निकलने वाली डस्ट से गांव में रात दिन कोहरे व धुंध की तरह छाई रहती हैं, जिससे ग्राम वासियों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है एवं गांव में दमा, श्वास, चर्म रोग एवं एलर्जी जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। मोहनपुरा गांव के बचे हुए हिस्से जोधपुरा जिसे अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है के निवासियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, अधिकृत भूमि पर बसे हुए गांव का पुनर्वास दर्शा रखा है जबकि हकीकत में केवल मोहनपुरा के 120 घरों का ही पुनर्वास किया गया है मोहनपुरा के ही मोहल्ले जोधपुरा का पुनर्वास बाकी छोड़ दिया गया है। अब दूसरी युनिट लगाई जाने से बाकी बचे गांव के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है।

क्रेशर निर्माण से पूर्व दिनांक 12.12.2022 को ग्रामवासियों द्वारा इस क्रेशर को लगाने का विरोध भी किया गया था, इसके बावजूद प्रशासन ने दिनांक 28.06.2023 को क्रेशर लगाने की अनुमति प्रदान कर दी।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः चार मिनट की जगह तीस मिनट दे दिये और क्या चाहिये। इससे बड़ा न्याय हो ही नहीं सकता।

श्री कुलदीप (विराटनगर): प्रदूषण विभाग की अनुमति के बिना NOC के चलना पाया जाने के कारण दिनांक 29.06.2024 को प्रदूषण विभाग के अधिकारियों द्वारा मौक़े पर जाकर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को बंद किया गया है इसकी उचित कार्यवाही होनी चाहिए एवं बचे हुए गांव मोहनपुरा के ही मोहल्ले जोधपुरा का पुनर्वास होना जनहित में सही होगा।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट मोहनपुरा कोटपुतली द्वारा आबादी के पास चलाई जा रहे पत्थर पीसने के क्रेशर एवं हैवी ब्लास्टिंग को बंद करवाने या फिर ग्राम मोहनपुरा के बचे हुए शेष भाग जोधपुरा का पुनर्वास करवाना जनहित में सही होगा।

आदर सहित। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री अध्यक्षः पर्ची। श्री गोविन्द प्रसाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सामुदायिक केन्द्र मनोहर थाना को उपखण्ड चिकित्सालय/सैटेलाइट चिकित्सालय में एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना बिलकुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और राजस्थान विधान सभा का 200 नम्बर का विधान सभा क्षेत्र है। वहां पर 150 गांवों के ग्रामीण आस-पास से आते हैं और आबादी लगभग 1 लाख 30 हजार है, तो मैं आपसे और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो वर्षों से 30 बेड का चला आ रहा है, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को तुरन्त प्रभाव से जिला अस्पताल बनाने का मैं अनुरोध करता हूं और...।

श्री अध्यक्षः सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक भोजन अवकाश के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Kas/rtm/05.02.2025/14.00/2c

(समय:14.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि एक बार अपनी

सीटों पर चले जाएं। एक बार अपनी सीटों पर चले जाएं तो व्यवस्था हो सकती है, नहीं तो फिर कार्यवाही होगी और फिर मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपके नेताओं से भी बात कर ली, इधर से भी की है। आप अपनी सीटों पर चले जाओ, अपनी सीटों पर चले जाओ, इस विषय पर मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

सब अपनी सीटों पर विराज जाएं। आज जीरो ऑवर में जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने और पक्ष ने चर्चा की, जिस स्थगन की चर्चा को लेकर जो वातावरण बना, मैंने उस पर विपक्ष के नेताओं की भी बात सुनी और पक्ष के भी संसदीय कार्य मंत्री और अन्यों से मैंने चर्चा की है और नियम भी देखें हैं। मैं यह सदन को स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि मैं न पक्ष के दबाव में हूं, न विपक्ष के दबाव में हूं, यह बहुत साफ कह रहा हूं। इस नाते इस मुद्दे पर मैंने शकधर का भी पढ़ा है और नियमावली की उस पुस्तक को भी मैंने पढ़ा है। उसमें एक ही व्यवस्था हो सकती है कि आज जो व्यवस्था हो गई, यदि कल इस स्थगन पर दो सदस्य, जिनके नाम आज घोषित हुए, केवल वो ही दो सदस्य बोलेंगे और इधर से सरकार के द्वारा एक मंत्री उसका जवाब देगा, यह इसकी व्यवस्था की जाती है। इसमें आपके स्थगन की बात भी आ गई, क्योंकि मैंने उसमें लिखा है स्व विवेक से अध्यक्ष व्यवस्था दे सकता है। ....(व्यवधान).... कोई बीच में नहीं, मैंने बात कर ली है, अगर मैं 200 के 200 को अनुमति दूंगा तो शाम इसी में हो जायेगी। इसलिए आज मैंने जिन दो लोगों को बोलने की अनुमति दे दी, उसमें शायद एक तो रामकेश जी हैं और एक सुरेश मोदी जी हैं। सुरेश मोदी और रामकेश मीणा को बोलने की अनुमति होगी और इधर से उसका जवाब एक मंत्री देंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने तीसरी अनुमति अध्यक्ष जी की भी दे दी थी, तीन लोग हमारे बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, फिर वह चर्चा हो गई। तीन करना है तो फिर आधे घंटे की चर्चा पर जाओ और इस विषय को समाप्त करो। दो की घोषणा की है और इधर से भी सरकार जिस मंत्री को तय करेगी, वो ही इसका जवाब देंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार तो किसी भी स्थगन पर जवाब नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष: नहीं दे रही, मैं दिलवा रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा एक आदमी और बोल लेगा तो भी जवाब दे देंगे, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार का एक आदमी बोलेगा तो एक आदमी हमारा भी तो बढ़ाओ।

श्री अध्यक्ष: ....(व्यवधान).... ऐसा क्यों, यह सौदेबाजी है क्या? व्यवस्था, व्यवस्था है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय स्पीकर साहब, आपका आदेश, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। मेरा आपसे और सरकार से निवेदन है कि हमारे दो ही सदस्य बोल

लेंगे, लेकिन जब मंत्री जवाब दें तो नेता प्रतिपक्ष भी बोले और उसके बाद मंत्री जवाब दे दें, इतना सा कर दें तो हम सब संतुष्ट हैं, हमें तीसरे से कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्षः इस मुद्दे पर नहीं। अगर स्थगन इनका होता तो, मैंने अनुमति दो को ही दी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनका है, इनके साइन हैं।

श्री अध्यक्षः इन्हीं की सहमति से दो को अनुमति दी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन उसमें मंत्री नहीं बोल रहा था।

श्री अध्यक्षः मंत्री का जवाब दिलाना तो चेयर का काम है। चेयर जिस पर चाहे जवाब दिलवा सकती है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): स्थगन पर हम नहीं बोल सकते क्या? ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः अब हो गया। मेरी व्यवस्था को विपक्ष ने शिरोधार्य कर दी और मैं समझता हूं कि आप सबको भी माननी चाहिये कि कल जो स्थगन आयेंगे उसमें दो लोग, एक सुरेश मोदी और दूसरे श्रीमान रामकेश जी, जैसे स्थगन में होता है दो-दो मिनट बोलेंगे और उसके बाद सरकार इसका संक्षेप में जवाब देगी।

पर्ची का मुद्दा उस समय आधा चला था, श्री हरलाल सहारण।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चूरू में मिनी सचिवालय का निर्माण

श्री हरलाल सहारण (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र चूरू का जिला कलेक्टर भवन जो 68 साल पुराना है, वर्तमान में जर्जर अवस्था में है, जिसमें आकस्मिक हादसा होने का खतरा बना हुआ है। पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उक्त भवन की जर्जरता को मद्देनजर रखते हुए उसके पुनर्निर्माण हेतु 49 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा की थी, परन्तु यह घोषणा मात्र वोट बैंक की राजनीति के मद्देनजर रखते हुए की गई थी। कांग्रेस सरकार की हठधर्मिता के कारण भवन निर्माण की घोषणा मात्र घोषणा बन कर रह गई। वर्तमान भवन का काफी हिस्सा खराब हो गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई। जिला कलेक्टर परिसर में संचालित भवन, जैसे कलेक्टर कार्यालय, एस.पी. कार्यालय, एस.डी.एम. कार्यालय, तहसील कार्यालय इत्यादि सभी कार्यालय अलग-अलग संचालित किये जा रहे हैं, जिसके कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलावा संपूर्ण जिले से आने वाले नागरिकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही राजकीय कार्य क्षमता में भारी गिरावट आई है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की थोथी घोषणा की नाकामी की वजह से इस भवन का निर्माण आज दिनांक तक नहीं हो सका। इस भवन के निर्माण में 49 करोड़ की लागत आनी थी, परंतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपनी घोषणा पूर्ण नहीं करने के कारण वर्तमान भवन

की लागत बढ़ कर 100 करोड़ हो गई है, जिससे राजकीय धन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उक्त भवन के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि चूरू हैड क्वार्टर होने के कारण वहां मिनी सचिवालय के लिये 100 करोड़ रुपये की राशि देने की कृपा करें ताकि सचिवालय भवन निर्माण सुचारू रूप से हो सके। आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल शर्मा।

जयपुर में मादक पदार्थों की बिक्री

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, जयपुर शहर में लंबे समय से बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की अनधिकृत बिक्री हो रही है। विशेष रूप से कच्ची बस्तियों में यह अवैध कारोबार संगठित रूप से संचालित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन को लंबे समय से पूरी जानकारी होने के बावजूद समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्षेत्र के नवयुवक नशे के आदि होते जा रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ने की संभावना है। दिल्ली रोड सहित कुछ इलाकों में कुछ नौजवानों की मौत भी हुई है। अत: पर्ची के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आतंक और ड्रग्स, इन दोनों समस्याओं के प्रति समान रूप से जागरूक रहकर इनका निदान करवाने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल कोलाना।

बडौद पी.एच.सी. की 108 एम्बुलेंस का दीगोद से पुन: बडौद हस्तान्तरण

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में बड़ौद पी.एच.सी. में पूर्व में 108 एम्बुलेंस संचालित थी, जिसका नंबर था, जो गत कांग्रेस सरकार द्वारा जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दी गई थी, जो दीगोद तहसील के आखिरी छोर तक अपनी सेवाएं देती थीं। हमारे पास में ही सांगोद विधान सभा क्षेत्र है, जहां से माननीय ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी विधायक भी हैं। सांगोद विधान सभा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी द्वारा आयोजित जन सुनवाई में उनकी विधान सभा क्षेत्र में दीगोद पी.एच.सी. हेतु उन्होंने ब्लॉक सी.एम.एच.ओ. सुल्तानपुर को दिशा-निर्देश दिये, जिसकी पालना हेतु बी.सी.एम.एच.ओ. ने सी.एम.एच.ओ. को अवगत करवाया और इस विषय हेतु जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सी.एम.एच.ओ. कोटा ने सत्ता के भय से, सत्ता के डर से पीपल्दा विधान सभा में बडौद पी.एच.सी. की एम्बुलेंस को सांगोद विधान सभा की पी.एच.सी. दीगोद में भेज दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या पीपल्दा विधान सभा में मरीज नहीं हैं? क्या यहां दुर्घटना नहीं होती? और तो और क्योंकि पीपल्दा में विपक्ष का विधायक है, इसलिए बिना क्षेत्रीय विधायक या किसी भी क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधि से चर्चा किये कैसे सी.एम.एच.ओ., कोटा ने यह कार्यवाही की? माननीय अध्यक्ष

महोदय, यह बड़े ही शर्म की बात है, इस विषय में पीपल्दा क्षेत्र के लोगों ने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी पीपल्दा दौरे के दौरान इस पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। हम इस सरकार से हमारे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कोई नई एम्बुलेंस की उम्मीद नहीं करते, लेकिन जो हमारा हक था, हमारा अधिकार था, हम उसको मांग रहे हैं।

Msk/rtm/05.02.25/1410/2d

और हमारा अधिकार एवं हमारा हक हम लेकर रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के गांव बड़ौद में पीएचसी में जो एंबुलेंस संचालित थी, उससे दीगोद में शिफ्ट कर दिया, उसे पुनः बड़ौद में संचालित किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद। जो आदेश सीएचएचओ, कोटा ने जारी किया, उसकी रिपोर्ट मैं अनुमति से सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखने जाने वाले पत्रादि। ..(व्यवधान).. यह पूरा हो जाये, पत्रादि हो जायें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह काफी गंभीर विषय है। मंत्री जी आश्वासन दे दें, दूसरी एंबुलेंस लगवा दें। ऊर्जा मंत्री जी ने उनकी एंबुलेंस अपने क्षेत्र में ले ली और वहां एंबुलेंस नहीं है तो दूसरी लगवा दो।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर अभी तक जवाब आया नहीं है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। सुश्री दिया कुमारी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त (आबकारी) विभाग

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (आबकारी) विभाग की 01 व आयोजन विभाग राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की 02 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं।

अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2024/पार्ट दिनांक 30.08.2024, जिसके द्वारा राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के उप निदेशक व राजस्व आसूचना अधिकारी को राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 43, 44, 45 व 47 के तहत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है।

आयोजना (राजस्थान जन आधार प्राधिकरण) विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ17(8)41/डीईएस/रा.ज.आ.यो./विनियम/2021/2445 जी.एस.आर.71 दिनांक 24.10.2024 जिसके द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 41 के तहत राजस्थान जन आधार प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य का आदान-प्रदान) विनियम, 2024 विरचित किया गया है; एवं

2. अधिसूचना संख्याः एफ17(8)41/डीईएस/रा.ज.आ.यो./विनियम/2021/2446 जी.एस.आर.72 दिनांक 24.10.2024 जिसके द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 41 के तहत राजस्थान जन आधार प्राधिकरण (एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठकों में कार्य का आदान-प्रदान) विनियम, 2024 विरचित किया गया है।

श्री अध्यक्षः श्री मदन दिलावर।

पंचायती राज विभाग

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की 04 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं।

1. अधिसूचना संख्याः प.4(22)संशो./नियम/विधि/पंरा/2024/10698809 दिनांक 24.09.2024 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-266 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्याः एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/02 दिनांक 10.01.2025 जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के नवसृजन एवं पुनर्गठन हेतु जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है;

3. अधिसूचना संख्याः एफ.15(2)प्रशासक/विधि/पंरा/2025/05 दिनांक 16.01.2025 जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया गया है; एवं

4. अधिसूचना संख्याः एफ.4(1)/नियम/संशो/विधि/पंरा/2024/06 दिनांक 17.01.2025 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-157 के तहत जारी पट्टों के प्रारूप में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्षः वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। सुश्री दिया कुमारी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्षः श्री गजेन्द्र सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 सदन

की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

1. राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन; एवं

राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अन्तर्गत राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 ।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के वार्षिक लेखे मय ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2023-24)

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन के नियम-46 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के वार्षिक लेखे मय ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 98 के अन्तर्गत राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्रा, माननीय मंत्री।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

जयपुर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

1. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24; एवं

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

2. राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी अधिनियम 2016 की धारा 78 के अन्तर्गत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे (वर्ष 2023-24)

एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुमति से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखे एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,

राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा-12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई, उद्योग राज्य मंत्री।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज रखता हूं:-

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

1. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32(4) (अध्याय 9) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2024-25;

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024)

2. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 (अध्याय 8) के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024;

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

3. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 (अध्याय 8) के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25;

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024)

4. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 (अध्याय 8) के अन्तर्गत

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024;

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024)

5. कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 (अध्याय 8) के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024; एवं

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 65वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

6. भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा-31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 65वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23।

श्री अध्यक्षः प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु, श्री कन्हैयालाल, सभापति, प्रवर समिति।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर गठित प्रवर समिति के प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापन हेतु नियत समय को वर्तमान तृतीय सत्र के अन्तिम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्षः इस पर चर्चा नहीं होती।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): चर्चा नहीं, ये कह रहे हैं कि अंतिम सप्ताह में लेकर आयेंगे। अंतिम सप्ताह में लेकर आयेंगे तो चर्चा कब होगी? अंतिम सप्ताह में आयेगा तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप इसको जल्दी बुलाइये, जिससे हम सदन में चर्चा तो करें। पिछली बार भी ये जल्दबाजी में लेकर आये और चलते विधेयक को दोपहर में ही सरकार को वापस लेना पड़ा। कितनी किरकिरी हुई थी? वही स्थिति फिर करना चाहते हैं। आप इसको टाइम से लेकर आयें, जिससे कि सदस्य इस पर अपनी बात रख सकें। बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इस पर कुछ कहेंगे?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): प्रवर समिति के जितने भी सदस्य थे, पक्ष और विपक्ष के, सबने तय किया, आखिरी सप्ताह में आयेगा तो जो भी चर्चा होगी तो वह भी इस सदन में ही होगी, पूरे दिन चर्चा चलेगी।

श्री अध्यक्षः मेरी सोच यह है कि इसी सत्र में ही उस पर चर्चा होनी है। तब यह करें कि अंतिम सप्ताह की जगह, उससे एक सप्ताह पहले।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु जो संशोधित नियत समय की चर्चा हुई है कि वर्तमान तृतीय सत्र के अंतिम से एक सप्ताह पहले तक बढ़ा

दिया जाये?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे जी के अभिभाषण पर विचार प्रकट करने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जिस तरह अभिभाषण यहां पर पढ़ा गया और जिस तरह उन्होंने राजस्थान की माटी को प्रणाम करते हुए इसके शौर्य, त्याग और बलिदान की जो विवेचना की, उसको सुनते वक्त ऐसा लगा, जैसे महाराष्ट्र से आया हुआ सपूत, वीर शिवाजी के सपूत के रूप में उन्होंने राजस्थान आकर यहां की मिट्टी को तिलक किया, ऐसा अभिभाषण उनका था।

mdp/rtm/05.02.2025/14:20/2e

मान-सम्मान और स्वाभिमान की ऐसी वीर प्रसूता भूमि राजस्थान के अभिभाषण पर जब उन्होंने चर्चा की, अध्यक्ष महोदय, उस अभिभाषण में कई चीजें थी, लेकिन हम सबको, पक्ष को, विपक्ष को इस बात को मानना पड़ेगा कि आज इस देश की कमान इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी जी के हाथ में है, इस राजस्थान की कमान राजस्थान के एक लोकप्रिय व्यक्तित्व श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के हाथ में है ...(व्यवधान)... आपको कौन कह रहा है कि आप मानिए, लेकिन ...(व्यवधान) हमें इस बात का गर्व होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: दोनों पक्षों को सुनिए। ...(व्यवधान)...आप बैठिए। अंकित नहीं होगा। आप खड़े हो गये। यह तरीका नहीं है।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्री अध्यक्ष: मैं फिर आगे से आपका नाम भी आयेगा तो बोलने नहीं दूंगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, हमको इस बात को मानना पड़ेगा कि पहली बार हिन्दुस्तान में कोई प्रधान मंत्री बना, जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करता है। पहली बार राजस्थान का कोई मुख्य मंत्री बना है, जो 24 घंटे में 20 घंटे में काम करते हैं और 4 घंटे आराम करते हैं। इसी बात की जलन है इन लोगों को। आपने पिछले पांच साल जो राज किया, साढ़े आठ करोड़ राजस्थानियों के साथ जो कुठाराघात आपने किया है, उसी का नतीजा आपने चुनावों में एक साल पहले देख लिया। यह सच्चाई है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे कैलाश जी वर्मा साहब बैठे हैं, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर शुरूआत कर रहे थे। डोटासरा जी अभी नहीं है तो मुझे बोलने का मजा भी नहीं आयेगा।

इन्होंने डोटासरा जी के गमछे की, क्या की थी, गमछा घूमा कर बताया इन्होंने। आपने देखा होगा कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनावों में संविधान के नाम पर लोगों को भड़का कर इन्होंने राजस्थान में 11 सीटें जीत ली। अब मोरिया बोल गया उप चुनावों में।

श्री अध्यक्षः व्यक्तिगत नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): देखिए जूली जी, मुझे खुशी है इस बात की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की है कि अभी थोड़ी देर पहले डोटासरा जी ने आपको संबोधन करते हुए निवेदन किया था कि हमारे विपक्ष के नेता को भी बोलने का मौका दीजिए। उन्होंने माना मुझे इस बात की बहुत खुशी है, वैसे मानते नहीं है वे आपको।

राजस्थान की सरकार ने पिछले एक साल में जो किया है, उसका जिक्र राज्यपाल महोदय अभिभाषण में कर रहे थे, लेकिन उस दिन जिस तरह गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, जो आपकी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की। राज्यपाल की उम्र को लेकर टिप्पणी की। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की बात इस राजस्थान के लिए नहीं हो सकती। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जूली साहब, धारीवाल साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब की कितनी उम्र है? कितनी उम्र है उनकी?

श्री अध्यक्षः आप तो बोलिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 80 साल है उम्र उनकी। हमारे राज्यपाल महोदय की उम्र कम है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की, हालांकि राज्यपाल जी ने उनकी औकात भी दिखा दी हाथोंहाथ ही उनको। वह पूरे राजस्थान के पूरे मीडिया में छपा है। आज राजस्थान में पांच साल के कांग्रेस के कार्यकाल की, जो कांग्रेस ने पांच साल में किया, उसको लोग भुला नहीं पा रहे हैं। उसका परिणाम हमने विधान सभा चुनाव में देखा, उसका परिणाम अभी जो बॉई-इलेक्शन हुए 7, उसमें देखा। पेपर लीक का मामला हो, लूट हो, चोरी, डकैती, बलात्कार, कितनी घटनाएं हुईं? लॉ एंड आर्डर की कितनी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। इसको अब आप महसूस कर रहे हैं। डोटासरा जी होते तो उनको मैं कहता, जैसा कैलाश जी ने कहा, जूली साहब, ये गमछे कहां से लाते हैं, ये तो बताइए मुझे। मुझे गमछों का आर्डर देना है। एक दर्जन।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): गमछों ने 11 सांसद घर भेज दिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरी बात सुनिए, मुझे गमछे की गठान मंगानी है, क्योंकि जहां-जहां भी ये गमछा घूमता है, वहां कांग्रेस का सफाया होता जाता है। हरियाणा गये, साफ हो गयी, महाराष्ट्र गये, साफ हो गयी। राजस्थान की सब सीटों पर गये, कांग्रेस साफ हो गयी। हम एक गठान मंगवा लेते हैं और ...(व्यवधान)...सब राज्यों में, दिल्ली में भी, आप दिल्ली गये या नहीं गये? ...(व्यवधान)... विकास जी, अभी एक साल पहले हमारे देहरी लगाते थे आप, एक साल पहले और परसों क्या बोल रहे थे?

श्री अध्यक्षः व्यक्तिगत वार्ता नहीं। आप तीसरी बार खड़े हो रहे हैं, याद रखना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इन्होंने परसों अभिभाषण में जो बात कही, अध्यक्ष महोदय, उसका हमको विरोध करना चाहिए। डाक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा का नाम लेकर जो बात इन्होंने यहां पर की, विकास जी ने, इनको नहीं कहनी चाहिए थी। ...(व्यवधान)... डाक्टर किरोड़ी लाल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, हैं और रहेंगे जिंदगीभर। हमारी पार्टी के वरिष्ठ हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप सरकार को समझाओ कि उनकी सुने। आप समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सरकार समझ रही है। सरकार के मंत्री हैं। लेकिन आपने यह बात कही कि मेहनत करे किरोड़ी लाल, मेरी बात तो सुनिए ...(व्यवधान)... आपने हमारे मुख्य मंत्री जी पर टिप्पणी की। मुझे आप एक बात बता दीजिए कि राजस्थान में सचिन पायलट जी भी चले गये, पांच साल तक सचिन पायलट जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पांच साल मेहनत उन्होंने की। कांग्रेस का जो जहाज था रन-वे पर उन्होंने उतारा चुनाव में और हवाई जहाज लेकर कौन भाग गया? गहलोत साहब। ...(व्यवधान)... पायलट बनकर भाग गये और दिल्ली से सोनिया गांधी से डीजल भरवा कर आ गये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): आपकी वसुन्धरा जी कहां है? ...(व्यवधान)... कहां पर है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): देखिए आज जो राजस्थान की एक साल में व्यवस्था हमारे मुख्य मंत्री जी ने की है, राजस्थान का जो बजट हमारे मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, उसकी आपको जलन है, मुझे पता है। लेकिन आपमें से कोई एमएलए यह नहीं कह सकता कि राजस्थान की इन 200 विधान सभा क्षेत्र में कोई विधान सभा क्षेत्र उन्होंने छोड़ा हो। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था करनी हो, हर चीज में जो एमएलए ने कहा या वहां के लोगों ने कहा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अभिभाषण है, बजट पर नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): देखिए, इनके जलन एक और हो रही है। इनके जलन हो रही है कि कल दिल्ली का बजट आया।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): ये तो बहुत असत्य बोलते हैं। मेरे ऊपर 302 का मुकदमा कराया कांग्रेस ने कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष +++ की हत्या कर दी। अब इससे असत्य कौन होगा? ...(व्यवधान)... इससे असत्य कौन होगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, विराजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, यह अंकित नहीं होना चाहिए। +++ यहां के सदस्य नहीं है, उनका नाम अंकित नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: जो भी यहां सदस्य नहीं है, उनका नाम अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जूली साहब, परसों आपने केन्द्र सरकार का बजट सुना, रात को नींद आयी या नहीं आयी आपको। ...(व्यवधान)... नींद आ गयी तुम्हें, हाकम साहब।

श्री अध्यक्ष: व्यक्तिगत पूछताछ मत कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि केन्द्र में जो बजट प्रस्तुत किया है, इन्होंने कहा और बजट की बात की कि राजस्थान के बजट की चर्चा मत कीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप पूछिए मत। आप बोलिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आज दिल्ली में वोटिंग हो रही है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, एक सीट आ जाए दिल्ली में तो मुझे कह देना कांग्रेस की ..(व्यवधान)... भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। 12 लाख तक, आपके राज में 2 लाख आयकर पर छूट थी। आज हमको धन्यवाद देना चाहिए ताली बजाकर हमारे प्रधान मंत्री जी को, जिन्होंने 12 लाख तक छूट दी। बजट पर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... 3 लाख से 5 लाख किया। आप मुझे बताइए कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए इस हिन्दुस्तान में अगर किसी ने शुरूआत की आजादी के बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। जिन्होंने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनायी, स्वर्ण चतुर्भुज सड़क बनायी, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की, फसल बीमा योजना उन्होंने बनायी। सबसे बड़ा काम क्या किया, पता है, उन्होंने हिन्दुस्तान को परमाणु ताकत वाला मुल्क बनाया। पोकरण में जो विस्फोट हुआ, पूरे विश्व में हिन्दुस्तान का नाम हुआ और आज हमारे मोदी जी उस नाम को आगे बढ़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी, इस अभिभाषण में कहा गया 350 बिलियन डालर तक हमारी अर्थव्यवस्था को ले जाने का प्रयास हमारे मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं।

Ans/rtm 14.30 2f 05.02.2025

35 लाख करोड़ के राइजिंग राजस्थान में अभी एम.ओ.यू. हुए, उसकी भी इन लोगों को जलन। 32 देशों के प्रतिनिधि यहां पर आये, उन्होंने एम.ओ.यू. किए। यह होने के बाद बार-बार बेरोजगारी की बात कर रहे है ना, हमने जो वादा किया है कि इन चार सालों में चार लाख बेरोज़गारों को रोजगार देंगे, 100 परसेंट मिलेगा। हमने जो काम किए हैं वह छिपे हुए नहीं है। जूली साहब यह एक्शन करने से नहीं होता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो कुछ नहीं बोला।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप इशारा कर रहे हो। साहब, यह मुझे गंदे-गंदे इशारे कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दो करोड़ की भी आपने ही कही थी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो किया है ...(व्यवधान)... नहीं बोलेंगे, जानता हूं मैं इनके लक्षण। हमारे मुख्य मंत्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण में जो कहलवाया, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, राजस्थान इनवेस्ट एम.ई. नीति 2024, राजस्थान एकीकृत कलस्टर विकास योजना 2024 लागू की गई, इससे राजस्थान का आने वाले चार सालों में जो भविष्य बदलेगा वह पूरा राजस्थान देखेगा।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों का जाल बिछाना हो, चाहे मगरें में हो, टीएसपी क्षेत्र में हो, हर जगह, राज्यपाल के अभिभाषण में हमारे मुख्य मंत्री जी द्वारा जो काम किए गए हैं उनको जनता को बताने का प्रयास किया गया है।

मेरा माननीय विपक्ष के सदस्यों से निवेदन है, बार-बार कहते हो कि हमने चुनाव में जो घोषणा की थी, बजट में कहा, हमारा घोषणा पत्र था उसकी क्रियान्विति नहीं की। जूली साहब, 450 रुपये में गेस सिलेण्डर मिल रहा है या नहीं? आप लोगों से जाकर पूछना। हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि में 06 हजार के 12 हजार करेंगे, 02 हजार बढ़ा दिए। 02 हजार से बढ़कर 08 हजार हो गए। ...(व्यवधान)... आपके नहीं आ रहे होंगे, आपके तो जमीन है ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार ईआरसीपी की बात करते हैंकि कुछ नहीं हुआ। उस दिन डोटासरा जी भी कह रहे थे क्या हुआ ईआरसीपी में। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने जब ईआरसीपी के बारे में विचार किया ...(व्यवधान)... उसको धरातल पर कौन लाया? उसको धरातल पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री भजनलाल जी शर्मा लाए। आपको तो वैसे ही राम के नाम से चिढ़ है। कांग्रेस वालों को तो राम के नाम से चिढ़ है। भजनलाल जी ने उसका नाम भी राम जल सेतु लिंक परियोजना रख दिया, उसके बाद जलन होना स्वाभाविक है। ईआरसीपी, यमुना समझौता, ब्राह्मणी नदी से भी जयपुर में पानी लाना, ऐसी कई योजनाएं हैं।

धारीवाल साहब, राजा की नीयत ठीक होती है तो भगवान भी सुनता है। हमारे राजा की नीयत ठीक है। आज आप हवाई जहाज में यात्रा करते हो, इस राजस्थान में हवाई जहाज से जहां-जहां भी जाएंगे, पूरे राजस्थान में पानी ही पानी नजर आ रहा है, यह है भजनलाल जी। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): महारानी को छोड़कर राजा पर आ गए क्या ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका नम्बर आए तब आप खडे होना। आपका जब नम्बर आए तब बोलना, बार-बार नहीं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपकी नीयत को मुख्य मंत्री जी नहीं समझ पा रहे, हम तो समझ रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरी नीयत तो धारीवाल जी से ज्यादा कोई समझ ही

नहीं सकता, यह मेरे पुराने दोस्त है। वसुन्धरा जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्य मंत्री है, हमारी नेता है। लेकिन आज भजनलाल जी शर्मा हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री है। राजस्थान के साढे आठ करोड़ लोगों की ...(व्यवधान)... आप क्यों लड़ाना चाह रहे हो? कभी किरोड़ीलाल जी, भजनलाल जी लडाओंगे। कभी वसुन्धरा जी और भजनलाल जी की बात करोंगे। अभी अभिभाषण में जल जीवन मिशन के तहत 15 हजार करोड़ देकर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): भूल जाओ। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके तो लगवा ही देंगे। श्रवण जी, मैं आपको बताऊं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): भूल जाओ, काहे का जल जीवन मिशन ...(व्यवधान)... सारा बंटाधार है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): हर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस ने उसमें घोटाला कर दिया। ...(व्यवधान)... कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे इसलिए हो गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): प्रधान मंत्री जी ने हर घर में जल पहुंचाने का प्रयास किया, राजस्थान की जनता खुश है लेकिन आपने अवरोध पैदा किया उसमें, भ्रष्टाचार कर गये, आप खा गये। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने पांच सालों में जे.जे.एम. में भ्रष्टाचार किया। लूटकर नहीं खाते तो आज यह स्थिति नहीं होती, आप सामने नहीं बैठे होते। परसों भाषण में श्रवण जी खुद ही कह रहे थे। आप कह रहे थे कि हमारे 22 मंत्री घर बैठे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह बात मान रहे हो तो यह भी मानो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्रवण कुमार जी, जब आप बोलने खड़े हुए और इन्होंने डिस्टर्ब किया तो फिर आप मुझे मत कहना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जूली साहब, वक्त कहता है सम्भल जाओ, कहीं ऐसा ना हो वह भी हो जाए जो कभी आपने सोचा ना था।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

पानी से प्यास बुझाई जाती है, पानी से आग बुझाई जाती है, फितरत आपके घोटालों की क्या कहूं कि आपके पानी के घोटालों ने आपको ही बुझा दिया। आपको निपटा दिया।

सभापति महोदय, बिजली की आपके राज में क्या व्यवस्था थी? हमारे पास पूरे दिन लोगों के मोबाइल आते थे कि बिजली बंद है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के पांच साल के राज में थ्री फेज तो छोडो सिंगल फेज ही नहीं आता था। अभी आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य अभिभाषण पर बोल रहे थे ...(व्यवधान)...

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): आपके भाषण देने से कुछ नहीं होता ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने थर्मल प्लांटों व कोयला में कितनी कालाबाजारी की मुझे सब पता है। मुझे पता है कांग्रेस के राज में कितनी कालाबाजारी हुई थी। ...(व्यवधान)... यह तो हमारे मंत्री जी हीरालाल जी नागर साहब बैठे हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया। छत्तीसगढ़ से समन्वय बनाकर कोयले की व्यवस्था की। दो दिन पहले विपक्ष के, आपके सदस्य श्रवण जी कह रहे थे कि बिजली बहुत बढ़िया आ रही है, कोई शिकायत नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठिये, बार-बार खड़े हो जाते हैं। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, इस पूरे विपक्ष में अगर एक आदमी भी अगर सच्चा बोलता है तो वह श्रवण कुमार जी है। यह कभी असत्य नहीं बोलते, मैं मान गया। इन्होंने कह दिया कि बिजली आ रही है तो आ रही है, किसी का काकाजी भी नहीं रोक सकता उसको तो। भीमराज जी भाटी भी बोलते हैं। भीमराज जी के लिए ताली बजा दो अपने तो, इतना बढ़िया बोलते हैं।...(व्यवधान)...

हमने एक साल में किसानों को 01 लाख 10 हजार कृषि कनेक्शन दिए, 05 लाख से अधिक घरेलू कनेकशन दिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर घर सूर्य घर बन रहा है। आने वाले पांच साल में राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। आपने क्या किया? डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे। वह बार-बार कह रहे थे ना कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नकल में व पेपर लीक में बड़े मगरमच्छों को पकड रहे हैं, नहीं पकड़ेंगे। यह मगरमच्छ हम गमछे में लपेटकर ही पकडेंगे। गमछे से ही लपेटकर ले जाएंगे मगरमच्छों को, आ रहे हैं नम्बर उनके भी। उनके नम्बर भी आ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

VPS-RTM-05.02.2025-14.40-2g

क्या-क्या गिनाऊं करतूतें तुम्हारी, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। जूली साहब, राजस्थान के बेरोजगारों का खून खौलता है। थोड़ा सुधरो और कुछ नहीं। देखो, वैसे तो यह मानकर चलो कि इस हिंदुस्तान में कांग्रेस खतम है, बिलकुल खतम है, थोड़ी बहुत राजस्थान में बची है तो इन चार सालों में ये भजन लालजी निपटा देंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता, अभी मैं कल ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वे बोल रहे हैं आप सुनें। आपका नम्बर आये तब आप जवाब दे देना। बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा, उनका समय कट रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, हमने यह कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अभी 2024 में लगभग 60 हजार नियुक्तियां राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री भजन लालजी की सरकार ने दी हैं। 1 लाख 73 हजार भर्तियां प्रक्रियाधीन है और 2025 में 21 हजार पदों पर जो भर्तियां होने वाली हैं उनका कलैंडर जारी

कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। उसका श्रेय भी ये लेना चाहते हैं कि हमारे टाइम में यह भर्तियां, हमने खोल दी थीं। अब यह मेरे समझ में नहीं आया कि कल-परसों ही डोटासराजी एक बात कह रहे थे कि मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि सफाई कर्मचारियों की आप भर्ती कर रहे हो तो सफाई कर्मचारी क्या कर्मचारी नहीं होते हैं क्या? हाकम साहब, आपके कांग्रेस के राज में सफाई कर्मचारियों की भर्तियों में दो-दो लाख रुपये रिश्वत ली गयी है, एक-एक कर्मचारी की भर्ती में। दो-दो लाख रुपये, मैं सबूत दे सकता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज, बैठिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप तो उनको नौकरी लगाओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उनकी नौकरी भी लगेगी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उनको पीड़ा हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य श्रवण कुमारजी, प्लीज। आपका नम्बर आये तब आप बोलना, आपको कौन रोक रहा है? आपका नम्बर आये तब आप जवाब दे देना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रारंभ की। आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की। मुख्य मंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के माध्यम से प्रदेश को स्वस्थ एवं निरोगी राजस्थान बनाने का प्रयास हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने किया। गांव-गांव और मजरों-मजरों तक चिकित्सा की व्यवस्था कराने का प्रयास हमारे मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक वर्ष में 40 जन कल्याणकारी योजनाओं से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से जो राज्यपालजी ने भी अभिभाषण में कहा कि 1440 किसानों को 23 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गयी है, यह कोई छोटी-मोटी राशि नहीं है। चुनाव घोषणा पत्र का 60 प्रतिशत काम राजस्थान की सरकार ने एक साल में कर लिया, इससे बड़े गर्व की बात नहीं हो सकती। आज केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार, ये बारबार डबल इंजन की बात करते हैं, केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर डबल इंजन के रूप में जो काम कर रही है, यह भूतो न भविष्यति, ऐसे काम राजस्थान में हमने एक साल में देखे हैं। चाहे आप ई.आर.सी.पी. को ले लो या चाहे बड़ी-बड़ी योजनाओं को ले लो। मेरे पास समय नहीं है, मुझे 20 मिनट का समय दिया है लेकिन इतने काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइजिंग राजस्थान है, ऐसी कितनी ही चीजें हुई हैं और यह आपका जो बजट प्रस्तुत होता था न धारीवालजी, कांग्रेस के राज में तो मुझे पता है, मैं मेरे एरिया का ही बता दूं, मेरे जिले का ही बता दूं कि आपके मंत्रियों ने भाटे लगा रखे हैं उद्घाटन के, शिलान्यास ही नहीं हुआ उनका,

खाली बजट में बोल दिया, हमारे निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ रोड है, यह बैठे हैं चित्तौड़ के एम.एल.ए., इनसे आप पूछें, 150 करोड़ का रोड, उसका शिलान्यास हो गया, पत्थर लगा दिये पर काम स्वीकृत ही नहीं, कागज में ही काम नहीं है, ऐसे काम कांग्रेस के राज में हुए। पुराना बजट पढ़ लिया वह अलग चीज है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण राजस्थान की सरकार कर रही है। हमने गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल खोल दिया। हमारा संकल्प है विकसित भारत बने, विकसित राजस्थान बने, कमजोर व्यक्ति आगे आये, गरीब का भला हो, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हो, जनजाति लोगों का भला हो और वह भला हम देख रहे हैं। इस एक साल में ये हेमन्तजी और हमारे कई जनजाति क्षेत्र के लोग बैठे हैं। ये बता सकते हैं कि इन्होंने एक साल में कितना काम किया है, जिनके साथ पांच साल से कुठाराघात हो रहा था, पांच साल से जिनके काम रुके हुए थे। एक साल में ही लोग यह महसूस करने लगे कि राजस्थान में कोई कल्याणकारी सरकार आयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि अब, विपक्ष के नेताजी, अभी तो आप ही बैठे हो, डोटासराजी कह कर गये हैं। जूली साहब, महाकुंभ स्नान करने चल रहे हो क्या 8 तारीख को? नहीं जा रहे हो? फिर आएंगे भी नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप लोग जो जा रहे हो या तो पूरी विधान सभा के सभी सदस्यों को लेकर जाते, हमने कोई मना किया है क्या? यह इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए थीं। सदन के सभी सदस्यों को लेकर जाते, यह कोई बी.जे.पी. की मीटिंग नहीं हो रही। आप मंत्रिमंडल और विधायकों को ले जा रहे हो तो ये भी विधायक हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आपने तो भगवान राम का अस्तित्व ही नकारा था। आप जनता को विश्वास ही नहीं दिलवा सकते। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप पहले खड़गे साहब से इजाजत ले लो ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): आप एक भी कांग्रेस के नेता को बता दो जिसने कुंभ में डुबकी लगायी हो। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप पहले खड़गे साहब से इजाजत तो ले लो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, यह चर्चा का विषय नहीं है। माननीय सदस्य, आपकी बात समाप्त। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, यह चर्चा का विषय नहीं है लेकिन चर्चा इन्होंने निकाल दी। हमारा यह विचार था कि इस महाकुंभ में सबको ले जाये ताकि इनके भी पाप धुल जाये विपक्ष वालों के लेकिन, माननीय सभापति महोदय, हुआ क्या?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसका मतलब पाप धोने जा रहे हो आप। पाप धोने जा रहे हो, आपने यह खुद ही कह दी। सच्चाई आ गयी, सभापतिजी, सच्चाई अपने आप इनके होठों पर आ गयी। आप धो आओ अपने आप। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने क्या कहा? साहब, बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप समाप्त करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा महाकुंभ के बारे में?

श्री सभापतिः नेता प्रतिपक्ष, आपका बोलने का मौका आये तब आप जवाब दे देना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, जो सदन का मैम्बर नहीं है, उसका नाम क्यों ले रहे हैं? जो आदमी यहां पर मौजूद नहीं है उसका नाम क्यों ले रहे हैं बारबार। खड़गेजी का नाम ले रहे हो, यह गलत है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह नियमों में ही नहीं है। आप नियमों से बाहर जा रहे हो। आप डाक्टर साहब के चक्कर में मत आओ, डाक्टर साहब तो मेरे साथ हैं। डाक्टर साहब की बातों में मत आओ, वे मेरे साथ हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि हम ...(व्यवधान)... विश्वास नहीं करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, ये मंत्री फिर खड़ा होकर +++ कर रहा है। इनको यह ही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं? ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो व्यक्ति इस सदन का मैम्बर नहीं है, उसका नाम नहीं ले सकते आप। बारबार क्यों लेते हो? आपके कोई प्राब्लम है क्या? प्राब्लम है? दिक्कत है? दिक्कत है क्या? सभापतिजी, इनको बैठाओ मंत्रियों को।

श्री सभापतिः आप उनको बोलने दो। वे बोल रहे हैं, उनका समय समाप्त हो रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, ये समझ ही नहीं रहे हैं। इन्होंने पांच साल जो पाप किये, इनको धुलाने ले जाने की जिम्मेदारी तो हमारी है न इसलिए हम ले जाना चाह रहे हैं। ये अब मान ही नहीं रहे हैं लेकिन हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्रीजी माननीय अमित शाहजी कुंभ गये, स्नान किया लेकिन ठंड लग गयी खड़गे साहब को। ठंड खड़गे साहब को लग गयी। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, हमको एतराज है कि जिस प्रकार से यह कहा जा रहा है कि कुंभ में पाप धोने जा रहे हैं, वह गलत है। लाखों हिंदुओं की श्रद्धा से आप खिलवाड़ कर रहे हो। लोग अपनी इच्छा से जाते हैं। लेकिन पाप धोने के लिए आप लोग पाप धोने जा रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह गलत बात है। माननीय सभापति महोदय, आप इस प्रकार से कैसे कह रहे हो? आप पाप धोने जाओ, जनता तो अपनी श्रद्धा से जा रही है, उनको जाने दीजिए। इस धर्म का मजाक मत बनाइये, कुंभ का मजाक मत बनाइये। लोग अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि वे पाप धोने जा रहे हैं। यह गलत बात है।

श्री सभापतिः प्लीज जूलीजी, नेता प्रतिपक्ष, आप विराजिये। ...(व्यवधान)... आप कंक्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, जिस कुंभ में हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग जा रहे हैं, उस कुंभ के लिए अशोभनीय बात कहना आपको अच्छा लगता है? आपके खड़गे साहब ने कही। महाकुंभ के विरोध में आपके राष्ट्रीय अध्यक्षजी बयान दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको।

ssy/rtm/05.02.2025/14.50/2h

उन्होंने क्या कहा बताऊं पढ़कर के? खड़गे जी ने कहा कि गंगा में डूबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, पेट को खाना नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती।

श्री सभापतिः जो असंसदीय बात हो उसको हटा दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सबसे पहले तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहें कि हिन्दुस्तान की जनता से माफी मांगे।

श्री सभापतिः प्लीज, आप अपनी बात को क्लोज कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अमित शाह जी कुंभ में गये, इनको ठंड लग गई। आपको पता है, आज मोदी जी गये हैं कुंभ में।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आसन को संबोधित कीजिये। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है। प्लीज, क्लोज कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): समय कहां, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं 15 मिनट बोलूंगा ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, मुझे एक बात यह श्रवण जी ने उस दिन भाषण में कहा, आपने भी सुना कि राजस्थान के नेता और अफसर साथ में दारू रोज पी रहे हैं। क्या शोभा दे रही है राजस्थान के लिए कि राजस्थान के अफसर और नेता रोज दारू पीते हैं? कांग्रेस के राज में, यही कहा था ना इन्होंने।

श्री सभापतिः प्लीज, अपनी बात समाप्त कीजिये। आपका समय हो गया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, अब इनका तो क्या है, राज्यपाल के अभिभाषण में एक साल की जो बातें कही गई हैं, जो हमने एक साल में काम किये हैं वह राज्यपाल के अभिभाषण में कही गई हैं। सभापति महोदय, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 4 साल में, हालांकि इनकी स्थिति तो और बिगड़ेगी। दिल्ली के रिजल्ट 8

तारीख को आयेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री बना देंगे आपको।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरे मंत्री बनने की चिंता मत करो। कांग्रेस के मंत्रियों की हालत तो इनके एमएलए ही बता रहे थे।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 22 मंत्री 50 हजार से हारे हैं। कांग्रेस के मंत्री 60 हजार से हारे हैं। यह श्रवण जी ही बता रहे थे। आपके लक्षण तो आपके एमएलए ही बता रहे थे और कोई नहीं बता रहा है।

श्री सभापतिः आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, इन्होंने एक नारा दिया, 5 साल में गहलोत साहब ने नारा दिया, 'काम किया है दिल से कांग्रेस सरकार फिर से' और जनता ने कहा इनकी करतूतें देखकर, 'भ्रष्टाचार किया है दिल से अब तुम घर बैठो आराम से।' कोई टेंशन मत पालो आप। सबको घर बैठा दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप इतने पुराने आदमी हो, पहले मंत्री रहे हो, मंत्री बनने के लिए इतना क्यूं कर रहे हो? ऐसे ही बनवा देंगे आपको। हम कह देंगे।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, दो-तीन लाइनें और हैं।

श्री सभापतिः उनका समय कटेगा आप चिंता मत करो। इन्हीं का समय कट रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कांग्रेस ने पिछले 50 वर्ष तक देश पर राज किया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपकी पालना नहीं हो रही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 50 साल तक कभी गरीबी हटाओ का नारा देते, लेकिन गरीबी हटायी इन्होंने? इस हिन्दुस्तान में गरीबी हटाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन 10 सालों में किया है। हमने गरीबों को 4 करोड़ आवास दिये। मोदी जी 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से 10 साल में बाहर लाये। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। डीबीटी, उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ फर्जी ...(व्यवधान)... नाम जो इन्होंने लिखे थे कांग्रेस ने, वह 10 करोड़ फर्जी नाम हटाये गये।

आप बता दो हरीश जी, अखबारों में पिछले सालों में कोई न्यूज नहीं आती थी, भ्रष्टाचार की खबरों से भरी रहती थी।

श्री सभापतिः आप क्लोज करो। आपका समय समाप्त हो गया। मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इन 10-11 साल के मोदी जी के राज में एक मंत्री पर किसी माई के लाल ने आरोप लगाया हो तो बता दो। सारा ईमानदारी से चल रहा है।

श्री सभापतिः श्री शान्ती धारीवाल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, 5 मिनट और बोलूंगा।

श्री सभापतिः हो गया, समय हो गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मेरा आधे घंटे का समय है।

श्री सभापतिः समय हो गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 2 मिनट लास्ट, एक मिनट। लास्ट, एक शेर बोल देता हूं। आपके लिए है। जनता के सपनों से छलावा करने वाली कांग्रेस अब सत्ता से हमेशा रहेगी आउट, सपने नहीं, हम हकीकत को बुनते हैं इसीलिए तो अब सब लोग मोदी और बीजेपी को चुनते हैं। मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। 31 जनवरी को माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो इस पवित्र सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा गया, मैंने बहुत ही गौर से उसका एक-एक शब्द पढ़ा। इतनी गौर से पढ़ने का मकसद यह था कि मैं उसमें कोई न कोई एक उपलब्धि देख लूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें एक भी उपलब्धि नहीं मिली। अगर एक भी उपलब्धि मिल जाती तो मैं यह मानकर चलता कि मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो चारों तरफ बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये गये हैं कि बजट की 55 परसेंट हमने पालना कर दी, 55 पर्सेंट काम कर दिया। आप मेहरबानी करो कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप मेहरबानी करके मेरी बात सुन लो। मैं यह मानकर चलता था कि अगर मुझे एक उपलब्धि भी मिल जाये तो मैं उसको 55 परसेंट के बराबर मान लूंगा। लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। उनका भाषण नीरस भी था और निर्जीव भी था।

सभापति महोदय, 4 लाख 59 हजार करोड़ रुपये का इस सरकार का बजट था। मैं अभिभाषण पर बोल रहा हूं। मुझे दुःख हुआ आपका भाषण सुनकर के कि आप जैसा सीनियर आदमी 90 प्रतिशत इस अभिभाषण पर तो नहीं बोला, पता नहीं आप कहां-कहां बोले। इससे मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मुझे इन्होंने अभिभाषण पर बोलने ही नहीं दिया। इनको जवाब देना जरूरी था। इनका इलाज करना जरूरी था।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, जो 4 लाख 59 हजार का बजट था, उसके बारे में मैंने सोचा कि क्या काम किया है? मैंने उसको पढ़ा तो हर चीज में यही बात लिखी हुई मिली कि स्वीकृति जारी कर दी है। स्वीकृति जारी कर दी है। लोगों ने विधान सभा में सवाल भी उठाये। उनके प्रश्न का जो उत्तर आया उसमें भी यही आया कि स्वीकृति जारी कर दी है। स्वीकृति जारी कर दी है। एक माननीय सदस्य ऐसे थे जिसके प्रश्न का जवाब यह आया कि स्वीकृति जारी कर दी है और निविदा जारी कर दी है। हाल यह है। पूरा एक साल प्रक्रिया में ही निकाल दिया।

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पूरा एक साल प्रक्रिया स्वीकृति में ही निकाल दिया। कोई काम नहीं हुआ। पूरे राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ। आपने अभिभाषण के पैरा 37 में लिखा कि एक साल में 59336 पदों की नियुक्ति दे दी।

मेरा एक मित्र, उसके 2 लड़के, अपने 5-6 साथियों के साथ कुंभ में गये। उन्होंने वहां राजस्थान के मंडप को भी देखा1 देखने के बाद जब वापस आये तो बाहर एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि 55 पर्सेंट बजट की पालना कर दी गई है और 59 हजार से भी ज्यादा सरकारी पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। उनके कदम वहीं ठिठक गये। वह आपस में चर्चा करने लगे। सब हताश हो गये कि हम भी राजस्थान में ही रहते हैं। कौनसी भर्तियां निकली? ना तो क्लर्क की निकली, ना ही एलडीसी की निकली, ना ही पुलिस कांस्टेबल की निकली, ना ही टीचर्स की निकली, ना ही फोर्थ क्लास की निकली और ना ही सफाई कर्मचारियों की निकली। सबसे बड़ी नियुक्तियां तो इनकी ही होती हैं। बाकी और क्या है? रेडियोग्राफर की नियुक्ति निकालनी हो तो 20-25 की निकाल दो, 30 की निकाल दो।

Spp/rtm/05.02.2025/15.00/2j

डॉक्टरों की निकाल दो तो 400-500 की निकाल दो। तो बड़ी-बड़ी नियुक्तियां तो यह हैं। वह सब ठिठक गये। वह इस नतीजे पर पहुंच गये कि यह सरकार महा असत्य सरकार है और यह बोर्ड जो लगाया गया है, जिसमें यह बताया गया है ..(व्यवधान)..

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): यह असत्य बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरियां दी हैं। अब आपको दिखाई नहीं देता, आप चश्मा बदलवाओ। 59 हजारे लोगों को नौकरियां दी हैं। आपने निकाली होंगी, लेकिन क्या हुआ? पेपर आउट, पेपर में लूट मचा दी आप लोगों ने। ...(व्यवधान)... बड़ा धन कमाया। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: माननीय दिलावर साहब, आप बोलें तब जवाब दे देना। ..(व्यवधान)..

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): राजस्थान को लूटकर खा गयी यह कांग्रेस।..(व्यवधान)..

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): और वह कोटा के नवयुवक इस नतीजे पर पहुंचे कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बोर्ड इसलिए लगाया है कि योगीजी को चिढ़ाया जावे कि आपसे बढ़िया काम तो मैं कर रहा हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैंने एक तारांकित सवाल लगाया 1526 नंबर का और उसमें पूछा था कि विभिन्न विभागों में कुल कितने पद रिक्त चल रहे हैं? इतनी सी बात थी कि विभिन्न विभागों में कुल कितने पद रिक्त चल रहे हैं? उन पदों को भर्ती करने के लिये क्या विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है? रिक्त पदों को भरने की सरकार की क्या योजना है और उन्हें कब तक भर दिया जाएगा? यह मेरा सवाल था। मुझे जवाब मिला कि आपका सवाल बहुत लम्बा है। अब इसमें क्या लम्बा था। यह तो सब बातें आप नहीं भी बोलते तो और लिखकर दे देते मुझे तो ही मान लेता मैं। क्यों नहीं दे रहे हो, छिपा क्यों रहे हो? आप क्यों असत्य पर असत्य प्रचारित कर रहे हो? ..(व्यवधान)..

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): हम पदों को भरेंगे। आपने एक भी पद नहीं भरा न इसलिए।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय बिराजें। ..(व्यवधान)..

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, हिम्मत होती तो सिलसिलेवार, तारीखवार, पदवार, विभागवार बताते कि फलां-फलां तारीख को विज्ञप्ति निकली थी और फलां-फलां तारीख को नियुक्ति दे दी गयी। ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने कैलेण्डर देखा है या नहीं देखा आपने?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय सदस्य, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप थोड़ा-सा पेशेंस भी रखो। मुख्य मंत्री युवा सम्बल योजना में 2 लाख बेरोजगारों को सहायता देने का वादा किया था। इसके लिये 866 करोड़ रुपये का आपने बजट में प्रावधान रखा। वित्त मंत्रीजी अभी चली गयीं। कितने को सहायता दी? अभिभाषण में आपने बताया कि 448 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। यह आधा ही हुआ है। यह उपलब्धि है आपकी? 866 करोड़ रुपये रख रहे हो और खर्चा 448 करोड़ रुपये का कर रहे हो। नोनेरा बांध की बात की आदरणीय कृपलानी साहब ने। निश्चित तौर पर ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, बिराजें। ..(व्यवधान)..

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): निश्चित तौर पर यह विचार तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे का था। लेकिन यह बता दो कि एक पैसा भी भारतीय जनता पार्टी की वह सरकार और इस सरकार ने नोनेरा बांध को बनाने में खर्च किया क्या? वह कम्पलीट हो चुका बांध। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: धारीवाल साहब, आसन की तरफ सम्बोधित करते हुए बोलें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, जहां पर बांध बन रहा है। देखिए, कब तो चालू हुआ उसका काम और कब खत्म हुआ? यह कांग्रेस के टाइम पर काम चालू हुआ और कांग्रेस के टाइम पर काम पूरा हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैंने पार्वती-काली सिंध और चम्बल, जिसको PKC Link project का नाम दिया है और ERCP का MOU मांगने के लिये एक प्रश्न लगाया कि मुझे MOU की कॉपी दे दो। उसको रिजेक्ट कर दिया और जवाब आया कि आपका प्रश्न बहुत लम्बा है। MOU तो सब-डाकुमेंट है। उस डाकुमेंट को यहां पर रख देते। आपको लिखित में ही तो देना था। MOU के लिये मैंने यह थोड़े ही कहा था कि पढ़कर सुनाना मुझे। अब MOU को खत्म हो गया और MOA आ गया। ..(व्यवधान).. माननीय सदस्य, आपके हाथ जोड़ता हूं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय दिलावर साहब। दिलावर साहब प्लीज, आप तो रूको न। ..(व्यवधान)..मैं बैठा हूं न यहां। आप शांति रखो न।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): MOA आ गया, कोई बात नहीं। PKCL और ERCP का जो MOA है, वही दिखा दो। अगर वही दिखा दोगे तो हमारी आंखों को तसल्ली हो जाएगी और हम यह समझ लेंगे कि राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात नहीं कर रही है। जो बात कह रही है, वह सच कह रही है। हम यही मान लेंगे। लेकिन जवाब क्या दिया कि आपका प्रश्न बहुत लम्बा है। लम्बा कहां से, यहां से कोटा तक था क्या? आपने रिजेक्ट कर दिया। आप बात करते हो यमुना की। कल हमारे प्रदेशाध्यक्षजी

ने एक भाषण दिया था। उसमें कहा था कि आपने चार महीने में उसकी डी पी आर बनाने के लिये कहा था, आज चौदह महीने तो हो गये। मैं कह रहा हूं कि चौदह महीने नहीं, दस साल हो जाएंगे, लेकिन हरियाणा कभी भी आपको डी पी आर बनाकर नहीं देगा। यह मेरे वर्ड्स हैं, इसको कोई भी पढ़ना चाहे तो पढ़ लेवे, आज शामिल हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक कल्याणकारी सरकार का दायित्व क्या होता है? माननीय सभापति महोदय, सरकार कल्याणकारी काम करने के लिये चुनी जाती है। उसका दायित्व होता है कि वह गरीबों पर ध्यान दे। सामाजिक कल्याण पर ध्यान दे, वेलफेयर पर ध्यान दे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दे। सुनियोजित विकास पर ध्यान दे और कानून-व्यवस्था पर ध्यान दे। लेकिन इस सरकार का किसी पर ध्यान नहीं है। अगर इस सरकार ध्यान वाकई किसी पर है तो सिर्फ एक बात पर है कि कांग्रेस के द्वारा जो जनहित की योजनाएं चलायी गयीं उनके नाम बदल दो। ..(व्यवधान).. मदनजी, बैठ जाओ, आपके हाथ जोड़ लूं। ..(व्यवधान).. आप बैठ जाओ।

श्री सभापतिः दिलावर साहब, प्लीज बैठें। ..(व्यवधान)..

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, क्या पता, क्या कारण है? ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, दिलावर साहब की जगह मैं खड़ा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापतिः बिराजो-बिराजो। ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं खड़ा हो जाऊंगा इनकी जगह।

श्री सभापतिः माननीय बिराजिये। ..(व्यवधान)..

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या पता क्या कारण है, माननीय सभापति महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी के नाम पर इतना एतराज क्यों है? वजह क्या है? क्यों इनका दिल धड़कता है उनके नामों पर? 30 से भी ज्यादा योजनाओं का नाम बदल दिया गया है और कल एक और योजना का नाम बदल दिया। कुलपति के बजाय अब कुलगुरु होगा। अब कुलपति और कुलगुरु में क्या फर्क हो गया। यह जितने भी इनके बैठे हुए हैं न कुलगुरु, कुलगुरु जो भजनलाल जी हैं महाराज। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः प्लीज दिलावर साहब। ..(व्यवधान).. आपका नंबर आये तब जवाब दे देना न। प्लीज बैठिये। ..(व्यवधान).. प्लीज मंत्री महोदय बिराजें। ..(व्यवधान)..

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, 87 लाख 96 हजार व्यक्तियों को मुख्य मंत्री पेंशन सम्मान योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था और 13 हजार करोड़ रुपये उसके लिये रखे गये थे। दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं आज वृद्धावस्था सम्मान पेंशन लेने वाले।

jyg/rtm/05.02.25/15.10/2k

विधवा पेंशन लेने वाले, विकलांग पेंशन लेने वाले और चार-चार, पांच-पांच महीने हो गये, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है उनकी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): धारीवाल साहब, यह बिलकुल असत्य है। दिसम्बर तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सबके खाते में डाल दी गयी है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बाद में जवाब दे देना, दे देना जवाब बाद में।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): दिसम्बर तक का किसी का भुगतान बकाया नहीं है, आप इस प्रकार की असत्य बात नहीं करें। आप सीनियर आदमी हैं। आप सीनियर नेता हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों बार-बार असत्य बोल रहे हो? आपका जब बाद नम्बर आये तो जवाब दे देना। ...(व्यवधान)... पूरे-पूरे पांच माह तक आप पेंशन नहीं दे रहे हो, यह क्या बात हुई?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): दिसम्बर तक की पेंशन खाते में जा चुकी है। पालनहार की जा चुकी है, सब जा चुकी है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कब जा चुकी है बता दीजिये। आपका मौका आये तो बता देना। आप भी पूरा लिये बैठे हो।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): चार-चार महीने पैंडिंग रहना गलत बात है। ऐसे सीनियर व्यक्ति को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पेंशन कब डाली है, सबको पता है। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इस प्रकार की गलत बात नहीं कहनी चाहिए। उन लोगों की बकाया है जिनकी बैंक डिटेल पूरी नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपका नम्बर आये तब बोलना। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): यह मुझे लिखकर भेज देना +++।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सारी पेंशन जा चुकी है। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 1 लाख 30 हजार सहरिया, खैरवा और केथोड़ी जाति के व्यक्तियों के लिये बजट में प्रावधान किया गया कि उनको दाल, तेल और देशी घी का वितरण किया जायेगा। एक भी घर बता दो मुझे इन जातियों का, एक भी घर जहां पर ये सामान पहुंचा हो। यह बजट का प्रावधान है। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा की बात करूं तो बजट में यह प्रावधान किया गया था ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप पता करवा लीजिये, उनके अंगूठे हैं। आप असत्य बोल रहे हैं, उनके अंगूठे हैं। ऐसे कैसे बोल रहे हो फर्जी है, सबको

मिल रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो हर आदमी कैसे खड़ा हो जाता है?

श्री सभापति: धारीवाल साहब आप आसन को सम्बोधित करते हुए बोलें। ...(व्यवधान)...आप विराजिये। आदरणीय मंत्री महोदय, खराड़ी साहब।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, गंगानगर मेडिकल कॉलेज को और कोटा मेडिकल कॉलेज को बजट में यह प्रावधान किया गया था कि लीनियर एक्सीलेटर मशीन उपलब्ध करा दी जायेगी, नहीं हुआ, साल भर हो गया।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की बात करूं, तो 2024-25 के बजट में यह बताया गया था कि 50 नये प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। था न सही? उसके बजाय ...(व्यवधान)... विद्वान शिक्षा मंत्री, ...(व्यवधान)... अति विद्वान, इन्होंने 450 स्कूल ही बंद कर दिये। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह बिलकुल असत्य बयान है। एक भी विद्यालय बंद नहीं किया है। एक भी विद्यालय बंद नहीं किया है। ...(व्यवधान)... एक भी विद्यालय बंद नहीं किया है। जहां बच्चे कम थे उनके पास के विद्यालय वालों को दिये हैं। कोई भी विद्यालय बंद नहीं किया है। ये असत्य बयान कर रहे हैं। अपनी गलती को सुधारें। धारीवालजी, अपनी गलती को सुधारो, एक भी बंद नहीं किया है। ...(व्यवधान).. जो खाली पडा था स्कूल, बच्चे नहीं थे, जिसमें छात्र नहीं थे, उनकी बिल्डिंग थी उसको हमने पास के विद्यालय में बदला है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप इसको अलग से बता देना। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसे होता नहीं है, अभिभाषण पर कोई सदस्य अपनी बात रखता है, यूं तो सारे मंत्री खड़े होकर जवाब दे देंगे। या तो मुख्य मंत्री जवाब दें ...(व्यवधान)... या तो मुख्य मंत्री जवाब देगा या संसदीय कार्य मंत्री जवाब देगा।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, जब श्रीचन्दजी बोल रहे थे तब क्या चल रहा था?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): श्रीचन्दजी और हमारी आपस की बात है। मंत्री खड़े होकर जवाब देंगे तो व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)... यह व्यवस्था का प्रश्न है, आप क्यों इस विधान सभा को तमाशा बना रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिये। ...(व्यवधान)... आप इतने सीनियर माननीय सदस्य हैं। ...(व्यवधान)... आप विराजिये प्लीज। आपके इतने सीनियर माननीय सदस्य, मंत्री रहे हुए हैं, धारीवाल साहब, वो सक्षम हैं, वो जवाब दे रहे हैं। प्लीज, गहलोत साहब। आप विराजिये। आप दो मिनट विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है,

आप व्यवस्था दीजिये। आप व्यवस्था दीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप रुको तो सही। आप विराजिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपने कहा कि चार महीने की पेंशन बकाया है। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, धारीवालजी ने कहा कि चार महीने की पेंशन बकाया है। इस प्रकार का गलत कथन इस हाउस में नहीं दिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: गहलोत साहब, विराजिये। मैं दोनों ही दलों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई सीनियर लीडर बोल रहा है तो कोई माननीय सदस्य इनको इंटरफेयर न करे। आपकी बारी आये तो जवाब दे देना। वो बोल रहे थे तो आप जवाब दे दो। धारीवाल साहब बोल रहे हैं तो आप जवाब दे दो। बीच में नहीं बोलें। प्लीज।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर जिन शर्तों को भ्रष्टाचारी बताया था कि ये शर्तें इसलिए लगायी गयी हैं कि टेंडर में भ्रष्टाचार होता है। सत्ता में आकर उन्हीं शर्तों पर काम कर रहे हो? ...(व्यवधान)...प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क बांटने वाली किताबों के कागज की खरीद में बड़ा घालमेल चल रहा है। राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के कागज खरीद का जो टेंडर निकाला है उसकी शर्तें चुनिंदा लोगों को ही मिलें, ऐसी बनायी गयी हैं। मेरा आरोप है कि तीन-चार मिलों को, तीन-चार मिलों को लाभ पहुंचाने के लिए यह किया गया है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): यह गलत बात है। ...(व्यवधान)... इसकी जांच करा लो, ईमानदारी से काम किया है। ये असत्य बयान कर रहे हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो याद आ रहा है धारीवालजी को। ...(व्यवधान)...भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार ही याद आता है धारीवालजी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): भजनलालजी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हर विभाग में ईमानदारी से काम हो रहा है। लेकिन आप तो भ्रष्टाचारी हो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्रीजी विराजिये। ...(व्यवधान)...फिर वो की वो बात है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, बजट में 157 स्टेट हाईवे, 12 बाइपास सड़कें, 31 रेलवे ओवरब्रिज, अण्डरब्रिज, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और 11 हाई लेवल ब्रिज बनाने की घोषणा की। अभिभाषण में एक का भी उल्लेख नहीं है, एक का भी उल्लेख नहीं है, साल भर हो गया। जयपुर में हाइटेक सिटी बनाने की बात की, जमीन ही चिह्नित नहीं की +++। बताइये। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): +++ क्या होता है? ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर):जमीन ही चिह्नित नहीं की, ...(व्यवधान)...लैंड पूलिंग

का क्या हुआ?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः यह कुछ शब्द आया है उसको डिलिट कर दीजिये। '+++' शब्द को डिलिट कीजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वो अंकित हो गया है उसको हटा दो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पटेल साहब, ये सब काम होंगे भी क्यूं? क्योंकि दिल्ली दरबार में हाज़िरी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। काम कौन करेगा? ...(व्यवधान)...1000 इलेक्ट्रिक बसें चलायी जायेंगी। एक भी इलेक्ट्रिक बस राजस्थान की किसी सड़क पर चलती हुई दिखी क्या आपको? 1650 कर्मचारी रोडवेज में भर्ती किये जायेंगे। और भर्ती कितने की निकली, 500 की। विद्युत मंत्रीजी बैठे हुए हैं, आप जब छोड़कर गये थे।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आप अपने एमएलए से पूछो, मैं बस से आया हूं रोडवेज की से। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): विद्युत मंत्रीजी, बैठे हुए हैं, सुन लो। जब आप लोग छोड़कर गये थे। विद्युत मंत्रीजी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य, आप विद्युत मंत्रीजी को सीधा सम्बोधित नहीं कर सकते।

श्री सभापतिः माननीय धारीवाल साहब, आसन को सम्बोधित करते हुए अपनी बात रखें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनको बताओ कि किनको सम्बोधित करना है। मंत्रीजी को सम्बोधित करना है क्या?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप सीनियर सदस्य हो, आसन को सम्बोधित करते हुए आप अपनी बात रखें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): उस वक्त कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 21077 मेगावाट थी जिसको हमने 3707 मेगावाट की वृद्धि करके 24783 मेगावाट किया।

MLS/RTM/05.02.2025/15:20/2l

आपने कहा कि साहब, आपने एक मेगावाट भी नहीं बनाया है। हमने सारे तंत्र को सुधारकर इतनी बड़ाई की है। ये आंकड़े मेरे नहीं, आपकी आर्थिक सर्वेक्षण की किताब के हैं। उसमें देख लें आप कि हमारे वक्त में कितनी बढ़ गयी और आपके वक्त में क्या थी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): प्रोडक्शन कैपेसिटी 26325 मेगावाट आप बता रहे हैं। अगर आपकी बात सही है तो मैं यह मान लूं कि 1542 मेगावाट बढ़ गया होगा, लेकिन राज्यपाल महोदय के भाषण में आपने उनसे मिथ्या बुलवाया कि उत्पादन क्षमता में 2180

मेगावाट की वृद्धि की है।

श्री सभापति: अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 765 केवीए के 6, 400 केवीए के 2, 220 केवीए के 12, 132 केवीए के 40 जीएसएस स्थापित करने की घोषणा की गयी बजट में। कितने बन गये? एक का भी अभिभाषण में जिक्र नहीं है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। बहुत गम्भीर बात है यह। सुधारने के लिए सुझाव है। जो रूफटॉप सोलर लगाता है, उसका जब एक्सेस आ जाता है तो एक्सेस का आप क्या करते हैं, उसका पेमेंट कर देते हैं। आप पेमेंट क्यों करते हैं? उसे उसके बिल में शामिल करें न। तब जाकर उसे फायदा होगा। आप तो पेमेंट करते हैं 2 रुपये 40 पैसे का और बिल आता है +++ 7-7, 8-8 रुपये यूनिट का। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप उसे करें, ताकि आपके रूफटॉप सोलर को लगाने में विस्तार होगा। एक बात और बता दूं आपको, आपका सोलर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है, वह 2222 करोड़ रुपये का है। उसकी शर्तें बदल दीं। शर्तें बदलकर किस कम्पनी को देना चाहते हैं? किस कम्पनी को देना चाहते हैं? ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, अब मैं कानून-व्यवस्था की बात करूं, सिर्फ इतना-सा कहूंगा कि प्रदेश में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। यह प्रदेश अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। इसमें कई लम्बे-चौड़े किस्से हैं। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं बोल नहीं पाऊंगा इतना। पोषाहार की बात करता हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, समाप्त कीजिये अपनी बात।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैंने एक बार दो आंगनबाड़ियों को विजिट किया कि उनके क्या हाल हैं। पोषाहार में सिर्फ 5 से 10 परसेंट तक विटामिन और 26 परसेंट ही कैल्शियम मिलता है। कुपोषण दूर करने के लिए राज्य सरकार हर साल 1 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सरकार पोषाहार बांटने पर खर्च कर रही है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर घटिया फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड पूरक पोषाहार सप्लाई हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केन्द्र पर जो नया पोषाहार पैकेट सप्लाई किया जा रहा है, वह घटिया किस्म का है।

श्री सभापति: अपनी बात समाप्त कीजिये। श्री छोटूसिंह जी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आंगनबाड़ी में बच्चे उसे खाना पसन्द नहीं करते। उसमें जो दलिया है, वह मवेशियों को दिलवाया जा रहा है।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)... आदरणीय आप बोल सकते हैं, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, लेकिन आपके बोलने की आदत, हम आपसे बखान सुनना चाहते हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, इसे भजन लाल मंत्री मण्डल की बजाय पलटूराम जी का मंत्री मण्डल कहना चाहिये।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आदरणीय, अभिभाषण पर कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे, पक्ष और विपक्ष ने भी चर्चा की। सभी के विचार स्वागत योग्य हैं। आदरणीय, विपक्ष ने अपने विचार में आरोप भी लगाये और प्रत्यारोप भी लगाये। अच्छी बात है। आरोप लगाना आपका धर्म है, लेकिन आरोपों के साथ-साथ कुछ शाबाशी भी देते। कहते कि यह अच्छा काम हुआ है। मैं यह कह सकता हूं कि हमारी सरकार आते ही जो बजट आपको मिला है, ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया। मेरा भी तीसरी बार यहां आने का अवसर हुआ है।

आदरणीय, हम सबकी सोच, अपन चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अन्तिम छोर पर बैठे हुए मेरे भाई का कल्याण हो, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो उसकी सोच होती है कि मैं कॉम्पीटिशन में आगे आऊं। अपनी सबकी सोच है कि अपन आमजन का दिल कैसे जीतें, उन्हें लोक कल्याणकारी योजनाओं से कैसे जोड़ें। यह हर एक की भावना है। आपकी भी होनी चाहिये, लेकिन विगत सरकार में आप थे, हो सकता है कि आपमें यह सोच नहीं आयी होगी, तब हम यहां आ गये और आप वहां पधार गये।

माननीय, उस अन्तिम व्यक्ति के मतदान द्वारा ही आज हम इस पवित्र सदन के अन्दर विराजे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास हम पर किया है। हम सबका दायित्व बनता है कि उनके विश्वास पर हम खरे उतरकर उनकी हर योजना का काम, उनकी हर सोच को पूरा कर सकें। माननीय सभापति महोदय, देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में देश ने अद्भुत प्रगति की है। हाल ही में, 2025-26 का केन्द्रीय बजट आया। यह बजट जन केन्द्रित और विकासोन्मुखी है।

मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को उनके 8वें बजट के लिए बधाई देता हूं। बजट देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। आदरणीय, यह बजट राजस्थान समेत देश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। आयकर सुधार में मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आयकर छूट 6 लाख से 12 लाख देना एक स्वागत योग्य कदम है। आम मध्यम व्यापारी, मध्यम वर्ग के आदमी को बहुत बड़ा बैनिफिट मिला है। यह बजट न केवल परिवार को राहत देगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा।

आदरणीय, हम सबकी सोच है, हमारा मूल मंत्र है कि हमारा देश प्रथम हो। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अपार सम्भावनाएं हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छे लक्ष्य तक पहुंचे, ऐसी हम सबकी सोच है। इसे साकार करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की। उनकी दूरदृष्टि सोच का सफल उदाहरण आया है। आदरणीय, साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मजबूत बुनियाद रखी है। माननीय सभापति महोदय,

प्रदेश के पूर्व माननीय मुख्य मंत्री का भी एक लक्ष्य था और सोच थी, उनके नेतृत्व में तत्कालीन राज्य सरकार ने पहली बार एक योजना के माध्यम से राजस्थान को विकसित बनाने का एक महत्त्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि विगत सरकार के समय राजनीतिक लाभ के कारण इस परियोजना को अटकाया जाता रहा। यह क्यों अटकाया गया, यह विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को सोचना है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में सदियों से जल संचयन और जल संरक्षण की परम्परा रही है। विशेषकर, हमारा पश्चिमी राजस्थान, जिसके अन्तिम छोर जिला जैसलमेर में मैं रहता हूं, वहां जल संचय का महत्त्व और बेहतर तरीके से समझा जाता है। वहां पानी मांगा जाता था तो घी का लोटा दिया जाता था। पानी इतना अमूल्य था। आदरणीय, उस सोच के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह प्रयास किया है कि गांवों और ढाणी में बसे लोगों की पेयजल व्यवस्था सुलभ हो।

mkd/rtm/05.02.2025/15:30/2m

जल जीवन मिशन के रूप में विगत सरकार को हर घर नल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला था। दुर्भाग्य हो, सरकार ने इसे शुरू करने का अपना कीमत समय जाया किया। आपके पास बहुत बड़ा समय था, बहुत बड़ी सोच थी, इस जल जीवन मिशन को ढाणी और गांव तक पहुंचाये, कार्य शुरू किया तो आदरणीय बहुत सारे घोटाले हुए। आदरणीय, इस प्रदेश का मैसेज देश में बदनामी के लिए हुआ। यह आप हम और आमजन को पता हो गया है।

माननीय, अब हमारी सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी है। आदरणीय, जैसलमेर एक अलग जिला है और मानव पेयजल के लिए इस जल जीवन में 55 लीटर दिया है। आदरणीय, हम पशुपालक हैं, हम चाहते हैं कि हम भी पीयें और हमारे पशु भी प्यासे नहीं रहें, क्योंकि योजना के हिसाब से 55 लीटर पानी मिलेगा, उसमें पशुधन को भी जोड़ा जाये,ताकि हमारा पशु भी वहां प्यासा नहीं रहे।

माननीय सभापति महोदय, गत सरकार के समय प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में अंधेरे में डूबा था। कोयले की कमी, ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारी सरकार ने सेवा का दायित्व सम्भालने के साथ केन्द्र सरकार के माननीय नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार से सामंजस्य बिठाकर कोयला लेकर थर्मल इकाइयों को शुरू करवाया, यह आपको और हम सबको पता है।

माननीय सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में जैसलमेर को, विशेषकर सोलर में आपने चुना है। हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय, निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पूर्व में बहुत सारी सेटलमेंट की भूलें हैं। हमारे पूर्वजों ने कई वृक्ष लगाये थे, चाहे वह खेजड़ी हो, चाहे वह जाल हो, चाहे बोरड़ी हो और उसका हमने नाम दिया था मुंह मुखी, यह हमारी ओरण है, इन-इन देवताओं के नाम होगी और गांव के अन्दर इस प्रकार के आघोर थे, चाहे तालाब हो, चाहे पशु विचरण के लिए जगह हो, लेकिन भूल

इतनी रही आदरणीय कि उसको सेटलमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा पाये। चाहे उसको शिक्षा की कमी समझो, चाहे हमारी खुद की भूल समझो तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोलर आयेगा। राजस्थान में जैसलमेर बहुत बड़ा जिला है, आप लगाइयेगा, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम ऐसी जगह देना चाहते हैं, जहां इस प्रकार का ओरण विद्यमान नहीं हो, बगैर ओरण विद्यमान के हमारे पास जमीन है। आपके पास उसका रिकॉर्ड है।

आदरणीय, ओरण, खेतों के आघोर, हमारे एनिकट्स के आघोर, हमारे तालाब के आघोर और हमारी ओरण जो आज विद्यमान है, उसको छोड़कर आगे जगह दी जाये, जिससे ऊर्जा पैदा हो और जैसलमेर को भी मिले और मेरे पूरे राजस्थान को मिले, ऐसी हमारी कामनाएं हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, प्रदेश के मुखिया का भी विजन है कि हमारा प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बने। यह लक्ष्य, जो आपने सोचा है, वह लक्ष्य आपका पूरा हो। आने वाले वक्त में हमने 10 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन भी दिये, 5 लाख 6 हजार घरेलू कनेक्शन भी दिये, क्योंकि मेरे क्षेत्र बहुत लम्बा है, छितराई आबादी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और माननीय देश के मुखिया आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को, जिन्होंने इस सोच के साथ देखा कि छितराई आबादी के गांवों तक लाइट कैसे पहुंच सकें। आज हम खुशहाल हैं, हर घर उजाला है और जब सीमान्त पर हम खड़े रहते हैं तो आम जगह पर यह लाइट लगती है तो कहीं यह शहर तो नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बारम्बार धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूं, अभी आदरणीय पूर्व सीनियर सदस्य ने कहा था कि एक भी ऐसा जीएसएस बताओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे यहां दो जीएसएस का काम सुचारू चालू हो गया है।

श्री सभापतिः आदरणीय, समाप्त कीजिये।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): दूसरे, जीएसएस भी आने वाले समय में होंगे। आदरणीय सभापति जी, दो मिनट और दीजिये। मैं थोड़ा-सा और बताऊं, यह मेरी विशेष व्यथा है। आदरणीय, हम चाहते हैं, अभी बातें हुईं कि गत सरकार के समय पेपर लीक, नकलबाजी, हमने उस पर अंकुश लगाया।

श्री सभापतिः क्लोज कीजिये।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आदरणीय, इस चीज का सोच किया, आज एक भी ऐसा कोई नकल गिरोह नहीं पकड़ा गया और कोई परीक्षा स्थगित नहीं हुई।

श्री सभापतिः डॉ. शिखा मील बराला। (अनुपस्थित)

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आदरणीय, थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। आपकी और हमारी सीट बिलकुल नजदीक है। इसलिए थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान रखो।

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से आज सरकार की प्रोग्रेस हो

रही है, सरकार के जो काम हो रहे हैं, उसमें विशेषकर सड़क निधि के लिए निवेदन कर रहा हूं। आदरणीय, आपने सड़कें हमें दीं और पूर्ववर्ती बजट में सड़क की घोषणा हुई, उसका कार्य भी हुआ, लेकिन एक निवेदन आदरणीय और कर सकता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा कि जैसलमेर छितराई आबादी का क्षेत्र है, कोई भी नजदीक का गांव, चाहे दूसरा जिला हो या कोई नजदीक का गांव हो, वह यदि पांच किलोमीटर लाइन ले जायेगा तो पांच गांव जुड़ जाएंगे और पांच किलोमीटर जैसलमेर जिले में जायेगा तो उनका वन फोर्थ भी वहां तक पहुंच पायेगा।

मैं चाहता हूं कि जैसलमेर के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाये, दूरी के हिसाब से, क्योंकि जैसलमेर आपका कमाऊ जिला है, चाहे वह लाइट के हिसाब से हो, चाहे आपके खनिज के हिसाब से हो, चाहे आपके उद्योग के हिसाब से हो, मेरा निवेदन है जैसलमेर के लिए विशेष पैकेज रखा जाये। आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हरिमोहन जी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आदरणीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलेने का अवसर दिया, उसके लिए आभार। शुरुआत तो मैं करना चाहता था राज्यपाल के अभिभाषण से, लेकिन एक माननीय सदस्य ने गंगा स्नान का प्रश्न पैदा कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि वे अपनी पूरी कैबिनेट को ले जाकर त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं और पवित्र होना चाहते हैं।

मुझे भरोसा है, अच्छा तो यह होता कि सबको साथ लेकर जाते। मैं इस बात पर भी भरोसा नहीं करता कि वहां जाने से कोई पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पुण्य अर्जित करने के लिए जो कैबिनेट वहां जा रही है, मेहरबानी करके वहां से वापस आने पर पुण्य के ढंग से ही वे काम करें और अपने पापों का पश्चाताप वहां करके आएं तो मैं स्वागत करूंगा, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय का भी मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि डॉ. सम्पूर्णानन्द जी के बाद ये पहले राज्यपाल हैं राजस्थान में, जिन्होंने अपने सिर पर गांधी टोपी रखकर के अपना प्रवचन दिया है, इसके लिए भी मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के मन मस्तिष्क में गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने का मन हो या नहीं हो, लेकिन राज्यपाल ने गांधी टोपी पहनकर जो अभिभाषण दिया, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात राज्यपाल के अभिभाषण में, आप कह रहे थे ना अम्बेडकर के समर्थक हैं, संविधान के समर्थक हैं, लेकिन एक भी शब्द अनुसूचित जाति के लिए माननीय आपके अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने न बोला, यह राजस्थान की सरकार की मनोवृत्ति, मंशा को दर्शाता है, कम से कम एक पैरा तो होना ही चाहिए था ना अनुसूचित जाति के लिए, एक पैरा उनका उसमें नहीं था।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था की बात, कानून और व्यवस्था के मामले में आज ही आपने देखा होगा कि राजस्थान पत्रिका में ही लिखा है कि इस वर्ष में छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ है।

Bhs/Rtm/05.02.25/15.40/2n

जो व्यभिचार हुआ है उसमें राजस्थान नम्बर 1 पर है और लगातार एक सप्ताह में 600 लोग यहां से गायब होते हैं उसमें 76 प्रतिशत महिलाएं गायब होती हैं इस राजस्थान में। यह राजस्थान के कानून-व्यवस्था की हालत है। यही नहीं पूर्व में भी जो राजस्थान सरकार का मुझे जवाब दिया गया था उस जवाब में भी राजस्थान में अपराधों में विशेष रूप से महिलाओं के अपराधों में वृद्धि हुई है। यह रिकार्ड की बात है और आप बलात्कार में भी चालान पेश करने की स्थिति में इसलिये नहीं हैं कि वहां पर आपके विभाग को आपके पुलिस स्टेशन को वह जो एफ.एस.एल. की रिपोर्ट है वह गत 6 महीने में 1600 कैसेज ऐसे हैं जिनमें उस रिपोर्ट के अभाव में चालान पेश नहीं हो पा रहे हैं। यह राजस्थान में कानून-व्यवस्था के हालात हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं।

सभापति महोदय, बेरोजगारी का जो मामला है, उसमें माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यहां बैठे हैं एक भी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई आपने बड़ी दबंगता के साथ कहा था और हमने भी आपकी तारीफ की थी कि मुख्य मंत्री जी बड़ा मजबूत स्वायत्त शासन मंत्री आपने बनाया है। यह रिकार्ड पर है जो मैं बोला था उस समय लेकिन यह क्या हो गया? एक भी आदमी की नियुक्ति नहीं की। आपने यह काम जरूर किया कि आप नगरपरिषद और नगरपालिकाओं के जो कांग्रेस के बैठे हुए सभापति थे और जो अध्यक्ष थे उनको हटा दिया, यह काम आपने जरूर किया और यह भी ध्यान रखा कि वहां पर उपाध्यक्ष या उप सभापति अगर उसी वर्ग का है तो फर्जी जांच करा करके दूसरे- तीसरे दिन उसको हटा करके अपना आदमी नियुक्त कर दिया शायद इसलिये अब चुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपने तो ठान ली कि जितने भी कांग्रेस के बोर्ड में बैठे हैं उनको किसी न किसी बात पर हटा लो और हटाने के बाद कानूनी रास्ते से अपने आदमियों को बैठा लो यह लोकतंत्र के लिये आप अच्छी बात नहीं कर रहे हो।

सभापति महोदय, राजस्थान में एक काम आप बता दो जैसे बूंदी नगर परिषद में, आपने बूंदी नगर परिषद में दिये हुए स्वीकृत बजट में से 10 करोड़ रुपये की सड़कें वहां से वापस ले ली, नयी देना तो दूर की बात है। 12 कर्मचारी वहां से हटा दिये और दो कर्मचारी वहां पर भेज दिये। आपका वहां का जो कमिश्नर है वह डिफंक्ट है। एक पट्टा भी वहां से जारी नहीं हुआ। एक परमीशन वहां से जारी नहीं हुई। एक लेंड कन्वर्जन का मामला वहां से जारी नहीं हुआ। आप जैसे मजबूत स्वायत्त शासन मंत्री हैं और नगर परिषद की और नगर पालिकाओं की पूरे राजस्थान में जो दुर्दशा है वह चिन्ताजनक है।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आपने राजीव गांधी युवा मित्रों को

हटाया। आपसे मेरा निवेदन है कि उन राजीव गांधी युवा मित्रों को क्या कसूर था और आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आपने इसी प्रकार से यूटीबी के जो कार्यकर्ता थे जो उस समय पर लगाये गये थे उस समय पर उन लोगों को आपने अभी तत्काल हटा दिया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज ही यह कहा है कि स्वीकृत पदों के अगेंस्ट में कोई अस्थायी कर्मचारी आपने लगाये हैं तो आप उनको नियमित कर सकते हैं और आप उसको लगा सकते हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत देता है कि जो वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन्होंने उस समय जो काम किया जब उस समय लाश के कोई आदमी हाथ नहीं लगा रहे थे, जब उस मुर्दे को देखने नहीं जा रहे थे, जब परिजन वहां से हट गये थे, उन लोगों को जो 5-6 साल से नौकरी कर रहे हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और निवेदन है कि कृपा करके उन लोगों को वापस नौकरी में लगायें और नौकरी में लगा करके उनको नियुक्ति देने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी को आप ही लोग फैल करना चाहते हैं। यह मेरा आरोप है आप पर। आप अन्तर्विरोधों में हैं। डॉ. किरोड़ी लाल जी जिस प्रकार की जो बात कर रहे हैं जो हालात पैदा कर रहे हैं, पूरी सरकार और पूरा नेतृत्व मौन है। क्या इससे मुख्य मंत्री जी को बल मिल रहा है? क्या उनकी छाप ठोक रहे हैं वो? आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री जी। आपको निर्णय लेना चाहिये। आपके विधायकों का आप पर विश्वास नहीं है और तभी तो कोई मीट की दुकान पर जाकर लाइसेंस मांगता है कोई मेडिकल की दुकान पर जाकर एक्सायरी डेट की चीज देखता है कोई कहां जाकर के क्या करता है। अपने मुख्य मंत्री जी पर विश्वास करो भाई, उनकी सरकार है, वो सब कर देंगे। आप खुद ही अधिकारी बन रहे हो और मुख्य मंत्री जी को बदनाम करने में लगे हो।

सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपने भाषण पर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिये नहीं तो यह महसूस होता है कि माननीय भजन लाल जी जैसे सज्जन आदमी की कैबिनेट में कैसे-कैसे मंत्री हैं जिनको न बोलना आता है, न शिष्ट भाषा है, न विचार करना आता है और न बल देना आता है और लगातार एक उलटे-सीधे अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे मुख्य मंत्री जी की प्रतिष्ठा गिरती है तो मेरा निवेदन है अभी आपने देखा होगा, पहले आरोप लगाये थे...। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं करें। अगर आपको लगता है कि मंत्री की भाषा गलत है तो आप आइये, सदन में लिख कर दीजिये मंत्री जी जवाब देंगे। ऐसे व्यक्तिगत कमेंट्स आपको अलाऊ नहीं करना चाहिये।

श्री सभापति: प्लीज-प्लीज। सीनियर सदस्य हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप विराज जाइये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपकी उम्र का ख्याल करते हुए आप थोड़ा ख्याल रखें क्या कह रहे हैं आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप विराज जाइये। स्थानान्तरण की बात आई। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ...(व्यवधान)... या तो निकलवायें या मंत्री जी को जवाब का अवसर दें। व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी मना है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप बैठ जाइये। स्थानान्तरण की बात आई। आज आपने देखा। आपने कहा था न कि व्यापार होता है, पैसे लेते हैं, पूर्ववर्ती सरकार में ऐसा हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सीनियर सदस्य हो, आसन को सम्बोधित करें, उधर ध्यान न दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नजर सामने आती है न, साहब।

श्री सभापति: इधर घूम जाइये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप एक बात बताइये आपने जो भी ट्रांसफर किये अभी, कितनी अपीलें ट्रिब्युनल में पेंडिंग हैं? आप बताइये, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट ने पहली बार एक हजार ट्रांसफर जो पंचायत राज मंत्री ने किये उस पर स्टे दिया यह नया रिकार्ड बना है। एक हजार ट्रांसफर जो किये हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, न्यायालय में पारित आदेश के सम्बन्ध में विवेचना करना पूर्ण रूप से गलत है। कैसे आदेश किया है, क्यों आदेश किया है वह न्यायालय का विषय है। यह न्यायालय का विषय है इसकी विवेचना यहां नहीं हो सकती। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): न्यायालय में पारित आदेश की कोई विवेचना यहां नहीं हो सकती।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): इनको रोको न आप। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... मेरा अधिकार है बोलने का। नहीं है, आपका अधिकार। आपका अधिकार ये बोलेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप धमका क्यों रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज। माननीय सदस्य, आपके सीनियर लीडर बोल रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, मेरा सबमिशन है न्यायालय के आदेश की कोई विवेचना यहां नहीं हो सकती। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): संसदीय कार्य मंत्री अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेंगे?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जिस प्रकार से खड़े होकर धमका रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अगर संसदीय कार्य मंत्री जी व्यवस्था नहीं देंगे ...(व्यवधान)... माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय।

श्री सभापतिः प्लीज, विराजिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अगर किसी व्यवस्था पर संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे? इस सदन संसदीय कार्य मंत्री जी अगर अपनी बात नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां तो वो बोल रहे हैं तो आप बैठो न तो फिर आप क्यों खड़े हो रहे हो?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): स्प्रिंग क्यों लगी है इनके पीछे से। ये स्प्रिंग निकालो न इनकी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपके संसदीय कार्य मंत्री हैं न।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): निकालिये न स्प्रिंग उनकी एक बार।

श्री सभापतिः प्लीज। प्लीज, गहलोत जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यहां लड़ने के लिए आते हैं या काम करने के लिए आते हैं? यहां जनता की बात करने के लिए आते हैं कि लड़ने के लिए आते हैं? ...(व्यवधान)... धमकाओगे?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपके नेता खड़े हैं वो बोल रहे हैं। वहां से हरएक आदमी के स्प्रिंग लगी है खड़े हो जाते हैं।

श्री सभापतिः आप विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आपके भी मंत्री बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, विराजिये। बोल रहे हैं न आपके नेता जी।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): आप बैठ जाइये, ये भी बैठ जायेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति जी, यह व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी, जब यहां संसदीय मंत्री हैं तो दूसरा मंत्री क्यों उठ रहा है और संसदीय मंत्री भी अपनी बात आपको कह सकता है, धमका नहीं सकता सदस्यों को। ये भी बराबर की रोटी खाते हैं कोई इनकी डांट खाने नहीं आते हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, शान्ति से। शान्ति-शान्ति।

Kas/rtm/05.02.2025/15.50/2o

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह सदन नियम और परम्पराओं से चलेगा।

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए। ....(व्यवधान).... माननीय सदस्य, बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह पहले अपने साथियों को सिखाओ।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इनको बोलो कि पढ़े

किताब को।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सारा ठेका आपने ले रखा है क्या? आपका नंबर आये, जब बोलना। ....(व्यवधान).... प्रश्न का जवाब तो दे नहीं पाते ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ....(व्यवधान).... आपकी दादागीरी चलेगी क्या? राजस्थान की जनता ने भेजा है, आपने नहीं भेजा है। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, प्लीज, प्लीज, अपनी-अपनी बात मर्यादा में रह कर करें और आपस में उलझने के बजाय अभिभाषण पर वाद-विवाद पर ध्यान देते हुए आसन को इंगित करते हुए अपनी बात रखें। प्लीज, शांति से अपना उद्बोधन शुरू करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आज ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने ....(व्यवधान).... श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अगर आप इजाजत दो तो।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, इनको बोलने दो, बाद में बात करेंगे।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, हमारे नियमों में न्यायालय के फैसले का उल्लेख नहीं करने के अधिकार के सन्दर्भ में कहीं भी पाबंदी नहीं है। हमारे ज्ञानी मंत्री जी ने यह बात रखी है ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: आप विराजिए, विराजिए। ....(व्यवधान).... अंकित नहीं होगा।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हरिमोहन जी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कल ही राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा जो 1000 ट्रांसफर किये गये हैं, हिन्दुस्तान में राजस्थान में यह रिकार्ड कायम है कि 1000 ट्रांसफर को राजस्थान हाई कोर्ट ने रोका, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): याद करो वह दिन जब राजस्थान हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन पास किया था कि सरकार है या जंगल राज है, याद करो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं आपकी +++ के लिये आपको धन्यवाद देता हूं। 1000 ट्रांसफर का स्टे मिलने का राजस्थान के रिकार्ड में आज तक यह नहीं हुआ है और इसीलिए ....(व्यवधान)....

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): सभापति महोदय, +++ के शब्द को डिलीट कराइए। आपको ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। +++ के शब्द को डिलीट कराइए।

श्री सभापति: ऐसा शब्द है तो उसको अंकित ना करें। ऐसा कोई शब्द हो तो उसको अंकित नहीं करें जो मर्यादा से बाहर है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): जो अंतरविरोधों में माननीय मुख्य मंत्री जी को कमजोर कर

रहे हैं, अलग-अलग डिवीजन पर अलग-अलग मुख्य मंत्री बने हुए हैं। कोटा संभाग के मुख्य मंत्री अलग हैं, बीकानेर संभाग के मुख्य मंत्री अलग हैं, जोधपुर संभाग के मुख्य मंत्री अलग हैं और जयपुर में दिखते-दिखाते यहां के मुख्य मंत्री अलग हैं ....(व्यवधान)....

श्री सभापतिः आपकी बात समाप्त कीजिए। ....(व्यवधान)....

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): राजस्थान में भजन लाल जी के अलावा कोई मुख्य मंत्री नहीं हैं। ....(व्यवधान)....

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ....(व्यवधान).... वह काल गया जब मुख्य मंत्री एक उप मुख्य मंत्री को निकम्मा कहा करते थे, वह काल गया।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): राजस्थान में भजन लाल जी के अलावा कोई मुख्य मंत्री नहीं हैं आज की तारीख में। ....(व्यवधान)....

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज। श्री जेठानन्द जी व्यास।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरे नाम का उल्लेख किया गया है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि स्टे दिया गया है तो उसका कारण क्या है, यह बताइए। स्टे दिया है तो क्या कारण है, बताइए? माननीय न्यायालय का फैसला पढ़ा होगा ना आपने, बताइए क्या है? ....(व्यवधान)....

श्री सभापतिः माननीय दिलावर जी, प्लीज, प्लीज। अंकित नहीं होगा। श्री जेठानन्द जी व्यास।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री सभापतिः दिलावर जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): 000

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): मां भारती के चरणों में नमन, जय श्री राम। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं पहली बार विधायक बन कर आया और जब इस सदन में मैं आया तो मैंने देखा कि यहां बहुत ही बुद्धिजीवी लोग आये हैं, लेकिन जब भी कांग्रेस का कोई भी माननीय सदस्य बोलता है तो वह असत्य के अलावा कुछ नहीं बोलता। मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस के जितने भी विधायक यहां आये हैं और वे जो भी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि असत्य का एक बड़ा पुलिंदा बनाकर रख दिया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य यहां बीच में खड़े थे, नारेबाजी कर रहे थे। इनके एक वरिष्ठ नेता सचिव पायलट जी बैठे-बैठे सोच रहे थे कि मैंने कैसे लोगों को टिकट देकर जिता कर भेज दिया जो यहां अव्यवस्था करने के लिये आये हैं। वे खड़े इसलिए नहीं हुए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारी पार्टी ने क्या कर दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सुनो, नाम फिर हम भी लेना जानते हैं, आप क्यों नाम लेते हो? आप इधर-उधर क्यों देख रहे हो, ऐसे नहीं।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): वह सदन के सदस्य हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वह सदस्य यहां पर मौजूद नहीं हैं।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): तो मदन जी कौनसे मौजूद थे जब माननीय हरिमोहन जी बोल रहे थे। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए, उनको बोलने दीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं फिर कह देता हूं मुख्य मंत्री जी जब बोलेंगे तब एक-एक जवाब ले लेंगे, यह जो बीच में गदर मचा रहे हो। बता दिया है, मुख्य मंत्री को नहीं बोलने देंगे अगर बकवास की तो। ....(व्यवधान).... नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे ....(व्यवधान)....

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सदन विपक्ष की दादागीरी से नहीं चलेगा, सदन चलेगा नियम मर्यादा से। ....(व्यवधान).... आप इस तरीके से धमकाने की बात नहीं कर सकते।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ....(व्यवधान).... बकवास कर रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, प्लीज विराजिए, विराजिए। अविनाश जी, मंत्री महोदय, विराजिए। आप बोलो, सबको खड़ा क्यों कर रहे हो? विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं कि जो सदस्य बोल रहे हैं, उनकी बात पर ध्यान दें, अगर आपस में उलझेंगे तो इस वाद-विवाद का मैटर ही क्लोज हो जायेगा। अभी हरिमोहन जी बोल रहे थे तो मैं कितनी देर से कह रहा था क्लोज करो, क्लोज करो, वो आपस में उलझ रहे थे तो उनका समय खतम हो गया, अभी इनका भी समय जा रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आसन को इंगित करते हुए बात करें, आपस में उलझने का प्रयास न करें और ऐसा कोई शब्द न बोलें जो मर्यादा से बाहर हो। ऐसा कोई वाक्य आ जाये तो उसको अंकित ना करें, बोलिए।

Msk/rtm/05.02.25/1600/2p

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति जी, जब कोई सही बात यहां कही जाती है तो मेरे हिसाब से उनको बुरा लगता है और वे अपने स्थान पर खड़े होकर विरोध करते हैं। ...(व्यवधान)... यह तो आप सोचो। आप हमारे आदरणीय हो। आपके साथी सोचें।

हमारे एक माननीय सदस्य कैलाश जी वर्मा तथ्य की बात रख रहे थे। उसमें भी इनका विरोध था और इनके एक माननीय सदस्य ने कल हमारे मुख्य मंत्री पर असत्य आरोप लगाये, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वे हमारे कैलाश जी के कंपीटिशन में बोल रहे हो, जोर-जोर से, युवा बनकर, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन उनको पता नहीं कि वे इस सदन में क्या बोल रहे हैं। उनको स्वयं को पता नहीं, ऐसी भाषा, ऐसे गलत आरोप लगाने वाले सदस्य पर कार्यवाही होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी श्री भजन लाल जी ने पिछले बजट में जो भी घोषणाएं की हैं, वे धीरे-धीरे पूरी होने जा रही हैं। कांग्रेस, इन्होंने बजट पर पहले तो प्रशंसा की थी, बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इनका यह धर्म बनता है कि ये सदन में आकर कुछ तो विरोध करें। कुछ विरोध करें और पिछले बजट का, यह अपनी छाती पर हाथ रखकर कह दें कि इनके क्षेत्र में फायदा मिला कि नहीं मिला। ये केवल यहां विरोध करने के लिए आये हैं।

माननीय सभापति जी, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी से पहले कांग्रेस के जितने भी प्रधान थे, उनकी स्थिति क्या थी? वे विदेशों में जब जाते थे तो विदेशों के प्रधान से मिलने के लिए लाइन में खड़े होते थे, लेकिन आज समय बदला है। हमारे प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिए अन्य देशों के प्रधान मिलने के लिए लालायित होते हैं, यह आप स्वयं सोच रहे हैं। कांग्रेस के राज में इस देश की स्थिति सामाजिक, सामरिक, आर्थिक दृष्टि से बहुत खराब हुई थी, लेकिन जब हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी सीट पर आये, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद आप स्वयं सोच लें कि देश में कितना परिवर्तन हुआ है, देश कितना आगे बढ़ा है? यह आप स्वयं सोच सकते हैं। ...(व्यवधान)... वह तो मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। आज स्थिति क्या है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से? यानी एक समय ऐसा था कि चाइना जब चाहे भारत को धमका देता था, आज उसकी हिम्मत नहीं होती है। पाकिस्तान जब चाहे अमरीका में जाकर भारत के खिलाफ बोलता और हमारे देश का जो भी प्रधान वहां जाता तो पता नहीं ऐसे चुपचाप सुनकर आ जाता। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के खिलाफ विदेश में जाकर कोई बोलकर दिखाये। यह देश के प्रधान की एक विशेषता है और इस प्रधान की सफलता है, यह भारतीय जनता पार्टी के राज की सफलता है, जिसने इस देश को बचाया है। अगर कांग्रेस सरकार वापस आती तो आम आदमी की जो भाषा है, मैं बताता हूं। वे कहते हैं, यह देश डूब जाता। यह देश बर्बाद हो जाता। यह देश बिक जाता। यह मैं आपको आम आदमी की चर्चा बता रहा हूं। आप जाकर पूछ लीजिये। इन्होंने भाजपा को हराने के लिए लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे असत्य प्रचार किये, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खतम कर देंगे। आज भी ये पीट-पीटकर रो रहे हैं कि ये ऐसा कर देंगे। आप सोचें कि पिछले 65 साल में कांग्रेस ने कितने नियम बदले हैं, संविधान में कहां-कहां कितना परिवर्तन किया है। आप सोचकर देखें। भारतीय जनता पार्टी ने देश के विरोध में कहीं ऐसा नहीं किया। आपने देश को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो जम्मू-कश्मीर देश से अलग हो जाता। 370 हटाने वाली जो सरकार है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

माननीय सभापति जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले अगर आप आम आदमी की जुबान पर जाते तो वे कहते, आज तक की जितनी भी कांग्रेस सरकारें आयी हैं, उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है, वह पिछली कांग्रेस सरकार थी। यह आम आदमी के मुंह पर है। इसी कारण जनता ने इनको शासन से बाहर कर दिया। रोजगार की बात करते हो। ...(व्यवधान)... आप अच्छी तरह से सुन लें। जब आप रोजगार की बात

करते हो, कांग्रेस के राज में जो भी विज्ञप्तियां निकलीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय समाप्त हो रहा है।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): मेरा समय है। मेरे पांच मिनट इन्होंने खराब कर दिये, ऐसे क्या करते हो, पहली बार जीतकर आया हूं तो भी नहीं बोलने देंगे। ऐसा थोड़े ही होता है। नहीं-नहीं, मैं बोलूंगा।

श्री सभापति: 5 मिनट बर्बाद कर दिये।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): रोजगार की जब बात आती है, जितनी भी विज्ञप्तियां निकलीं, उन सबमें स्टे आया, लेकिन इस सरकार में जितनी विज्ञप्तियां निकली हैं, सबकी परीक्षा हो रही है। कोई नकल नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं है। यह जो पिछले राज में हुआ, उसमें आम युवा यह कह रहा है कि इस राज के आने के बाद हमारा भविष्य बनने जा रहा है। यह आम युवा की बात है।

माननीय सभापति जी, हमारी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है और बराबर की है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिले। छोटे शहरों और कस्बों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ हों और अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर हो। इसके लिए एक वर्ष में पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज और तीन निजी कॉलेज प्रारंभ हुई हैं। हर गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): वसुन्धरा राजे जी के राज में बीकानेर में सैटेलाइट को 2007 में जिला अस्पताल घोषित किया गया था, लेकिन वह एक स्वास्थ्य केन्द्र जैसा बनकर रह गया था। वहां मरहम पट्टी भी नहीं थी, लेकिन फिर जब बीजेपी में उसका काम शुरू हुआ, फिर इन्होंने उसकी वही हालत कर दी। आज भाजपा की सरकार बनने के बाद वहां सब प्रकार की सुविधाएं हैं, सब प्रकार की जांच हो रही है। मैं आपको बता दूं कि वहां गायनिक के तो ऑपरेशन भी शुरू हो गये हैं। इस प्रकार हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी व चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम किया है, आज तक नहीं हुआ। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि राजस्थान में हर गांव ढाणी तक स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंच रही हैं।

श्री सभापति: डॉ. शिखा मील बराला।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): जब पानी की बात करें तो आप देखें कि राज्य सरकार का प्रयास है कि गांव, ढाणी में बसे हुए लोगों को स्वच्छ पेयजल सुलभ हो। जल जीवन मिशन के रूप में विगत सरकार को हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रारंभ करने में कीमती समय गंवा दिया और कार्य प्रारंभ नहीं किया। जब कार्य प्रारंभ कर दिया, उस पर कांग्रेस सरकार ने घोटाले ही घोटाले किये हैं। यह सबके सामने विदित है। यह लगातार हो रहा है।

सूचना

चोमू में सड़क दुर्घटना में एक छात्रा की मृत्यु

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सभापति महोदय, सर्वप्रथम आज सेवेर चौमू में स्कूल बस की दुर्घटना के हादसे में एक बच्ची की जान गयी, उसकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करती हूं।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति जी, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जनता का शोषण किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दूसरे का समय चालू हो गया। आपके 11 मिनट होने वाले हैं। यह समय दूसरे का चालू हो गया।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आज मेरे चोमू विधान सभा क्षेत्र में स्कूल बस के हादसे में जिस लड़की ने जान गंवायी, उसकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करती हूं और उसके जो परिजन हैं, उनके लिए संवेदना व्यक्त करती हूं।

हमारे क्षेत्र में पिछले दो महीने में यह दूसरा स्कूली बस हादसा है। दो महीने पहले ऐसे ही हादसे में एक शिक्षक ने अपनी जान गंवायी और कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। दुख की बात यह है कि जो शिक्षा विभाग है और जो परिवहन विभाग है, वह इस मुद्दे को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है।

श्री सभापति: आपकी बात आ गयी।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय एवं परिवहन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो फर्जी बसें चल रही हैं, बच्चों की जिंदगियां ताक पर हैं। ऐसे जो फर्जी फिटनेस सेंटर्स हैं, ऐसी जो फर्जी बसें चल रही हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।

एक माननीय सदस्य: शिक्षा मंत्री जी, सुनो।

श्री सभापति: वह अंकित हो रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, स्कूल बस का कोई हादसा हुआ है।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): मैं आपके माध्यम से फिर से शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी कि आपका विभाग और परिवहन विभाग स्कूली बसों की दुर्घटनाओं को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। आज हमारे क्षेत्र में एक बच्ची ने जान गंवायी है, दो महीने पहले एक शिक्षक ने जान गंवायी थी। इसके लिए जो संवेदनहीनता पूरी सरकार की है, वह बहुत ही चिंता का विषय है।

mdp/rtm/05.02.2025/16:10/2q

हमारे जो समाज के बच्चे हैं, भविष्य हैं, इन बसों में उनकी जिन्दगियां ताक पर हैं। आप इसे गंभीरता से लीजिए और इस पर कार्यवाही करें।

श्री सभापति: हो गयी आपकी बात। श्री हरेन्द्र मिर्धा जी।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर): सभापति महोदय, आपका बहुत आभारी हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का आपने मुझे मौका दिया। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विस्तार से बात की। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह बजट की स्पीच है, पब्लिक स्पीच है या अभिभाषण की स्पीच है। जो मन में आ रहा है, वह कह रहे हैं। मैं मेरी बात अभिभाषण तक ही सीमित रखूंगा।

सभापति महोदय, यह परम्परा है कि हर साल अभिभाषण होता है महामहिम का और गवर्नमेंट की मंशा उसमें आती है। जो गवर्नमेंट ने जनता से वादा किया, जो जनता को कहकर उनका विश्वास लिया, उस सम्बन्ध में वह क्या करने जा रही है, क्या कर रही है और भविष्य में क्या करना चाहती है, उसका विस्तार अभिभाषण में आता है। इस अभिभाषण में कहीं भी किसी रूप में इनके वादे किये हुए, जो भी इन्होंने काम किया एक साल में, इसका विवरण इसमें नहीं आ रहा है। एक ही बात आ रही है कि कांग्रेस सरकार की आलोचना हो रही है। जो मेन मुख्य बातें हैं, उसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।

सभापति महोदय, समाज के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए कुछ अहम बिंदु हैं। बिजली है, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा हो गयी। मैं सीमित रखना चाहूंगा दो-तीन बातों पर। सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक नागौर जिले से है। पश्चिमी राजस्थान में ढाणियों से बसा हुआ पूरा इलाका है, बड़े-बड़े कस्बे बहुत कम हैं। छोटी-छोटी ढाणियां 100-150-200 लोगों की, जब तक वहां विकास नहीं पहुंचेगा, आम आदमी तक विकास नहीं पहुंचेगा, तब तक सही मायने में विकास पूरा नहीं हो सकता। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो भी अभिभाषण में लिखा गया है, इसका कोई भी विकास का काम पिछले साल-डेढ़ साल में ढाणियों में नहीं पहुंचा है, चाहे वह सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। लम्बा-चौड़ा इलाका है, एक ढाणी से दूसरी ढाणी लंबी है। बिजली के तार बहुत लंबे हैं, वोल्टेज बहुत कम आता है। ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, तार टूट जाते हैं और जब जनता अफसरों के पास जाती है तो वह अक्सर यह कह देते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है। हम जब उन लोगों से बात करते हैं तो आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन के बाद आगे कुछ नहीं होता।

पानी की बहुत समस्या है। कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 20-30 सालों में पानी के मद के ऊपर कांग्रेस सरकार ने बहुत इंवेस्टमेंट किया है। कोई ढाणी, कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा, किसी न किसी रूप से पानी से जुड़ा हुआ है। आज मुख्य काम, मंत्री जी, आपका यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर उसको आप सही ढंग से मेंटेन कर लें तो मैं समझता हूं कि लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल जायेगी। ये इतने सालों की मेहनत है। अभी पिछले सालभर से हम देख रहे हैं कि आपका जो क्रम है वह पूरा का पूरा कोलेप्स

हो गया है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन कोलेप्स हो गया। टंकियां सूखी पड़ी हैं, जीएलआर सूखे पड़े हैं, पाइपलाइन लीक कर रही है, बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं। हालत ऐसी हो रही है कि पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या गांवों में हो रही है और यही हाल बिजली का है। बिजली, पानी जैसी मेन सुविधा अगर आम आदमी को हम नहीं दे सकते तो बाकी की चीजें कोई मायने नहीं रखती है।

अब मैं सीधा आता हूं आपकी स्वास्थ्य सेवाओं पर। हमारे जिले के मंत्री जी यहां नहीं हैं। 25 लाख तक का पूरा का पूरा मेडिकल का जो खर्चा था, वह हमारी सरकार ने चिरंजीवी योजना में किया था। अब उस स्कीम का नाम बदल दिया और उस स्कीम को इतनी कॉम्प्लीकेट कर दी, इतनी कागजी कार्यवाही कर दी, इतनी फॉर्मैलिटीज इसमें कर दी कि आदमी जितना लाभ लेना चाहता है, उतना लाभ नहीं ले पाता। दवाइयां नहीं हैं, ओवर-डेटेड दवाइयां हैं, अस्पतालों में इतनी लंबी-लंबी क्यू लगती हैं कि आम आदमी को सुविधा लेने के लिए लगभग पूरा दिन लग जाता है। स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आते हैं। कभी-कभी तो जनता हमको फोन करके कहती है कि डॉक्टर नहीं हैं, वह बैठे चाय पी रहे हैं और अन्दर नहीं आ रहा है। हमें फोन करना पड़ता है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त कीजिए। हमने भी इसमें बहुत मेहनत की है। कांग्रेस सरकारों ने 40-50 सालों में बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया है। इसको आप मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को फायदा मिलेगा।

सभापति जी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं, जिन पर सरकार को भी चिंता होनी चाहिए और हमको भी चिंता है। जब तक दोनों मिलकर, पूरी विधान सभा मिलकर चिंतन नहीं करेगी तब तक अपने देश के, अपने प्रांत के भविष्य के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।

ये जो ड्रग्स का मामला है, ये एमडी जो है बाड़मेर से लेकर ठेठ बार्डर एरिया, बीकानेर, गंगानगर तक ये मामला बना हुआ है, ये दिन-ब-दिन बहुत बिगड़ रहा है। आपके हाईवे पर किसी भी ढाबे पर, किसी भी होटल पर आप चले जाइए खुले ड्रग्स मिल रहे हैं। पुलिस कोशिश भी करती है, ऐसा नहीं है कि वह रेड नहीं मारती है, पंरतु इतनी मिलीभगत है कि रेड मारते हैं उसके पहले सूचना मिल जाती है और वह अपना सारा सामान ठिकाने लगा देता है। इतने सालों से हम इस बात को देख रहे हैं। यह इतना गंभीर विषय है कि आप और हमको सबको बैठकर इस विषय में चिंतन करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे। यदि वह इस ड्रग्स में आ गयी तो आप मानिए कि हमारे समाज और प्रांत का क्या भविष्य होगा।

लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन, सभापति महोदय, लॉ एंड आर्डर भी ड्रग्स से लिंक है। जितनी भी डकैती हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रंगदारी हो रही है, ये बेसिकली ड्रग्स ओरियंटेड लोग हैं। ये ही ज्यादातर कर रहे हैं। अनएम्प्लायमेंट है, नौकरी मिल नहीं रही, काम मिल नहीं रहा, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, इतने गंभीर विषय के ऊपर आप और हम

सबको असेम्बली में, सरकार को मिलकर इसकी कोई लॉग-टर्म प्लानिंग या कोई न कोई लॉग-टर्म समाधान निकालने की बहुत आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर कुछ करेंगे। मुख्य मंत्री जी अपने संबोधन में इसके सम्बन्ध में कुछ हमें मार्गदर्शन देंगे।

सभापति जी, रूलर एरिया में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं। सीमेंट के ब्लॉक्स अभी ऑक्शन हुए हैं। हजारों करोड़ों रुपये की गवर्नमेंट की इनकम हुई है। बड़े-बड़े सीमेंट के प्लांट्स कुछ लगे, कुछ पाइपलाइन में हैं। लेकिन ये लगने के बाद में जो पॉल्यूशन क्रियेट हो रहा है, उद्योग मंत्री जी यहां नहीं हैं, आप टीम भेजकर स्वयं देख लीजिए, अम्बुजा प्लांट हमारे म्यूनिसिपैलिटी एरिया में लगा हुआ है मुंडवा में, जो नागौर से मात्र 15 किलोमीटर पर है और पूरा का पूरा एरिया 50-60-100 किलोमीटर के एरिया में इतना प्रदूषण हो गया है कि आदमी वहां पर खड़ा नहीं रह सकता। बच्चे, बूढे, औरतें, प्रेग्नेंट वुमन, उनका सिस्टम इतना खराब हो रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया। इन बड़े प्लांट्स पर अंकुश लगना चाहिए कि एनवायरमेंट ठीक रखने लिए उनका जो दायित्व था, जब प्लांट लगा तब सरकार ने जो शर्तें लगायी थी, उनका पालन पूरा हो। नये प्लांट जो भी आयेंगे, उनके ऊपर भी पूरा अंकुश हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि लोकल एम्प्लायमेंट जब तक बड़े प्लांट्स नहीं देंगे, बाहर से लोगों को लाएंगे तब तक उन प्लांट्स का फायदा उस लोकल एरिया को ज्यादा मिलेगा नहीं।

सभापति महोदय, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं। यह गंभीर विषय है। सबसे पहले अभी जिन्दल स्टील कंपनी ने ब्लॉक ऑक्शन कराए थे। लोग अपना मुआवजा मांग रहे थे। जमीनें उन्होंने खरीदी। जब मालूम पडा कि जमीन की वेल्यू ज्यादा है तो उन्होंने वापस उनसे कहा। पीसफुल धरने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और भयंकर रूप से लोग घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। बाकी का प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बड़े टार्गेट्स तो मीट होते रहेंगे, परंतु रोजमर्रा की जिदंगी में आम आदमी को जो दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसमें भागीदार आपका और हमारा बनना बहुत आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर कुछ ध्यान देंगे ताकि हम एक नयी दिशा में राजस्थान को लेकर जा सके।

सभापति जी, पीने के पानी की समस्या है और काश्तकार की सबसे बड़ी समस्या है। ये जो मुआवजा है, काश्तकार को जो मिलता है, इसमें भी बहुत बड़ा घपला है। लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। एम.एस.पी. पर खरीद नहीं हो पा रही है। राज्यपाल महोदय ने इसके ऊपर अभिभाषण में कहा भी है। लोग अपना अनाज लेकर जाते हैं मंडी में, कई दिनों तक वहां खड़े रहते हैं। ये डाक्यूमेंट लाइए, वह डाक्यूमेंट लाइए, पर-हैक्टेयर क्या कोस्ट है, पर-बीघा क्या कोस्ट है, उसके बाद भी कोई न कोई कमी निकाल कर उसके सही दाम उनको नहीं मिलते। दाम तय करने के बाद भी कई महीनों तक इनको पैसा नहीं मिलता। यह बड़ा अन्याय हो रहा है। 60-70 परसेंट लोग खेती में इंवाल्व हैं, चाहे वह आपके वोटर हों, चाहे हमारे वोटर हों, जब तक गांव का आदमी खुशहाल नहीं होगा और उसको हक नहीं

मिलेगा, तब तक मैं समझता हूं कि ये देश और ये प्रांत आगे नहीं बढ़ सकता। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत आभार आपका।

श्री सभापतिः श्री जयदीप बिहाणी जी।

Ans/Rtm 16.20 3a 05.02.2025

श्री जयदीप बिहाणी (गंगानगर): जय श्री राम। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अंतःकरण से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं अपने अंत:करण से जब दुःखी हुआ जब परसों महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, विपक्ष के अध्यक्ष ने अपने चिर परिचित अंदाज में ठुमका लगाते हुए आपके राज्यपाल शब्द इस्तेमाल किया, यह मैंने सुना, सदन की रिकार्डिंग में भी नोट है। क्या राज्यपाल सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के है? क्या राज्यपाल सदन के 200 एमएलएज के नहीं है? क्या राज्यपाल कांग्रेस के नहीं है? क्या राज्यपाल राजस्थान की आठ से साढ़े आठ करोड़ जनता के नहीं है? यह बात अत्यंत अशोभनीय थी। इससे मेरा जैसा व्यक्ति जो समाज की सेवा राजनीति के माध्यम से करना चाह रहा है उसके दिल को दुःख पहुंचा है। ...(व्यवधान)... अभी ठुमका भी दिखा दूंगा आपको, अंत में आप वह भी देख लेना। आप तो रोज देखते हैं। इस अवसर पर मैं गंगानगर विधान सभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिसने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में जनसेवा का मौका दिया है।

माननीय सभापति जी, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र किया है। यह उपलब्धियां वह हैं जिनके साकार होने की बात प्रदेश की जनता बेसब्री से जोह रही थी। पिछले पांच साल, एक साल हमारे आने से पहले यानी 2023 से पहले जनता इस बात के लिए बेसब्र थी कि कब यह राज बदले और कब जनसेवा का मौका मिले। यह उपलब्धियां किसी एक क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं थी बल्कि हर उस क्षेत्र से जुड़ी उपलब्धियां थी जिससे प्रदेश का विकास होता है और जनता को राहत मिलती है।

माननीय सभापति जी, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में तीसरे पर ले जाने की थी। माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा उनकी सोच को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के विकास को गति देने के हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान खनिज, खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में समृद्ध है। यहां औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ। यह आयोजन ना केवल प्रदेश की राजधानी बल्कि हर ज़िले में हुआ। सरकार के पहले ही कार्यकाल में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू होना बड़ी उपलब्धि है। जब यह एमओयू मूर्त रूप लेंगे तो प्रदेश में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होगा और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार मिलने का

सपना भी पूरा होगा। माननीय महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी राइजिंग राजस्थान पहले बजट में आया है, दूसरे बजट में स्पार्कलिंग राजस्थान आएगा, तीसरे बजट में शाइनिंग राजस्थान। ...(व्यवधान)... अभी परतें खुलेगी। रुको, जिस क्षेत्र से मैं जुड़ा हूं वह भी बताऊंगा।

सभापति जी, प्रदेश के कई ज़िले आज भी जल संकट का सामना कर रहे हैं। चुनाव के समय प्रधान मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को लेकर जो वादा जनता से किया था उस पर काम शुरू हो गया है। इस परियोजना के पूरा होने से प्रदेश के 17 ज़िलों की पेयजल आवश्यकता तो पूरी होगी साथ ही लगभग 04 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होने से प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ेगा। प्रधान मंत्री जी की पहल पर भारत सरकार, हरियाणा तथा राजस्थान के बीच जो समझौता हुआ है इससे यमुना जल सीकर, चूरू, झुन्झुनूं ज़िलों की धरा पर जाएगा और इन जिलों में भी खुशहाली की नई इबादत लिखी जाएगी।

सभापति महोदय, पिछली सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए हुई प्रतियोगी परीक्षाओं का जो हश्र हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। पेपर लीक होना, तत्कालीन सरकार के समय इस प्रदेश की नीति बन गया था। सरकारी नौकरी की आस में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं के हितों पर जो कुठाराघात हुआ उसके पन्ने परत दर परत खुलते जा रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने पद भार ग्रहण करते ही एसआईटी का गठन कर निष्पक्ष जांच के आदेश दिये तो पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामे, बेरोजगार युवाओं के साथ हुए छल की कड़वी सच्चाई सामने आ गई। निष्पक्षता और पारदर्शिता से परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी इस राजस्थान सरकार की पहल थी और एसआईटी जांच से साफ हो गया कि पूर्ववर्ती सरकार ने दूध की रखवाली बिल्ली का सौंप रखी थी। ज्ञात रहे, कांग्रेस सरकार के शासन काल में इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया और लोगों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया।

सभापति जी, सरकार ने ना केवल विगत सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए भर्तियों में की जा रही गड़बड़ियों को पकड़ा बल्कि ऐसे अपराधियों को जिन्होंने युवाओं का भविष्य खराब किया उनको भी जेल की सीख़चों के पीछे डाल दिया। कांग्रेस सरकार जो इतना हो-हल्ला कर रही है उनका भ्रष्टाचार के साथ चोली दामन का साथ है। पूर्ववर्ती सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचार में किस क़दर लिप्त थे इससे पता चलता है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय गठित आरसीए कार्यकारिणि के खिलाफ स्टेडियम निर्माण से लेकर मैच के दौरान हुए घोटाले के विरुद्ध वर्तमान आरसीए की एडहॉक कमेटी ने जांच करवाते हुए 363 पन्ने, सुन लो कांग्रेसियों, 363 पन्नों की एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके ज्योति नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी और उसमें करोड़ों रुपये का घोटाला। यह ना केवल अर्थ पर कुठाराघात था बल्कि उन युवा प्रतिभावों के लिए भी एक दर्दनाक था जिनके पैसे का हक तत्कालीन कमेटी ने अपनी जेब में डाल लिया। यह मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं एडहॉक कमेटी का कन्वीनर हूं। ...(व्यवधान)... हां, उधर से आवाज आई। उधर से आवाज आई, really it is a shame for

you!

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार के कार्यकाल में हाल ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा सम्पन्न हुई है। मुख्य मंत्री जी ने इस परीक्षा को लेकर प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को जो निर्देश दिए थे उसी का परिणाम है कि परीक्षा निर्विघ्न सम्पन्न हुई और परीक्षा देने वाले परिक्षार्थियों ने पेपर और व्यवस्था को लेकर संतोष व्यक्त किया।

सभापति महोदय, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार करवाते-करवाते परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है। मेरे ज़िले में कैंसर रोगियों को उपचार के लिए बीकानेर, जयपुर और अन्यंत्र उच्चतर सेंटर्स पर जाना पड़ता है। आप आज भी देखे, गंगानगर से बीकानेर का ट्रैफिक कैंसर मरीजों का लगभग तीन हजार के करीब है। ऐसे में सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में गंगानगर के जिला चिकित्सालय में कैंसर विंग की स्थापना की। कैंसर रोगियों व उनके परिवार पर जो उपकार किया उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और गंगानगर की जनता की तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कैंसर के बेहतर इलाज के लिए आधुनिक लिनियर एक्सीलेटर मशीन भी श्री गंगानगर जिला चिकित्सालय को मिल गई है, जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का पुनः आभार।

माननीय सभापति महोदय, एक बात आपको और बताना चाहूंगा। कैंसर का इंजेक्शन तीन लाख रूपये का आता है जो बार-बार लगवाना ना केवल सामान्य व्यक्ति के लिए बल्कि आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है, वह भी राजस्थान सरकार निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है, यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

VPS-RTM-05.02.2025-16.30-3b

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री जयदीप बिहाणी (गंगानगर): बस अंतिम, साहब। घर-घर जल पहुंचाने के माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी के सपने को कांग्रेस शासन काल में बिलकुल धराशायी कर दिया गया। जल जीवन मिशन की जो धज्जियां कांग्रेस शासन काल में उड़ी, यह राजस्थान की जनता के साथ सबसे बड़ा छल था और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इसकी परतें दर परतें प्याज के छिलकों तरह उधड़ती जा रही है।

श्री सभापतिः श्री उमेश मीणा, विभाजन संख्या-23.

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र और पूरे प्रदेश की ओर से धन्यवाद, जोहार।

आज राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष और विपक्ष के मध्य काफी चर्चाएं हो रही थीं और हम यह देख रहे थे और मैं भी मेरी बात को आज यहां पर रखना चाह रहा हूं। मैं राजस्थान के दक्षिणी एरिया से आता हूं और वहां पर जो विद्यालय हैं, उनमें अभी तक भी रिक्त पद पड़े

हुए हैं, उनको सरकार भरने के लिए ध्यान नहीं दे रही है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खातों में तीन से चार साल की छात्रवृत्ति जमा नहीं हो रही है, उस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जो स्कूटी 2022-23 की एक हजार से ऊपर स्कूटी बकाया है, उसको देने की सरकार बात नहीं कर रही है। इससे यह साबित होता है कि दक्षिणी राजस्थान के एरिया के अन्दर जो मांगें हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, इससे हम कहीं न कहीं भाजपा को आदिवासी विरोधी मानते हैं।

आज जो मेन आरक्षण का मुद्दा है, जो हमारे एरिया का ही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टी.एस.पी. क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था की जो विसंगति है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। अनुसूचित क्षेत्र में टी.एस.पी. एरिया में हंड्रेड परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, जिसमें टी.एस.पी. के निवासरत स्थानीय निवासियों के लिए अधिसूचना 2013 व संशोधित अधिसूचना 2016 के अनुसार कुल पदों में से एस.टी. के 45 परसेंट और एस.सी. के 5 परसेंट और शेष 50 परसेंट जो पद अनारक्षित श्रेणी के हैं, स्थानीय समस्त वर्गों से वरीयता के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है। अन्यथा, ओपन केटेगरी के जो 50 परसेंट पदों को सभी वर्गों से, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., जनरल, सभी अभ्यर्थियों से वरीयता के आधार पर भरा जाना है किंतु पिछले कुछ वर्षों से अधिसूचना 2013 व संशोधित अधिसूचना 2016 की पालना नहीं हुई है। स्थानीय एस.टी. और एस.सी. अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में उच्च अंक लाने पर भी उन्हें अनारक्षित पदों पर नहीं भरा गया है।

माननीय सभापति महोदय, अधिसूचना 2013 और संशोधित अधिसूचना 2016 से 2025 तक टी.एस.पी. क्षेत्र में विभिन्न विभागों में कितने पदों पर भर्तियां निकाली गईं, 2013-14 से 2025 तक की सूचना सदन की मेज पर रखें।

माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. क्षेत्र में 75 परसेंट जनसंख्या आदिवासी बाहुल्य है। पिछली सभी भर्तियों में लगभग अधिसूचना की पालना नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पर मैं एक भर्ती बताना चाहूंगा। कांस्टेबल की भर्ती विज्ञप्ति जो निकली है 04 दिसम्बर, 2019 को, जो जनजाति अभ्यर्थी के लिए उदयपुर के लिए 153 पद, डूंगरपुर के लिए 25 पद, प्रतापगढ़ के लिए 8 पद और सिरोही के लिए 50 पद और बांसवाड़ा के लिए 36 और राजसमन्द के लिए 8 और चित्तौड़गढ़ के लिए 4 और पाली के लिए जीरो है, इस प्रकार 318 पद ही मिले जो कुल पद 1597 है और इसका परसेंटेज निकाला जाये तो 20 परसेंट भी नहीं हो रहा है, तो आखिर इसका क्या कारण रहा, यह भी हम जानने चाहेंगे टी.एस.पी. एरिये के लोग।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार वर्ष 2021 में जो विज्ञप्ति जारी हुई, ग्राम विकास अधिकारी वाली, इसको भी मैं इस सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। इसमें विज्ञप्ति बिंदु संख्या-2, परीक्षा शुल्क नम्बर-3 में लिखा है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित श्रेणी में शुल्क जमा कराने पर अभ्यर्थी उसी श्रेणी में माना जायेगा। यह एक विसंगति है। क्या यह अधिसूचना 2013 व 2016 के अनुसार लागू होता है या नहीं, यह भी हम जानना चाहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही टी.एस.पी. क्षेत्र में जो पदोन्नति आरक्षण को लेकर

भी बहुत विसंगति है जो मैं बताना चाहूंगा कि एस.सी., एस.टी. अभ्यर्थी को पदोन्नति अधिसूचना की पालना करते हुए नहीं की जा रही है। उदाहरण मैं एक यह बताना चाहूंगा कि जो कृषि विभाग में हुआ था। कृषि आयुक्तालय, जयपुर के आदेश क्रमांक 32877-33277, दिनांक 22.01.2024 के अनुसार कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक से वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक की पदोन्नति में अधिसूचना 2013 व 2016 की पालना नहीं करते हुए एस.टी., एस.सी. अभ्यर्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया और यही हाल अभी फिलहाल जो प्रधानाचार्य के अन्दर है, उसमें भी यही हुआ है। टी.एस.पी. क्षेत्र में जारी पदोन्नति सूची के कुल 251 पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापन किया गया है, जिसमें एस.टी. को 113 पद, एस.सी. को 12 पद और सामान्य को 125 पदों पर पदोन्नति की गयी है जबकि सामान्य वर्ग से 125 पदों पर पदोन्नति की गयी है। दरअसर उसे अनारक्षित श्रेणी में माना गया है। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को पदोन्नति दी जानी चाहिए थी। हमारा यह निवेदन है कि अधिसूचना के पश्चात जारी समस्त भर्तियों के आकड़े इस सदन की मेज पर रखें।

श्री सभापतिः आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): ताकि हमारे टी.एस.पी. एरिये को और हमको यह पता चले कि पक्ष और विपक्ष की सरकार ने हमारे साथ किस तरह से भेदभाव किया है, यह हम जानना चाह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री पब्बाराम विश्नोई।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया इस हेतु मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के 168 बिंदुओं में इस सरकार के विकासवादी विजन को परिभाषित किया है। मात्र एक वर्ष के कार्यकाल में ही यशस्वी युवा मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने अपने सांगठनिक अनुभवों के आधार पर राज्य के विकास की जो ठोस आधारशिला रखी, उसकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी कम है। आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में हमारा देश व राजस्थान प्रदेश ने अद्भुत प्रगति अर्जित की है। जैसा कि अभिभाषण से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार वादों पर नहीं अधिक काम करने के इरादों पर विश्वास करती है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार मात्र सब्ज-बाग़ दिखाने और घोषणा करने वाली सरकार थी, जनता ने जिनको ठुकरा दिया। पूरे पांच वर्ष तक इन्होंने गांव, गरीब, किसान, शोषित, मजदूर, दलित और मध्यम वर्ग के लिए बिलकुल कुछ भी काम नहीं करके केवल कुर्सी की दौड़ में ही लगे रहे और एक दूसरे के विरुद्ध आपसी नूरा कुश्ती में ही अपने पांच साल बरबाद कर दिये।

कोरोना जैसी महामारी में जब लोगों की जानें जा रही थीं तब पूरी सरकार होटलों में महीनों भर के लिए गुल-छल्ले उड़ा रही थी और लोग मर रहे थे। यह तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वह कैडर था जिन्होंने उनके भोजन, गौ माताओं के लिए चारा, लोगों

के लिए उपचार, अपनी जान पर खेल कर सहायता की। हमारे अनेकों कार्यकर्ता संक्रमित होकर अपनी जान भी गंवा बैठे, उन सभी पुण्यात्माओं को मैं अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

पांच साल तक भ्रष्टाचार व फिजूलखर्ची के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी थी। हर विभाग में भ्रष्टाचार का आलम था। हर विभाग में भ्रष्टाचार की इस परिस्थिति में जनता त्राहि-त्राहि करने लगी थी। केन्द्र द्वारा संचालित जल जीवन मिशन जैसे जन हितकारी योजनाओं के अन्दर भी भ्रष्टाचार कर इस योजना को पटरी से उतारने का जो काम इन्होंने किया वह जगजाहिर है और उसकी सारी योजना को इन्होंने बेपटरी करने का प्रयास किया है। डिस्कॉम को भी भंयकर घाटे में छोड़कर ये गये हैं। ऐसी परिस्थिति में इस राज्य की बागडोर एक सांगठनिक कौशल के धनी, ऊर्जावान, युवा व मजबूत इरादों वाले मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा के हाथों में आयी जिस पर यह चार लाइनें समीचीन होंगी-

कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें,
लहर के हर तूफान मिले और मोड मोज मजधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और फिर यह दिखा देंगे सबको,
यह इन हालातों में भी आते हैं, दरिया पार करना हमें।

पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा इन मूलभूत आवश्यकताओं पर फोकस कर आम जनता को राहत प्रदान करने का भरपूर प्रशासनिक प्रयास किया गया। एक वर्ष के, पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए टॉस्क फोर्स बनाकर प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव को घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिये और वह जिलों में जाकर उन्होंने यह प्रयास किये।

ssy/rtm/05.02.2025/16.40/3c

राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री जी स्वयं ने मॉनिटरिंग करते हुए पिछली बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजना है, जो 17 जिलों की धरती को सर सब्ज बना देगी। इसी प्रकार से यमुना जल समझौता जो 3 जिलों को सर सब्ज बनायेगा। इसी प्रकार से जो गुजरात में हमारी अरावली पर्वतमाला का पानी जा रहा है, वह जवाई बांध में लाकर के 2 जिलों सिरोही और जालौर में भेजने की जो योजना बन रही है, इससे आधे से अधिक राजस्थान सर-सब्ज होगा और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

इन्होंने पिछले 5 साल में ERCP की योजना इसलिए नहीं लागू की कि यह बीजेपी सरकार द्वारा की गई थी। कांग्रेस सरकार किसी भी ऐसी योजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी जो बीजेपी सरकार ने शुरू की हो। वह उसको अटकाना, लटकाना, भटकाना और अगर शुरू भी कर दी तो उसको गटरकाना करना उनका काम हो गया था। यूं कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी कि श्री भजन लाल शर्मा इस आधुनिक राजस्थान के भागीरथ हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ी आवाज कम करें।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): मैं चार पंक्तियां कहना चाहता हूं, 'कुछ तो फूल खिलाये हमने और कुछ फूल खिलाने हैं, मुश्किल यह है कि बाग़ में अब तक कांटें कई पुराने हैं'। उन्हीं कांटों को एक तरफ करते हुए पश्चिमी राजस्थान के लिए हम एक बहुत बड़ी मांग करना चाहते हैं कि ERCP की तरह ही हमारी WRCP योजना लाकर के पश्चिमी राजस्थान की धोरों की धरती को सर-सब्ज करने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के कार्यकाल में जब पार्टी ने सत्ता संभाली तो देश में 18 हजार गांव बिना बल्ब के थे। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रत्येक घर को कनेक्शन देने का काम किया। यह योजना पूर्णता की ओर थी कि राज्य सरकार बदल गई और उन्होंने कोई भी योजना चाहे जनहित की भी हो, बीजेपी द्वारा शुरू की गई योजना को बंद करने का काम किया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनेक लोग इससे वंचित रह गये। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इसको बंद कर दिया। प्रधान मंत्री ने दोबारा सौभाग्य योजना के द्वारा उनको कनेक्शन देने के लिए कहा। परंतु उसके अन्दर भेजी गई राशि भी इन्होंने वापस लौटा दी और कह दिया कि सभी कनेक्शन कर दिये गये। दो बार प्रधान मंत्री जी ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत राशि भेजी, लेकिन इनको तो वह काम करना नहीं था। सरकार ने अब वादा किया है कि 2027 तक किसानों को दिन में सिंचाई हेतु बिजली देंगे।

बड़े-बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जा रहे हैं। इसमें हमारा पश्चिमी राजस्थान ऊर्जा की दृष्टि से पावर इंजन का काम करने वाला है। वहां पर सौर ऊर्जा के बड़े-बड़े संयंत्र लग रहे हैं। वह ना सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में बिजली पूरी करने का काम 2027 तक करेंगे। कुसुम योजना के तहत अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर किसान भी ऊर्जा दाता बन रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाकर फ्री बिजली देने का काम सरकार त्वरित गति से कर रही है। इस प्रकार किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने का काम सरकार करने वाली है।

एक बात मैं विशेष तौर से शिक्षक होने के नाते कह सकता हूं, मैंने अनेकों परीक्षार्थियों की परीक्षा लेते हुए वीक्षण कार्य किया है। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सदस्य रहा हूं, तब भी मैंने देखा है कि जब कभी भी विद्यार्थियों के पेपर खराब हो जाते थे तो उनकी आंखों से आंसू झर-झर बहते थे। लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्दर जो चोरी का काम किया है, पेपर्स के अन्दर भ्रष्टाचार करके लोगों को पहले से ही नौकरी बेचने का काम किया है। लोग कह रहे हैं कि 17 परीक्षाओं में नकलें हुई हैं, उनका पेपर लीक हुआ है। मेरा यह दावा है कि आपके कार्यकाल में एक भी परीक्षा बगैर पेपर लीक हुए हुई नहीं है। इस प्रकार की नौकरी बेचने वाली सरकार हमेशा-हमेशा के लिए इस राजस्थान से चली गई है।

इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में तुष्टिकरण की एक बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा। तुष्टिकरण का यह आलम है कि आपने हर पंचायत के अन्दर एक महात्मा गांधी

अंग्रेजी विद्यालय खोलने का किया था। आपने हमारे ही विद्यालयों में अंग्रेजी विद्यालय का बोर्ड लटका करके, उन्हीं अध्यापकों के द्वारा जिन्होंने खुद ही कभी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई नहीं की, हमारे स्टूडेंट्स का भाग्य खराब कर रहे थे। मेरे वहां पर होपालड़ी नाम की ग्राम पंचायत है। वह 5 हजार की जनसंख्या वाला गांव है। उस गांव के अन्दर वह विद्यालय ना खोलकर के लाल खां की ढाणी एक स्थान है, वहां अंग्रेजी विद्यालय खोल दिया।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): कौन जायेगा? कौन अपनी बेटी को उन घरों के बीच में भेजेगा? इस प्रकार के काम किये। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप इसकी जांच करवाइये। सभी जगह इसी तरह इन्होंने स्कूल खुलवाये हैं। इस प्रकार से तुष्टिकरण की स्थिति पैदा की है।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): आयुष्मान भारत के तहत नागरिकों को फ्री इलाज के लिए अभी-अभी बताया। कैंसर तक के इलाज के लिए, जहां अधिक संख्या में कैंसर रोगी हैं वहां पर भी आपने खुलवाया। यहां तक कि व्यक्तियों के उपचार की बात छोड़िये, पशुओं और गौ माता के स्वास्थ्य के बारे में भी सरकार चिंता कर रही है।

श्री सभापतिः समाप्त करिये। कृपया समाप्त करिये। श्रीमती इन्द्रा।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): पशुओं की चिकित्सा के लिये कॉल सेंटर्स ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया मेरी पार्टी के लोगों ने, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि राज्यपाल के अभिभाषण के वाद-विवाद पर मैं बोल रही हूं और पक्ष-विपक्ष को मैंने सुना भी है। लेकिन जो पक्ष के लोग हैं, श्रीचन्द कृपलानी जी बात कर रहे थे राइजिंग राजस्थान की। इनके अलावा राइजिंग राजस्थान की बहुत सारे लोगों ने बात की। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि राइजिंग राजस्थान है क्या, सब लोगों को समझ में आना चाहिए। राइजिंग राजस्थान के अन्दर यह भी आप लोगों को बता देना चाहिए कि +++ का कितनी फर्मों में टेंडर आप लोगों ने शामिल करके करवाया। यह बता दीजिये। यह रिकार्डली है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप प्रूफ दीजिये पहले ...(व्यवधान)... आप प्रूफ दीजिये पहले ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आप लोगों की तरफ से कोई आरोप लगता है तो ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बोलने से पहले आप प्रूफ दीजिये ...(व्यवधान)... निकालिये प्रूफ ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सब देख रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत कमेंट है

...(व्यवधान)...आप प्रूफ लाइये पहले।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज, प्लीज।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप प्रूफ लाइये ...(व्यवधान)... प्रूफ लाइये पहले ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): सबूत पेश करो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आसन को इंगित करके ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): पता लग जायेगा आपको धैर्य रखिये ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिये ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): पता लग जायेगा आपको किस-किस ने एमओयू किया है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): बैठिये, बैठिये ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं बोलने देंगे हम आपको ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): टाइम खराब मत करिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रूफ लाइये ...(व्यवधान)...पहले अपना प्रूफ लाइये ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या आडम्बर किया ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पहले प्रूफ लाइये ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मैं सारे प्रूफ दूंगी ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पहले प्रूफ लाइये ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। अगर ऐसा कोई शब्द हमारे इसमें आया है उसको अंकित ना करें। प्लीज, प्लीज, विराजिये ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): इनके +++ का नाम लेते ही आग लग जाती है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): प्रूफ सहित पेश करेंगे ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): सबूत पेश करो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आप बैठिये, आप सब के सब, आपके भी सबूत दूंगी ...(व्यवधान)...आपके भी दूंगी, सबके दूंगी, आप बैठिये। बैठिये आप, सबूत देंगे आपको ...(व्यवधान)...बैठिये आप, सबूत देंगे। सबूत लाऊं क्या अभी? अभी लाऊं बोलो?

श्री सभापति: ऐसा कोई शब्द आया है तो उसको अंकित ना करें।

Spp/rtm/05.02.2025/16.50/3d

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज बिराजिये। ..(भारी व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अभी लाऊं सबूत जाकर। माननीय सभापति महोदय, सबूत दूं तो पता लग जाएगा क्या होगा? ..(भारी व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज बिराजिये। ..(भारी व्यवधान)... बिराजिये। बिराजिये। प्लीज..(भारी व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): बैठो-बैठो, मंत्री पद नहीं जाएगा। बैठो। ..(भारी व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज बिराजिये। बिराजिये। ..(भारी व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): वफादारी करना ठीक है, पर इतनी भी नहीं। ..(भारी व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, ..(भारी व्यवधान)... आसन की तरफ देखकर अंकित करें और ऐसा शब्द ना बोलें जो मर्यादा से बाहर हो। ..(भारी व्यवधान)... प्लीज। ..(भारी व्यवधान)... बिराजिये। प्लीज, प्लीज विश्नोई जी। ..(भारी व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आप बैठो, सारे सबूत मिल जाएंगे।

श्री सभापतिः वाद-विवाद में ऐसा शब्द न बोलें जो मर्यादा से बाहर हो और आसन की ओर देखकर बात करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): ठीक है। सबूत सहित आएंगे। ..(भारी व्यवधान)... सबूत पेश करेंगे। मैंने कहा न, सबूत पेश करूंगी। ..(भारी व्यवधान)... आप चुप रहिए। ..(भारी व्यवधान)... यह जो आडम्बर किया है न आप लोगों ने राइजिंग राजस्थान का, उसकी सच्चाई सुन लो। ..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्या, आपका समय बीता जा रहा है।..(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): उसकी सच्चाई मैं आपको बताती हूं। जो आपने एम ओ यू किया उसमें आपने क्या शर्तें रखीं? किसी प्रकार का ..(व्यवधान)... आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को बोलने दो न। ..(व्यवधान)... अब देखिये, जो आडम्बर किया, दो-तीन दिन का जो आडम्बर किया और करोड़ों रुपये आपने खर्च किये, लेकिन एम.ओ.यू. क्या उसी दिन हुए, बाद में नहीं हुए, उसके बाद भी चलते रहे। क्या जरूरत थी प्रधान मंत्रीजी के आने की? क्या जरूरत थी यहां सब करवाने की? क्या जरूरत थी इवेंट करवाने की? लगातार चल रहे हैं। ..(व्यवधान)... आपके मतलब की बात है सुन लो। ..(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपसे पूछकर आयेंगे क्या प्रधान मंत्रीजी?

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अगर कोई रह गया होगा न ..(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): प्रधान मंत्रीजी को पूछकर आना पड़ेगा क्या? ..(व्यवधान)... नहीं, नहीं बोलने देंगे। ..(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): कोई रह गया हो न, वह एम.ओ.यू. कर सकता है अभी। आपको खुली छूट दे रखी है सरकार ने, यह ध्यान रखना। ..(व्यवधान)... बिना कोई डिटेल

बताये..(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं बोलने देंगे। प्रधान मंत्रीजी कैसे आ गये? ..(व्यवधान)... कैसे आ गये प्रधान मंत्रीजी?

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आप लोग सुनना नहीं चाहते क्या? सच्चाई नहीं सुनना चाहते क्या? आपके अन्दर इतनी भी औकात नहीं है सच्चाई सुनने की। बैठ जाइए और सच्चाई सुन लीजिए। सुन लीजिए अभी तो मैं आपकी परतें खोल रही हूं। ..(व्यवधान)... सच्चाई सुन लीजिए। बैठिये और सच्चाई सुनिए। ..(व्यवधान)... आप टाइम खराब मत करिए। यह आपकी पॉलिसी है टाइम खराब करने की। ..(व्यवधान)... टाइम खराब कर दो ताकि कुछ कह ही नहीं पाएंगे। ..(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: अंट-शंट कुछ भी बोले जा रहे हो। ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज सब माननीय सदस्य बैठिये। ..(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): उनको जमीन अलॉट करने का काम कर रहे हैं। ..(व्यवधान)... एम ओ यू तो साढ़े 11 हजार लोगों ने किया है। ..(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): राजस्थान के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। 35 लाख ..(व्यवधान)... राजस्थान के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ..(व्यवधान)...आपको तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान में एक गांव से आये हुए मुख्य मंत्री कैसे बन गये। 24 घंटे में से 20 घंटे मुख्य मंत्रीजी कैसे काम करते हैं। यह कांग्रेस को पचता नहीं है। यह राजस्थान राज्य के मुख्य मंत्रीजी की निष्ठा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ..(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सच्चाई होगी तो चाहे प्रधान मंत्री होगा तो उसके लिये भी बोलूंगी। ..(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): देश में राजस्थान को नंबर दो पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजस्थान आपके समय में अपराध में, बेरोजगारी में नंबर एक पर था। ..(व्यवधान)... आप विकास के मामले में नंबर वन और नंबर दो पर है। यह शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ..(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): प्रधान मंत्री हो चाहे मुख्य मंत्री, गलत होगा तो बोलूंगी। ..(व्यवधान)... आप पूरा सुनिए, बैठिये। आपको ठेका दे रखा है बोलने का। ..(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कांग्रेस के शासन में राजस्थान का आपने बेड़ा गर्क किया था। आपने बेड़ा गर्क किया कांग्रेस के समय में।

श्री सभापति: प्लीज, आसन पांवों पर खड़ा है। ..(व्यवधान)... प्लीज बैठिये। प्लीज आसन पांवों पर है। ..(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): 32 लाख करोड़ रुपये ..(व्यवधान)...मात्र 554 लोगों को लाभ देने का काम किया है। ..(व्यवधान)... 554 लोगों के लिये ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: गोदारा जी, प्लीज। ..(व्यवधान)... प्लीज, माननीय सदस्य, बिराजें। ऐसी

बात नहीं करें। ..(व्यवधान)... शांति से अपनी बात मर्यादा में रखकर कीजिए। आप शुरू करिए। ..(व्यवधान)... इन्द्राजी, आप शुरू करिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट का समय लूंगा। आप इजाजत फरमाएं। माननीय सभापति महोदय, जब भी प्रतिपक्ष की ओर से कोई बोलना शुरू होता है तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहते हैं। या तो हमको यह करना चाहिए ..(व्यवधान).. माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से बात बोल रहा हूं। या तो यह करना चाहिए कि संसदीय कार्य मंत्री हमको लिखकर देदे और हम उसका वाचन कर दें। प्रतिपक्ष इसलिए बैठा हुआ है कि वह अपने मन की बात कहेगा। ..(व्यवधान)... यह कभी नहीं संभव है। यह बर्दाश्त के नाकाबिल है। ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: बिराजिये प्लीज। ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह क्या तरीका हुआ जब भी कोई प्रतिपक्ष की तरफ से बोलने के लिये खड़ा होता है तो आप सबके सब एक साथ खड़े होते हैं। ..(व्यवधान)... आप भी नहीं बोल पाएंगे। अगर इस तरह का आचरण करेंगे तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। ..(व्यवधान)... बिलकुल गलत है यह।

श्री सभापति: प्लीज मंत्री महोदय। ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। प्रतिपक्ष का ..(व्यवधान)... आप इनकी हालत देखिए। ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज बिराजिये। ..(व्यवधान)... दोनों ही तरफ के दलों से मैंने आग्रह किया है ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष का कोई माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहता है तो अपने तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखेगा। असंसदीय हो तो आप उसे डिलीट करें। तथ्यों के विपरीत हों तो आप उसकी जांच मांग लें। लेकिन यह कतई संभव नहीं है कि जो कुछ माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमको सुबह लिखकर देंगे, हमारे प्रतिपक्ष की तरफ से जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहेगा तो माननीय संसदीय मंत्री हमको लिखित में भाषण देंगे और हम उसका वाचन करेंगे? प्रतिपक्ष के लोगों की यह जिम्मेदारी है और यदि यही आचरण तो, माननीय सभापति महोदय, यदि हम नहीं बोल पाये तो वह भी नहीं बोल पाएंगे। यह नहीं कि..(व्यवधान)... यह व्यवस्था का प्रश्न है। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह सदन नियमों से चलता है और मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस पवित्र सदन में आपको यहां राजस्थान की जनता ने एक-एक अमूल्य वोट देकर भेजा है। प्लीज दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से मैं यह आग्रह करता हूं कि इधर से कोई बोला तो टोका-टोकी नहीं करें और आप भी इधर से बोलें तो कोई भी माननीय सदस्य टोका-टोकी नहीं करें और जो भी बोलें वह मर्यादा में रहकर बात कहें। प्लीज माननीय सदस्य। ..(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत बहुत पुराने सदस्य हैं और बहुत अनुभवी भी हैं। आप आसन पर भी अक्सर बिराजते हैं और नियमों और प्रक्रिया के बारे में आपको सबसे ज्यादा जानकारी है। सदन में बोलने का अधिकार सबको है लेकिन निरकुंश कोई भी नहीं है, न तो सत्ता पक्ष है और न ही विपक्ष है। आप बिना किसी तथ्यों के बोलेंगे, आपको आरोप लगाना है तो आइए, हम चैलेंज करते हैं। आप नियमों में आइए, आरोप लगाइए, पर ऐसे बकवास नहीं करने देंगे हम। आप जो मर्जी आवे वह बोलते जाओगे क्या? नहीं बोलने देंगे हम। ..(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आप बोलें तो बकवास नहीं है। आप लोग कांग्रेस वालों को को भ्रष्टाचारी बताएं तो बकवास नहीं है और आप लोगों पर आरोप लगाएं तो बकवास है। ..(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): किसी भी वक्त कुछ भी बोल देते हो। आप आरोप लगाओ, प्रक्रिया से आओ, नोटिस देकर आओ। आप आरोप लगाओ, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बोलने देंगे आपको। नहीं, कुछ भी मर्जी आयेगा जो बोल देंगे। ..(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): यह सच्चाई है, सच्चाई, ध्यान रखना। ..(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कैसे बोल रहे हो आप?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): वेल में खड़े-खड़े क्या नारे लगा रहे थे, आपको पता नहीं क्या? और आप कितने दूध के धुले हो, हमको पता नहीं है क्या? ..(व्यवधान)...आप कितने दूध के धुले हो, हमको पता नहीं है क्या? इधर बैठते थे तब क्या कर रहे थे, हमको पता नहीं है क्या? ..(व्यवधान)... ऐसे बेलगाम नहीं बोलने देंगे।

श्री सभापति: प्लीज माननीय सदस्य, बिराजें। ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यदि कोई चीज तथ्यों के विपरीत है तो आप माननीय सदस्य को वार्निंग करें, लेकिन यह कैसे बर्दाश्त होगा कि जो कुछ माननीय सदस्य बोल रहा है, उसके लिये क्या आसन सक्षम नहीं है? आसन उसके लिये सक्षम है। यदि कोई माननीय सदस्य विपरीत आचरण कर रहा है। ..(व्यवधान)...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आसन निर्देशित करें, यही हम कहना चाह रहे हैं आपसे। आसन निर्देशित करे, यह संभव है। कोई माननीय सदस्य आपको लगता है कि असंसदीय बोल रहा है, तथ्यों के विपरीत बोल रहा है तो आसन इस बात के लिये सक्षम हैं। लेकिन यह कैसे बर्दाश्त होगा कि सामने से सारे सदस्य एक साथ खड़े हो जाएं।

श्री सभापति: मैं दोनों ही दलों से यही आग्रह कर रहा हूं। ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): उनसे कहिए, हम तो निर्देशित ही हैं। ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: दोनों ही तरफ के माननीय सदस्यों से कह रहा हूं। ..(व्यवधान)... प्लीज बिराजें। इन्द्रा जी, आप बोलें। ..(व्यवधान)...

jyg/rtm/05.02.25/17.00/3e

मैं दोनों से ही कह रहा हूं। ...(व्यवधान)... प्लीज इंदिराजी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मुख्य मंत्री को पावर है, संसदीय कार्य मंत्री को पावर है, वो बोलें बीच में। बाकी सारे लोग क्यों खड़े होते हैं? कोई भी बात है वो बतायें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इंदिराजी। ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, राइजिंग राजस्थान का जो इवेंट हुआ, उसमें मैं यह कहना चाह रही थी कि जो इवेंट हुआ, उसके बाद भी वो एमओयू लगातार चल रहे हैं, कोई रह गया हो तो वो कर सकता है। मैं यह कहना चाह रही थी कि यह अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है। उसके अलावा 37 लाख करोड़ का साढ़े ग्यारह हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 32 लाख करोड़ रुपये के एमओयू केवल 554 लोगों का हुआ तो सरकार का फोकस है कि 554 लोगों पर ही फोकस डाला जाये। न कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इनके पास में, कोई बनायी ही नहीं ऐसी और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि राज निवेश पोर्टल पर जब ये राइजिंग राजस्थान इवेंट हुआ, उससे पहले से चालू था, उससे पहले जो रोजगार देने का डाटा था, वो 25 लाख लोगों का आ गया। 25 करोड़ लोगों का, जबकि राजस्थान की जनसंख्या तो 8 करोड़ ही है। ...(व्यवधान)... सुनिये आप, सुनिये। बात सुनिये। ...(व्यवधान)... मैं यह बात कहना चाहती हूं कि 8 करोड़ की आबादी है, ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा भाषण कर रही हूं, बोल रही हूं, बीच में न इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए।

श्री सभापति: प्लीज। ...(व्यवधान)... आप बोलें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): 8 करोड़ जनसंख्या पर 25 करोड़ लोगों को रोजगार देना बता दिया। अब इन्होंने देखा कि यह तो बहुत बड़ा मामला हो जायेगा, बात खराब हो जायेगी तो उसको डिलिट कर दिया, उसको डिलिट कर दिया, आज वो नहीं दिख रहा है। लेकिन उस

समय वो इस टाइम से दर्शा रहा था।

अब सौर ऊर्जा वाले प्लांट आप लोगों ने लगाने का विचार किया और जमीन अलॉट करने का विचार किया है, उनसे किसी प्रकार की आप कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, वो तो हम बाद में बात और कर लेंगे। अभी तो चल रहा है आपका, उसके बाद देखते हैं। कई सारी हमारी उद्योग लगाने की छोटी-छोटी योजनाएं थीं, जो हमने चालू की थी। आपके प्रधान मंत्रीजी आते हैं चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के, वो कहते हैं, पिछली सरकार की कोई योजना बंद नहीं की जायेगी, लेकिन अपने वायदे पर वो ही खरे नहीं उतरते हैं जो सारी की सारी योजनाएं राजस्थान सरकार बंद कर देती है।

आप बात करते हो बाबा साहब की, अभी अभिभाषण में बाबा साहब को याद किया, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को यह पता नहीं है, पूरा देश जानता है इस बात को, देश के गृह मंत्री संसद में अपमान करते हैं उनका, मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। फिर आप शर्म से वापस बाबा साहब को याद करते हैं। बाबा साहब का मजाक बनाया जाता है। आप कहते हैं, ये देश 2014 में आजाद हुआ। आजादी को आप लोग मानते नहीं हैं।

श्री सभापति: प्लीज सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): एक मिनट, इंद्राजी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं विपक्ष से और चुनौती दे रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के विषय पर इस सदन में पूरे एक दिन की चर्चा रख लीजिये, किसने क्या किया हम बता देंगे आपको। आपने अपमान किया बाबा साहब का, कांग्रेस ने अपमान किया हमेशा, हमेशा अपमान किया है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): 2014 में आप आजादी बताते हैं। आपको आजादी का पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एक अंगुली कटायी नहीं आजादी के आंदोलन में तो आप लोगों को आजादी का पता नहीं है। ...(व्यवधान)... आप महात्मा गांधी की बात करते हैं, जो लोग गोडसे की पूजा करते हैं वो लोग क्या महात्मा गांधी की बात करते हैं। अभिभाषण में महात्मा गांधी की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिये, ये क्या कर रहे हैं, महाकुम्भ, महाकुम्भ, महाकुम्भ। अपनी-अपनी आस्था होती है। महाकुम्भ में कोई नहाने जाये, कोई नहीं जाये, जो भी है, सारी चीजें लेकिन क्या हुआ? आपके योगी सरकार ने बोला कि हम 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं वैसे आयेंगे 6 करोड़। लेकिन वो व्यवस्था का क्या हुआ? साधु-संत मौनी अमावस्या पर नहा ही नहीं पाये, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। ऐसी अव्यवस्थाएं हमें नहीं चाहिए, हम नहीं नहायेंगे। आगे दूसरा अमृत स्नान हुआ, उसके अन्दर 2.33 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो इतना घट गया क्या डाटा? आपकी व्यवस्थाएं कितनी थी? यह आप लोगों पर पूरा देश जान रहा है, इन चीजों को। वहां पर कोई जाकर आ रहा है, जा तो शौक-शौक से रहा है, लेकिन जो आ रहा है वापस वो सोशल मीडिया के थ्रू कह रहा है कि बहुत गंदगी है, शौच कर रहे हैं बाहर लोग, बहुत अव्यवस्था है, वहां कोई जाना मत, अपनी-अपनी

राय दे रहे हैं सोशल मीडिया पर जो कि मैंने देखा बहुत उसके अन्दर। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, आगे आप सुनिये। आगे ये बात करते हैं स्वास्थ्य की, दुर्घटना बीमा, दस लाख रुपये हमने किया। हमारी सरकार ने किया, जिनका एक्सीडेंट हो जाता था, मौतें घर में हो जाती थी, उनके लिए बहुत बड़ा सम्बल था, उसको आप लोगों ने बंद कर दिया। आपको राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। यह कहावत है, कहते हैं कि बिल्ली के भाग से छींका टूट जाता है, बाकी ऐसा था नहीं माहौल, पर हो गया, जो भी है। लेकिन आगे आप लोगों से राजस्थान की जनता इतना धाप चुकी है एक साल के अन्दर, उसका जवाब आप लोगों को देगी।

बालिका शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो अभिभाषण में राज्यपालजी ने भी बोला। अभिभाषण में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आपने बालिका विद्यालय मर्ज कर दिये। बालिकाएं विरोध कर रही हैं वो असत्य है क्या? टीवी चैनल अख़बार यह बता रहे हैं कि बालिकाएं रोड पर आकर विरोध कर रही हैं कि हमारा विद्यालय बंद कर दिया, मर्ज कर दिया, जो भी कर दिया, ये गुमराह कैसे करते हैं, कैसे हैं ये लोग, बार-बार कहते हैं कि बंद नहीं किया। बंद किया, मर्ज किया, एक ही बात है। हमने 500 बालिकाओं पर कॉलेज खोलने का वादा किया और हमने खोले। माननीय गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी कि बालिका शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी दो कॉलेज खोले। आप लोगों ने क्या किया, आप एक साल के अन्दर ढूंढते फिरे, आप ग्राम पंचायत तक के प्रधान मंत्रीजी से उद्घाटन करवा रहे हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाकर कोशिश करते हैं कि उद्घाटन कर दें, लेकिन मैं भी एडवांस ही कर देती हूं सबके उद्घाटन, गांव वाले बुला लेते हैं और मैं कर आती हूं। आप लोगों को मौका नहीं दे रही हूं मैं।

आप देखिये, इंग्लिश मीडियम विद्यालय आपने बंद कर दिये, और यहां शिक्षा मंत्री बोल दे, छोरी ने बोल दिया, एक लड़की ने, टेंथ में पढ़ रही हूं। यह शर्म आने की बात है कि टेंथ और दसवीं का फर्क नहीं जानते हैं ये, इनको शर्म आती है इंग्लिश बोलने पर इसलिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय इन्होंने बंद किये।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अंग्रेजी स्कूल खोले ही नहीं कांग्रेस ने।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): इनको यह लगता है कि कोई बालक गांव का इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। आज बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है। शिक्षा मंत्री द्वारा बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अपना जवाब दे देंगे, वो सब देख रहे हैं, सबको पता है। ...(व्यवधान)... माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, विराजिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): करना यह चाहिये था, इंग्लिश मीडियम विद्यालय हमारी सरकार ने खोले, आप लोगों को यह करना चाहिए था अगर आप लोगों के अन्दर इंसानियत होती, आपके अन्दर राजस्थान के ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए थोड़ी-सी दया होती, आप लोग इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करते और उनको व्यवस्था देते न कि

उनको बंद करते। आप देखिये, बंद करने का और नाम बदलने का, दो ही काम है आप लोगों के पास और कुछ किया नहीं आप लोगों ने।

ऐसे ही विकसित राजस्थान की कल्पना आप लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, हमने तो जो किया वो इतिहास में आज तक कर नहीं सकता है। आपकी डबल इंजन की सरकार बेरोजगारों को समय पर भत्ता नहीं दे रही है, काफी महीने हो गये, एससी-एसटी के बच्चों को स्कॉलरशिप छह साल से नहीं आ रही है। ...(व्यवधान)... समाज कल्याण मंत्री बता दें। क्या हो रहा है?

श्री सभापति: छह साल? ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, एससी के बालकों की छह साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, इन्द्राजी।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, पांच साल हमारी सरकार थी, केन्द्र सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया, अब तो सरकार आपकी है, ...(व्यवधान)... अब कहां प्रोब्लम है?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, हमारी माननीय सदस्य कह रही हैं कि छह साल से नहीं मिल रही है, इनमें से पांच साल तो आपकी सरकार रही है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): पेपर लीक, पेपर लीक करते रहे पानी पी पीकर आप लोग, सत्ता में आ गये पेपर लीक का बहाना करके आज तो आपसे छठी, सातवीं, दसवीं के पेपर नहीं बच रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यहां इतना असत्य मत बोलिये कि बाहर आपको सफाई देना पड़े। ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आप लोगों ने हिम्मत नहीं है प्रतियोगी परीक्षा कराने की, करा कर देखिये, पता चलेगा आपको, यहां यह अलग बात है कि आप अखबारों में नहीं छपने देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आप कोशिश करोगे उनको रोकने की, लेकिन पेपर लीक रुक नहीं रहा है आपसे। जितनी भी परीक्षाएं करायीं आपने, सबके पेपर लीक हुए हैं, और यह रिकॉर्डली आपको बता देंगे चिंता मत करो। ...(व्यवधान)... आप देखिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मेरा आधा समय तो यूं ही चला गया।

माननीय सभापति महोदय, आरपीएससी भंग करने की बात थी, आपके मंत्रीजी किरोड़ीलालजी को तो सम्भाल लो, वो एसआई भर्ती रद्द करने की बात करते-करते बूढे हो

गये हैं। आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो। वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान कर रहे हैं भाजपा वाले, मैं भाजपा सरकार का मंत्री हूं।

श्री सभापतिः सुश्री नौक्षम।

MLS/RTM/05.02.2025/17:10/3f

सुश्री नौक्षम (कामां):

इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उलफतें,
इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उलफतें,
कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं है।
आज मैं हूं जहां, कल कोई और था,
आज मैं हूं जहां, कल कोई और था,
ये भी इक दौर है और वो भी एक दौर था।।

माननीय सभापति महोदय, एक नयी सदस्या होने के नाते महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने विचार प्रस्तुत करने का जो आपने मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। 40-45 सालों से जिस विधान सभा में कांग्रेस की हुकूमत थी और जिसे मुंहतोड़ जवाब देने का काम मेरे कामां विधान सभा क्षेत्र की पूजनीय जनता ने, ब्रज-मेवात क्षेत्र की अवाम ने किया है, उसे भी इस मंच से आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, धन्यवाद करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत कुछ सुन रहे हैं। हमारे पक्ष के साथीगण को भी और हमारे विपक्ष के सम्मानित साथीगण को भी। एक-एक शब्द, एक-एक लफ्ज यहां पर चिह्नित किया जाता है। तभी हम और आप यहां के दिग्गज साथी, जैसे स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत जी को याद करते हैं। आज भी उनका एक-एक लफ्ज इस सदन के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। मैं डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब को याद करना चाहती हूं। उनके द्वारा रचित संविधान को 75वां साल शुरू हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जब संविधान की बात आती है, मेरे साथीगण देखते होंगे, अभी पीछे लोक सभा का चुनाव हुआ, विधान सभा का चुनाव हुआ, विपक्ष के एक साथीगण संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। जब भी जाते हैं, बड़े सदन में चले जाइये, देश की सबसे बड़ी पंचायत में चले जाइये या प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में चले जाइये, संविधान की कॉपी को साथ रखते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, किसी दिन समय निकालकर गहनता से पढ़ लीजिये, देखिये उसमें क्या लिखा है। संविधान में जितने अमेंडमेंट्स पिछले 75 सालों में कांग्रेस सरकार ने किये हैं, किसी ने नहीं किये। आप लोग तो हमें गुमराह करते रहे। लोक सभा का चुनाव आया, विधान सभा का चुनाव आया कि ये तो आरक्षण हटा रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, तब्दीली कर रहे हैं।

जिन्होंने देश के टुकड़े-टुकड़े कर दिये, जिन्होंने देश को तकसीम कर दिया, वे भारत जोड़ो

यात्रा की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिये। अभी कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। अभी हम भी नये सदस्य होने के नाते बहुत गहनता से सुनते हैं। हमसे कोई गलती हो जाये, सत्तापक्ष भी और विपक्ष भी, हमारे लफ्जों में कोई हेर-फेर हो जाये, कोई गलती हो जाये तो उसकी हम माजरत चाहते हैं। आपके साथीगण जिस तरीके से प्रदेश के मुख्य मंत्री पर आरोप लगा रहे थे, मैं उसका उल्लंघन करते हुए माननीय सभापति जी से निवेदन करती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये ताकि कोई भी सदस्य ऐसी बात न रख सके।

यह आपका निजी सदन नहीं है। यह परम्पराओं से चलता है, यह नियमों से चलता है, यह तौर-तरीकों से चलता है। उसूलन, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, गरिमामय कुर्सी पर बैठे हैं, उसे सारा सदन सलाम करता है, पर आप अपने शब्दों की वाणी से जिस तरीके से गुमराह करते हैं, मुझे लगता है, आपको एक विधायक दल की बैठक अलग करनी चाहिये। सिर्फ मैनरिज्म्स पर करनी चाहिये, सिर्फ जैस्चर्स पर करनी चाहिये। एक सैशन आप भी लगाइये। हमारे यहां तो प्रशिक्षण का बहुत बड़ा केन्द्र है। प्रशिक्षण होते रहते हैं। एक प्रशिक्षण आप भी संविधान पर रखिये तो पता चलेगा कि संविधान में अंकित क्या है।

जब महामहिम राज्यपाल जी बोल रहे थे, अभिभाषण दे रहे थे, Constitution of India declares it, जो वे स्टेट के पूरे वला वली हैं, हैड हैं, he exercises the same powers as the President of the Country. If you are in a position, कि राज्यपाल अभिभाषण दे रहे हैं और आपके साथीगण उठ-उठकर उन्हें टोक रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिन्दगी की बात इस सदन में देखने को नहीं मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि जो कांग्रेस सरकार का एक मैनिफेस्टो था, मेरी कम उम्र है तो कम तजुरबा भी है, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, इसका अर्थ जनता का, हम लोकतंत्र की मूल भावना को अगर लेकर चलेंगे, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। जिस प्रकार से ''पांच साल बेमिसाल'' में हर विधान सभा क्षेत्र में एक मुख्य मंत्री आपने बैठाया, आपने जनता को किस प्रकार से लूटा, किस प्रकार से गुमराह किया और लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या की, इसका करारा जवाब हमने तो आपको दे ही दिया था। जनता ने आपको दिया है।

अभी 90 दिन पहले एक उप चुनाव हुआ है। हमारा तो कुछ नहीं था, आप ही का था। हमने क्या ले लिया? हमने तो वही लिया कि 3-4 जगह ऐसी हैं, जो आपके थे, वहां आपकी जमानत जब्त हुई है, हमारा कुछ नहीं था। इन चीजों पर आपकी जवाबदेही होनी चाहिये। आपकी जमानतें वहां जब्त हुईं, जहां आपके अपने आदमी थे। ...(व्यवधान)... समय बतायेगा। समय और जनता सबकी भाग्यवान है, हमारी अकेले की नहीं।

सभापति महोदय, दूसरा, संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही होगी। आपसे जनता जवाब मांगती रही और आपके जो नेता हैं, पांच सितारा होटल में बैठकर डील करते रहे। आप यहां पर आरोप लगा रहे हैं, पिछले पांच सालों के कागज और अख़बार निकालकर देखिये, बजरी माफिया, लैंड माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया, सब के सब के ताल्लुकात अन्दरूनी और

बाहरी रूप से आपके यहां से निकले हैं। ...(व्यवधान)...

किरोड़ी लाल जी हमारे बहुत ही प्रिय साथी हैं, सम्मानित साथी हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत और कद्दावर नेता आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। ...(व्यवधान)... यह इस प्रदेश का सौभाग्य है कि भजन लाल शर्मा जैसा ईमानदार, कर्मशील और काम करने वाला मुख्य मंत्री मिला है, जो अपनी जनता को नहीं, अपने विधायकों को नहीं, विपक्ष के विधायकों को भी जब समय मांगते हैं, तब मिलता है। आपने वह समय देखा है कि आपका आपसी तालमेल बिगड़ा रहता था, आपको यह पता नहीं था, किसके द्वार पर जाकर क्या कहना है, कहां जाकर क्या मांगना है, किनसे जाकर कैसे टिकट मांगेंगे। आप तो पांच के पांच साल आपसी तालमेल को बिगाड़ने में लगे रहे।

यह डबल इंजन की सरकार है। यह एकजुट होकर चलने की सरकार है। यह विकास की सरकार है। यह प्रगति की सरकार है। आपकी तरह आपसी तालमेल बिगाड़ने वाली सरकार नहीं है। हमारे मंत्री गण बैठे हैं। किसी भी मंत्री पर एक रुपये का आरोप नहीं लगा सकते आप। एक साल की जो पूरी हमारी भागीदारी है, वह यह है। आपने बोला ट्रांसफर खोल दिये, आपके एक मजबूत बड़े साथी कह रहे थे, बहुत अच्छा किया जी, ट्रांसफर खोल दिये। यह वह सरकार है कि आपके ही लगाये अधिकारियों को, राज कैसे बदलता है और भ्रष्टाचार छोड़कर जनता के लिए कैसे काम करना है, वह इस सरकार ने सिखाया है। यह कोई और सरकार नहीं सिखा सकती थी।

महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद चर्चाएं आती रहीं कि विजनलेस है, मार्ग नहीं है, किसी तरीके का आगे डिटेल्ड परपज नहीं है। एक साल का जो मार्गदर्शन होता है, हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपके पास पांच साल थे, आप राजस्थान को किसी भी प्रकार से कैसे भी डवलप कर सकते थे, आपने उस पर गौर नहीं किया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आपका जो एक स्टेट का न्यूट्रल हैड है, पहले तो हमारे राज्यपाल नहीं हैं वे, आप सभी के राज्यपाल हैं, 200 के 200 विधायकों के राज्यपाल हैं, किसी एक पार्टी के, किसी एक विधायक के राज्यपाल नहीं हैं, आप सभी के राज्यपाल हैं। आप उसे इन्क्लूजन में लेते, आप कुछ अपनी जब आपके पास समय था, उस हिसाब से उसको लेते, पर नहीं।

राइजिंग राजस्थान का मुद्दा चल रहा है। मैं पहले मुख्य मंत्री जी का बहुत अभार प्रकट करना चाहती हूं। ये ग्लोबल समिट तो होते ही हैं। हर सरकार करती है। आपने भी किये हैं। आपने किस प्रकार की इंडस्ट्रीज, उद्योग, लघु उद्योग, स्किल डवलपमेंट इंडस्ट्रीज, किस तरह की इंडस्ट्रीज आपने लगायी हैं, उन सभी को हमने देखा है।

mkd/rtm/05.02.2025/17:20/3g

पहले साल में, 365 दिन के अन्दर हर जिले में और पूरे प्रदेश में राइजिंग राजस्थान का सक्सेसफुल इवेंट करने के लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

सुश्री नौक्षम (कामां): सभापति महोदय, इनका स्वास्थ्य, किसान, गरीब कल्याण, दलित, महिला, भ्रष्टाचार किसी से कोई सम्बन्ध नहीं था। जिस तरीके से महिलाओं के साथ दरिंदगी हमने देखी है, जो कुशासन हमने देखा है, ये ई-गवर्नेंस की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ती हुईं हमने कांग्रेस शासन में देखी हैं, उसका एक नुमाइंदा मैं आपका बताना चाहती हूं। एक और गम्भीर बीमारी से आप और हम पीड़ित हैं, उसको साइबर क्राइम कहते हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये। श्री घनश्याम जी मेहर।

सुश्री नौक्षम (कामां): उसका पूरे देश का अड्डा कामां विधान सभा क्षेत्र को बनाकर, वहां पर साइबर क्राइम को इन्हीं की साथियों ने प्रमोट किया और साइबर क्राइम की जितनी गतिविधियां थीं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): पहली बार निर्वाचित होकर आई हैं, एक बिलकुल युवा विधायक हैं, इतनी बढ़िया तरीके से बोल रही हैं, दो मिनट और बोलने दीजिये, हमारी पार्टी का समय कम कर दीजियेगा भले।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, माननीय सभापति, पदासीन)

सुश्री नौक्षम (कामां): सभापति जी, हम साइबर क्राइम से पीड़ित हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने साइबर क्राइम की जो गतिविधियां, जिससे पूरा देश जूझ रहा था, कामां विधान सभा क्षेत्र, झुझेडा से लेकर पहाड़ी तक, उसको 70 परसेंट रोककर आम जनता को एक विश्वास दिलाया है कि ऐसा आगे नहीं होगा।

साइबर क्राइम का अड्डा यह विधान सभा क्षेत्र बन चुका था, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। गौ हत्या और गोकशी के जो मुकदमे दर्ज नहीं होने देती थी आपकी सरकार, आपकी सरकार यह सोचती थी कि किस प्रकार से यह जीव हत्या हो रही है, पशु हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, उसको दर्ज नहीं होने देती, उसमें 70 परसेंट कटौती लाकर मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त आरोपियों को गिरफ्तार करके एक ऐसा नुमाइंदा इस प्रदेश के लिए पेश किया, जिससे सुखद और प्रगतिशील राजस्थान की हम उम्मीद कर सकते हैं।

मन्दिर माफिया, ब्रज क्षेत्र सबसे ज्यादा मन्दिरों के लिए जाना जाता है। श्रीकृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली के लिए जाना जाता है। वहां पर आपके मन्दिर माफियाओं को नगरपालिकाओं द्वारा अवैध पट्टे दिये जाकर उनकी अवैध रूप से रजिस्ट्रियां हो रही थीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान में लेकर ऐसे मन्दिरों की जमीनों पर जो अतिक्रमण हो रहे थे, उसको रोका है और जवाब दिया है कि पिछली जितनी भी रजिस्ट्रियां कांग्रेस के टाइम में अवैध रूप से करोड़ों अरबों रुपये की हुई हैं, उनको लिया जाये और उनको निरस्त किया जाये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात रखना चाहती हूं, हमारी संस्कृति में और हिन्दुस्तान में, हर मजहब और हर धर्म में गऊ का बहुत बड़ा दर्जा माना जाता है। गौ हत्या के बहुत सारे केस न केवल हमारी साइड है, बल्कि पूरे राजस्थान में देखे जाते हैं। इसके लिए

एक नियम, गौ हत्या को रोकने के लिए एक नियम लाना चाहिए, ताकि हम जीव हत्या से बचकर यह पूरा सन्देश दे सके कि यह किसी एक मजहब का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक जात का नहीं, एक-एक नागरिक का है। मुझे लगता है इस सदन में बैठे हमारी साथी, इसके साथ समर्थन करेंगे, आपने मुझे इतना बोलने का समय दिया, आप सभी का धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय राजस्थान। बोल गिरिराज महाराज की जय।

श्री सभापतिः श्री घनश्याम, प्रारम्भ करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, आपका और मेरी पार्टी के नेताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़वाया गया है, उसमें 168 पैरा हैं। उसमें एक बहुत ही दुखद बात है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई उल्लेख नहीं है। इस बात से यह साबित होता है कि राजस्थान की सरकार एससी, एसटी के लोगों से कितनी नफरत करती है, ईर्ष्या करती है। माननीय सभापति महोदय, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापतिः प्लीज, शान्ति रखें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पेपरलीक को लेकर बहुत ढिंढोरा पीटा गया और पेपर लीक का दुष्प्रचार करके आप सत्ता में आये पर आज आपको 14 महीने हो गये, 14 महीने में आपने कोई नौकरी नहीं लगाई। जो हमारी सरकार ने नौकरियां दीं, उन्हीं से लोगों को गुमराह करके यह साबित करना चाहते हो कि हमने 68 हजार, 62 हजार नौकरियां लगाई। आप लाखों-लाखों नौकरियां लगाने की बात करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि आप इंग्लिश स्कूलों को बन्द कर रहे हैं। आप प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, अस्पतालों का, स्कूलों का, सब चीजों को आप प्राइवेट में दे रहे हैं तो आप उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रदेश की जनता इन सब बातों को देख रही है।

माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो आपकी माध्यमिक शिक्षा की अर्द्धवार्षिक परीक्षा थी, वह परीक्षा आप नहीं करवा पाये, वह पेपर आपको तीन बार बदलना पडा। यह साबित करता है कि आप माध्यमिक शिक्षा की अर्द्धवार्षिक परीक्षा नहीं करवा सकते तो आप और परीक्षा तो क्या करवायेंगे। आपको पता लगेगा जब प्रदेश में आप नौकरियां देंगे और अभी भी आरएएस के पेपर की क्या हालत हुई तो प्रदेश की जनता सब देख रही है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि इस तरह की भ्रान्ति प्रदेश में नहीं फैलाई जावे और जो करना है। यह राजस्थान की जनता आपको और हमको चुनकर भेजती है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है और जनता को धोखा नहीं दिया जाये, जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये। आज 14 महीने में लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है और जैसे हालात आपने प्रदेश में पैदा किये हैं, वे सब अब 14 महीने में पता लगने लगे हैं।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अर्द्धसरकारी सम्पत्तियों को निजी हाथों में बेचने व पूंजीवाद को बढ़ावा देना का काम कर रही है। इस बात से साबित होता है कि राइजिंग राजस्थान का भी आपने बड़ा भारी ढिंढ़ोरा इस प्रदेश में पीटा, पर राइजिंग राजस्थान में आप 35 लाख करोड़ के एमओयू की बात करते हैं, जिसमें से 28 लाख करोड़ तो सोलर पर ही देना है, जब 28 लाख करोड़ दिया तो उसमें 7 लाख करोड़ ही बाकी रहे तो वो कौन-कौन सी कम्पनियों को, किन-किन को किया है, राजस्थान की जनता भी इस चीज को जानना चाहती है। सोलर को तो हम प्रदेश की अमूल्य भूमि है, उसको कम्पनियों को फ्री में दे रहे हैं तो इस बात से भी जनता को पता लग रहा है कि यह सरकार क्या करने जा रही है और 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़, उसमें 28 लाख करोड़ तो सोलर पर ही इंवेस्टमेंट हो रहा है तो सोलर को जो हम जमीन दे रहे हैं, उसका तो एक रुपया ले नहीं रहे हैं तो इस तरह से हम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उद्योगपतियों को सरकार ज्यादा बढ़ावा दे रही है। यह बहुत चिन्ता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी गलती नीतियों से आज डॉलर की जो स्थिति है, वह 87 रुपये पहुंच गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मोदी जी कहते थे कि रुपया पतला होता जा रहा है, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। इस बात को समझना चाहिए कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर होती जा रही है। इस बात पर आप लोग भी ध्यान दें।

पक्ष-विपक्ष दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, हम सबको साथ मिलकर इस देश का, इस प्रदेश का विकास करना चाहिए, लेकिन जिस तरह का आपका कुप्रबन्धन हो रहा है, उसके कारण जनता भुगत रही है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से हमारी जीडीपी बढ़ाई थी, उस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी और किसानों जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

Bhs/Rtm/05.02.25/17.30/3h

हमने घरेलू कृषि उपयोगों के लिये बिजली के बिलों में जनता को सौ यूनिट फ्री की आज आपने उसमें एक भी आदमी को प्रदेश में कोई और जोड़ने का काम नहीं किया और उसको आप खतम करना चाहते हैं तो आज प्रदेश की जनता यह भी देख रही है कि बिजली के जो हालात पिछले एक साल में रहे हैं और जो बिजली लोगों को नहीं मिली वह ऐसी स्थिति है कि तीन-तीन घंटे से ज्यादा बिजली किसानों को नहीं मिली। किसान इतने परेशान रहे इस कार्यकाल में जो पहले कभी सत्तर साल के इतिहास में नहीं रहे। मैं आपको सही बता रहा हूं मैं किसान का ही बेटा हूं और मैं किसान, गांव, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। बिजली में किसानों की जो हालात रही है तीन घंटे से ज्यादा बिजली किसानों को नहीं मिल पायी और पिछले

साल गर्मियों में तो जो हालात जनता के रहे वो कभी सत्तर साल में नहीं रहे। लोग गर्मियों में बाहर बैठे रहते थे। बच्चे परेशान होते थे, महिलाएं परेशान होती थी तो आप लोगों को बिजली पर विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, सरकार अभी इसको प्राइवेट को देना चाह रही है तो प्राइवेट से तो आम जनता को और किसानों को और ज्यादा नुकसान होगा। किसानों को, ग्रामीण लोगों को परेशान किया जायेगा, प्राइवेट लोग किस तरह की हठधर्मी करते हैं इससे लोगों को बहुत परेशानी आने वाली है तो आप सभी डिपार्टमेंटों को प्राइवेट सेक्टर को नहीं देकर सरकारी उपक्रमों का ध्यान रखें। प्राइवेट आदमी की कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती। सरकारी आदमी चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वह सरकार से डरता है और प्राइवेट आदमी नहीं डरता।

सभापति महोदय, आज स्कूलों की स्थिति देख लो। स्कूलों में जो अभी कल-परसों मेरा एक तारांकित प्रश्न था उसकी भी अब प्रदेश में चर्चा है कि लोगों को जो फ्री शिक्षा दी जाती है वह बिलकुल खानापूर्ति हो गई। प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, घरेलू कनेक्शन, कषि कनेक्शनों के जो हालात आप कर रहे हैं इस पर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, आज हाशिये पर खड़े वर्ग के जो लोग हैं, आज हमने उनके लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का प्रबन्ध किया था और गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की वर्तमान सरकार की सामन्ती सोच से गरीबों का अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना रास नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूल और पूंजीवादियों को बढ़ाया दिया जा रहा है। नये सृजन तो दूर की बात है चालू विद्यालयों को भी बन्द किया जा रहा है। अगर इस तरह से स्कूलों को बन्द करेंगे तो आम गरीब किसान को इस बात से भारी नुकसान होगा। एम.एल.ए., एम.पी., मिनिस्टर, आई.ए.एस., आई.पी.एस. के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में ग्रामीण गरीब का बच्चा पढ़ता है और अगर गरीब के बच्चे को आप शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं तो इस बात से यह साबित होता है कि हम इस प्रदेश को वापस गरीबी में या फिर अशिक्षा में लाना चाहते हैं। अगर आप सही मायने में गरीब के बच्चों के प्रति आपकी सहानुभूति है तो आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को वापस चालू करें, उनमें अध्यापक लगायें और गरीब के बच्चे का भी अधिकार है उसका भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना है, उसको पूरा होने दें, उसको नहीं रोकें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण समस्या है तो वह है पानी की। आज पानी चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, पूरे प्रदेश में पानी की बड़ी समस्या है। जल जीवन मिशन में बड़ी वह हुई है, टंकियां बन गईं, लाइनें डल गईं, पाइप लाइन डल गई, कनेक्शन हो गये पर एक बून्द पानी उनमें नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में हमको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जल जीवन मिशन, आज विधायक कोष से भी हम ट्यूबवैल खुदवा देते हैं,

कोई गांव में भारी समस्या है तो उसका कोई प्रबन्ध करने वाला नहीं है, उसका कोई बिजली कनेक्शन देने वाला नहीं है, उसके बिजली के पैसे जमा कराने की स्थिति में नहीं है तो आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उस ट्यूबवैल को पी.एच.ई.डी. को दिया जाये और जल जीवन मिशन में भी कार्य हुए हैं उनको भी आप पी.एच.ई.डी. को हैंडओवर करें। अगर पी.एच.ई.डी. से बात करते हैं तो कहते हैं जल जीवन मिशन वालों का काम है और वो कहते हैं चम्बल वालों का काम है, चम्बल वाले कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है पी.एच.ई.डी. वालों की जिम्मेदारी है तो इस तरह की एक भ्रान्ति है उससे जनता को नुकसान हो रहा है और लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि जिस तरह से वैक्सीन की जो बात है वैक्सीन से पूरे प्रदेश में...।

श्री सभापति: विराजिये। श्री मनोज कुमार। आपका समय है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): एक सेकंड। हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं, आज नये-नये बच्चों में इस तरह के हार्ट अटैक आ रहे हैं रोज गांवों में सुनने को मिल रहा है और जो हमारी नयी जेनरेशन आ रही है उस नयी जनरेशन में भी इस तरह की बीमारी पैदा हो रही है तो यह वैक्सीन का असर है इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री सभापति: सरकार का पूरा ध्यान है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नकली वैक्सीन लगने से प्रदेश में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और उससे...।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, लम्बे समय से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष-विपक्ष की तरफ से अपने-अपने विचार रखने का मौका सबको मिला और सबने अपने-अपने विचार रखे। मैं कहना चाहूंगा कि यह राजस्थान प्रदेश की जनता का एक बहुत सुन्दर मन्दिर है जिसमें राजस्थान की जनता के आखिरी पड़ाव के उस व्यक्ति की बात को हम रख कर जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत बातें हैं उन पर हमको इस सदन में सार्थक रूप से चर्चा करनी चाहिये। 70 वर्षों में सरकारें आयी हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी आयी हैं, कांग्रेस की भी आयी हैं हर व्यक्ति ने, हर सरकार ने अपना विजन लेकर इस राजस्थान के प्रदेश के हित में काम किये होंगे और उनका प्रयास भी रहा होगा कि हम अच्छा करने का प्रयास करें लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमारे लोग आखिरी पड़ाव में जब गांव में रहते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों के बीच जाकर देखते हैं तो हमारी प्रशासनिक मोनोपॉली या हमारी विचित्र समस्याएं जो इस रूल और कानूनों के हिसाब से जनता को मिलती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले इस बात पर बात करना चाहूंगा कि हमारे

सामने ई.आर.सी.पी. का बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान प्रदेश की जनता के सत्रह जिले तीन करोड़ जनसंख्या का इस अभिभाषण में आकलन किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार आपकी डबल इंजन की है। इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करके तुरन्त राजस्थान की जनता को लाभ दिया जाये जिससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, यमुना जल समझौता 17 फरवरी, 2024 को हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि चूरू, झुंझुनू और सीकर को हम यमुना जल समझौते से पानी देने का काम करेंगे और उस समझौते में मात्र चार माह का समय दिया गया लेकिन चाह माह के बजाय एक वर्ष होने जा रहा है आज तक हमें कहीं नहीं लगा कि उसकी डी.पी.आर. बन पायी है या संयुक्त रूप से दोनों की टास्क फोर्स गठित करने की जो बात हुई, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार की, आज तक भी उस पर मुझे लग रहा है कि जीरो रिजल्ट है। हमें कहीं भी दिख नहीं रहा है कि उसका लाभ जनता को मिलने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे एरिये में सिद्धमुख नहर क्षेत्र जिसमें चकबन्दी और मुरब्बाबन्दी को लेकर किसान लम्बे समय से संघर्षरत हैं, लम्बे समय से आन्दोलनरत हैं, लेकिन यह सरकार चाहे वह पिछले वर्ष में कांग्रेस की रही हो, चाहे आज आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमने इस बात को माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय के सामने, हमारे राजस्व मंत्री महोदय के सामने रखा है उसके बाद भी चकबन्दी और मुरब्बाबन्दी नहीं होने से राजस्थान की हमारी जनता को उस जल से सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं दूसरा कहना चाहूंगा कि इसके पैरा नम्बर 121 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पेज नम्बर 32 घुमन्तू और अर्द्ध घुमन्तू जनता को 17 हजार पट्टे जारी करने की बात कही गयी है। राजस्थान में करीब 15 हजार ग्राम पंचायतें हैं और आपने 17 हजार पट्टे देने की बात की है। एक ग्राम पंचायत में एक पट्टा और वह भी उन घुमन्तू जाति के लोगों को दिया गया जो आबादी क्षेत्र में बसे हुए हैं उसमें सरकार का योगदान नहीं है। सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू को अगर पट्टा देना चाहती है सरकार तो जो लोग गोचर भूमि में बसे हुए हैं, जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि उपलब्ध करा कर पट्टे जारी करने का काम करें तो सरकार का सराहनीय कार्य होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं पेज नं.22 पैरा 76 गोशालाओं के लिए बार-बार सरकार चर्चा करती है और यह राजस्थान की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह गोशालाओं के संरक्षण के लिए बहुत ताकतवर मान रही है अपने आपको, मैं कहना चाहता हूं कि गोशालाओं के लिए गोचर भूमि का नाम ही गोशाला के लिए है गौ के लिए है गौ चरेंगे इसलिये गोशाला में अनुदान देने के लिए गोचर भूमि को भी अनुमत करें जिससे गोशालाओं को अनुदान मिल सकें और ज्यादा गोशालाएं खुल सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह पशु मंगला बीमा योजना का जिक्र किया है, उसमें

पशुपालकों को सिर्फ दस पशुओं को आपने शामिल किया है। पशुपालन का जो काम करता है उसके पास सैकड़ों पशु, बकरी, भेड़ हैं उनको दस की बजाय जितना पशुपालक के पास पशुधन है उसको सारे को बीमा राशि में शामिल किया जाये क्योंकि नेशनल लेवल की एक योजना है जिसमें सरकार सौ बकरियों और भेड़ पालन करने वालों को पचास प्रतिशत अनुदान देती है उसका एक का भी बीमा इस पशु मंगला योजना में नहीं हो पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही भूमि विभाजन सहमति बंटवारा ओनलाइन का इन्होंने पेज नं. 79...।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट साहब, मैं एक ही बोलने वाला हूं।

Kas/rtm/05.02.2025/17.40/3j

श्री सभापतिः समय हो गया, पांच मिनट अलोटेड था। श्री भागचन्द टाकडा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमारा 10 मिनट का समय है।

श्री सभापतिः पांच मिनट दिया है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं, किसने? हमारी पार्टी का 10 मिनट का है, मैं अकेला ही बोलूंगा, हमने समय लिखा ही नहीं।

श्री सभापतिः लिखा हुआ है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं लिखा। हमारी पार्टी का दूसरा सदस्य नहीं बोलेगा।

श्री सभापतिः आपका पांच मिनट का ही समय है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं किसान का जो सबसे बड़ा भूमि बटवारे का विवाद है, जब खाता विभाजन का सवाल आता है, इसमें लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन होगा। मैं कहता हूं यह भ्रष्ट अंतर हो रखा है, राजस्व मंडल में किसान रोता रहता है, सहमति के दावों का विभाजन नहीं करते, जब तक उनको कुछ राशि नहीं मिल जाती है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही किसान को ब्याज मुक्त ऋण की बात की गई। मैं कहना चाहता हूं कि आपके आंकड़ें तो अच्छे हो सकते हैं, आपने संख्या अच्छी दी है, लेकिन आप पांच हजार रुपये से शुरू कर रहे हो और नाम ले रहे हो कि डेढ़ लाख रुपये तक हम किसान को ब्याज मुक्त ऋण देंगे। आप डेढ़ लाख रुपये दीजिए, तब आप संख्या गिनाने का काम कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसान के कृषि बीमा क्लेम की बात करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, किसान को 2018, 2022, 2023, 2024 का फसल बीमा का प्रीमियम कटता है, लेकिन जब बीमा मिलने की बात आती है तो किसान को सालों तक भटकाने का काम किया जाता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसान को पीड़ित मत करो। किसान की चिंता करते हुए फसल बीमा तुरंत दिलाने की

बात करें।

सभापति महोदय, मैं समर्थन मूल्य की बात करूं तो सरकार ने समर्थन मूल्य की बहुत बड़ी चर्चा की, रेटें बढ़ा दीं, लेकिन समर्थन मूल्य पर किसान बेच कितना पा रहा है, यह सबसे बड़ा गंभीर विषय है। टोकन क्षमता एक दिन में समाप्त कर दी। मैं आग्रह करता हूं कि इन संस्थाओं को बंद करते हुए पूरे बारह महीने तक समर्थन मूल्य पर किसान की जिन्स व्यापारियों के माध्यम से खरीदें, हरियाणा मॉडल पर खरीदें, जिससे आपकी यह लूट और क्रय-विक्रय समिति में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस लूट को रोका जा सके और प्रत्येक किसान का समर्थन मूल्य पर अनाज बिकना चाहिये। बीज वितरण की प्रक्रिया में ऐसी स्थिति है कि किसान बीज बो लेता है उसके दो-दो महीने बाद मिलता है। किसान मेरे क्षेत्र में झींगा फार्म लगाता है, किसान के झींगा फार्म को आपने उद्योग मानते हुए आप उसकी कामर्शियल रेट लेते हैं। सभापति महोदय, किसान की अगर आप वीसीआर देख लो तो 40-40 लाख रुपये की वीसीआर भरी जाती है। किसान अगर संपूर्ण जमीन बेच दे तो भी वह उसका भुगतान नहीं कर सकता। इसलिए मैं आग्रह करता हूं किसान के झींगा फार्मो को बिजली कृषि रेट से दी जाये।

इसके साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, एक मेरा गंभीर विषय स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। एक डायलिसिस मशीन 20 करोड़ रुपये की सरकार ने खरीद ली, डेढ़ वर्ष का समय हो गया, लेकिन वह स्थापित नहीं हो पाई है। जनता को इसकी सख्त जरूरत है। मशीनें स्थापित नहीं होना और जनता को लाभ नहीं मिलना, यह बहुत गंभीर विषय है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं बी फार्मा के राजस्थान में सिर्फ 40 कॉलेज हैं और डी फार्मा के 324 कॉलेज हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं बी फार्मा की एनओसी जारी करें। कॉलेज खोलने से युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनको स्थान मिलेगा। डी फार्मा में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, खाली स्थान पड़े हैं।

सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना में सामान्य प्रसव को शामिल नहीं किया, उसमें शामिल करने का काम करें। महिला के बच्चेदानी का ऑपरेशन महिलाओं की गंभीर समस्या है, इसको भी आपने चिरंजीवी में और आर.जी.एच.एस. दोनों में शामिल नहीं किया, उसको शामिल करने का काम करें।

सभापति महोदय, मेरे यहां सिद्धमुख सीएचसी का एक दानदाता मनीष गुप्ता ने 10 करोड़ रुपये की राशि से निर्माण किया।...

श्री सभापति: श्री भागचन्द टांकडा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री सभापति: आपके सुझाव आ गये।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): महामहिम जी ने जो अभिभाषण यहां प्रस्तुत किया है वह माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार का एक वर्ष के कार्यकाल में आमजन के हितार्थ लिये गये फैसलों तथा सरकार की आगामी रूपरेखा को प्रदर्शित कर रहा है। माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार केवल वादे ही नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें पूरा करने में विश्वास भी रखती है। इनका मानना है कि जिन कार्यों का शिलान्यास किया जाता है, उनका लोकार्पण भी हमारे ही कार्यकाल में हो, ताकि सरकार आमजन के विश्वास पर खरा उतरे।

सभापति महोदय, अभी विपक्ष के माननीय सीनियर साथी यह कह रहे थे कि बजट में जो भी घोषणाएं हुईं, उनकी कोई निविदा जारी नहीं हुई। मैं विपक्ष के साथियों को मेरे विधान सभा क्षेत्र में आने का न्योता देता हूं। मेरे यहां 5 कार्यों की निविदाएं जारी हुई हैं, एक कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, दो कार्यों की डीपीआर बनाने का टेंडर हो गया है, दो कार्यों का टेंडर खुलना बाकी है। माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे कि कहीं भी एक भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं खुला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय होडी का गोला चालू करवा दिया है और उसमें 17 नामांकन भी हो चुके हैं और स्कूल चालू है, इसलिए विपक्ष थोड़ी सोच समझ कर बात रखे। पिछली सरकार द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन्होंने दर्जनों उप स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणाएं कीं, लेकिन उनकी यह जमीन भी अलॉट नहीं करा पाये, बनाना तो बहुत दूर की बात है। अब जब नई सरकार बनी है तो उसमें जमीनें अलॉट कराई हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार में एक ट्रोमा सेंटर की भी घोषणा की गई थी, उसकी भी जमीन यह अलॉट नहीं करा पाये।

सभापति महोदय, यह इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करें या खुले, आपने खोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनके नये भवन बनाकर खोलते, आपने तो नाथी का नाम भौंरी रख दिया। नाथी के बाड़ा को भौंरी का बाड़ा बना दिया, यह ठीक नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि एस.टी, एस.सी. की स्कॉलरशिप 6 साल से नहीं मिली है। इसमें 5 साल तो सरकार कांग्रेस की ही थी, क्यों नहीं मिली? ....(व्यवधान).... तो देनी चाहिये, राजस्थान सरकार का भी तो हक बनता है। ....(व्यवधान).... माननीय सदस्य, एक कहावत है कि एक किसान मथुरा से एक गाय ले आया और मथुरा में गाय हरा ही हरा चारा खाती थी। जब राजस्थान में बारिश हुई तो गाय ने हरा चारा खा लिया और जब बारिश खतम हुई तो उस चारे को सुखा कर एक गड्डी लगा दी। जब वह हरा चारा खाती रही तो 10-12 किलो दूध देती रही और ज्यों ही सूखा चारा मिला तो दूध कम होता गया। किसान ने सोचा कि इसका तो कुछ न कुछ इलाज किया जाये अपने तो पैसे भी बरबाद हो गये और अपनी गाय 12 किलो से 4 किलो पर ही रह गई। तो किसान ने गाय को एक हरे रंग का चश्मा लगवा दिया तो उसको सूखी घास भी हरी ही दिखे। इसलिए माननीय सदस्य एक चश्मा बनवा लो और पिछली बातों को भूल जाओ, अब हरा चारा बंद हो गया, इसके लिये तो आपको चश्मा लगवाना ही पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान में पानी की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया था, जिसे अब मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सानिध्य में पूरा करने में जुटे हुए हैं। सरकार रामजल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती-कालीसिंध चंबल परियोजना को धरातल पर उतारने में लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सानिध्य में राज्य सरकार के कार्यकाल की प्रथम वर्षगांठ पर इस परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान-प्रदान किया जा चुका है।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र, जननी सुरक्षा योजना, निःशुल्क सोनोग्राफी जांच सुविधा से आम अल्प आय वर्ग के लोग काफी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले का महिला शिक्षा में योगदान को सम्पूर्ण देश की आधी आबादी भुला नहीं सकती है। किन्तु सम्पूर्ण भारत की तरह राजस्थान में भी महिला शिक्षा पुरुषों के मुकाबले में अभी भी कम है। भारत की उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की उच्च दर की तुलना में राजस्थान अभी भी पीछे है और महिलाओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामले में बहुत पीछे है।

Msk/rtm/05.02.25/1750/3k

इसके लिए उचित होगा कि महाराष्ट्र, आंधप्रदेश व मध्यप्रदेश राज्य की तर्ज पर राजस्थान राज्य द्वारा वित्त पोषित सावित्री बाई फूले राजकीय आवासीय महिला विश्वविद्यालय खोला जाये। यह प्रयोग अपने आप में राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं के लिये एक स्वप्न साकार होने जैसा कदम होगा। महोदय, बांदीकुई को जिला का दर्जा दिये जाने की मांग करता हूं, क्योंकि बांदीकुई सुगम यातायात की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। बांदीकुई के पास में होकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाई-वे गुजरता है। देश की दूसरी रेल लाइन एवं राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन है, जो कि अब जंक्शन है। यहां पर देश के प्रत्येक कोने से यातायात सुविधा उपलब्ध है।

इससे राज्य की महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा, बल्कि मां सावित्री के नाम से यह संस्थान स्थापित होने पर पूरे दौसा, जयपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर जिले के लोगों की जनभावना भी संतुष्ट होगी।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित उप जिला चिकित्सालय बांदीकुई को जिला चिकित्सालय में और कोलवा, पण्डितपुरा, नन्देरा, रानापाड़ा उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा बड़ियाल कलां,

गोलाड़ा, अरनिया, खेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने हेतु अनुरोध करता हूं। साथ ही, हरसोरा, शेखपुरा, टीकावाली की ढाणी, झांज्या का बास, बास गुढलिया, मेड़ी, अलवारिया का बास, आशापुरा, बच्छी का बास, कलाली का बास में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग करता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बांदीकुई में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय, बडियाल कलां को पंचायत समिति बनाने, बडियाल कलां को उप तहसील से तहसील बनाने, बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खुलवाने, बांदीकुई में केन्द्रीय बस स्टैण्ड निर्माण, बसवा से गोवर्धन गिर्राज जी सड़क मार्ग निर्माण, बांदीकुई में डाक बंगला निर्माण, गुढ़ाकटला में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने, बांदीकुई में कृषि महाविद्यालय एवं संस्कृत महाविद्यालय, बांदीकुई एवं बसवा नगरपालिका क्षेत्र में भूमिगत सीवरेज लाइन तथा एडीजे बांदीकुई को पॉक्सो, एससी/एसटी केसों की सुनवाई प्रारम्भ करवाने की मांग करता हूं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से देश के युग पुरुष प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राजस्थान विशेष के विकास के लिए अभूतपूर्व योगदान किया है। माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने केन्द्रीय योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम कुसुम योजना, ग्राम सड़क आदि को राज्य में उच्चतम स्तर पर क्रियान्वित किया है, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। आज राजस्थान न केवल बुनियादी ढांचे में बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में भी नई ऊचाइयों को छू रहा है।

हमारी भजनलाल सरकार 2047 तक विकसित राजस्थान व मोदी सरकार के संकल्प के साथ, मैं अन्त में श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी की चंद लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं:-

मुझे सत्ता का लोभ नहीं है,
लेकिन सत्ता को मैं साधन मानता हूं, सेवा का।

जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री पूसाराम गोदारा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले, जल ही जीवन है, पानी पर बात शुरू करुंगा। सबसे महत्पपूर्ण योजना, जेजेएम। जल जीवन मिशन में सबसे बड़े घोटाले की बात पर लगातार हमारी तात्कालिक सरकार पर चार्ज लग रहा है, लेकिन यह गलत बात है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि आज भी जेजेएम में घोटाला, मैं समझता हूं कि पिछले टाइम से ज्यादा बढ़ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय को,

जो विराजमान हैं, उनसे भी निवेदन किया कि रियान और एल. एंड टी. जैसे कीड़े हैं, इन ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है और इतने ताकतवर हो गये हैं कि एस.ई., एक्स.ईएन. और सीई तक ट्रांसफर करा देते हैं। हालांकि, यह बात सही है कि अब की बार मंत्री जी ने इनकी बात नहीं मानी। इसका इतना तो इनको धन्यवाद दूंगा, ताकि कम से कम इन पर नकेल कसें। आज 6091 करोड़ रुपये, 11 लाख 17 हजार परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने की बात है। मैं सही बात कह रहा हूं। मैं गलत बात थोड़े ही कह रहा हूं। जो किया है तो किया, नहीं किया इन्होंने। इसमें क्या है? लेकिन ...(व्यवधान)... डटो, जोगाराम जी डटो। माननीय सभापति महोदय, आज भी कहीं पाइपलाइन नहीं डाली गयी, पाइपलाइन डाल दी तो उसको जोड़ा नहीं गया, जोड़ा गया तो उसमें पानी नहीं है। जहां कनेक्शन हो गया, 50 परसेंट पानी मिलता है। मैं चूरू जिले और बीकानेर रेंज की बात करता हूं। उसमें बहुत स्पष्ट है कि पानी नलों में ही रहता है और सरकार के करोड़ों रुपये खर्च हो गये। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसमें समय रहते सुधार किया जाये और रियॉन जैसी कंपनियों पर नकेल कसी जाये, नहीं तो आपकी सरकार भी बदनाम हो जायेगी, इसमें शक वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि ये भी स्क्रू शुरू हो गये हैं।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पीएचईडी में कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं। आज की तारीख में हर सब-डिवीजन में 5-7 कर्मचारियों से ज्यादा नहीं बचे हैं। आप कह रहे हैं कि हम चार लाख लोगों की भर्ती करेंगे, चार लाख लोगों को रोजगार देंगे, आप पीएचईडी में भी भर्ती करिये। जितनी चपरासी की आवश्यकता है, उससे चार गुना पानी के कर्मचारियों की भी आवश्यकता है। यह मैं जनहित की बात कह रहा हूं। इसलिए अगर पानी पिलाना है तो कर्मचारियों की भर्ती भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आज मोटर नहीं है, पंप नहीं है, केबल नहीं है और बार-बार मोटरें जलने की शिकायतें आती हैं। जहां रीजनल स्कीमें हैं, वे तो 15-15 दिन तक बन्द रहती हैं। लॉकल रिसोर्सेज सात-सात दिन बन्द रहते हैं। अगर यही हालत रहे तो आने वाले वक्त में पानी का संकट खड़ा हो सकता है।

जहां तक धरती में पानी रिचार्ज का प्रश्न है, उसके लिए आपको जल संग्रहण की योजना कंटीन्यू चालू रखनी चाहिए, ताकि जितना पानी दोहन हो, उतना पानी धरती में वापस आये। नहीं तो, लगातार जो हमारे ट्यूबवैल सूख रहे हैं, उनकी और ज्यादा स्थिति खराब होगी। अब जो ट्यूबवैल सूखे हुए हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि उनकी जगह नये ट्यूबवैल तत्काल स्वीकृत किये जाने चाहिए। आज एक गांव में दो सोर्स हैं, दोनों एक साथ सूख गये तो इतनी लंबी प्रक्रिया है कि मंत्री जी तक आना पड़ता है, तब जाकर सेंक्शन होती है। इसमें दो-तीन महीने लगते हैं। इसकी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था गांव में नहीं होती है। कितना बड़ा संकट खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

इसके अलावा ढाणियों में, अब तक आपणी योजना में, ढाणियों में जेजेएम में, जो रिकॉग्नाइज्ड ढाणियां हैं, उनमें अभी तक लाइन नहीं डाली गयी है। यदि डाली गयी है तो उसको जोड़ा नहीं गया है। टंकियां तो बनी हैं, उनको जोड़ा नहीं गया है। पिछले दो साल से

जो टंकियां पूर्ण हो गयीं, उनमें एक घूंट पानी नहीं है और टंकियां टूटने के स्तर पर जा रही हैं। जीएलआर बन्द कर दिये। रिपेयर बन्द कर दी, यह कौनसी बात हो गयी? उन स्टोरेज को आप ठीक नहीं करेंगे, तब तक पानी की व्यवस्था सही नहीं हो सकती। स्टोरेज के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है तो पानी का संकट रहेगा। सबसे बड़ा काम, जल ही जीवन है, इस पर चलना जरूरी है।

इसके अलावा मैं विद्युत की बात करना चाहता हूं। आपने भले ही बोला है कि परसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक से कोयले का खनन पुनः शुरू हो गया है और आपने 35,131 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की बात कही है, लेकिन आज किसान को चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। मैं सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। ट्रिपिंग इतनी है कि छह घंटे का ब्लॉक बारह घंटे में पूर्ण होता है और रात भर किसान इंतजार करता है। आप कह रहे हैं कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे। आज मेरी सुन लें, 10 परसेंट से ज्यादा दिन में बिजली नहीं मिल रही है। रात को कितनी जबर्दस्त ठंड पड़ती है। किसान पूरी रात ठिठुरता है और उस पाइपलाइन को बदलता है। आप और हम सबको मालूम होना चाहिए। हालांकि बिजली मंत्री जी यहां नहीं हैं। बिजली मंत्री जी ने तो सारे सब-डिवीजन में ए.ईएन. खाली कर दिये, एक्स.ईएन. खाली कर दिये और कोई जॉइन नहीं कर रहा है। आज वहां व्यवस्था वीरान पड़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत की स्थिति राजस्थान में बहुत खराब है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। जहां 132 पर ट्रांसफार्मर जल गये, मेरे रतनगढ़ में एक साल में 132 में 100 एमवीए ट्रांसफार्मर जला हुआ पड़ा है। उसके साथ-साथ 200 के जीएसएस पर ट्रांसफार्मर जला हुआ पड़ा है।

mdp/rtm/05.02.2025/18:00/3l

कई बार कहने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगे, जबकि वह एग्रीकल्चर बेल्ट है। किसान को 7-7 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते। आप कह रहे हैं कि हम बिजली में बहुत काम कर रहे हैं। हालत बहुत खराब है। जर्जर पोल है, लाइनें नीचे लटक रही हैं। आप पांच लाख रुपये दे देंगे केजुअलटी होने पर, क्योंकि लोग आंदोलन करके ले लेते हैं, लेकिन आप उन पोल को बदलने के लिए हजार रुपये खर्च नहीं करते हैं। इस व्यवस्था को बदले, लेकिन बोले किसको, मंत्री जी तो यहां है नहीं, भाषण देकर चले गये। मेरा निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। पूरे राजस्थान में आज बिजली को लेकर जगह-जगह आंदोलन चल रहे हैं। गंभीर बात है।

पिछले हमारे कांग्रेस के शासन में 132, 220, 33 केवी के सब-स्टेशन खूब बने। आज चूरू जिले में मैं कह सकता हूं कि हमारे चूरू के मुख्यालय पर एक जीएसएस 132 का जरूर दिया है, इसके अलावा कोई 33 केवी जीएसएस नहीं है, जबकि वहां एग्रीकल्चर बेल्ट डवलप है। 132 नहीं है, 220 नहीं दिया गया है। रतनगढ़ पूरे चूरू जिले का हब है, उस पर 400 केवी का बिजलीघर है, लेकिन उसके ऊपर आज ट्रांसफार्मर नहीं है। एडिशनल ट्रांसफार्मर के

लिए दो साल से जूझ रहे हैं। इस कारण से पूरा जिला प्रभावित है। बिजली को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लगातार मांग कर रहे हैं कि हर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम दो हजार ढाणियां ऐसी हैं। लोग गांवों में इसलिए नहीं रह सकते कि आबादी विस्तार बंद है। जमीन नहीं है। लोग ढाणियों में रह रहे हैं। एग्रीकल्चर बेल्ट है। उनको रेगुलर स्कीम में राजस्थान सरकार को कनेक्शन देने चाहिए, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। आरडीएसएस दे रहे हैं। 2019-20 के बाद एक भी कनेक्शन नहीं किया। आपकी सरकार ने दावा किया है कि घरेलू कनेक्शन दिए हैं। सिर्फ आबादी में दिए हैं। कोई भी कनेक्शन इन्होंने ढाणियों में नहीं दिए। कोई भी कनेक्शन आबादी क्षेत्र के आर-पार के एरिये में नहीं दिए। जो भी एग्रीकल्चर प्लाट पर बस गया, करोड़ों रुपये, लाखों रुपये खर्च कर दिए, आज उनको बिजली नहीं मिल रही है। उसको अधिकार नहीं है बिजली लेने का। जो सरकार बिजली, पानी देने में सक्षम नहीं है, आपको पता है उसकी क्या हालत होती है? इसलिए बिजली को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

लम्बी बात नहीं कहते हुए आगे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य सेवाएं, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं। माननीय मंत्री, जिला हॉस्पिटल जैसे आज 30 परसेंट पद भरे हुए हैं। मेरे यहां जिला अस्पताल है, जिसमें 45 में से आज सिर्फ 20 डाक्टर हैं। वे भी स्पेशलिस्ट नहीं हैं। आपको मिलकर मैंने दस बार कहा और कई नाम भी दिए। उनका आपने तबादला तक नहीं किया। चलिए नहीं किया तो नहीं किया तबादला, लेकिन कम से कम मेरा आपसे निवेदन था कि इन हॉस्पिटल्स को भरा जाए। लोगों की हालत बहुत खराब है। जिला हॉस्पिटल की बात कह रहा हूं। रही बात तहसील की, मेरी तहसील है राजदेसर, उसमें आदर्श सीएचसी है, उसमें सिर्फ एक डाक्टर बैठा है, 7 में से। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत खराब है। सारी खाली पड़ी हैं।

श्री सभापतिः श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): ग्रामीण क्षेत्र में कोई डाक्टर नहीं रहता। इसके अलावा मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना हमारे कांग्रेस के गहलोत साहब के समय में शुरू की। आपने दूसरी योजना शुरू की है। उसमें मैं कहना चाहता हूं कि आपने उसका सिर्फ नाम बदला है।

श्री सभापतिः आप विराजिए। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने जिस प्रकार से ...(व्यवधान)... महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुना होगा। शुरूआत में ही महामहिम ने राजस्थान की माटी को नमन किया है।

श्री सभापतिः आप स्टार्ट कीजिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): राजस्थान की माटी को नमन करने का मतलब यह धरती शौर्य की धरती है। उन्होंने कहा कि यह धरती त्याग की धरती है, यह धरती बलिदान की गाथाओं की धरती है, इसलिए महामहिम ने इस धरती को नमन करते हुए अपना

अभिभाषण शुरू किया। महामहिम के बिंदु संख्या 3 को आपको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मतदाताओं ने जिन उम्मीदों के साथ चुनकर इस पवित्र सदन में हमें भेजा है, उन पर हमें खरा उतरना है, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिले। मैं देख रहा हूं पक्ष और विपक्ष, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने, भाजपा की सरकार ने जो बजट दिया इस वर्ष, उसको 6 महीने हुए है और इसमें यशस्वी मुख्य मंत्री जी का जो विजन है, मुख्य मंत्री जी का विजन है कि पेयजल पूरे राजस्थान में, जो मूलभूत आवश्यकता है कि पेयजल, पिछले 70 वर्षों से हम लोगों की और पूरे राजस्थान की विशेषकर एक इच्छा है कि पेयजल सबको मिले। उसको लेकर आपने देखा होगा कि अभी एक वर्ष पूरा होने पर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने राम जल सेतु लिंक परियोजना के मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट का आदान-प्रदान किया। इससे करीब 17 जिलों को और करीब 3 करोड़ आबादी को पेयजल के लिए पानी मिलेगा। सिंचाई के लिए लाखों हैक्टेयर पानी मिलेगा। इससे पेयजल व सिंचाई दोनों की व्यवस्था होगी।

दूसरी बात अगर मैं करूं तो अभी देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी की पहल पर हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य भी समझौता हुआ। इसमें सीकर, चूरू, झुंझनूं, तीन जिलों के लिए यमुना का जल लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कल कहा था और कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी हरियाणा समझौते को लेकर चर्चा की कि पानी कैसे आयेगा? बिलकुल सही बात है, जब इनके हरियाणा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय घोषणा पत्र में लिखा था कि राजस्थान के लिए जो समझौता हुआ है, उसको हम कैंसल करवाएंगे। यह इनके घोषणा पत्र में है। इनकी कथनी व करनी में फर्क होता है। राजस्थान में अलग बात करते हैं और हरियाणा में जाकर अलग बात करते हैं, जबकि भाजपा का विजन होता है कि पूरे भारतवर्ष में, भले ही वह राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो सभी के लिए पेयजल की उपलब्धता हो, सभी के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता हो। इसको लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं।

आपने देखा होगा कि हमारी एक और तीसरी योजना माही सोम नदी के मानसून सत्र की अवधि का अधिशेष जल, जो जयसमंद बांध को भरते हुए जवाई बांध तक लाने के लिए उदयपुर, सिरोही और जोधपुर जिले के लिए बात की थी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री दोनों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जालौर जिले को भी सम्मिलित किया है। पेयजल, सिंचाई और शेष पानी नदी में छोड़ने के लिए हमें आशान्वित किया है। मैं इस मंच से उन्हें भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जालौर जिले को भी जोड़ा है। यह बहुत बड़ी योजना है। जालोर जिले के लिए वरदान साबित होगी, जिस प्रकार से राम जल सेतु योजना है, यमुना की योजना है और जो माही वाली योजना है, इस प्रकार से पूरे राजस्थान में अलग-अलग क्षेत्रों में पेयजल के लिए योजनाएं बन रही हैं। आने वाले समय में जो काम होना चाहिए पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, ये जो विजन है राजस्थान के मुख्य

मंत्री जी का, इन्हें भागीरथ यूं ही नहीं कहा जाता। अभी पहले ही वर्ष में इन्होंने जिस प्रकार से घोषणाएं की हैं, ये हमारे लिए वरदान साबित होगी।

आपने पांच वर्षों में जो काम किया था। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, विपक्ष के नेता अपनी-अपनी बात कह रहे हैं कि पहले वर्ष आपने नाम बदलने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम किसने परिवर्तन किया था? मुझे यह बताएं अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने परिवर्तन किया था? मुझे यह बताएं पालनहार योजना किसने शुरू की थी? मुझे यह बताएं कि श्रमिकों के लिए श्रमिक डायरी जो बनी थी, वह किसने बंद की? मुझे यह भी बताएं कि शुभ शक्ति योजना में पांच वर्षों तक एक भी रुपया नहीं दिया, माननीय विपक्ष के नेता बैठे हैं, उनके पास में मंत्रालय था, एक भी पैसा नहीं दिया पांच वर्षों में। नि:शुल्क साइकिल वितरण का काम किसने किया था?

Ans/rtm 18.10 3m 05.02.2025

अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की चर्चा हो रही है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आपने चार वर्षों तक कुछ नहीं किया, फिर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने का काम किया। आपको पता है कि पायलट स्तर पर जो योजना शुरू की थी विवेकानंद मॉडल स्कूल, अंग्रजी माध्यम का, सुचारु रूप से वसुन्धरा राजे जी की सरकार ने जो योजना शुरू की थी उसको ही आप आदर्श मानकर उसका काम करवाते। उसी विवेकानंद मॉडल स्कूल को अगर आप अलग-अलग रूप से पहले उप खण्ड स्तर पर, तहसील स्तर पर, फिर ग्राम पंचायत स्तर पर खोलते तो वास्तव में लगता, जिस प्रकार से अभी बात कर रहे थे ना कि गरीब अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, तो आप गरीब पढ़ाना चाहते तो इस प्रकार के विवेकानंद मॉडल शुरू की थी उसको आप आगे बढ़ाने का काम करते। आपने क्या किया, उस विवेकानंद मॉडल स्कूल तो आपने ठण्डे बस्ते में डाला और नये नाम से खोलकर जो स्कूल बंद पड़ी थी वहां खोलने का काम किया। वहां कोई व्यवस्था नहीं दी, शिक्षकों की भी नहीं।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में बताना चाहूंगा। सियाणा की स्कूल है, वहां पर 900 स्टूडेंट थे उसको तत्काल रूप से अँग्रेज़ी में कर दिया, आज वहां यह स्थिति यह है बदलकर जहां अँग्रेज़ी माध्यम किया, जहां हिन्दी थी वहां 150 है। इसी प्रकार से आकोली में भी आपने अंग्रेजी माध्यम कर दिया, वहां 800 स्टूडेंट थे, वहां सभी अपने नाम कटवाकर दूसरी जगह चले गए,यह किस प्रकार की शिक्षा है? मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अलग से मॉडल स्कूल खोलते विवेकानंद मॉडल स्कूल की तर्ज पर तो बच्चे वहां पर एडमिशन लेते। नये एडमिशन लेते तो उनको भी पता रहता कि हमें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना है, लेकिन आपकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क देखा।

आपने गौरव पथ की तुलना में काम करना चाहा। पूर्ववर्ती सरकार ने जो गौरव पथ बनाये थे, आपको लगा कि पूरे क्षेत्र में वाह-वाही हुई, आपने नाम बदलकर विकास पथ

किया। पांच वर्षों में आपने एक विकास पथ बनाया वह भी क्वालिटी पूरी तरह से घटिया थी। पांच वर्षों में दूसरा बनाने का काम आपने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ घोषणा करने का काम किया था। फिर भाजपा की सरकार आई, यशस्वी मुख्य मंत्री भजनलाल जी ने एक विजन रखा कि हम पूरे राजस्थान में 10 हजार की आबादी से ऊपर जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन पर अटल पथ बनाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मात्र छह महीने में 10 हजार आबादी वाले गाँवों में 3-3 किलोमीटर की, करीब चार करोड़ रूपये की एक-एक सड़क और उसका निर्माण का काम, अभी माननीय कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अभी तक स्वीकृत हो चुके, चार महीने में काम स्वीकृत होना और निविदा कार्यादेश दे देना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैंने तो पिछले पांच वर्षों में देखा। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की आपके बजट की कॉपी देख लेना, 15-15 पेज हैं, उसमें कोई घोषणा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुटकुले हैं, डॉयलॉग है, उसमें किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है।

अब पहले ही वर्ष में आपने देखा होगा राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जो बजट दिया है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर इस प्रकार से काम कर लिया तो, हम 66 हैं लेकिन अब की बार 16 भी नहीं रहेंगे, आपको यह डर सता रहा है इसलिए आप विजन के साथ नहीं बोल रहे। मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्य जिस प्रकार से अपनी बातें रख रहे हैं,आप सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उनके बारे में भी बताना चाहिए। **(समय समाप्ति सूचक घंटी)**

जब हमारे मुख्य मंत्री जी ने बात की कि प्रत्येक विधान सभा में पांच आंगनबाड़ी केन्द्र खोलेंगे तो पांच आंगनबाड़ी केन्द्र प्रत्येक विधान सभा में खोले हैं। प्रत्येक विधान सभा में हम पांच करोड़ के रोड़ देंगे, पांच करोड़ के रोड़ दिए हैं। 10 हजार की आबादी वाले को अटल पथ दिया है। ओपन जिम और खेल के मैदान 10 हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायत में देने का काम किया है यह बात आपको करनी पड़ेगी। काम करने में किसी भी विधान सभा को नहीं छोड़ा है। 17 ज़िलों में, ईआरसीपी योजना चल रही है, राम जल सेतु योजना, उसमें कई विधायक हमारे नहीं है, लेकिन पेयजल के लिए पूरे प्रदेश की जनता को पानी मिलना चाहिए। अगर इस प्रकार का काम किसी ने किया है तो....

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, मेरे तो तीन मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: आपके पूरे दस मिनट हो गए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): शिक्षा के क्षेत्र में...

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यह अभिभाषण केवल नाम मात्र का है, इसमें आदिवासी, दलित की कोई चर्चा नहीं हुई है। हर साल अभिभाषण होता है, बजट आता है

लेकिन आज तक आदिवासियों, दलितों पर कोई चर्चा नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि धरती पर सबसे पहले निवास करने वाले आदिवासी लोग थे। आदिवासियों का योगदान प्राचीन काल में रहा, मुगल काल में रहा, अभी भी है लेकिन उनको आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। महाराणा प्रताप हमारे देश का गौरव है, हमारा गर्व है, मेवाड़ का स्वाभिमान है, हम उनको नमन करते हैं, उनको पूजते हैं लेकिन एक तरफ राणा पूंजा भील को भूला जाता है, उनको इतिहास से दूर किया जाता है क्योंकि वह भील योद्धा थे। 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में पूंजा भील ने भीलों की सेना लेकर महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया? आज भी मेवाड़ का जो चिन्ह है उस पर एक तरफ महाराणा प्रताप का प्रतीक चिन्ह है और एक तरफ राणा पूंजा भील का चित्र है। उनकी वेशभूषा से ही पता लगता है, उन्होंने धोती पहनी है, हाथ में तीर-धनुष है, उनका नाम पूंजा है लेकिन आप उनको भील मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या आदिवासियों ने योगदान नहीं दिया है? देश की स्वतंत्रता में योगदान नहीं दिया? अंग्रेजों को भगाने में क्या आदिवासियों का योगदान नहीं रहा? इतिहास में आदिवासियों को हटाया गया। आदिवासियों को उनके अधिकार आज तक नहीं दिए गए। ...(व्यवधान)... बोलने दो, डिस्ट्रब मत करो।

माननीय सभापति महोदय, मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। टीएसपी क्षेत्र में 75 परसेंट जनजाति लोग निवास करते हैं। आज भी आर्थिक स्थिति खराब है, गरीब है, पिछड़ापन है लेकिन आज भी उनको सही तरीके से आरक्षण नहीं दिया जा रहा। प्रशासनिक सेवा में राज्य को एसटी का 12.5 परसेंट आरक्षण मिलता है उसमें टीएसपी क्षेत्र को पृथक से 06 या 6.5 परसेंट अलग से आरक्षण चाहिए, तो वहां भीलों का उद्धार होगा, भील आगे बढ़ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र में जो भी नौकरियां लगती है उसमें हमारे आदिवासी बच्चे कम लगते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में जो भी भर्ती हो, जो भी नौकरी लगाए, जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर एसटी का लड़का जनरल मेरिट टॉप कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी मेरिट एसटी में बनाई जाती है, ऐसा क्यों। पहले आप जनरल की मेरिट बनाए उसमें एससी, एसटी सभी आ गये, उसके बाद आप एसटी की बनाए। हमारे साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात होता है।

माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र में 1971 से पहले वहां निवास कर रहे हैं उनको ही मूल निवासी माना जाए। 1971 के बाद टीएसपी में जिसका भी मूलनिवास व जाति प्रमाण पत्र बना है उनकी जांच की जाए। फर्जी तरीके से टीएसपी का प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी लग गए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए, उनको निरस्त किया जाए, यह मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में एमबीसी, अंग्रेजों के टाइम मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। 1841 ई0 में, मेवाड़ के भील हैं उनको ही उस

बटालियन में लिया जाएगा। वह वहां की भाषा समझने के लिए, उनकी संस्कृति समझने के लिए और आस-पास छोटा-मोटा विद्रोह होगा, उसको दबाने के लिए अँग्रेज़ो ने मेवाड़ भील कोर की 1841 में स्थापना की।

VPS-RTM-05.02.2025-18.20-3n

तो अब उस मेवाड़ भील कोर में सभी को ले लिया गया है। धीरे-धीरे भीलों को उस मेवाड़ भील कोर बटालियन से हटा दिया गया और वह बटालियन भी अब खेरवाड़ा से हटा दी, कहीं और बटालियन ले गये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य, असत्य न बोलें।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मंत्रीजी, आप बैठ जाओ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का अभी-अभी एक बड़ा फैसला आया है। दो वर्ष से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पद सामान्य से भरे जाएंगे, यह अभी इस सरकार का है। यह इस सरकार का है। एस.टी. के बेकलॉग को जनरल से भरा जाएगा, यह आपकी सोच है, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह मीडिया बोल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह थानों और चौकियों में, टी.एस.पी. क्षेत्र में 16-17 थाने हैं उनमें एस.टी. थानेदार को नहीं लगाया है। चौकियों पर एस.टी. के हैड-कांस्टेबल को भी नहीं लगाया है। आज भी हमारे साथ पक्षपात होता रहा है। पहले भी होता था और आज भी हो रहा है और सदन में भी हमारे साथ पक्षपात होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने क्या ऐसा गुनाह किया है कि आदिवासियों को आप अलग रखना चाहते हैं, आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं दिलाना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बिछीवाड़ा रतनपुर बोर्डर पर एक थाना है। अभी आठ बजे बाद बीस-पच्चीस गुजरात की गाड़ियां आ जाएंगी, बड़ी-बड़ी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, इनोवा, वह गुजरात की गाड़ियां उस थानेदार से सेटिंग करती है और रात को वहां से शराब की गाड़ियां निकलती हैं, उनके खिलाफ प्रशासन और यह सरकार कार्यवाही नहीं करेगी, क्योंकि उनको वहां कमीशन मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, लेकिन एक गरीब आदिवासी के घर उसका कोई प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम है, उसके घर एक लीटर या दो लीटर शराब मिल गयी तो उसके खिलाफ मुकदमा बनाएंगे लेकिन ट्रक के ट्रक, गाडियां गुजरात जा रही हैं, गुजरात में शराब जा रही है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आप तैयार नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने नरेगा में 125 दिन किये थे गहलोत सरकार ने लेकिन आपकी सरकार ने वह 25 दिन काट दिये। आज हमारे पास वहां पर उद्योग-धंधे नहीं हैं, रोजगार के लिए कुछ नहीं है, पलायन करना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है और नरेगा में अभी मजदूरी भी नहीं मिल रही है, काम भी नहीं मिल रहा है। कलक्टर काम ही नहीं निकाल रहे हैं, नरेगा में सेंक्शन ही नहीं कर रहे हैं और अबकी बार आंखों वाली वह

हाज़िरी भी कर दी है। अब हमारी यह संस्कृति है, यह परंपरा है कि हमारे से जो बड़ा है उससे हम घूँघट निकालते हैं। अब हमारी जो भाभियां हैं या जो बहुएं हैं तो वे हमारे सामने घूँघट से आंखें यूं-यूं करेंगी तो आपने इस तरह की हाज़िरी कर दी है। कम से कम आप तो जानते हो। यह सिस्टम वहां टी.एस.पी. क्षेत्र में तो कम से कम बंद किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा की ये बात कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा में आठ लाख से ऊपर नाम काट दिये गये। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सर, मेरे दस मिनट हैं, अभी तो केवल नौ मिनट ही हुए हैं।

खाद्य सुरक्षा में आठ लाख से ऊपर नाम काट दिये हैं। गहलोत सरकार ने फूड पैकेट भर कर दिया था लेकिन मोदीजी की खाली थैली देने वाले ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, यह है इनकी सोच और बिजली की तो बात ही मत करो। बिजली की ये 24 घंटे की बात करते हैं पर सिंगल फेस भी गांवों में नहीं आ रही है, दस बजे ही चली जाती है तो फिर सुबह आती है, वापस छह बजे नींद उड़ती है तब। वह थ्री-फेस तो भूल ही जाओ, यह आपका सिस्टम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सेंसस ऑफ इंडिया, 1951 में हमारी जनगणना हुई थी, उसमें हमारा धर्म कोड अलग था। आदिवासी कोड अलग था, नौ नम्बर का हमारा कोड था, उसको हटा दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा आदिवासी धर्म कोड लागू किया जाये और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 आदिवासियों पर लागू नहीं होता है।

श्री सभापति: श्री रेवन्तराम डांगा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मैं पुन: आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा धर्म कोड अलग से लागू किया जाये। धन्यवाद, जय हिंद।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): राम-राम सा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार उप चुनाव जीतकर इस सदन में आया हूं इसलिए अपनी कुछ भावनाएं आप सभी विद्वान लोगों के सामने रखना चाहता हूं, कोई गलती हो तो नया सदस्य समझकर माफ करना। मैं एक सीधा-साधा किसान पुत्र हूं जो पहली बार गांव की पंचायत से निकलकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधान सभा के इस पवित्र सदन में आया हूं इसलिए मैं सबसे पहले खींवसर विधान सभा क्षेत्र की देव तुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने मुझे एक ऐतिहासिक चुनाव जिताया, इसलिए खींवसर की जनता का मैं विशेष रूप से दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं खींवसर के भाजपा कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारियों, हमारे प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं जिनका भरपूर सहयोग और समर्थन मुझे उप चुनाव में मिला है। मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदीजी और माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ साधारण से व्यक्ति पर भरोसा जताया और उप चुनाव में फिर

से टिकट दिया। मैं आपके माध्यम से खींवसर की जनता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुझे विधान सभा तक भेजा है, आपने अपना काम कर दिया, अब मुझे आपकी सेवा करनी है। खींवसर की जनता की आवाज को राजस्थान की विधान सभा और सरकार तक पहुंचाना है। मैं खींवसर की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं रेवन्तराम डांगा आपके लिए 365 दिन, 24 घंटे तैयार मिलूंगा। कभी भी किसी को भी मेरे से कोई भी काम हो, बेझिझक मुझे बताओ, मैं आपका काम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरज़ोर समर्थन करता हूं। इस अभिभाषण में राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह तारीफ के काबिल है। सालों से टलते आ रहे जनहित के कामों को प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। यह सरकार जन कल्याण के लिए समर्पित सरकार है जो केवल थोथी घोषणाएं करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनको धरातल पर उतारकर प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।

(समय: 18.26 बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

हमारी सरकार किसान, युवा, महिला, गरीब, मध्यम वर्ग सहित सभी आम जन के कल्याण और विकास के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन कर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की नींव रखने का काम किया है। अब तक उद्योग लगाने में आ रही अड़चनों को दूर कर निवेशकों को प्रोत्साहन देने का संकल्प लिया है।

हमारी पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी ने पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए जो सोच रखी थी, आज वह साकार होने जा रही है, क्योंकि उसमें आ रही सारी अड़चनों को हमारी डबल इंजन की सरकार के साथ-साथ पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में भी भाजपा की सरकार होने का फायदा मिला है। इसका परिणाम है कि आज राम जल सेतु लिंक परियोजना धरातल पर फलीभूत होने जा रही है। इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी को पीने का पानी मिलेगा। राजस्थान का किसान मजबूत होगा तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो राजस्थान के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्माजी ने जो 350 मिलियन डालर की अर्थव्यवस्था का सपना देखा है, वह निश्चित रूप से पूरा होगा।

मुझे यह खुशी है कि हमारी सरकार में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व काम संभव हुआ है। मैं मुख्य मंत्रीजी से इस सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे नागौर जिले सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर में भी भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया है इसलिए अब आप नागौर जिले को भी सिंचाई के लिए किसी नहर परियोजना से जोड़ने के लिए

फिजिबिलिटी सर्वे करवाकर डी.पी.आर. तैयार करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप सीकर, चूरू और झुन्झुनूं जिलों में यमुना का पानी लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उनके साथ हमारे नागौर जिले को भी जोड़ दिया जाये तो हमारे जिले को भी लाभ मिलेगा। हमारा नागौर जिला इन जिलों का पड़ोसी जिला ही है तो नागौर पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे नागौर जिले में पीने के पानी की बहुत समस्या है। पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन में जो घोटाले किये, वे सबको पता हैं। इन्होंने तो लोगों के पानी पीने पर ही डाका डाला है। हमारे से पूर्व सदस्यों ने जो बात रखी है कि पाइप लाइनें तो बिछा दीं, हर गांव में टंकियां तो बन गयीं पर उनमें सप्लाई नहीं है। यह काम पूर्ववर्ती सरकार का है। हमारे नागौर में घर-घर पानी, जो आज कम से कम डेढ़ साल से जो टंकियां बनी हुई हैं, उनमें एक बूंद पानी भी आज तक नहीं आया है।

ssy/rtm/05.02.2025/18.30/3o

हमारी सरकार इस पर ध्यान दे रही है और उनकी खानापूर्ति हमें करनी है। अब हमारी सरकार ने इसको सुधारने का काम किया है। आशा करता हूं कि अगले 2-3 सालों में राजस्थान के हर घर तक नल से जल उपलब्ध हो जायेगा। साथ ही जलदाय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ठेकेदारों ने जो घटिया पाइप डाले थे, वह बिना पानी आये ही फटने लग गये हैं। जो टंकियां बनाई थीं उनमें आज तक पानी नहीं आया है, जिससे वे फटने लग गयी हैं। कृपा करके पहले इनके द्वारा खोदे गये खड्डों को भरवाने का काम करें। मतलब, अच्छी क्वालिटी का पाइप और टंकियों की मरम्मत करवाने जैसे काम करवायें।

गांवों में सरपंचों पर दबाव बनाकर टोंटी में पानी आये बिना ही एनओसी ले ली गई। इसकी जांच कराई जाये। जहां एक भी घर में पानी नहीं आया है वहां की एनओसी रद्द की जाये। एक यह भी निवेदन है कि पहले उपभोक्ता से सहयोग राशि के नाम पर एक से डेढ़ हजार रुपये लिये थे, जिसे बाद में फ्री कर दिया था। जिनसे पहले पैसे लिये थे उनको पैसे वापस लौटाये जायें।

बिजली की समस्या हमारे प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने सौर ऊर्जा के रूप में इसका समाधान करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू करके जो रास्ता दिखाया है, उस पर सही तरीके से अमल करने की जरूरत है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को ज्यादा प्रचार-प्रसार की जरूरत है। मैं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप विभागीय अधिकारियों को निर्देश दें कि यह फील्ड में जाकर लोगों को इसके फायदे समझायें।

साथ ही यह भी निवेदन करुंगा कि नागौर एक बड़ा जिला है और यहां पर लाखों की संख्या में घरेलू, कृषि, वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शन चालू हैं। परंतु प्रसारण तंत्र बहुत

कमजोर है। नागौर क्षेत्र के आसपास एक भी जीएसएस नहीं बना है, जिससे समस्या हो रही है। कृपा करके आने वाले इसी बजट में नागौर में 400 केवी का जीएसएस बनवाने की घोषणा करवा दें। नागौर की जनता खासकर किसान आपको धन्यवाद देंगे।

आने वाले बजट में कालियास, भोजास, बैराथल खुर्द, चावण्डिया, सेंधणी और जोगीनाड़ा में 33 केवी जीएसएस की घोषणा करवाने की कृपा करें। खींवसर और मुंडवा में अजमेर डिस्कॉम का एक्स.ईएन. ऑफिस खुलवाने की कृपा करें। पांचोड़ी, शंखवास, कुचेरा, खरनाल में ए.ईन. ऑफिस और रूण में जे.ईएन. ऑफिस खुलवाने की घोषणा करने की कृपा करें। फिर खींवसर में बिजली की समस्या लगभग समाप्त हो जायेगी।

हमारी सरकार ने प्रदेश की युवा शक्ति के लिए पिछले एक साल में 59236 पदों पर नियुक्ति देकर जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वह आज तक किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में नहीं किया है। हर बार यही सिस्टम चलता आया था कि चुनावी साल में बंपर घोषणा करने की नीयत से 4 साल यूं ही निकाल देते थे। लेकिन आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी की सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में नियुक्तियां देकर युवाओं के सपनों को जो उड़ान दी है, आने वाले 4 सालों तक लगातार जारी रहेगी और इसी युवा शक्ति के दम पर अब हमेशा के लिए राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जो गरीब, युवा अन्नदाता और नारी के लिए दिया है, वही देश की आत्मा है। अभी कुछ दिन पहले 1 फरवरी को केन्द्रीय बजट पेश हुआ था। वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने दिखा दिया कि नारी शक्ति केवल घर का बजट ही नहीं बना सकती है, वह देश का बजट भी बना सकती है। क्या शानदार और ऐतिहासिक बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। दो मिनट, सत्ता पक्ष की ओर से टेबलें बजाई जा रही थी। उसका विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं था। बजट में मिडिल क्लास को जो राहत दी गई, निश्चित रूप से वह अगले 4 सालों में भारत की आर्थिक गति को तेज करेगी। केन्द्रीय बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस किया गया है। यह बजट निश्चित रूप से भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मैं, हमारे विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि आने वाली 19 फरवरी को जब हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी राजस्थान का बजट पेश करेंगी तो आपको टेबल बजाने का काम भी करना है।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): मुझे पूरी उम्मीद है कि वह बजट भी केन्द्रीय बजट की तरह शानदार एवं ऐतिहासिक ही होगा। हमारी वित्त मंत्री जी महिला हैं, इसलिए नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए टेबल बजाने में आप पीछे नहीं रहेंगे।

हमारी सरकार का स्पष्ट विजन है कि हमारा प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर हो। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): एक मिनट, एक मिनट सर।

आज राजस्थान पूरे देश में एक एजुकेशन हब बनकर उभरा है। अगले कुछ वर्षों में हमारा प्रदेश मेडिकल हब बनने जा रहा है। पिछले वर्ष हमारे नागौर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गये हैं और 3 प्राइवेट खोले गये हैं। एमबीबीएस की 850 सीटों की वृद्धि हुई है। प्रदेश के युवा डॉक्टर बनेंगे।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): एक मिनट, एक मिनट सर। मैं नया हूं, एक मिनट।

जन औषधि केन्द्र खोलने, 6 उप जिला सेटेलाइट हॉस्पिटल सीएचसी को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने, 4 नये सेटेलाइट हॉस्पिटल की स्थापना, 3 शहरी पीएचसी और एक सीएचसी को सेटेलाइट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करने के अलावा 41 सब सेंटरों को सीएचसी में क्रमोन्नत करने का ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से उनका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल जी शर्मा। प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): एक सैकण्ड सर, मेरा लास्ट है।

श्री सभापति: गोपाल लाल जी आप बोलिये।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ही हैं और इनकी हमेशा खींवसर पर विशेष कृपा रही है।

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): 000

श्री सभापति: बोलिये, गोपाल जी बोलिये। आपका समय चालू है।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): राम-राम सा। मान्यवर सभापति जी, 16वीं विधान सभा के तीसरे सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपका आभार।

मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ करूंगा, 'पसीने की स्याही से लिखते हैं, जो लिखते हैं इरादों को उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं'। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण ऐसे ही भावों को प्रदर्शित कर रहा है।

प्रदेश में माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को विकास के नये आयामों की ओर अग्रसर किया है। मैं इस अभिभाषण के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित माननीय मुख्य मंत्री महोदय की कर्मठ व संकल्पित कार्य शैली को देखकर मुझे दो पंक्तियां फिर याद आ रही हैं, 'मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, मन में हो हौसला तो फिर फासला क्या है'। माननीय मुख्य मंत्री जी और पूरी सरकार के मन में प्रदेश के सर्वांगीण विकास का हौसला है।

महामहिम राज्यपाल महोदय का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभिभाषण में एकात्म

मानववाद के प्रणेता युग पुरुष पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के एकात्म मानववाद की अवधारणा का उल्लेख किया है। देश व प्रदेश की सरकार अंत्योदय के महामंत्र को आधार मानकर काम कर रही है। महामहिम ने अभिभाषण में भारत माता के लाडले सपूत, देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की जन्म शताब्दी की चर्चा की है। देश व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार माननीय अटल जी के कामों को आगे बढ़ा रही है।

मैं इस अवसर पर माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री जी जो हमारे राजस्थान के भागीरथ भी कहलाते हैं, जो राजस्थान के विकास पुरुष भी कहलाते हैं, उनका और उनके पूरे मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सरकार ने कार्यभार संभालते ही संकल्प पत्र की घोषणाओं की क्रियान्विति का काम तेजी से प्रारंभ किया।

मैं पिछली सरकार के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का प्रतियोगी परीक्षाओं से विश्वास समाप्त कर दिया था। परंतु हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने एसआईटी गठित कर युवाओं के भाग्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे, ऐसे 260 पेपर लीक माफियाओं को अन्दर किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने युवाओं के लिए कितनी बड़ी सोच के साथ काम किया है। हमारी सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित करके, समयबद्ध परीक्षाओं के आयोजन की अभिनव पहल की है। अब पेपर लीक करने वालों पर लगाम लगी है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन के काम को यथोचित प्राथमिकता नहीं दी, जिससे प्रदेश की जनता को उसका पूरा अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। पिछली सरकार में जल जीवन मिशन में हुए घोटालों की जांच प्रक्रिया में है। ऐसे घोटालों ने देश में राजस्थान की छवि को आघात पहुंचाया है।

Spp/rtm/05.02.2025/18.40/3p

हमारी सरकार आने के बाद निष्पक्ष परीक्षाओं का आयोजन करके सरकार ने जहां युवाओं व बेरोजगारों के मन में विश्वास व आशा का संचार किया है, वहीं विगत वर्ष में लगभग 60 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। पांच वर्षों में 4 लाख नौकरियां देने का संकल्प सरकार ने लिया है। सरकार ने वर्ष 2025 में 81 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर भी जारी कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में समानता है। पूर्ववर्ती सरकार के समय मैं भी इस सदन में था, वह कहती क्या थी और करती क्या थी। उनकी हर बात में फर्क था। हमेशा नाथी का बाड़ा के अलावा कुछ भी नहीं चलता था। पूरे पांच साल तक नाथी का बाड़ा चला, वह सब आपके सामने है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, चिकित्सा एवं अन्य सभी क्षेत्रों में काम ने गति पकड़ी है। ERCP का MOU हुआ। ऊर्जा के क्षेत्र में MOU करने से ऊर्जा तंत्र को नई ऊर्जा मिली है। मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं है कि विगत सरकार के समय थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझते रहे। हमारी सरकार ने

1.58 लाख करोड़ के MOU करके 33 हजार 138 मेगावाट की परियोजना को मूर्त रूप देने का काम प्रारंभ किया। वही प्रसारण तंत्र के लिये भी 10 हजार करोड़ का MOU हुआ और पहले वाली सरकार, जब हम यहां थे, हमारे गांव में, क्षेत्र में जाते ही जनता घर पर आ जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी। लाइट का नाम कभी आता नहीं था। खेतों में मोटरें चलाते तो पानी नहीं पहुंचता उससे पहले तो लाइट बंद हो जाती थी। काफी देर बाद लाइट आती थी, वह सब आपके सामने है। माननीय सभापति महोदय, आम किसान और मजदूर दिन में मजदूरी करने जाता था और शाम को घर पर आता था तो घर पर आते ही लाइट बंद। एक किसान परिवार, एक गरीब परिवार घर पर आने के बाद अंधेरे में कैसे खाना बनाता है, वह आपके सामने है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री, विकास पुरूष भजनलाल जी शर्मा के आने के बाद आज शाम के समय पूरी लाइट मिल रही है और खेतों में भी लगातार छह घंटे लाइट आ रही है, यह आपके सामने है। आने वाले समय में जो MOU किये हैं, वे धरातल पर उतरेंगे तो राजस्थान में 24 घंटे लाइट आयेगी। 2027 में हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया जो आपके सामने है। हमारे नेता जो कहते हैं, वह करते भी हैं। आपके नेता जादूगरी दिखा देते हैं। हम सब जादू देखते थे केवल और वास्तव में रिजल्ट जीरो आता था। यह चीज भी आपके सामने है। जूली जी भी हमारे साथ थे। आप भी उस समय मंत्री थे, आप भी देखते थे। क्या करें, कोई उस समय सुनने वाला नहीं था।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राजस्थान की प्रगति का दस्तावेज है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। इस अभिभाषण में सभी क्षेत्रों के नवीनतम प्रगति के आंकड़ों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। राइजिंग राजस्थान, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करके 35 लाख करोड़ के निवेश की बुनियाद रखने के लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में 11 नये औद्योगिक क्षेत्रों के लिये भूमि का आंवटन भी खोले गये हैं। प्रदेश में 11.17 लाख परिवारों को नल से जोड़ा गया है। 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में अटल भूजल योजना की क्रियान्विति की जा रही है। विगत एक वर्ष में 01 लाख 10 हजार कृषि व 5 लाख 6 हजार घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी हुए हैं। प्रदेश में 5 राजकीय व 3 निजी मेडिकल कॉलेज खोले गये हैं। चिकित्सा विभाग में 15 हजार 500 पदों पर नियुक्तियां दी गयी हैं। प्रदेश की संवेदनशील व कृषि हितैषी सरकार ने मुख्य मंत्री कृषि सम्मान निधि योजना में 2 हजार रुपये अतिरिक्त दिये हैं। हमारी सरकार जो कहती है, वह करती भी है। यह चीज आपके सामने है।

माननीय सभापति महोदय, 01 हजार 357 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में जमा करवाए गए। किसानों को प्रदेश में 25.51 लाख मीट्रिक टन यूरिया व 6.84 लाख मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया। प्रदेश में 01 हजार 40 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। हम पिछले समय में पांच साल यहां थे तो गरीब आदमी को राशन नहीं मिलता था और

प्रधान मंत्री आवास के लिये कुछ भी फार्म भरने की सुविधा नहीं थी। अभी हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने आम आदमी के लिये पोर्टल खोल रखा है। राशन से कोई भी वंचित नहीं रहे। जिसके पास मकान नहीं है, उनके लिये पोर्टल खोल रखा है।

माननीय सभापति महोदय, गत दिनों हमने गणतंत्र दिवस मनाया। भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए संविधान से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे संविधान की मूल प्रति को योजनाबद्ध रूप से आपने प्रचलन से बाहर कर दिया। भारतीय संविधान की मूल प्रति पर भगवान राम, बुद्ध, महावीर, छत्रपति शिवाजी सहित कई महापुरूषों व तीर्थों के चित्र बने हुए थे, लेकिन हमारी वर्तमान पीढ़ी इस तथ्य से अवगत नहीं है, क्योंकि संविधान की मूल प्रतियां बाहर या तो आयी नहीं और आयी तो न्यून संख्या में आयीं। यहां तक कि विधि के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में संविधान की इबारत तो पढ़ा दी जाती है लेकिन भारतीय संविधान का यह पक्ष जानने में हमारे विद्यार्थी भी अछूते रहे गये। मेरा निवेदन है कि संविधान की मूल प्रति का यह पक्ष पाठ्यक्रम में जोड़ा जाये और संविधान की मूल प्रति की प्रतियां आमजन को उपलब्ध करायी जायें। सरकार इसकी व्यवस्था करे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं समय की सीमा को देखते हुए विस्तृत आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के हौंसले और विकास के संकल्प को प्रणाम करता हूं।

'जब हौसला बना लिया ऊंची उडान का
फिर देखना फिजूल है, कद आसमान का।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): एक मिनट और लूंगा। मुझे प्रतिपक्ष के मित्रों के वक्तव्य सुनकर आश्चर्य हुआ। इन मित्रों को यह काम दिखते ही नहीं। मैं हमारे विपक्ष के मित्रों का ध्यान दिलाना चाहता हूं नवम्बर, 2024 में प्रदेश में 7 विधान सभा सीटों के उप चुनाव हुए। उसके परिणाम आप सबके सामने हैं। सरकार ने काम किया जब ही रिजल्ट आया। आप सब चुनाव से पहले कहते थे कि एक भी सीट नहीं आयेगी। परंतु आप लोगों से चार सीटें हमने छीन लीं, यह आपके सामने है। सात में से चार सीटें कांग्रेस से छीनी हैं। लेकिन इन प्रतिपक्ष के मित्रों को केवल अपनी बात कहकर उपस्थिति ही दर्ज करानी है। यह जनता सब देख रही और समझ रही है और समय पर अपना निर्णय भी दे रही है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय सभापति महोदय, आधा मिनट और लूंगा। केन्द्र में माननीय नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में और राजस्थान में भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार विकास और प्रगति के नये आयाम साबित कर रही है। मैं डबल इंजन की सरकार के नेतृत्वकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं दो लाइन की कविता समर्पित

करना चाहता हूं।

'उसे गुमान है हमारी उडान कम है,

हमें यकीन है कि आसमान कुछ कम है।

श्री सभापति: श्रीमती शिमला देवी।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर एक साल ...(व्यवधान)..

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): इस देश में, प्रदेश का कीर्तिमान बनाने के लिये मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी व सरकार को बधाई देते हुए अभिभाषण के लिये राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत। जय जय राजस्थान।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): आप सभापति महोदय, इनका स्पीकर बंद करिए। आप अब मेरा समय स्टार्ट कीजिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सदन के अन्दर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद और चर्चा हम सुन रहे हैं कि एक साल के अन्दर भाजपा की सरकार ने क्या काम किया। महिला, पुरूष और श्रमिक सभी का आपने समग्र विकास किया और पिछले तीन सदन हमने देखे हैं, तीनों सदनों के अन्दर हमने कांग्रेस पार्टी को कोसते हुए ही देखा। कांग्रेस ने यह नहीं किया, कांग्रेस ने वह नहीं किया तो जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया? एक साल में आपने क्या किया? आपने एक साल के अन्दर ऐसा क्या काम किया धरातल के ऊपर, आप वह बताइये। आपने जो काम किये, वह मैं आपको बताती हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: प्लीज बिराजिये। ..(व्यवधान)..

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): क्या कह रहे हो?

एक माननीय सदस्य: नाम सही नहीं आ रहा है।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक साल के अन्दर भाजपा ने क्या काम किया? मैं आपको बताती हूं।

सुशीला की जगह मेरा नाम था। माननीय सभापति महोदय ने शिमला देवी का नाम पुकारा है, उसी के हिसाब से मैं बोल रही हूं। ..(व्यवधान).. सर, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। आप इतने सम्माननीय सदस्य बोलते हैं तो मैं एक बार भी आपके बीच में खड़ी नहीं होती, न हम बीच में बोलते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नाम चेंज आ रहा है, उसे ठीक करवा रहे हैं। इतना डिस्टर्ब मत करो। कोई बात नहीं। शिमला जी बोल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): आसन से शिमला देवी पुकारा गया तो मैं खड़े होकर मेरी बात कह रही हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नाम सही हो गया, अब बोलो आप।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): आप सभी मेरे सीनियर हैं और सम्माननीय हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि हम आपसे सीखते हैं, लेकिन बार-बार आप डिस्टर्ब करते हो, यह बात आपको शोभा नहीं देती है। यह सदन की मर्यादा नहीं है।

एक साल के अन्दर भाजपा ने क्या किया, वह मैं आपको बताती हूं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनूपगढ़ को जिला बनाकर 12 साल का जनता का मान और सम्मान रखा। जनमानस की भावना को देखते हुए जिला बनाया, लेकिन आपने 28 दिसम्बर, 2024 को अनूपगढ़ जिले को निरस्त करके वहां की जनता की भावना को आपने ठेस पहुंचाई। यह निर्णय आपने राजनीतिक विद्वेषतापूर्ण किया। आपने भौगोलिक, सामरिक, जनसंख्या हर दृष्टि से देखते हुए हमारा अनूपगढ़ क्षेत्र डिजर्व करता था। आपने डीग को कैसे रखा, क्योंकि वह माननीय मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला आता था। डीग की हैडक्वार्टर से दूरी मात्र 38 किलोमीटर थी, जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर बैठे हुए गांव की दूरी 225 किलोमीटर है।

jyg/rtm/05.02.25/18.50/3q

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि 2008 के अन्दर प्रतापगढ़ जिला बना था उस वक्त माननीय मुख्य मंत्री हमारी माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया जी थी। वो जिला भी चुनाव से छह महीने पहले बना था। चुनाव जस्ट हुए उसमें भाजपा के विधायक बने थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत जी ने प्रतापगढ़ जिले को निरस्त नहीं किया था, उसे यथावत रखा था। हमारे भी जब अनूपगढ़ को जिला बनाया गया उस वक्त लगातार भाजपा के विधायक थे, वहां सांसद थे, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने जनता की भावना को देखते हुए जिला बनाकर दिया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि जब प्रतापगढ़ और अनूपगढ़ की तुलना करते हैं तो जनसंख्या भी 7 लाख है, तहसीलें भी 5 हैं, उप खण्ड भी 4 हैं, क्षेत्रफल देखें तो 1520 और 1820 वर्ग किलोमीटर है। हर क्षेत्र से वो समान है, जब प्रतापगढ़ जिला रह सकता है तो अनूपगढ़ क्यों नहीं रह सकता?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करती हूं कि अनूपगढ़ को आप जिला बनायें, उस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ मेरा क्षेत्र है और वहां पर अंतिम क्षेत्र की दूरी मुख्यालय से बहुत दूर है, 225 किलोमीटर के आसपास है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ महामहिम राज्यपाल जी के भाषण में हमने देखा कि किसान की बहुत बड़ी बात कही गयी, लेकिन आज भी किसान सड़क पर है। किसान फसल पकाव के लिए भी सड़क पर रहता है, पकी हुई फसल को बेचने के लिए भी

सड़क पर रहता है, उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। माननीय सभापति महोदय, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करती हूं कि आईजीएनपी की प्रथम चरण शाखा के लिए हमारे 5 फरवरी तक रेगुलेशन है उसको नया जारी करें, क्योंकि डैम का लेवल 1305 फीट है, और बहुत बार जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसके अन्दर 1270 फुट डैम के लेवल को डाउन करके किसान की रबी की फसल, गेहूं, सरसों, चना, को पकाया गया है। 1300 जब डैम का लेवल डाउन करके आठ बार किसानों को पानी दिया गया है और हमारी फसल को पकाने का काम किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि यह सरकार तुरंत प्रभाव से बीवीएम बोर्ड, भाखड़ा-व्यास मैनजमेंट बोर्ड की तुरंत प्रभाव से बैठक बुलाकर अन्य राज्य चाहे वो पंजाब है या हरियाणा है, उनसे मांग करके, उनसे बातचीत करके हमारे किसानों को रबी की फसल के लिए पानी दिया जाये, अगर आपने पानी नहीं दिया तो 10 तारीख को वहां हमारे किसान महा पड़ाव डालेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज मैंने आपके माध्यम से देखी है, इसके अन्दर यह बात कही गयी है कि मूंग के बीज की, जब तक आपने मूंग की खरीद चालू की, हजारों क्विंटल मूंग किसान बेच चुका था और प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को दो से ढाई हजार रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ था, क्योंकि नियम यह कहते हैं कि कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत एमएसपी पर सरकार खरीदेगी, लेकिन दो दिन मात्र आपने पोर्टल चालू किया और किसान को बहुत बड़ा आपने नुकसान किया। आपके घोषणा पत्र के अन्दर हमने देखा कि बहुत वाह-वाही लूट रहे हैं, 125 रुपये हमने गेहूं पर बोनस दिया है जबकि आपके घोषणा पत्र में आपने कहा था कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर हम गेहूं खरीदेंगे। आपने 275 रुपये प्लस 125 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदा तो यह 2400 रुपये हुआ।

माननीय सभापति महोदय, आपने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की बात की। 2699 करोड़ रुपये हमने किसानों को फसल बीमा का दिया है, लेकिन मेरे रावला क्षेत्र की 3500 रुपये आपने प्रीमियम काटा।

श्री सभापतिः एक मिनट में समाप्त कीजिये।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): किसानों को 257 रुपये, और बड़े शर्म की बात है कि 36 रुपया किसानों के खातों में प्रीमियम आया। आप डीएपी की बात करते हो, आज भी किसान सड़क पर, आज भी किसान रात भर लाइन में लगता है और अपने उस चीज की मांग करता है। आप हमें मीट्रिक टन यूरिया और डीएपी देने की बात करते हो।

श्री सभापतिः आप समाप्त कीजिये।

श्री हरलाल सहारण जी।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): हमने 108 करोड़ रुपये दिये, लेकिन आईजीएनपी में आपने एक भी रुपया नहीं दिया। स्वास्थ्य के बारे में अंत में एक मिनट में अपनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय सदस्य, आप बैठिये। माननीय सभापति महोदय,

मेरा टाइम शुरू नहीं हुआ है, मैं वैसे ही खड़ा हुआ हूं।

श्री सभापति: प्लीज।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): आप कह रहे हैं कि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाये।

(स्वीकृत)

श्री सभापति: सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया गया।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा लोकतंत्र के सर्वोच्च मन्दिर में दिये गये भाषण पर अपनी बात रखने खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले तो मैं मेरी चूरू की जनता को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि एक छोटे से किसान के बेटे को इस विधान सभा में भेजा है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 1 से 44 तक 168 बिन्दुओं को मैंने ध्यान से पढ़ा है, जिस पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकार की भजन लाल सरकार ने एक वर्ष में शानदार ऐतिहासिक फैसले लिये हैं। यह सरकार पहली सरकार है जिसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में अपनी उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, हमारे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी के सामने रखा। राजस्थान बनने के बाद यह पहला अवसर था जब प्रधान मंत्री मोदीजी ने पहली वर्षगांठ पर 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये के शिलान्यास और उद्घाटन की स्वीकृतियां जारी कीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार के मुखिया भजन लाल जी को जिन्होंने पांच साल के कार्यकाल में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया है।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा संख्या 36 पर सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अब तक 81 हजार पदों की भर्ती का कैलेण्डर जारी कर दिया जा चुका है तथा 60 हजार भर्तियां दी जा चुकी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। गत कांग्रेस सरकार की अंतर्कलह को पांच साल तक लगातार आम जन देखता रहा। अंतर्कलह से ही कांग्रेस ने सत्ता खोयी। वो ही अंतर्कलह आज जारी है। उप चुनाव में हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, यहां गमछा हिलाने वाले बाहर चले गये। ये कह रहे थे हमको, ठुमका लगा रहे थे कि आप बाइ-इलेक्शन में कैसे जाओगे? इनसे पूछ लीजिये कि अब आपके हालात क्या हुए, सात में से चार में तो जमानत जब्त, जहां रामगढ़ में सीट जीतने वाली थी, वहां अशोक गहलोत जी ने कहा कि अध्यक्षजी, वापस जाओ, वहां गमछा हिलाओ ताकि अपन जीत जायें तो जो जीतते उसको भी हरा दिया।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इनकी कई बातों को देखकर तरस भी आता है। मैं आपकी कृपा से हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा और मैं भूल नहीं पाऊंगा, यहां पर लगातार 35 साल इस विधान सभा में लाइब्रेरी के नाम से काम करने वाले मेरे गुरु राजेन्द्र राठौड़ को भी कि उन्होंने इस पार्टी को भी बहुत कुछ दिया और मेरे को यहां तक भेजने में बड़ा योगदान रहा।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यहां देखकर मैं कई बार सोच रहा हूं कि इतने बड़े सीनियर लीडर सामने बैठे हैं और इतना सफेद असत्य बोलते हैं, बड़े शर्म की बात है। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, सांप-घोयरा सदा ही देख्या, अजगर अबके देखो। सांप-घोयरा तो सदा ही देख्या, अजगर अब देखो। कहने का मतलब है कि मैं पंचायत समिति से लेकर जिला प्रमुख से लेकर, मैं सदनों में रहा हूं मगर यहां पर जिस तरह का वातावरण देखा मैंने विपक्ष के सदस्यों का, करना कुछ नहीं है, उसके बाद भी एकदम असत्य का पुलिंदा बोलते हैं। ...(व्यवधान)... आप कह रहे हो, मैं किसान की बात करने वालों से पूछना चाहता हूं कि पांच साल में किसान की एक ढाणी नहीं की आपने, आप यहां पर खड़े होकर कहते हो कि गांव का आदमी, किसान खेतों में बसता है। आप कहां गये थे? किसान की बात करते तो एक ढाणी तो करते, जब 2015 में वसुन्धराजी की सरकार थी, 2019 तक हजारों-लाखों ढाणियों में किये हैं। हम जो छोड़ गये थे उनको वापस हम ही करेंगे, 2019 की बाकी बची ढाणियां अब भी बाकी हैं।

अभी रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, एक ढाणी नहीं की, 3737 ढाणियां अभी स्वीकृत हुई हैं, चालू हैं। यह राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार की करामात है। कांग्रेस सात सीटों में जीतने वाली आज अंतर्कलह से जूझ रही है, शायद कांग्रेस के बड़े नेता बार-बार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक में शामिल बड़ी मछली सरकार पकड़ क्यों नहीं रही है? इशारों-इशारों में हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को याद दिला रहे हैं।

MLS/RTM/05.02.2025/19:00/4a

हमारा एक नेता मगरमच्छ बाहर क्यों घूम रहा है। अब बैठे तो नहीं है, मैं नहीं कहूंगा, मगर यह पता नहीं है। सास को कभी यह पता नहीं होता कि बहू बनकर झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सास भी कभी बहू बनकर आती है घर में। मैं सदन का ध्यान महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा नं. 28 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देगी। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी मेरे साथ बैठे हैं, आज की तारीख में मैं दावा कर सकता हूं, पूरे 6 घंटे किसान को बिजली मिल रही है और कांग्रेस की आपकी

पिछली सरकार में 4 घंटे भी नहीं मिली। यह मेरा दावा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में राइजिंग राजस्थान में एनर्जी उत्पादन के लिए 22 लाख करोड़ के एमओयू कुसुम योजना पर हुए, जो सिद्ध कर रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान के किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी। अभी कह रहे थे, माननीय सदस्य बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पता नहीं, किस पर आरोप लगा रहे थे पता नहीं, क्यों लगा रहे थे पता नहीं। एक तो बहुत सीनियर माननीय सदस्य कह रहे थे कि 6 महीने से पेंशन नहीं मिली। हमारे मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे। उन माननीय सदस्य को यह पता ही नहीं था कि 10 दिन पहले दिसम्बर तक सारी पेंशन लोगों को मिल गयी। माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, उन्हें बताते हैं नहीं, उनकी क्लास लेते हैं नहीं, उन्हें पता है नहीं कि कहना क्या है, बोलना क्या है। आप देख ही रहे हैं कि कितनी संख्या में बैठे हैं। कितना जनता को विपक्ष पर भरोसा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर बोलें तो कम से कम तथ्यों के आधार पर बोलें ताकि नेता, प्रतिपक्ष की भी बात रहे कि मेरा विपक्ष यहां बैठा है तो सही बोल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि जहां कांग्रेस सरकार में कर्जा माफी की जगह 19 हजार किसानों की नीलामी हुई थी और दर्जनों किसानों ने आत्महत्या की थी, वहीं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी की सरकार ने दिसम्बर 2024 में 16700 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त आपातकालीन फसली ऋण 30 लाख किसानों को देकर लाभान्वित किया था।

विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि कितने नये लोगों को दिया है। मेरे सामने सरदारशहर से और सुजानगढ़ से विधायकगण बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा, 1699 लोगों को अभी नये ऋण दिये हैं। नये-पुराने तो आपकी सरकार भी करती थी, पर 1600 कुछ लोगों को अभी दिये हैं नये और आप पूछ रहे हैं कितनों को दिये। अब राजस्थान का तो देख लेना। किसान सम्मान निधि में हमारी सरकार ने 70 लाख किसानों को कहा था, 2 हजार रुपये सम्मान निधि देकर 6 से 8 हजार रुपये किया है। मैं विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि कभी आप 100 रुपये भी देते न हर साल तो किसान को कितनी सम्मान निधि होती। आप किसान की बात करते हैं, किसान का चोला पहनकर आते हैं, कभी कहते हैं गरीब की कोई सुनने वाला नहीं, अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति की कोई सुनने वाला नहीं।

अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सुनने वाला था न, उसका नाम था स्व. भैरोंसिंह शेखावत। गरीब की बात करने वाले आप याद कर लें वो दिन। आप शिक्षा की बात करते हैं, आपने सिर्फ काम क्या किया, ''फूट डालो, शासन करो'', गरीब गरीब ही रहेगा, अनपढ़ रहेगा तो वोट देगा। यदि गरीब पढ़ जायेगा तो वोट नहीं देगा। अभी मेरे कुछ एससी के भाई बात कर रहे थे। आपको पता नहीं है, वसुन्धरा जी की सरकार में विपक्ष में एक सदस्य नहीं था, याद कर लें उस दिन को। आप बात करते हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका टाइम हो गया।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): सर, 10 मिनट थे मेरे।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट है अब। वाइंड-अप करें।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): मैं केन्द्र सरकार को क्रेडिट देना चाहता हूं कि जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में योजना लागू करने की घोषणा की है, उसमें मैं चाहूंगा कि मेरा चूरू जिला भी शामिल किया जाये। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राजस्थान और हरियाणा का चूरू, सीकर तथा झुंझुनूं के लिए यमुना जल समझौता किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि प्यासी धरती को पानी मिलेगा, किसान को पानी मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय फतेहपुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चिकित्सा मंत्री जी निकल गये, सबसे पहले मैं चिकित्सा की बात करूं तो हमारी सरकार ने जो मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना लागू की थी, उसका क्या हाल हो रहा है अब, चिरंजीवी और आरजीएचएस दोनों का ही। आरजीएचएस में आप और हम भी आते हैं, जबकि चिरंजीवी में आम आदमी आता है। चिरंजीवी में आम आदमी के ऊपर, चाहे सरकार आपकी हो या हमारी, कोई मेहरबानी नहीं थी, वह अपने 850 रुपये प्रीमियम जमा कराकर इंश्योरेंस ले रहा था। उसे भी आपने कम कर दिया। कम तो कर ही दिया, न किसी को इलाज मिल रहा है, न किसी की जांच हो रही है, न किसी को दवाई मिल रही है।

गरीब, किसान, मजदूर पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज लेता था, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने जब यह चिरंजीवी योजना लागू की तो उसके बाद वह गरीब, किसान, मजदूर प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इलाज लेने लग गया था। उसका भी मन करता था कि मैं भी लूं। उस योजना को आप लोगों ने बन्द किया है या इंश्योरेंस कम्पनियों को पैसे नहीं दे रहे हैं या क्या है? जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को फोन करते हैं कि चिरंजीवी में इलाज करोगे, तो कहते हैं कि बजट नहीं आ रहा है। आरजीएचएस की यह हालत हो रही है कि उसके लिए हम जब खुद हॉस्पिटल जाते हैं दिखाने के लिए तो हॉस्पिटल वाले यह कहते हैं कि आरजीएचएस का पेमेंट नहीं आ रहा है, हम आरजीएचएस में इलाज नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा चिकित्स मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि थोड़ा इस पर ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बात करूं गैस सिलेंडर की तो आपने गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने की घोषणा की और दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारे मुख्य मंत्री ने 500 रुपये में देने की घोषणा की। ...(व्यवधान)... मैं आप जो बात बोल रहे हैं, वहीं बोलूंगा। गोपाल जी, आपकी ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। उज्ज्वला योजना, जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने भारत सरकार की तरफ से लागू की थी, वह सिर्फ एक बार गांव के गरीब मजदूरों को गैस सिलेंडर

फ्री दिया था, जब वह दोबारा भराने के लिए गया तो उससे कहा कि 850 रुपये लगेंगे। उस मजदूर, गरीब किसान ने उस सिलेंडर को अपने घर में ले जाकर खाली रख दिया था, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उस उज्ज्वला योजना के जो भी धारक हैं, उन सबको अशोक गहलोत जी ने 500 रुपये में सिलेंडर देने की योजना लागू की थी। आप लोगों ने फिर 450 रुपये की घोषणा की। आपने 50 रुपये कम किये, क्या मेहरबानी की? 50 रुपये ही तो कम किये। आप करते तो पूरे भारत में करते। जहां-जहां आपकी सरकार थी, वहां करते, तब मानते कि आपने लोगों को गैस सिलेंडर में राहत दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्री जी आ गये हैं। बिजली की बात करूं। बिजली की बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। किसानों के लिए होती हैं, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी होती है, लेकिन किसानों की हालत क्या है? चाहे सरकार आपकी हो या हमारी, किसान पीड़ित हैं कि किसानों से डेढ़-डेढ़ साल से पैसे लिये हुए हैं डिमांड नोटिस के और उन किसानों के कनेक्शन नहीं हो रहे। ...(व्यवधान)... सुन लें मेरी बात, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपका जब था, आपने भाषण कर दिया।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): ...(व्यवधान)... मैं कह रहा हूं न। कृपलानी जी, मैं कह रहा हूं न। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं सौभाग्यशाली हूं कि जब मैं पिछले बजट में पहले बोला, उस टाइम भी माननीय मुख्य मंत्री जी आये थे और आज भी आये हैं, आपको सुनेंगे।

mkd/rtm/05.02.2025/19:10/4b

कृपलानी जी, मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सरकार हमारी हो आपकी हो, किसान पसीज रहा है, एक साल से किसान के डिमांड नोटिस के पैसे जमा हो गये हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। उस किसान का क्या कसूर है कि उसने एक साल से डिमांड नोटिस के पैसे जमा करा दिये हैं, लेकिन उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा है? अगर बिजली का बिल..

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका जब नम्बर आये, तब आप भी बोलना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सदन के नेता बैठे हैं, उसके बावजूद आप सब बोल रहे हों, कुछ तो सदन की गरिमा रखो।

श्री अध्यक्षः बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अगर बिजली का बिल जमा कराने में एक दिन लेट कर देता है तो उसको पैनल्टी दी जाती है और किसान के डिमांड नोटिस का पैसा लिये सरकार बैठी है, सरकार आपकी हो या हमारी हो, उस किसान का क्या दोष है? उसने ब्याज पर लाकर डिमांड नोटिस के पैसे जमा करवाये और उसको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, तो क्या दोगे आप?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): लगातार असत्य बोल रहे हैं।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): कृपलानी जी, प्रूफ दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रूफ दूंगा। एक साल से डिमांड नोटिस जमा है, मैं प्रूफ लाकर दूंगा। उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप इधर देखकर बोलें। माननीय सदस्य, उधर जवाब मत दो, अध्यक्ष को सम्बोधित करके बोलें। आपका टाइम हो रहा है।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): मैं आपको इंगित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रूफ दूंगा कि किसान का एक साल से पैसा जमा है और उसको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। अगर आप चाहे तो मैं कल ही प्रूफ पेश कर दूंगा तो फिर मैं क्या कह रहा हूं। ये कृपलानी जी कह रहे हैं, एक भी बाकी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाता है और किसान फोन करता है, लाइन मैन को कहता है या अधिकारी को फोन करता है कि मेरा ट्रांसफार्मर जल गया है। लाइन मैन कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, एईएन साहब को फोन करो। एईएन साहब को फोन करते हैं तो कहते हैं कि एक्सईएन साहब को फोन करो और किसान के पास लाइन मैन के अलावा एईएन, एक्सईएन के नम्बर बहुत कम मिलते हैं और मिलते हैं तो एक्सईएन साहब कहते हैं कि एसई साहब को फोन करो और एसई साहब फोन उठाते ही नहीं हैं।

जब हमारे पास फोन आता है, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का जनप्रतिनिधि, उनके पास फोन आता है तो वे एसई को फोन करते हैं, तब जाकर किसान को ट्रांसफार्मर मिलता है। ट्रांसफार्मर मिलता है तो किसान को यह कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर बिजली बोर्ड में पडा है, गाड़ी भेजकर ट्रांसफार्मर मंगवा लो, आपके खेत में ट्रांसफार्मर लगा दिया जायेगा। एक किसान के पास गाडी है, एक किसान के पास नहीं है, सब किसानों के पास गाड़ी नहीं होती है। फिर भी, उसको ढाई-तीन हजार रुपये में किराये की गाड़ी लेकर, ट्रैक्टर लेकर के उस ट्रांसफार्मर के लिए किसान को जाना पड़ता है, तब जाकर किसान को ट्रांसफार्मर मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसानों की सुनो, किसानों को बिजली दो और आप बार-बार कह रहे हो, पिछले 4-6 महीने पहले बिजली की क्या हालत थी। टाइम हो गया क्या?

शिक्षा की बात करूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं। शिक्षा मंत्री जी का तो कहना ही क्या है, कुछ भी बोल जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): 100 दिन की कार्ययोजना माननीय मंत्री जी ने बनाई कि कार्ययोजना के तहत अध्यापकों के लिए तबादला नीति बनायेंगे, जो आज तक नहीं बनाई। शिक्षक बैठे हैं कि हम हमारे जिले में जायेंगे, तहसील में जायेंगे, वह नीति आज तक नहीं बनी। आपने कहा था कि 100 दिन में बना देंगे और 100 दिन में बनाकर तबादला नीति को लागू कर देंगे, जो आज तक भी नहीं बनी।

आपने स्कूल खोलने की बात की, आपकी बहुत अच्छी घोषणा थी कि हम स्कूल खोलेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको बताना चाहूंगा कि विकास की क्रमिक अवस्था, नवजात शिशु किशोर से युवा बनता है, सरकार हमारी आती है तो इस नवजात शिशु को हम युवा अवस्था में खड़ा कर देते, लेकिन आपकी सरकार और आपके द्वारा सिर्फ नाम परिवर्तन करने का काम गत एक वर्ष में किया गया है। एक साल में नाम परिवर्तन के साथ-साथ आपकी सरकार छिद्रान्वेषण, आलोचना और जांच कर देंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाई। एक साल में दस योजनाओं से अधिक का नाम बदलने से क्या हुआ? राजीव गांधी युवा मित्र आप कोई और नाम कर देते।

श्री अध्यक्षः वाइंड अप कीजिये। आपका टाइम हो गया।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): आपने 450 स्कूलें बन्द कर दीं, खोलने की बात की थी। पीएचईडी मंत्री जी बैठे हैं, पीएचईडी के अन्दर हालत यह है कि आज भी एक ट्यूबवैल की अगर मोटर जल जाये तो अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, मोटर कहां से लाये। पाइप लिकेज निकालने के लिए, गांवों में पाइपों की लिकेज नहीं निकली है, हम अधिकारियों को मीटिंगों में कहते हैं तो कहते हैं कि, साहब, बजट नहीं है।

श्री अध्यक्षः श्री विक्रम सिंह जाखल। विराजिये।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की 16वीं विधान सभा के इस तीसरे सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय ने अंत्योदय के आदर्शों को आत्मसात करने वाली इस जनकल्याकारी सरकार की महत्वाकांक्षी नीतियों और कार्यक्रमों और उपलब्धियों को सदन के समक्ष रखा, मैं माननीय राज्यपाल महोदय का कोटि-कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत यह अभिभाषण सरकार के पिछले एक वर्ष में प्रदेश में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के साथ युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के अनुसार समाज के हर तबके के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण की भावना का पर्याय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व वाली इस कल्याणकारी सरकार ने पिछले एक वित्तीय वर्ष में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं को केन्द्र में रखकर प्रदेश के हर क्षेत्र कृषि, पशुपालन, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल, पर्यटन, मजदूर वर्ग के साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विकास का अनूठा संगम प्रस्तुत किया, जिसने प्रदेश के जनमानस के मन-मस्तिष्क में एक विशेष छाप छोड़ी है।

प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व में पिछले एक वर्ष में, गत सरकार में पांच सालों की भ्रष्टाचार की काली करतूतें चाहे वो पेपर लीक हो, खनन घोटाला हो, जल जीवन मिशन घोटाला हो, सहित समाज के प्रत्येक तबके के साथ और उसके जनमत के साथ छलपूर्ण व्यवहार किया गया। चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे महिलाओं के

साथ दुर्व्यवहार हो, इस पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने कड़ा रुख अपनाया, लगाम लगाई।

साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा, कल हमारे इस सत्र में हमारी विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा बीसलपुर से सम्बन्धित सात करोड़ रुपये के बजरी खनन सम्बन्धित घोटाले का जिक्र सदन में किया गया। मैं बताना चाहूंगा, आपका ध्यान गत सरकार के खनन विभाग के आज तक के राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़े लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के घोटाले की ओर ले जाना चाहूंगा। पिछली सरकार के समय में भरत सिंह जी सांगोद ने निरन्तर मुख्य मंत्री जी को लेटर लिखा और जांच करवाने के लिए लिखा था कि इसकी जांच करवाई जाये, सबूत सहित है मेरे पास, ऐसे नहीं बोलूंगा, जब आया हूं तो कुछ लेकर आया हूं।

आपको यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड से सम्बन्धित टेंडर प्रक्रिया और शर्तों में हेराफेरी कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्व खान मंत्री महोदय ने खनिज क्षेत्र में सबसे बड़े सावर्जनिक उपक्रम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड की साख को मिट्टी में मिला दिया। इस बारे में हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने भी एक सार्वजनिक सभा में जिक्र किया था, भाया रे भाया तूने खूब खाया, एक गांव को भी तूने नहीं छोड़ा। देश के प्रधान मंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में यह कहा है, सार्वजनिक सभा में।

अध्यक्ष महोदय, अगर आपका संरक्षण मिलता है तो मैं सदन के समक्ष इस सम्पूर्ण व्यापक घोटाले का विस्तृत ब्यौरा रखने, लगभग पांच हजार करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हो सकेगा। साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पिछले एक वर्ष में गत सरकार के पांच सालों की भ्रष्टाचार की काली करतूतें, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सुरक्षित हाथों में प्रदेश आज जनमानस के बीच बेहतर सुशासन का उदाहरण बनता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, लोककल्याणकारी सरकार के पिछले एक साल के बेमिसाल कार्यक्रम के कुछ महत्वाकांक्षी निर्णयों को सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु 350 बिलियन डॉलर के उद्देश्य को आत्मसात करते हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन किया और प्रदेश के लिए दूरगामी सोच रखने वाले हमारे मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के निवेश की मजबूत नींव रखी।

Bhs/Rtm/05.02.25/19.20/4c

जिसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले वक्त में भर्ती व कौशलपूर्ण माहौल में हमारे युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे और अवश्य ही प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के समिट का एक नया अध्याय लिखेगी। इसके साथ ही राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने में वित्तीय वर्ष 2024 में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति, राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति राज्य के विकास में अहम साबित होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में दशकों से राजनीतिक द्वेषता के कारण अटके पड़े महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट यमुना जल समझौते को माननीय मुख्य मंत्री जी व केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी के अथक प्रयासों से डबल इंजन की सरकार ने इस कार्य का एम.ओ.यू. करवाया जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस सौगात ने इस क्षेत्र के जनमानस में समृद्धि व खुशहाली के नये युग की शुरुआत कर आधारशिला रखी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं जो इस प्रकार है, पी.एम. मोदी जी के कैच द रेन कार्यक्रम को कर्म भूमि से मातृ भूमि अभियान के रूप में अपनाया जो भविष्य के लिए राजस्थान में जल सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। पी.एम. किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना लागू कर प्रदेश के किसानों को 2 हजार रुपये अतिरिक्त देने का प्रावधान किया। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना लागू कर 450 रुपये में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर प्रदान कर मुख्य मंत्री जी ने महिला सशक्तीकरण व सहयोग में एक वन्दनीय पहल की। एक पेड़ मां के नाम, प्रधान मंत्री जी के इस विशाल कार्यक्रम में राजस्थान को हरित राजस्थान के रूप में विकसित करने के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार में प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र अन्धेरे में डूबा रहा। प्रदेश का जन-जन इससे वाकिफ है। हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कोयले का खनन पुनः प्रारम्भ करवाया, जिसके परिणामस्वरूप आज हमारी थर्मल इकाइयों को भरपूर कोयला मिल रहा है जिससे प्रदेश आज ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। गत सरकार में जल जीवन मिशन के व्यापक घोटाले में पूरा प्रदेश बदनाम हुआ। अब हमारी सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता महत्वपूर्ण विषय है। गत सरकार में पेपर लीक घोटाला और भ्रष्टाचार में पूरे देश में राजस्थान हंसी-मजाक का पात्र बना। हमारी सरकार बनते ही लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में एस.आई.टी. गठित कर गत सरकार द्वारा की गई भर्तियों के घोटालों को उजागर कर दोषी व्यक्तियों को जेल में पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में मात्र एक वित्तीय वर्ष में लगभग साठ हजार के करीब नियुक्तियां मिल चुकी हैं और 2025 वित्तीय वर्ष में 81 हजार पदों पर भर्तियों का कलेंडर जारी करना हमारे युवाओं के प्रति सरकार का संवेदनशील कदम है। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान कर सम्बल प्रदान किया, लोकतंत्र सेनानियों के लिए लोकल व एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं देकर इनका मान और सम्मान बढ़ाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने खेल के क्षेत्र में खिलाडियों के लिए मिशन ओलम्पिक 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में राजस्थान टॉरगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम इसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान हित में हमारे मुख्य मंत्री जी ने निम्नानुसार प्रयास किया है - गोवंश संरक्षण हेतु गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का विवरण व पॉलिसियों का सृजन, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम सुलभ कराने के लिए ई-नाम योजना कृषि उजप मंडी व किसानों के बीच सेतु का काम करेगी। गोवंश संरक्षण के लिए गोशालाओं को अनुदान में दस प्रतिशत बढ़ोतरी की गई। पशुपालकों के लिए पशुधन सबसे बड़ी पूंजी है। पशुपालकों को सम्बल देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 400 करोड़ रुपये की मुख्य मंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में महिला सशक्तीकरण में अब नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में गर्भवती, प्रसूता व धात्री महिलाओं के लिए प्रथम बच्चे के जन्म पर स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार के लिए पांच हजार रुपये से बढ़ा कर राशि 6 हजार 5 सौ रुपये कर दी। वहीं दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए यह राशि पांच हजार से बढ़ा कर दस हजार रुपये कर दी। बालिका शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना व बालिका विकास में सरकार की सकारात्मक पहल की।

श्री अध्यक्षः विराजें। माननीय सदस्य, विराजिये, हो गया आपका।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्री अध्यक्षः श्री भगवाना राम सैनी।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभिभाषण के हमारे पेज नम्बर 17 पर मैंने देखा झुंझुनू जिले में यमुना का जल लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लोक सभा का चुनाव था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पधार चुके हैं, पूरे जिले में बड़े होर्डिंग लगे थे, यमुना का पानी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप यह जितना समय गुजर गया बजट के बाद में इसमें कितना आगे बढ़ रहे हैं? सदन में जब जवाब दें तो बताना कि आगे कितना बढ़े हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में हमारे सत्ता पक्ष के साथीगणों की सारी बातें सुन रहा था तो उन्होंने घोषणा की कि हमारी घोषणाएं 90 प्रतिशत पूर्ण हो गयी। मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में आपने 5 ट्यूबवैल दिये, 10 हैंडपम्प सूखे और के अगेंस्ट ट्यूटवैल गहरा कराने के लिए दिये। अभी एक ट्यूबवैल तो गहरा हो गया शायद बाकी न तो पांच ट्यूबवैल आये न हैंडपम्प आये। यह कितनी परसेंटेज है, यह जरा केल्कुलेशन निकाल लेना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जे.जे.एम. के बारे में आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, हकीकत यह है कि लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। मेरा एरिया पहाड़ी बैल्ट है, पानी बहुत गहराई पर चला गया। मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी बोला था। इसमें सोचने की बात यह है कि यह आरोप-प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। गर्मियां आने वाली है, ट्यूबवैल एक भी नहीं लगा है और जे.जे.एम. में ट्यूबवैल लगे हैं तो वह चालू नहीं हैं। टंकियां बन रही हैं तो उनमें

पाइप लाइन नहीं है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जांच कराते रहो, जेल भेजते रहो उससे कोई मतलब नहीं है, जनता को पानी चाहिये, तो सरकार पानी के लिए ठोस कदम उठाये वरना आने वाली गर्मियों में भयंकर स्थिति होगी, लोग सड़कों पर होंगे तो मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल की बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं पिछली बार मॉडल के नाम पर एक सी.एच.सी. दी थी वह अभी तक कहां मॉडल सी.एच.सी. है? बजट घोषणा में दी थी लेकिन अभी तक वहां कोई काम चालू नहीं है। इसके अलावा इतना बंटाढार हो गया विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की बात कर रहा हूं। मेरे 6 गांव सराय, छापोली, मणकसाज, भाटीवाड़, और चंवरा आदि ये 6 पी.एच.सी. ऐसी है जहां कोई डॉक्टर नहीं है 12 महीने से इनमें डॉक्टर नहीं है। दुर्भाग्य है एक मेडिकल जैसी जो मूलभूत आवश्यकता वहां 12-12 महीनों से डॉक्टर नहीं है। इसी तरह दो-तीन सी.एच.सी. हैं उदयपुरवाटी में 6 पद रिक्त हैं और बड़ागांव में 6 में से एक डॉक्टर है। पौंख सी.एच.सी. और उदयपुरवाटी में गुढ़ागौड़जी में एक-एक पद रिक्त है। मेरे उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में अब एक भी कोई सर्जन बड़ा डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात, ट्रोमा सेन्टर बन गया। 6 पद हैं उनमें से एक डॉक्टर है। हमारे यहां जब कोई एक्सीडेंट होता है तो सीटी स्केन कराने के लिए हमको उदयपुरवाटी से सीकर या जयपुर आना पड़ता है। एक भी सीटी स्केन का सेन्टर नहीं है। एक भी फिजीशियन डॉक्टर नहीं है, इतनी बड़ी विडम्बना है। पिछले विधान सभा सत्र में भी मैंने यह मामला उठाया था जबकि ट्रोमा सेन्टर बन चुका है। सारी सुविधाएं हैं अगर नहीं हैं तो उनमें सुविधाएं करनी चाहिये और एक लाख की पापुलेशन है, पचास हजार को नगरपालिका की है बाकी दस किलोमीटर में एक लाख पापुलेशन है। स्थिति इतनी गम्भीर है कि ये लोग मेडिकल जैसी सुविधा के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे यहां जो शिक्षा का मामला है, हम नयी स्कूल सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं चाह रहे हैं, सिम्पल सा निवेदन है कि जो ग्रामीण एरिये की स्कूलें हैं, गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे जाते हैं जो गरीबों के बच्चे होते हैं, बी.पी.एल. के बच्चे होते हैं, जिनके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है, उन स्कूलों के हालात ये हैं कि या तो उनकी छतों में पानी टपक रहा है या पट्टियां टूटी हुई हैं या फिर उनके मकान में कोई दरार आ रही है। सच्चाई यह है कि वहां न तो बैठने की व्यवस्था है और न वहां कोई दरी, टाटपट्टी वगैरह है। मैंने देखा है 5-10 स्कूलों को।

Kas/rtm/05.02.2025/19.30/4d

मेरा आपसे निवेदन है कि गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति को सुधारने का काम करें। हमारी पंचायत समिति उदयपुरवाटी में 12 महीनों से वहां कोई बीडीओ नहीं लगा है, एईएन को चार्ज दिया हुआ है। जो एईएन हमारे यहां बीडीओ लगा हुआ है, उनके खिलाफ हमने शिकायत की है, उनको अब तक 5-6 चार्जशीट मिल चुकी हैं। पंचायत समिति का पैसा बिना वार्षिक प्लान

के, बिना किसी स्टेंडिंग कमेटी के मनमर्जी से पैसा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक अकाउंटेंट महानुभाव तो ऐसे भी हैं जिनका ट्रांसफर हो चुका है, फिर भी वो वहां रजिस्टर में सिग्नेचर कर रहा है। यह क्या स्थिति है, क्या-क्या बोलेंगे इसके बारे में? उनको हटाएं और वहां स्थायी बीडीओ लगाएं।

इसके पेज नंबर 64 में कहा गया है कि 25,51,000 मैट्रिक यूरिया और 6,84,000 मैट्रिक टन डीएपी, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं हमारे हिस्से का डीएपी-यूरिया नहीं दिया गया है, हमारे झुंझुनूं जिले को वंचित किया गया है। उदयपुरवाटी में 2021-22 में 16,430 बैग दिये गये। 2022-23 में 11,522 और 2024-25 में मात्र 7070 बैग दिये गये और इसमें डीएपी और यूरिया, दोनों शामिल हैं। हमारे यहां 41 ग्राम पंचायतें हैं, 3 नगर पालिकाएं हैं और वहां केवल 7070 बैग, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बात करते हैं कि हमने यह कर दिया, वो कर दिया। जहां 15-20 हजार बैग आते थे, वहां 7070 बैग आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य की दुकानों में 2021-22 में मूंगफली खरीद हुई 1000 क्विंटल, 2022-23 में बाजरे की खरीद हुई नहीं और 2024-25 में मात्र 78 क्विंटल की खरीद हुई। शर्म की बात है कि समर्थन मूल्य की दुकानों पर केवल 78 क्विंटल खरीद हो रही है। किसान की बात करने वालों के लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार का व्यवहार किसान के साथ किया जा रहा है। 2023 में राजस्थान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आवंटन अनुसार राशि जमा कराई थी, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा माह जनवरी 2023 से खाद्यान्न नि:शुल्क कर दिया गया, जिससे क्रय-विक्रय समितियों को 20 लाख का भुगतान नहीं दिया गया, इससे वह कंगाली के कगार पर हैं।

श्री अध्यक्ष: वाइंडअप करो।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): इसके साथ ही गायों की रक्षा के लिये बोल रहे थे। हमारे यहां पैंथर का इतना बड़ा प्रकोप है। मैंने पहले भी बात कही थी कि वहां बिना किसी तैयारी के पैंथर छोड़ दिये गये और वे वहां पर लोगों की भेड़-बकरियां खा रहे हैं। किसान की भेड़-बकरी खा जाते हैं तो उसका परिवाद दर्ज होता है और उसको मात्र तीन हजार रुपये दिये जाते हैं। 20-25 हजार की बकरी का तीन हजार रुपये दिये जाते हैं, यह सदन के सोचने का विषय है। मेरा निवेदन है कि इस पर भी विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही सड़क निर्माण में उदयपुरवाटी में ककरना से पचलंगी, जोधपुरा से सुरपुरा, पचलंगी से सिरोही, उदयपुरवाटी से घाट बागोरा और धोलाखेड़ा तक सारी रोडें टूटी हुई हैं। मुंडावा से खोद तक की सड़क के निर्माण के लिये 22 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं, अभी तक उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। मेरे उदयपुरवाटी में तीन नगर पालिकाएं हैं, वहां 12 महीने से कोई स्थायी जेईएन नहीं लगा है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि वहां स्थायी रूप से वह लगाया जाये, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय विराजिए। श्री ताराचन्द।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार और

धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने आज मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में निरंतर विकास के नये आयाम स्थापित कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में अद्भुत प्रगति अर्जित की है। इसी कड़ी में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमारा प्रदेश भी अग्रणी रूप से विकास की और बढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में निरंतर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जैसे ठुमके लगाकर अनर्गल और तथ्यहीन बातें करके सदन का जो समय खराब किया गया, मैं मेरे विपक्षी भाइयों को कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जो काम कर रही है उसको राजस्थान की पूरी जनता देख रही है। इसलिए कम से कम सदन की गरिमा रख कर कोई बात करनी चाहिये। तथ्यहीन बातों में समय बरबाद करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को यहां जनता ने चुनकर भेजा है, जनता की समस्याओं को निराकरण करने के लिये भेजा है, ना कि हम एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करके समय बरबाद करें। आज जो सदन में हुआ है, वह सोचने का विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है की एक वर्ष में हमारी सरकार द्वारा जनता की हितों को ध्यान में रखते हुए इतने विकास कार्य किये गए हैं कि शायद ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान इतने कार्य किये होंगे। आज प्रदेश की जनता इस बात को लेकर प्रसन्न है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में क्रमवार विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। एक-एक कर विकास कार्यों का ब्यौरा देंगे तो कांग्रेस के साथियों को हजम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो केवल घोटालों के अलावा कुछ किया ही नहीं, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। हमारी सरकार केवल वादों पर नहीं, बल्कि काम में विश्वास करती है। "राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट" समिट सरकार की दूरदर्शी सोच का एक सफल उदाहरण है। कार्यकाल के पहले ही साल में इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जो कि एक मिसाल है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास के नये अवसर खुलेंगे। यह हमारे मुख्य मंत्री जी की सकारात्मक सोच का ही उदाहरण है कि आज पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के उद्यमियों ने खुले दिल से औद्योगिक क्षेत्र में भारी निवेश किया है। शायद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मन मस्तिष्क में ऐसा विचार ही नहीं आया होगा जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने कर दिखाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय आज भी हम लोगों के विचार सुनते हैं तो लोग यह कहते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हमें पीने का पानी ही नहीं मिलता था। हमारी सरकार का प्रयास है कि गांवों तथा ढाणियों में बसे लोगों को स्वच्छ पेयजल सुलभ हो। जल जीवन मिशन के रूप में केन्द्र सरकार के द्वारा विगत प्रदेश की सरकार को हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा

अवसर मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया तथा केन्द्र सरकार के दबाव में जब कार्य प्रारंभ किया तो प्रदेश की विगत कांग्रेस सरकार ने इसमें घोटालों के सिवाय कुछ नहीं किया, जिससे पूरा प्रदेश एक महत्वपूर्ण योजना से वंचित रह गया और राजस्थान के लोग प्यासे मरे। अब हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में अमृत-2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनेक शहरों एवं गांवों में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए हजारों करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान कर रही है, जो कि प्रदेश की जनता के लिए अभूतपूर्व कार्य है।

मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि गत सरकार के समय प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र, अभी जैसे कोयले की बातें कर रहे थे, कोयला घोटाला तो कांग्रेस की सरकार में कितना बड़ा हुआ था, सारी दुनिया जानती है, ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा। हमारे थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझते रहे। ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश का नेतृत्व जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के हाथ में आया तो 8 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा का दायित्व संभालने के साथ ही केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में ऊर्जा के क्षेत्र में एक वर्ष में ही एक नया आयाम स्थापित करते हुए हमारी सरकार ने अब तक 1 लाख 10 हजार से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन तथा 5 लाख 6 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं।

Msk/rtm/05.02.25/1940/4e

राज्य सरकार द्वारा 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी और 33 केवी के अनेकों ग्रिड सब 33 स्टेशन स्थापित किए हैं। साथ ही, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 'हर घर अब सूर्य घर के तहत रूफ टॉप सॉलर संयत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी तथा प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम को भी गति दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय गत सरकार के समय हुई पेपर लीक तथा नकल की घटनाओं से हमारे नौजवान अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया था और युवा निराश हो गये थे, लेकिन हमारी सरकार के आते ही प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता रखते हुए मजबूत इरादों और संकल्प शक्ति के साथ काम किया है। हमारी सरकार ने सख्त निर्णय से भर्ती संस्थाओं की गरिमा एवं विश्वास को फिर से स्थापित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बजट में हमारी सरकार ने 5 वर्षों में चार लाख राजकीय नियुक्तियों की घोषणा की थीं। मुझे आज प्रसन्नता है कि 1 वर्ष में ही माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में 59,236 पदों की नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा इसके अतिरिक्त 1 लाख 72 हजार 990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने का कार्य भी प्राथमिकता से किया है तथा चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में हमारी सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य किया है। वाजिब दरों पर दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की संख्या में बढ़ोतरी की है, जिससे आमजन को चिकित्सा सुविधा का निरंतर लाभ मिल रहा है। इसके अलावा अनेक उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अनेक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला अस्पताल में भी क्रमोन्नत करने का कार्य किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश में भर्तियों को बड़े स्तर पर पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में भी चिकित्सा क्षेत्र में अनेक भर्तियां की गयी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार के कार्यकाल को याद करते हैं तो वह दृश्य सोच कर के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं कोई किसान फसल के ख़राब होने व पूर्ववर्ती सरकार से सहयोग नहीं मिलने के कारण फांसी से झूल रहा था तो कहीं कर्ज के बोझ में दबकर मर रहा था, लेकिन आज मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में किसानों के चेहरों पर खुशियां छायी हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे प्रसन्नता है कि किसानों की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने एक वर्ष में लगभग 30 लाख से अधिक किसानों को हजारों करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण भी वितरित किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वंदनीय योजना है, इसके तहत देश के लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। दिन-रात मेहनत करके अन्नदाता किसान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में ज्यादातर लोगों का कृषि के साथ-साथ पशुपालन का भी अधिकाधिक कार्य है। गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। पंजीकृत गोशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान में भी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे हमारे पशुपालन भाइयों को इसका और अधिक लाभ हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है, जिससे किसानों को जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी तथा राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके मान-सम्मान के लिए भी संकल्पबद्ध है। प्रदेश के विकास में माताओं-बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में राज्य निधि से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है तथा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच नये आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से प्रदेश में कुल 1000 नये आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए उनके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए 'लाडो प्रोत्साहन' योजना प्रारंभ की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण सड़क तंत्र में सुधार करने के लिए 200 विधान सभा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन-पेचेबल सड़कों के अनेक कार्य प्रारंभ किए गए हैं तथा दस हजार से अधिक आबादी वाले गांवो में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए समन्वित प्रयास किया जा रहे हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: श्री अनिल कुमार कटारा।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): साथ ही, राज्य सरकार द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है, जिससे श्रमिकों को इसका ओर अधिक लाभ मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, तीन मिनट से घंटी से बज रही है। विराजो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य, आप बोलें नहीं तो अगले का नाम पुकारुंगा।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़):000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद, जोहार। आज इस सदन में मेरे वक्तव्य के लिए पहला अवसर है। मैं इस अवसर पर गोविन्द गुरु महाराज, मानगढ़ धाम पर शहीद 1500 से अधिक आदिवासी वीर-वीरांगनाओं, संत सुरमाल महाराज, ज्योतिसर महाराज, शिक्षा के लिए बलिदान देने वाली भील वीरांगना कालीबाई कलसुआ, नानाबाई खाट, सेंगाबाई रौत, रामा पथुर डामोर को नमन करते हुए, विशेष कर चौरासी की जनता को, जिन्होंने सभी राष्ट्रीय पार्टियों को चौरासी के चक्कर में डालकर मुझे भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीताकर इस सदन में भेजा है। तो मैं चौरासी की जनता को धन्यवाद

अर्पित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं राज्यपाल का अभिभाषण चौरासी की जनता की उम्मीदों, आशाओं और सपनों को साथ में लेकर सुन रहा था। इसी अभिभाषण में कडाणा बैकवॉटर का जिक्र होगा, ऐसा मानना था, किन्तु कडाणा बैकवॉटर का जिक्र नहीं हुआ। मुझे सदन में दुःखी मन से कहना पड़ रहा है कि जिस पानी के लिए, जब माही नदी पर 1966 से लेकर 1969 के बीच में जब कडाणा बांध बना, उस बांध के समय हमारे आदिवासी लोगों ने अपनी जमीनें छोड़ीं, अपना जंगल छोड़ा, अपना परिवार, अपने बच्चों की शिक्षा छोड़ी, न जाने कितने परिवार बेघर हो गये, विस्थापित हो गये, इसमें से कुछेक को जमीनें और मुआवजा मिला और कुछेक को मुआवजा एवं जमीनें नहीं मिलीं। यह कडाणा के पानी की जो कहानी है, तब से शुरू हुई थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद इतिहास में पहली बार जल यात्रा चौरासी की जनता के द्वारा निकाली गयी थी। कडाणा बांध बैकवॉटर से गेजी घाटा तक चार दिन की पैदल यात्रा सरकार को संदेश देने के लिए निकाली गयी थी। 2022 में 1886 करोड़ की पेयजल परियोजना स्वीकृत भी हुई, लेकिन सरकार बदलते ही काम रुक गया। वर्तमान सरकार से मांग है कि सच में आप विकास की बात करते हैं तो उस परियोजना की वर्तमान लागत के हिसाब से राशि बढ़ाकर जल्दी ही इस पेयजल परियोजना को स्वीकृत करायें। महोदय जी, 1966 में माही कडाणा बांध बनाने से डूंगरपुर के 4 हजार आदिवासी परिवार व बांसवाड़ा के 6 हजार आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया गया, जिसमें से कई परिवार आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उनके ही बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परियोजना को जल्द से जल्द से पूरी करे।

आरक्षण की जब बात आती है तो मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि वह स्पष्ट करे कि एसटी, एससी को संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप आरक्षण देना चाहती है या आरक्षण के नाम पर एससी, एसटी को ही आपस में लड़ाना चाहती है। अभी जो खेल चल रहा है, उस हिसाब से तो सरकार एसटी, एससी को आपस में लड़ाना ही चाहती है। सच में लाभ देना चाहती है तो क्षेत्रीय आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण का बंटवारा करे। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

10 से 15 सालों से एससी, एसटी का बैकलॉग था, उसे भरने की बजाय खतम कर दिया गया और अब पिछले दो सालों से रिक्त एससी, एसटी के पदों को सामान्य से भरने की बात हो रही है। एक तरफ सरकार एसटी, एससी के लिए 35 प्रतिशत व 40 प्रतिशत की बाध्यता रखी है, फिर कमजोर वर्ग का बच्चा कैसे पात्र होगा? बाध्यता रखनी हो तो आदिवासी क्षेत्रों में जितने शिक्षकों के रिक्त पद हैं, वे सारे भर दें और टीएडी फंड से ब्लॉक जिला स्तर पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले जायें, जिससे आदिवासी बच्चे मैरिट कैसे टॉप करते हैं, वह भी देखते जाओ। अध्यक्ष महोदय, अभी प्राचार्य डीपीसी में वरिष्ठता को भी दरकिनार किया गया। आरक्षित वर्ग के वरिष्ठ अभ्यर्थियों के स्थान पर सामान्य वर्ग के कनिष्ठ अभ्यर्थियों का चयन

किया गया। डूंगरपुर जिले में कुल 617 सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं, उसमें से 3188 कक्षा-कक्ष हैं। वर्तमान में 2219 कक्षों में कक्षाएं संचालित हो रही हैं।

mdp/rtm/05.02.2025/19:50/4f

श्री अध्यक्ष: वाइंडअप कीजिए।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): वर्तमान में 2219 कक्षा-कक्षों में कक्षाएं संचालित हो रही हैं, किंतु एक क्लास में वर्तमान में तीन-तीन क्लासों के बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान की यह स्थिति बहुत ही गंभीर है। वर्तमान में व्याख्याताओं के भी वहां पर 70 प्रतिशत पद रिक्त है। हमारे डूंगरपुर का सबसे बड़ा कॉलेज जहां 7000 बच्चों पर सिर्फ 13 व्याख्याता हैं और तकरीबन 22 के आसपास कमरे हैं। 13 में से भी 3 व्याख्याता डेपुटेशन पर हैं। हम चाहते हैं कि टीएडी का अधिकांश बजट शिक्षा पर खर्च किया जाए क्योंकि भारत का भविष्य विद्या के मंदिरों में पलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग में पिछले कई वर्षों से तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। पिछले सत्र में मंत्री महोदय ने कहा था कि हम जल्दी ही तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती जारी करेंगे। विभागीय जानकारी के अनुसार जलदाय विभाग में लगभग दस हजार के करीब तकनीकी कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: डा. ऋतु बनावत। आप शुरू कीजिए। माननीय सदस्य, आपके चार मिनट की जगह 6 मिनट हो गये, विराजिए।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभिभाषण का पहला पैरा राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि के अभिनंदन, वंदन से ज्ञात होता है कि सरकार राजस्थान के स्वाभिमान को जीवंत रखना चाहती है। अभिभाषण के 168 बिंदुओं में 'सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय'' का भाव परिलक्षित होता है। इस अभिभाषण के माध्यम से हमें सरकार की मंशा का यह पता चलता है कि सरकार हर वर्ग को बेहतर जीवन स्तर देना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की तो पिछली सरकार के समय में सुबह अख़बार की सुर्खियों में जब हम पढ़ते थे तो वह सुर्खियां हमें चेतावनी-सा प्रतीत होती थी और कहीं पर 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ कोई घटना हो जाती थी, तो कहीं मासूम बच्ची को दुष्कर्म के बाद भट्टी में झोंक दिया जाता था। साथ ही मैं एक बात कहना चाहती हूं कि विपक्ष की राष्ट्रीय नेत्री ने एक बात कहीं कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं, लेकिन उन्होंने कभी भी राजस्थान की पीड़ित महिलाओं का दर्द नहीं समझा और उनके आंसू पोंछने आने का काम नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय में राजस्थान की महिलाओं ने सशक्त होकर प्रण किया कि वह ऐसी सरकार को जो उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकती, उन्हें सत्ता के गलियारों से बाहर का रास्ता दिखायेगी और जिसके कारण से मजबूत इरादों वाली वर्तमान सरकार

अस्तित्व में आयी। आप देखिए कि पिछली सरकार में वही पुलिस थी, वही अधिकारी थे, बदला तो क्या बदला? सोच बदली, नीयत बदली, जिसके परिणामस्वरूप आज राजस्थान की जनता, राजस्थान की महिलाएं सुरक्षा का भाव अनुभव करती हैं। मैं कहना चाहती हूं, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं इस सरकार का, इस अच्छी कानून व्यवस्था के कारण से ही राइजिंग राजस्थान में उद्यमियों की राजस्थान में निवेश के लिए होड़ लग गयी, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तभी वहां पर आकर निवेश की बात सोचता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि इंडस्ट्रीयल एनवायरमेंट के लिए न केवल इस सरकार ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना भी शुरू किया, कनेक्टिविटी के लिए सड़कें, बिजली और पानी की व्यवस्था में ये सरकार दिन-रात जुटी है। समय उस सरकार का भी था, पिछली सरकार का भी था, उन्होंने केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से हितों की उपेक्षा करने की बात करके अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली। मैं कहना चाहती हूं कि राइजिंग राजस्थान की सबसे अच्छी बात क्या थी? राइजिंग राजस्थान की सबसे अच्छी बात है कि बड़े उद्योगों को ही नहीं, बल्कि छोटे उद्योगों और निवेश करने वालों को भी इसमें प्राथमिकता प्रदान की गयी। हर जिले में इसकी चिंता की जा रही है कि कैसे निवेश को बढ़ावा मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं वह सेंडस्टोन का क्षेत्र है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने ही, क्योंकि वहां पर पहले अवैध रूप से पत्थर निकलता था, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी ने वहां के पत्थर को वैधता प्रदान की और हमारा सौभाग्य है कि राम मन्दिर के निर्माण में हमारे क्षेत्र का पत्थर वहां पहुंच पाया। मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में स्टोन पार्क डवलप कर हमारे यहां पर स्टोन इंडस्ट्री पर विचार किया जाना चाहिए। अभी बयाना विधान सभा के बंशी पहाड़पुर क्षेत्र से 98 हैक्टेयर की लीज आर.एस.एम.एम. को दी गयी है। हमारे यहां पर रोजी-रोटी का साधन पत्थर ही है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि वहां पर जो 98 हैक्टेयर की लीज आर.एस.एम.एम. को दी गयी है, वहां छोटे-छोटे पट्टे काटकर लोकल व्यक्तियों को दिए जाए, जिससे वहां के लोकल लोगों को रोजगार के नव-अवसर प्रदान हो सकें।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि भरतपुर का जिला एन.सी.आर. और टीटी जेड के कारण से इंडस्ट्रीयल एनवायरमेंट नहीं बन पा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारा जो क्षेत्र है भरतपुर का, वह एन.सी.आर. क्षेत्र में आता है और दिल्ली से बहुत दूर है, लेकिन मथुरा वहां पर पास होने के बाद भी एन.सी.आर. में नहीं आता तो मेरा निवेदन रहेगा कि सरकार एक ऐसा प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे और हमें एन.सी.आर. से मुक्त किया जाए। साथ ही मैं बात करूंगी किसानों की और किसानों के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगी कि-

'खुद का तो पता नहीं परंतु कोई पेट भूखा न रह जाए,
इतना करूं परिश्रम की चारों धाम खेत से हो जाए।'

हमारा किसान हमारा अन्नदाता, उनके लिए सोचना सबका कर्तव्य था। पिछली सरकार ने

आते ही किसानों को बिजली में मिलने वाली सब्सिडी, जो माननीय वसुन्धरा जी के समय में वार्षिक तौर पर उनको दी गयी थी और किसानों को मुस्कराने का मौका दिया था, वह उनसे छीनने का काम किया। जब बीजेपी की सरकार वापस सत्ता में आयी तो उन्होंने किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर पुनः किसानों को मुस्कराने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र में आता है और यहां पर मिल्खपुर गांव में कृषि ग्राह्यता केन्द्र (एटीएफ) की उपलब्ध सरकारी जमीन का उपयोग करते हुए कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि महाविद्यालय या कृषकों के लिए कोई फार्मिंग इंस्टीट्यूट चलाकर वहां के किसानों को अच्छे प्रोडक्ट्स करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अभिभाषण में कुसुम योजना के माध्यम से भी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है, ऊर्जा के क्षेत्र में। इसके लिए भी ये सरकार साधुवाद की पात्र है। मैं सरकार के लिए यह भी कहना चाहती हूं कि-

'नेतृत्व कुशल हो, सोच सही हो, सबकुछ अच्छा होता है,
सकारात्मकता से चलो तो ईश्वर शक्ति देता है।'

इस वर्ष वर्षा ने यह साबित कर दिया कि यह सरकार लोन की नहीं सोन की सरकार है। यानी की शगुन की सरकार है। आगे भी सब अच्छा ही होगा।

अगर हम बात करें ई.आर.सी.पी. की, माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 जिलों की यह जीवनदायिनी योजना, पूर्वी राजस्थान की मृतप्रायः पड़ी धरती की पुकार थी, जिसे पूरा करने का कार्य भरतपुर के लाल आदरणीय माननीय भजन लाल जी ने किया। ई.आर.सी.पी. के विषय में विपक्ष के साथियों को बड़ी चिंता हो रही है कि एम.ओ.यू. में क्या है? आप क्यों चिंता करते हैं? अब तो ये योजना ई.आर.सी.पी. नहीं राम सेतु जल योजना है। जिसमें राम का नाम आ जाए वहां सब कुछ खुशहाल होता है और कहते भी हैं कि 'राम से बड़ा राम का नाम।'

आगे मैं बात कहूं तो कहा भी गया है कि 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी' जो निश्चय राजस्थान के इस भागीरथ ने किया है, दृढ़ संकल्प के साथ निश्चित तौर पर उनका संकल्प पूरा होगा। आप देखेंगे और मेरा निवेदन रहेगा कि सरकार बयाना के सेवला हेड तक नव-सृजन कर चौड़ाईकरण करे। इससे सम्बन्धित केनाल्स का भी पुनर्निर्माण करे। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान का अंतिम छोर जो मेरी विधान सभा में आता है मेडथमा, मिलसमा, वहां तक पानी पहुंचे ई.आर.सी.पी. के माध्यम से तो सरकार का साधुवाद रहेगा।

पर्यटन के मामले में यह कहना चाहूंगी कि इस अभिभाषण में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही गयी थी। मैं यह कहूंगी बंदबायटा में इकोलोजिकल पार्क, एडवेंचर पार्क स्थापित किया जाए। साथ ही हमारे क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग है, इसमें रोप-वे निर्माण में बजट आवंटन किया जाए। साथ ही रूपबास के लाल महल और मैं धन्यवाद दूंगी मुख्य मंत्री महोदय का

जिन्होंने हमारे शाही तालाब के लिए बजट आवंटन किया। मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि आप शाही महल के लिए भी बजट आवंटन करें।

Ans/rtm 20.00 4g 05.02.2025

साथ ही मैं कहूंगी कि महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल की बात आते ही विपक्षी साथी गण भडक जाते हैं, तब उन्हें गरीब व वंचित जैसे शब्द याद आते हैं। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि बिना भवन, बिना टीचर के व्यवस्था किए इन्होंने स्कूल खोल दिए और पिछली सरकार उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी लेना ही भूल गई। मैं यह कहूंगी कि समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा किस बात पर होगी कि उनका नामांकन किस स्टेण्डर्ड पर पहुंच गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बंसी पहाडपुर का एक स्कूल है, वहां पर 500-600 के लगभग नामांकन हुआ करता था वह आज 240 पर पहुंच गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि इन स्कूलों की समीक्षा अवश्य की जानी चाहिए।

चूंकि मेरा समय खतम हो रहा है। बात बहुत सी है। मैं यही कहूंगी कि घुमन्तू- अर्ध घुमन्तू, यह कहे कि महाराणा प्रताप के समय से ही भारत की स्वाधीनता में उनका अमूल्य योगदान था उनको आपने पट्टे देने का काम किया, यह बहुत सराहनीय काम है। युवाओं के संकल्प को पदस्थापित करने का काम किया यह भी बहुत अच्छा काम है। मैं अंत में सरकार के लिए यह कहना चाहती हूं कि समझने नहीं देगी हमको सच्चाई....

श्री अध्यक्ष: श्री ललित यादव।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): कहीं चेहरा नहीं मिलता, कहीं दर्पण नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): यहां चेहरा भी मिलता है, यहां दर्पण भी मिलता है।

श्री अध्यक्ष: तीन बार घंटी बजा दी, अंकित नहीं हो। तीन बार घंटी बजाई।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं मेरी पार्टी के नेता टीकाराम जी का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात शुरू करूँ,

ना हम सफर में किसी हमनशीं से निकलेगा,
राजस्थान प्रदेश के विकास का रास्ता हमी से निकलेगा,
वतन की रेत पर एडिया रगड़ने दो,
मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा,
पानी यहीं निकलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जैसे कई नौजवान साथी यहां चुनकर आए हैं। जब हम बाहर थे तो सोचते थे कि सदन में बैठकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के लोग इस प्रदेश को आगे ले जाने की दिशा में बात करते होंगे, चर्चा करते होंगे, लेकिन यहां आकर पता लगता है कि वह हमारी तरफ बोलते हैं और हम उनकी तरफ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। हम

जैसे नये लोगों से कोई गलती हो जाए तो चले, लेकिन +++ माननीय एस सी समुदाय से आते हैं।

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड रूकिये, आप बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्यपाल अभिभाषण पर बहस हो रही है, जो विषय नहीं है, जिस विषय का आपने निराकरण कर दिया, उस विषय को यहां नहीं उठाया जाए, इसको डिलिट कराया जाए।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): मैंने इसलिए कहा कि यह एससी समुदाय से आते हैं। इनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति बैठा होता तो आप हिम्मत नहीं कर पाते इस प्रकार की बात बोलने का।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजो। जिस पर निर्णय किया जा चुका है, क्षमा हो गई, उस विषय को दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप ना दोहराए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसको डिलिट कराये, साहब।

श्री अध्यक्ष: इसको डिलिट कर दें।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राइजिंग राजस्थान के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बात यहां हुई है, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। अभी हमारी माननीय सदस्या ने चर्चा की तो सत्ता पक्ष के लोगों को ना जाने क्या हो जाता है, मिर्ची क्यों लगती है, ठीक हाजमा रखना चाहिए, आप लोगों को सच्चाई सुननी चाहिए कि क्या ये जो एमओयू किए गए हैं ये धरातल पर आ पाएंगे। मैं दोनों जगह जाकर आया हूं उन मीटिंग्स में लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल वाह-वाही लूटने के लिए आप लोगों ने राइजिंग राजस्थान नाम का कार्यक्रम चलाया था। इसमें रोजगार की बात कही है लेकिन बात करने से रोजगार नहीं मिलेगा। आप यहां बैठकर कानून बनाइये, कानून बने और वहां के नौजवान को रोजगार मिल सके।

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात थी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहकर गए थे लेकिन इसको राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया। पीकेसी परियोजना बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप लोग खड़े होकर बात नहीं करें।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): भले ही योजनाओं का कुछ भी नाम निकाले लेकिन राजस्थान की जनता को पानी पिलाने की बात आप लोग करें। हरियाणा से यमुना का पानी लाने की बात कर रहे हैं। मैंने पिछली बार एक बात कही थी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14-15 गाँवों को जेजेएम की योजना बनाकर पानी पिलाने की बात कही थी लेकिन जिला चैंज हो गया। जिला चैंज होने के बाद वहां से पानी नहीं ले जाने दिया आपने। लोग प्यासे मर रहे हैं, गर्मी का समय आने वाला है, वह लोग क्या कहेंगे। आप यमुना का पानी और ईआरसीपी को पूरा करने का कैसे सपना देख रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की बात की गई है लेकिन चिकित्सा के नाम पर

सीएचसी और पीएचसी में डॉक्टर नहीं है। जिन सीएचसी के ऊपर 500-500 ओपीडी होती थी उनके अन्दर एक डॉक्टर बिठाने का काम नहीं किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सभी पदों को भरने का काम किया जाए।

आपने अन्नदाता की बात कही है। पेट और पीठ को एक करके इस मुल्क का, इस देश का पेट भरने का काम करता है, उस किसान के बारे में केवल भाषण देने का काम करते हो, केवल बात करते हो लेकिन उस किसान को ना बिजली मिली, ना उस किसान को अच्छी खाद मिली, खाद मिली वह भी थाने में डण्डे खाकर मिली। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसान की आय दुगुनी करने की बात आप लोगों ने कही, लेकिन किसान के बारे में आप लोग केवल यहां चर्चा करते हो, दुगुना करने का काम आप लोग नहीं करते।

माननीय मुख्य मंत्री जी की सुरक्षा में मेरे क्षेत्र का एक जवान शहीद हो गया। उसकी पत्नि के कहने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी 15 दिन के बाद वहां मौक़े पर गए, आपकी सरकार ने तय नहीं किया कि क्या कम्पनसेशन देने का काम करेंगे, मुख्य मंत्री जी गये, कुछ शब्द नहीं बोलकर आए। ऐसा व्यक्ति जो आपकी सुरक्षा में शहीद हो गया उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए और दोनों बच्चों को नौकरी देने का काम करना चाहिए था, यह काम आप लोगों ने नहीं किया।

बाबा साहेब अम्बेडकर की बात आप लोग करते हो लेकिन बाबा साहेब के सिद्धांतों को मानने की बात नहीं करते। +++ यह आपकी सोच है। आपकी यह सोच बताती है कि आपकी किस प्रकार की सोच है, बाबा साहेब की विचारधारा में आप लोग क्या विश्वास रखते हो। आप लोग केवल भाषण देने का काम करना चाहते हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्य अति उत्साहित होकर यह बात कहते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के अन्दर आप लोगों ने बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन मैं उन सदस्य से भी कहना चाहता हूं कुछ दिनों पहले आपको इसी सदन में खड़े होकर सफाई देनी पड़ी थी कि मेरे खिलाफ गलत वीडियो बनाकर डालने का काम कर रहे हैं, उस बात को आप लोग कैसे भूल गए।

मेरे ज़िले में एक आईपीएस अधिकारी जिसकी जासूसी होती है, उसकी जासूसी कौन करता है और उस मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से, सदन से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। जब आईपीएस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, आम जनता को सुरक्षित करने की बात आप लोग कैसे करते हो। आप उसकी जांच करवाईये। सीबीआई से उसकी जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 07 हजार बच्चियों व महिलाओं पर अत्याचार के मुक़दमे दर्ज हुए है। 40 हजार के समथिंग महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनके मुक़दमे दर्ज होने का काम हुआ है। केवल वाह-वाही लूटने की बात नहीं करनी चाहिए। हम सबको मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

भले ही भाषण देकर चले जाओ, नोट हो जाएगा लेकिन इस प्रदेश की जनता आपसे चार साल बाद आपसे हिसाब मांगेगी। मैं यह जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चार साल के बाद हमसे भी कम संख्या में आप इधर बैठे मिलोंगे, जैसा काम आप राजस्थान में करने का कर रहे हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी की तो बात ही छोड़ो, यहां मौक़े पर तो वह है नहीं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने 400 स्कूलें बंद करने का काम किया है। हमारे गांव के गरीब बच्चे पढ़ते थे उनको शिक्षा से वंचित करने का काम किया है, आप इस प्रदेश के अन्दर क्या दिखाना चाहते हो, किस प्रकार का चेहरा लेकर जाना चाहते हो। ग्रामीण परिवेश के गरीब परिवार से बच्चे-बच्चियां आते हैं उनको आप पढ़ाई से वंचित करना चाहते हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, महाविद्यालय की बात आप लोगों ने की लेकिन मेरे क्षेत्र में एक साल से भी ज्यादा टाइम हो गया महाविद्यालय का भवन नहीं बन पाया। मेरा महाविद्यालय प्राइमरी विद्यालय में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय को बनाने का काम आप लोग करें, ताकि वहां के बच्चों को सही शिक्षा मिल सके।

आप लोगों ने सड़क के बारे में चर्चा की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में साबी नदी पर बना पुल एक महीने से टूटा हुआ है, आवागमन में परेशानी हो रही है लेकिन आप लोगों ने उसको बनाने का काम नहीं किया। वहां एक महीने से तकलीफ झेल रहे हैं लेकिन सड़क बनने का काम नहीं हुआ।

मैं सीएचओ के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सात हजार सीएचओ काम कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना को वह आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको नियमित करने के लिए भारत सरकार का आदेश भी आ गया, उसके बाद भी उनको नियमित करने का काम नहीं किया। 15 से अधिक सीएचओ की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनको भी कोई कम्पनसेशन देने की बात नहीं की। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको भी परमानेंट का काम किया जाए।

VPS-RTM-05.02.2025-20.10-4h

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो 14 महीने के बाद आपने यह मान लिया इस बात को, हमारे अध्यक्ष महोदय यह कहते थे पर्ची सरकार लेकिन 14 महीने के बाद में अविनाश गहलोतजी ने इस बात को मान लिया कि केवल सरकार नहीं, यह पर्ची सरकार है और काम नहीं कर रही है। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दस मिनट का टाइम है। ये काम नहीं कर रहे हैं। गहलोतजी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बात को स्वीकार करने का काम किया। आप सब लोगों को यह ध्यान है, किरोड़ी बाबा की बात तो आप सबको पता ही

है कि किस प्रकार से एक महिला सी.आई. जिन्होंने किरोड़ी लालजी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम किया। सरकार के मंत्री के ऊपर किसका संरक्षण उनको है, यह भी बताने का आप लोग सदन में काम करें, यह बात मैं कहना चाहता हूं। आप ही की पार्टी के भाटीजी जिनके पौत्र यहां विधायक भी हैं और वे कल से आपके खिलाफ धरना देने का काम करेंगे, इसको बताने का आप लोग काम करें। यह आपकी सरकार के लोग क्या बात कह रहे हैं? **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सिंघवीजी हो या चाहे बैरवाजी हो, चाहे बैंसलाजी हो, बैंसलाजी भी आपके बारे में यह कह रहे हैं। आपकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार सही ढंग से नहीं चल पा रही है, इसको सही ढंग से चलाने का काम किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नीमराना क्षेत्र के अन्दर कल हमारे नीमराना के काफी लोगों ने धरना दिया था, उस मुद्दे को सुलझाने का आप लोग काम करें क्योंकि आपके शासन की गलती से उनकी जमीनों का रूपांतरण किसी अलग जगह हो गया इसलिए उनको भी ठीक करने का आप लोग काम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मण राम। माननीय सदस्य, आप विराजें। अंकित नहीं। अंकित नहीं।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): 000

श्री अध्यक्ष: विराजें। एक मिनट आपको ज्यादा दे दिया। श्री लक्ष्मण राम, आप शुरू करें।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. बी.आर. अंबेडकर साहब ...(व्यवधान)...

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे युवा साथी जब भाषण दे रहे थे तो माननीय गृह मंत्री, राष्ट्र के गृह मंत्री श्री अमित शाहजी के लिए एक भ्रामक बात कही गयी थी, वह गलत है इसलिए उसको डिलीट करा जाये इसमें से।

श्री अध्यक्ष: कोई असंसदीय होगा तो हट जायेगा।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): असंसदीय नहीं, उन्होंने अंबेडकरजी के लिए भ्रामक कहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: असंसदीय होगा तो हट जायेगा। माननीय लक्ष्मण राम। कोई भी असंसदीय होगा तो हट जायेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जो यहां पर है ही नहीं उनका नाम कैसे लिया?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके संसदीय कार्य मंत्री यहां पर बैठे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का इस ओर आपका ध्यान दिलाना था कि जो हमारे इस विधान सभा के सदस्य नहीं हैं माननीय अमित शाहजी, उनके सम्बन्ध में एक तो गलत तथ्यात्मक बात कही गयी

है और भ्रमित करने वाला कहा गया है इसलिए वह रिकार्ड पर नहीं रह सकता या फिर उनको एक्सप्लेनेशन का टाइम देना पड़ता है, उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी है इसलिए उसको हटाया जाये। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी ने यह व्यवस्था दे दी कि असंसदीय होगा तो हटा देंगे, आपको इतना भी यकीन नहीं है? इन्होंने बोल दिया है।

श्री अध्यक्ष: इसको चैक करके इस पर निर्णय किया जायेगा।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. बी.आर. अंबेडकर साहब के संविधान और मेड़ता की पवित्र जनता के आशीर्वाद से राजस्थान के सबसे पवित्र महा पंचायत में मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

महोदय, 31 जनवरी, 2025 को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत और हमारे इस पवित्र सदन में महामहिम राज्यपालजी के श्रीमुख से इस अभिभाषण का वाचन किया गया, जिसके लिए हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस अभिभाषण को सुनकर निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री मोदीजी, माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा के कुशल नेतृत्व में अग्रणी राजस्थान का संकल्प सिद्ध हो रहा है।

महोदय, प्रदेश के समग्र विकास के लिए हमारी भाजपा सरकार ने यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा के नेतृत्व में अनेकों दूरगामी निर्णय लिये हैं। प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए, प्रदेश की माताओं, बहिनों, युवा साथियों, किसान बंधुओं, श्रमिकों की बेहतरी के लिए अनेक बड़े फैसलों को क्रियान्वित किया गया है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में पेपर लीक के कई गिरोह पनपे हैं। गांव-ढाणी का किसान धरती का सीना चीर कर फसल उगाता है, अपने बच्चों को नौकरी के लिए बड़े शहरों में भेजता है लेकिन कांग्रेस के शासन में हुए पेपर लीक से आहत होकर प्रदेश के अनेक होनहार बच्चों ने मौत को गले लगाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा को जिनके नेतृत्व में हमारी इस सरकार ने उन पेपर लीक के गिरोह की नाक में नकेल कसने का काम किया। हमारी सरकार ने पेपर लीक गिरोह के खिलाफ एस.आई.टी. का गठन करके 250 लोगों को जेल में डालने का काम किया है। हमें यह प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा के कुशल नेतृत्व में हमारी भाजपा ने, भाजपा सरकार के युग पुरुष पंडित दीनदयालजी उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा को आत्मसात किया है। हमारी सरकार के कार्यकाल के पहले ही साल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन करके प्रदेश की आर्थिक प्रगति हेतु 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की बुनियादी नींव रखी है वरना कांग्रेस शासन में तो जैसलमेर-जयपुर-मानेसर होटलों में राइजिंग होती रही, यह भी हमने, प्रदेश की सात करोड़ जनता ने देखा है। राइजिंग राजस्थान के इस वैश्विक इंवेस्टमेंट समिट में दुनिया भर के 32 देशों ने हिस्सा लिया। महोदय, यह महज एक सब्मिट नहीं थी

बल्कि राजस्थान के भाग्योदय का आयोजन था। इससे प्रदेश की औद्योगिक क्रांति का विकास होगा। प्रतिभा कौशल के आधार पर हमारे युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी।

महोदय, बीते एक साल में इस प्रदेश में हमारी सरकार ने 59 हजार से अधिक लोगों को राजकीय नौकरी में नियुक्तियां देने का कार्य किया है और आज अनेकों भर्तियों की परीक्षाओं का सफल आयोजन किया है और आगे भी कराई जा रही हैं। हमारी सरकार किसानों और पशुपालकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने पंजीकृत गौ-शालाओं के देय अनुदान में दस प्रतिशत वृद्धि करके गोवंश के संरक्षण, संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया है। पशुपालकों के लिए पशुधन ही सबसे बड़ी पूंजी है। पशुपालकों के हितों की प्राथमिकता को देखते हुए हमारी सरकार ने 400 करोड़ रुपये की राशि से मुख्य मंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरूआत की है। यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के अंतिम छोर, ढाणी में बैठे किसान, नौजवान, महिला, मजदूर सबके हितों के लिए एक अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसे विपक्ष की कोई ताकत विचलित नहीं कर सकती। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वह फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं।

विपक्ष के साथी कल-परसों यह कह रहे थे कि यह भजन लाल भजन लाल नहीं, वजन लाल की सरकार है तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रदेश की उम्मीदों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के सम्मान का वज़न भजन लाल ही उठा सकता है, कांग्रेस में यह कूवत और दम नहीं है। कांग्रेस में कितना वजन है यह अभी उप चुनाव में प्रदेश की जनता ने देख लिया है। खींवसर सीट जहां उप चुनाव में लगातार एक महीने तक मेरा प्रवास रहा है, वहां से हमारे साथी माननीय डांगा जी जीतकर आये हैं, कांग्रेस तो वहां पर महज 5400 वोटों पर ही सिमट गयी। जहां आपके प्रदेश अध्यक्ष ने वहां गमछा हिलाया था जाकर, वहां पर जमानत जब्त हो गयी, 5400 वोट ही आये थे। अब आप यह आकलन कर लीजिए कि वजन किसमें ज्यादा है और किसमें वजन उठाने की ताकत है। 5400 वोट ही आये थे। हमारे एक मारवाड़ के नेता रिछपालजी मिर्धा साहब यह कहते हैं कि कांग्रेस की धूनी बुझ गयी तो यही हुआ। प्रदेश की जनता ने माननीय शर्माजी के नेतृत्व में भरोसा करके प्रदेश के विकास की कमान उनको सौंपी है और हाल ही उप चुनाव में फिर से जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देकर भाजपा को सात में से पांच सीटें जिताई है, यह एक ट्रेलर था। लोकल बोडी चुनाव में, पंचायत चुनाव में आपको जनता सिखायेगी। मैं विपक्ष के साथियों को यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता भजन लालजी का भरोसा स्वीकार कर चुकी है और माननीय मुख्य मंत्री भजन लालजी शर्मा ने जो कार्य किये हैं, जिस क्षेत्र के लिए वे कार्य करते हैं, उस क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों को, जनता को भरोसा में वे लेते हैं। हमारी पार्टी के प्रत्येक विधायक से चर्चा करके उनके क्षेत्र में घोषणा करते हैं जबकि कांग्रेस के शासन में तो जिलों की ऐसे ही घोषणा हुई, नगरपालिका की घोषणा भी ऐसे ही हुई है। हमारे नागौर जिले के जायल के कांग्रेसी नेता घूमते हुए यह कह रहे हैं, साहब, कल ज्ञापन दिया था कि जायल को वापस

आप ग्राम पंचायत बनाइये तो यह आपकी पिछली सरकार का हाल है।

माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लालजी शर्मा ने प्रदेश की तकदीर बदलने का कार्य किया है और उसी अटल ध्येय के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। आप चिल्लाते रहिये, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जिसे इस तकदीर के पन्ने पलटने हो, वह संघर्ष से डरता नहीं है।

महोदय, हमारी सरकार वादों पर नहीं काम करने पर विश्वास करती है। ई.आर.सी.पी. के मामले में यह बात सिद्ध हुई है। पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी राजे के नेतृत्व में तत्कालीन भाजपा सरकार ने पहली बार इस योजना के विजन को प्रस्तुत किया लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गयी, यह काम अटक गया। हमारी सरकार ने इस बार राम जल सेतु लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने की दिशा में मजबूत कदम उठाये हैं। इस प्रदेश की सरकार होने के नाते इन्होंने यह किया। इससे करीब तीन करोड़ आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा और वही करीबन 4 लाख हैक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंचित होगी, राजस्थान की समृद्धि, खुशहाली की एक नये युग की शुरूआत है।

मुझे तो यह कहते हुए भी खुशी है कि हमारा पश्चिम राजस्थान जो एक सुदूर मरू-प्रदेश का इलाका है, उस क्षेत्र में सभी डब्ल्यू.आर.सी.पी. की डी.पी.आर. अंतिम चरण में है और माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यकाल में एक बड़ी सौगात राजस्थान को मिलने जा रही है।

हमारे विपक्ष के साथी बाबा साहब के नाम पर बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। यह सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है और हमारा एस.सी., एस.टी. का युवा अब पढ़-लिख गया है, वह समझदार हो चुका है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब आजादी से पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात हुई थी तो पांच नाम भेजे गये थे, दस नाम भेजे गये थे। पांच हिंदू, पांच मुसलमान, एक पारसी, एक एस.सी. का, उसमें भी आप लोगों ने बाबा साहब का नाम नहीं भेजा, यह आपके सोचने की बात है और हमारे एस.सी., एस.टी. का युवा इस बात को समझ चुका है। बाबा साहब को आपने लोक सभा में जाने से रोका, कई बार उनका विरोध किया और हमारा युवा उस पत्र को पढ़ेगा जो बाबा साहब ने लोक सभा में खड़े होकर इस्तीफा दिया कि मैं इस सरकार से, इन नेताओं से आहत होकर मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं, यह बात भी हमारे एस.सी., एस.टी के युवा समझ चुके हैं। अब वह दुकान चलने वाली नहीं है। लोक सभा के आम चुनाव में आप लोगों ने जब चुनाव हो रहे थे तो बाबा साहब के नाम से, संविधान के नाम से, आरक्षण के नाम से लोगों को ठगा लेकिन यह भारत की जनता ठगी नहीं गयी और आपके खिलाफ वोट दिये। मोदीजी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी यह भाजपा की सरकार बनी है, जो जनता की बहुत भारी देन है।

ssy/rtm/05.02.2025/20.20/4j

यह सारी बातें मैं कहना चाहूंगा। हां, किसान बंधुओं को सौगात, हमारे आदरणीय अटल

बिहारी जी वाजपेयी हमेशा किसान, गांव की बात करते थे। उन्होंने प्रधान मंत्री सड़क योजना की शुरूआत की कि गांव के लोग शहर के साथ कैसे जुड़ें। पीएम सड़क योजना हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। किसान क्रेडिट कार्ड की किसानों मजदूरों के लिए योजना बनाकर व्यवस्था की गई कि हमारा किसान खुशहाल कैसे हो। कम ब्याज पर उसको लोन कैसे मिले। वह हमारे वाजपेयी जी की देन थी।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बजट पेश हुआ था उसमें भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिये गये। इससे हमारे गांव का किसान हमेशा खुशहाल रहेगा। यह मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। विशेष रूप से किसान और गांव का ध्यान रखा गया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी को, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो हमेशा गांव और किसान की चिंता करते हैं।

श्री अध्यक्षः खत्म करिये।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करुंगा। मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। मेड़ता 20 साल बाद में बोल रहा है, आप प्लीज बोलने दीजिये। मैं मांग करुंगा कि मेड़ता आजादी के समय जिला था, उसको वापस जिला बनाया जाये। मैं सदन से मांग करुंगा कि मेड़ता के साथ जिला बनाने में अन्याय हुआ। सदन के माध्यम से मांग करुंगा कि मेड़ता वापस जिला बने। बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम सा।

श्री अध्यक्षः श्री चेतन पटेल।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, मौन होकर देख रहा हर शख्स जिम्मेदार है, पर्दाफाश कर देने वाली हर आवाज पर अत्याचार है, सच को सच कह देना आज हो गया है गुनाह, सत्ता से नजर मिलाने वाला हर शख्स गिरफ्तार है। असत्य परोसने वाले घूम रहे हैं सड़कों पर और सच बोलने वाली हर आवाज अब बर्बाद है, इंकलाब की लड़ाई लड़ने वाले से भरी हुई है जेल, ताकतवर को प्रणाम करने वाले ही अब इस प्रदेश में आबाद हैं, लोकतंत्र को बचाने वाला हर पहिया अब लगता लाचार है, जो कुछ बच गये अब भी बोलने वाले उन पर भी हर वक्त दबाव है, खुद चुन लो अपना रास्ता सच और असत्य की इस लड़ाई में। लेकिन आप सच का रास्ता चुनोगे, प्रदेश का सबसे साहसी गांव समरावता का यह ख्वाब है। समरावता का यह ख्वाब है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिन्दु संख्या 153 को पढ़ना चाहूंगा। जिसमें वह कहते हैं कि किसी भी प्रदेश का विकास उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर है। कानून व्यवस्था मजबूत हाथों में होगी तो उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार राजस्थान को सुरक्षित और भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है।

मैं अपनी कविता के माध्यम से इस सरकार का कानून व्यवस्था के प्रति असली चाल, चरित्र और सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि सिर्फ भाजपा सरकार के सत्ता के अहंकार में लिप्त मजबूत हाथों के संरक्षण की वजह से पुलिस और प्रशासन के सरकारी तंत्र

ने प्रदेश की विधान सभा देवली उनियारा के गांव समरावता में रात के समय संपूर्ण गांव में बिजली कट करके मीटिंग कर रहे लोगों के ऊपर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, आंसू के गोले दागे। उनके वाहनों में आग लगाई। जिसके कारण से आगजनी हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस आगजनी में जो जानवर घरों में बंधे हुए थे, वह भी आग की लपटों में भस्म हो गये। महिला, बच्चों और निर्दोष लोगों से घरों में घुसकर मारपीट की, ज्यादती की, बदसलूकी की। उनसे छेड़छाड़ की। कोई अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूदा। कोई अपनी जान बचाने के लिए छत से कूदा। इससे भी जब इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने, इनके पुलिस प्रशासन ने निर्दोष लोगों पर केस लगाने का काम किया। आज उस गांव की मां रो-रोकर अपने बच्चों के लिए न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक पेड़ मां के नाम, लाड़ली बहन जैसी बड़ी-बड़ी बातें करके मां और बहन के नाम पर यह सरकार राजनैतिक रोटियां सेककर राजनीति करती है।

मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम अपने अभिभाषण में कह रहे थे कि सरकार राजस्थान को सुरक्षित और भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी कोशिश है कि देश-विदेश में राजस्थान की छवि अपराध मुक्त हो। क्या यह कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? यह मैं पूछना चाहता हूं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने, पुलिस और प्रशासन ने इस समरावता गांव को जलियांवाला बाग़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह तो गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई। वरना प्रदेश को पूरा देश और विदेश जलियांवाला बाग़ की तरह जानता।

मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन को यह अधिकार और आदेश किसने दिये? किसके संरक्षण से यह संभव हुआ? जिस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया गया उससे यह प्रतीत होता है कि एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया षड्यंत्र था। जहां ग्रामवासी मांग कर रहे थे कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसके एवज में हमें दुगुना मुआवजा दिया जाये। मुआवजा तो दूर इस सरकार ने उस पुलिस प्रशासन पर जिस पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, उसी को जांच दे दी। उस पुलिस प्रशासन ने निर्दोष लोगों पर केस लगाने का काम किया। उनका भविष्य खतरे में डालने का काम किया। यह स्वाभाविक है कि ग्रामवासियों का इस प्रकरण में जांच कर रहे संभागीय आयुक्त से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। आज इस निंदनीय घटना के बाद ना सिर्फ समरावता बल्कि आसपास के क्षेत्र के गांवों में, बल्कि पूरे प्रदेश में भय का माहौल व्याप्त हो चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक आखिरी मानवता की उम्मीद से न्याय के लिए आपसे समरावता, प्रदेश और समाज संरक्षण मांग रहे हैं कि आप समरावता में हुए अत्याचार में ग्राम वासियों को न्याय दिलाने के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से प्रकरण की जांच करवायें ताकि दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। निर्दोष लोगों पर केस लगाये गये, उन्हें वापस लिया जा सके। जिन ग्रामीणों की जान-माल का नुकसान हुआ है, उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके। एक कमेटी विधान सभा की गठित की जाये

जिसमें माननीय सदस्य हों, ताकि सत्ता के भय से, सत्ता के दबाव से किसी प्रकार का अन्याय घटित ना हो।

जब मैं महामहिम का अभिभाषण सुन रहा था तो उनकी चर्चा के दौरान बहुत सारे सदस्य भी बोल रहे थे कि बीच में अवरोध पैदा किया, बीच में अवरोध पैदा किया। पूरा का पूरा अभिभाषण देखकर बोला गया। सिर्फ बीच में कुछ शब्द उन्होंने बिना देखे बोले। वह यह बोले कि मैं आदिवासियों की विशेष चिंता करता हूं। आदिवासियों के प्रति मैं गंभीर हूं और मेरा परम दायित्व बनता है।

मैं, महामहिम को इस सदन के माध्यम से आदिवासियों की कुछ समस्याएं अवगत कराना चाहता हूं। आने वाले समय में उनकी गंभीरता को भी महसूस करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के एसटी समाज के विद्यार्थियों के विभिन्न कोर्सेज में आज वर्तमान सत्र 2024-25 तक की लगभग 750 करोड़ की छात्रवृत्ति लंबित हैं। राजस्थान सरकार का आदिवासी समुदाय के प्रति सौतेले व्यवहार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवम्बर, 2024 में 250 करोड़ की राशि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी, इस राशि के विरुद्ध 25 परसेंट राज्य अंश राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाना था। परंतु आज दिनांक तक एसटी समुदाय के विद्यार्थियों को छात्र वृत्ति की यह राशि प्राप्त नहीं हुई है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से विद्यार्थी फीस नहीं जमा करा पाने के कारण अपनी नियमित पढ़ाई छोड़ चुके हैं। आदिवासी छात्र-छात्राएं स्कूल और कॉलेज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

गरीब आदिवासी छात्रों का भी सपना है कि डॉक्टर बनें, आईएएस बनें, आईपीएस बनें। नौकरी पाने का सपना है। सपना है अपने पैरों पर खड़े होने का। लेकिन उनका सपना आज सपना बनकर रह गया है। विशेष बात यह भी है कि छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने से लेकर भुगतान तक इतनी जटिल पोर्टल आधारित प्रक्रिया बना दी गई है, जिसमें आम ग्रामीण विद्यार्थी छात्र वृत्ति से वंचित हो जाता है। जब विद्यार्थी नियमित छात्र है, रेगुलर छात्र है तो हर वर्ष उसको छात्र वृत्ति का फॉर्म क्यों भरना पड़ता है। यह मैं पूछना चाहता हूं। हर बार छात्र वृत्ति फॉर्म भरने में 500 से 1000 तक का खर्चा आता है। इससे भी बड़ी विडम्बना यह है कि छात्रों को छात्र वृति नहीं मिल पा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार सिर्फ आदिवासी बच्चों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक हनन करने का काम कर रही है। जिस तरीके से राज्य सरकार शिक्षा का निजी करण कर रही है। 400 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया गया है। गत सरकार के कार्यकाल में खुले 3741 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की तैयारी कर रही है। निजीकरण का काम कर रही है। सरकारी संस्थाएं बंद करने का काम कर रही है। उस हिसाब से सरकारी नौकरियों में संविदा, ठेके और कांट्रेक्ट बेस पर भर्तियां लाकर एससी, एसटी और ओबीसी के संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का काम भाजपा सरकार कर रही है।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह पूरा का पूरा एक ट्रेप है। भाजपा सरकार का फैलाया हुआ जाल है। यह कभी नहीं चाहेंगे कि प्रदेश के बच्चे शिक्षित हों। यह नफरत की राजनीति करते हैं। भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करते हैं। यह धर्म की राजनीति करते हैं। ईआरसीपी प्रोजेक्ट में भी पार्वती, काली सिंध और यमुना मां के नाम पर इन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी।

Spp/rtm/05.02.2025/20.30/4k

और राम जल सेतु उसका नाम कर दिया। हम उसका भी स्वागत करते हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जनता तक पानी पहुंचे। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के बिन्दु संख्या 15 में जो कालीसिंह नदी पर ऐबरा गांव में स्थित नोनेरा बांध का जिक्र उन्होंने किया है, वह मेरी पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में ही आता है। माननीय सदस्य गोविन्द सिंहजी ने भी बिलकुल सही कहा था कि नोनेरा बैराज को हमारी गत सरकार में बनाया गया। आपकी सरकार में तो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे कार्यकाल में बनाये हुए डेम को हैलिकॉप्टर से निरीक्षण करने का काम किया। जिस समय वह हैलिकॉप्टर से आये उस समय मैं भी वहां पर उपस्थित था और जिस जगह उन्होंने लैंडिंग की, वह गांव ऐबरा था जहां पर नोनेरा बैराज बना है और आज जिस प्रकार उस गांव ने माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्वागत किया, लोकतंत्र में कोई राजा होता नहीं है, पर राजा से कम भी उनका स्वागत नहीं किया। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि उस गांव को पूरा का पूरा खाली करने की तैयारी आज इस भाजपा सरकार ने कर ली है। ई आर सी पी प्रोजेक्ट के तहत इंटेक वैल बनाने के लिये 700 से 800 बीघा जमीन 70 से 80 प्रतिशत जमीन उस गांव में अधिग्रहण करने की तैयारी कर ली है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र जी। (अनुपस्थित)

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि उस जमीन के लिये वन विभाग की सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया जाये और इस गांव को खाली नहीं करवाया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़। आप तो बोलना शुरू कर दो। माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): 000

श्री अध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि सदन के नेता, आदरणीय भजनलाल जी ने युग पुरूष पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा को

आत्मसात् किया है। एक वर्ष में प्रदेश में समग्र विकास के लिये ऐतिहासिक निर्णय लिये गये हैं। पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश का MOU किया गया है। इसके ऊपर प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने कई तरह की प्रतिक्रिया दी है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं मेवाड़ की एक कहावत है, वह आपको सुना दूं। जिस तरह से आपने यहां पर बार-बार राइजिंग राजस्थान के लिये प्रश्न उठाया। हमारे मेवाड़ में कोई भी शुभ कार्य होता है तो गुड़ की लापसी बनायी जाती है। उसमें सभी को बुलाया जाता है। लेकिन आने वाले जब उनसे पूछते हैं कि लापसी में आप गुड़ कहां से लाये, लापसी के लिये आप दलिया कहां से लाए, लापसी के लिये आप घी कहां से लाओगे? तो यह कहा जाता है कि लापसी खाने से मतलब है, लपराई करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप सदन के नेता, भजनलाल जी पर भरोसा करो कि यह राइजिंग राजस्थान के लिये जो MOU हुआ है, यह चार साल में धरातल पर आयेगा। आप देखोगे और आप वही बिराजे रहोगे और हम इधर ही बैठे रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता का आभारी हूं कि पहले ही बजट में कुंभलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बेडच का नाका, झोप का नाका, 132 केवी जी एस एस, आमेट सी एच सी को उप जिला चिकित्सालय, कॉलेज को पी.जी. में क्रमोन्नत, पी एच सी को सी एच सी में माही जाखम परियोजना से 300 गांवों को पेयजल योजना की इस बजट में घोषणा हुई है और उस पर कार्य प्रांरभ होने की तैयारी हो गयी है। यह 135 केवी का जी एस एस बनेगा, उससे कुंभलगढ़ में अच्छी लाइट मिलेगी और आपके मिलने वालों की भी वहां एक होटल है, आप वहां आये हुए हो। अगली बार आओगे तो वहां आपको बिजली गायब नहीं मिलेगी।

यहां प्रयागराज के महाकुंभ पर भी कई प्रतिक्रियाएं आयी हैं। मैं सदन के नेता का बहुत आभारी हूं कि आपने वहां पर एक हजार लोगों के ठहरने की व्यवस्था और दस हजार लोगों के लिये रोज का भंडारा का काम राजस्थान सरकार का चल रहा है। ऐसा पुण्यार्थ काम करके आपने पूरे देश में और विश्व को एक संदेश दिया है कि अब राजस्थान में वह सरकार आयी है जो वास्तव में पुण्य के कामों में भी भागीदार बनती है। इसी एक वर्ष में किसान भाइयों को, माता-बहनों को, युवाओं को और श्रमिक भाइयों को ऐतिहासिक इस योजना में जो काम मिलना चाहिए, वह काम मिलना प्रारंभ हुआ है। राजस्थान में 3 हजार 43 गौशालाओं में 10 प्रतिशत अनुदान बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। यह भी सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पिछले दिनों कई गौभक्तों ने उपखण्ड और जिला स्तर पर ज्ञापन दिया है कि गाय को माता का दर्जा दिया जाये। हमें पूरी उम्मीद है कि भजनलाल जी के नेतृत्व में वह समय भी आयेगा कि गाय को राजस्थान में माता का दर्जा भी दिया जायेगा।

उदयपुर संभाग में, अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने अपनी बात

रखी थी कि मेवाड़ में भील समाज के साथ अन्याय हो रहा है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। जब वह बोल रहे थे तो प्रतिपक्ष के नेता, आप बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वह पिछले पांच साल की पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। जब मैं वहां बैठता था और यह भाई वहां बैठकर बोलते थे कि सरकार सुनो, हमारे एस.टी. के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं भी इनकी कुछ बातों से सहमत हूं कि मेवाड़ में टी एस पी क्षेत्र के अलावा, चाहे राजसमंद हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे चित्तौड़ हो, राजस्थान में जहां भी भील समाज रहता है, उनको एस.टी. के आरक्षण में जो न्याय मिलना चाहिये, वह न्याय नहीं मिला है। मेवाड़ में यदि भील समाज के साथ सब समाज है। लेकिन डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि महाराणा प्रताप को सम्मान मिला है, राणा पूंजा भील को नहीं मिला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्र के बाद आप कुंभलगढ़ आओ। कुंभलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आपको यह उदाहरण मिलेगा कि मेरे विधायक बनने के बाद जहां-जहां राणा प्रताप की स्टेच्यू लगायी है, उनके साथ राणा पूंजा भील की भी मूर्ति लगायी है। हम महाराणा प्रताप की जयंती भी साथ मनाते हैं और हम राणा पूंजा भील की जयंती भी साथ मिलकर मनाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बाबा साहब अम्बेडकर जी पर भी बहुत चर्चा हुई है। राजसमंद जिले में बाबा साहब की पहली मूर्ति भी कुंभलगढ़ के मैन चौराहे पर लगवाई है। जिस तरह का समन्वय बनाकर चल रहे हैं, लेकिन भ्रमित किया जा रहा है और भ्रमित करके आपको थोड़ा बहुत वोट लोक सभा में मिल गया है। लेकिन अभी जो उप चुनाव का परिणाम आया है, आप एक साल में ही सब हिसाब पूछ रहे हो। पांच साल तक तो आपने कुछ किया नहीं और एक साल में सब काम भजनलाल जी कर दें। यही आपकी एक मंशा थी, लेकिन एक साल में नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 11 साल पहले कभी आपने यह नारा लगाया क्या कि जय संविधान, जय भीम, जय बापू। कभी लगाया था क्या? लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी के बनने के बाद 11 साल में उनका चमत्कार देखो। उसके पहले नारा लगाते थे जय नेहरूजी, जय इंदिरा जी, जय राजीव जी, यह 11 साल में चमत्कार हुआ है कि आप कहने लग गये जय संविधान, जय भीम और जय बापू, क्योंकि उनके अनुयायी आपसे छिटक गये। आप इन तीन नेताओं को छोडकर आप यह नारा लगा रहे हो। ..(व्यवधान).. आप सुनो मेरी बात। आप जब बोलते हो तो मैं बीच में कभी नहीं बोलता हूं।

यही नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मेवाड़ के भील समाज को टी एस पी के बाहर जो हमारा एरिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो उदयपुर में कई वर्षों तक बिराजे हो, आज भी कुंभलगढ़ के भील को कृषि कनेक्शन लेने के लिये जनरल कैटेगरी में उसको कनेक्शन मिलता है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि भील समाज के साथ न्याय हो और वह कृषि कनेक्शन में जिस तरह से एस.सी.को एप्लाई करने के एक महीने बाद मिलता है तो भील समाज को भी उसी तरह से कनेक्शन एक महीने में मिलने की व्यवस्था की जाये। हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस तरह से ऐसे ऐतिहासिक फैसले और लेगी।

मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें आपसे ज्यादा सर्टिफिकेट लेने की

आवश्यकता नहीं है। अभी सात जगह उप चुनाव हुए हैं। आप तो वैसे समझदार हैं। प्रदेश अध्यक्षजी यहां हैं नहीं। उनके मैंने कई विडियो देखे हैं। वह फोर्चुनर गाड़ी के ऊपर चढ़कर गमछा हिलाते हुए देखा है। गुमराह होने से थोड़े से वोट लोक सभा में मिले हैं। आज की जनता बहुत होशियार है। आज की जनता इतनी होशियार है कि उप चुनाव आये न, तो जनता ने देखा कि अब सीटें और देदीं तो अभी तो यह गमछा ही घुमा रहे हैं, और सीटें आ गयीं न तो यह पागल होकर लोगों पर पत्थर फेंकेंगे।

jyg/rtm/05.02.25/20.40/4l

इसलिए जनता ने चार सीटों पर आपकी जमानत जब्त करवा दी। मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपको सावधान कर रहा हूं चार साल पहले, प्रतिपक्ष के नेता आप ध्यान से सुनना, मेवाड़ संभाग में जिस तरह का वातावरण बन रहा है, अगला चुनाव कांग्रेस 'जीरो' है। भाजपा और हमारी ही मित्र पार्टी 'बाप' पार्टी आपस में लड़ेगी और वहाँ पर कांग्रेस का नामोनिशान नहीं रहेगा मेवाड़ के अन्दर।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइंड अप कीजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः दस मिनट का समय था, साढे नौ मिनट हो गये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि कुम्भलगढ़ किला विश्व का ऐतिहासिक किला है। पिछले पांच साल में इनकी सरकार ने वहां पर इतने अतिक्रमण करवाये, वहां अजान प्रारम्भ करवायी, इसलिए मैं हमारी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन अतिक्रमणों को तत्काल वहां से हटाया जाये और अजान वहां पर पाबंद की जाये।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः सदन की कार्यवाही 6 फरवरी 2025 के प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.41 बजे गुरुवार, दिनांक 6 फरवरी 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)